LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Tuesday, August 6, 2024 / Sravana 15, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, August 6, 2024 / Sravana 15, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **1A – 30**
(S.Q. NO. 201 – 204)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **31 – 50**
(S.Q. NO. 205 – 220)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **51 – 280**
(U.S.Q. NO. 2301 – 2530)

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Tuesday, August 6, 2024 / Sravana 15, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, August 6, 2024 / Sravana 15, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 92

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 70TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING – LAID 292

Shri Rajiv Ranjan Singh *Alias* Lalan Singh

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 31ST REPORT OF STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ – LAID 293

Prof. S.P. Singh Baghel

OBSERVATION RE : STAGING OF DHARNA AND PROTESTS AT THE GATES OF PARLIAMENT HOUSE 293

MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE 294 - 319

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 320 - 33

Dr. K. Sudhakar 320

Shri P. P. Chaudhary 320

Shri Vishnu Dayal Ram 321

Shrimati Kamaljeet Sehrawat 321

Dr. Hemant Vishnu Savara 322

Shri Dilip Saikia 322

Shri Shankar Lalwani 323

Shri Mitesh Patel (Bakabhai) 323

Shrimati Manju Sharma 324

Shri Bhartruhari Mahtab 324

Shri Avimanyu Sethi 325

Dr. Lata Wankhede 325

Shrimati Anita Subhadarshini 326

Shri Ummeda Ram Beniwal 326

Shri Rahul Kaswan 327

Shri Kodikunnil Suresh 327

Sushri Praniti Sushilkumar Shinde 328

Shri V. K. Sreekandan 328

Shri Aditya Yadav 329

Shri Ramashankar Rajbhar 329

Shri Kirti Azad 330

Shri Murasoli S. 330

Dr. Byreddy Shabari 331

Shri Naresh Ganpat Mhaske 331

Shrimati Shambhavi 332

Shri Navaskani K. 332

Shri Joyanta Basumatary 333

Shri Vishaldada Prakashbapu Patil 333

FINANCE (No.2) BILL, 2024 334 - 85

Motion for Consideration 334

Shrimati Nirmala Sitharaman 334

Dr. Amar Singh 334 - 38

Dr. Nishikant Dubey 339 - 48

Shri Neeraj Maurya 349 - 52

Sushri Mahua Moitra 353 - 61

… 362

Shri Arun Nehru 363 - 68

Shri Lavu Shrikrishna Devarayalu 369 - 74

Shri Ramprit Mandal 375

Shrimati Supriya Sule 376 - 85

STATEMENT RE: RECENT DEVELOPMENTS IN BANGLADESH #386 - 87

Dr. Subrahmanyam Jaishankar

FINANCE (No.2) BILL, 2024 388 - 436

(Contd. – Inconclusive)

Shri Deepender Singh Hooda 388 - 92

Shri Basavaraj Bommai 393 - 400

Shri Abhay Kumar Sinha 401

Shrimati Shambhavi 402 - 06

Shri Ramashankar Rajbhar 407 - 08

@ Sushri S. Jothimani 409

Shri Anil Yashwant Desai 410 - 12

Shri P.P. Chaudhary 413 - 21

Shri K.E. Prakash 422

Shri Y.S. Avinash Reddy 423 - 24

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Sushri S. Jothimani in Tamil, please see the Supplement (PP 409A to 409D).

 # For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri K.E. Prakash in Tamil, please see the Supplement (PP 422A to 422D).

@ Shri R. Sachithanantham	**425**
Shri Tanuj Punia	**426 - 28**
# Dr. D. Ravikumar	**429**
Shri Sudama Prasad	**430 - 31**
% Shri Navaskani K.	**432**
Shri Rao Rajendra Singh	**433 - 36**

@ For English translation of the speech made by the Hon. Member, Shri R. Sachithanantham in Tamil, please see the Supplement (PP 425A to 425B).

 # For English translation of the speech made by the Hon. Member, Dr. D. Ravikumar in Tamil, please see the Supplement (PP 429A to 429B).

% For English translation of the speech made by the Hon. Member, Shri Navaskani K. in Tamil, please see the Supplement (PP 432A to 432D).

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, August 6, 2024 / Sravana 15, 1946 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS **PAGES**

XXX XXX XXX XXX

Xxx xxx xxx xxx

Xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

FINANCE (No.2) BILL, 2024 **409A - 09D & 422A - 22D & 425A - 25B & 429A - 29B & 432A - 32D**

xxx xxx xxx xxx

Sushri S. Jothimani **409A - 09D**

xxx xxx xxx xxx

Shri K.E. Prakash **422A - 22D**

xxx xxx xxx xxx

Shri R. Sachithanantham **425A - 25B**

xxx xxx xxx xxx

Dr. D. Ravikumar **429A - 29B**

xxx xxx xxx xxx

Shri Navaskani K. **432A - 32D**

xxx xxx xxx xxx

(1100/KDS/SNT)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगाँठ के विषय में उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज से 79 वर्ष पूर्व दिनांक 6 अगस्त और 9 अगस्त, 1945 को क्रमश: हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी, तथा लाखों लोग घायल हुए थे या जीवन भर के लिए अपंग हुए थे। इस घटना ने पहली बार मानवता का परमाणु बम की विभीषिका से परिचय कराया था। इस घटना के इतने वर्षों बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी परमाणु विकिरण के खतरनाक दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। आज अवसर है कि हम विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुन: दोहराएं। यह सभा परमाणु हथियारों को समाप्त करने और वैश्विक शांति, सद्भावना और मैत्री की भावना के प्रसार के लिए सामूहिक रूप से संकल्प लेती है। अब यह सभा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित व्यक्तियों की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगी।

(सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या-201,

श्री नव चरण माझी

(प्रश्न 201)

श्री नव चरण माझी (मयूरभंज) : स्पीकर सर, दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड प्रक्रिया को मजबूत करने तथा देश में फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों और फर्जी यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, ताकि पात्र व्यक्तियों को उनका अधिकार मिल सके?

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सरकार दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दिव्यांगजन को विशिष्ट पहचान-पत्र जारी करने के उद्देश्य से यूडीआईडी कार्ड योजना लागू की गयी है। वर्ष 2017 में इसकी स्थापना के बाद से अभी तक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 783 जिलों में 1 करोड़ 12 लाख, 22 हजार 237, जिसमें 74 लाख, 24 हजार 110 पुरुष और 37 लाख 98 हजार 125 दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाने का नया संस्करण 6 मई को शुरू किया गया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजनों के प्रति सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में जिस संवेदनशीलता के साथ कदम बढ़ाए गए हैं, उसमें यूडीआईडी कार्ड योजना आने वाले समय में दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

श्री नव चरण माझी (मयूरभंज) : ओडिशा राज्य के दिव्यांगजनों के पुनर्वास व आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभाग द्वारा क्या पहल की गई है तथा दिव्यांगजनों के लिए ओडिशा में कोई कौशल विकास केंद्र काम कर रहा है? ओडिशा में पिछले 24 वर्षों के अंतराल में कितने दिव्यांगजनों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी मिली है और बहुत से दिव्यांग खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत के नाम को बहुत से खेलों में गौरवान्वित किया है। उनके भविष्य के लिए पिछली ओडिशा सरकार ने क्या-क्या सहायता और आर्थिक मदद की है? पिछली ओडिशा सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सरकारी भत्ते को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है?

(1105/SPS/AK)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा बहुत सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके जानकारी मांगी गई है। जहां तक उनके द्वारा ओडिशा राज्य में दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सशक्तिकरण की बात की गई है तो केन्द्र सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पूरे देश के सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों में उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में उनके लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, राष्ट्रीय फेलोशिप, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और इसके साथ ही साथ उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ जोड़े जाने के भी उपाय किए जा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने खेलों के संबंध में बात की है और एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इस प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 के बाद देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया गया, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जो दिव्यांगता की सात श्रेणियां थीं, उनको बढ़ाकर 21 किया गया। जो

सरकारी उच्च शैक्षिक स्कूल्स हैं, कॉलेजेज़ हैं, उनमें एडमिशन के लिए तीन परसेंट से बढ़ाकर पांच परसेंट किया गया। बेंचमार्क सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण बढ़ाकर चार परसेंट किया गया। उन्होंने खेलों का भी उल्लेख किया है तो मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ग्वालियर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से लगभग 170 करोड़ रुपये की लागत से एक दिव्यांग खेल केन्द्र प्रारम्भ किया गया है। उसमें दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तरह-तरह के खेलों के कोर्ट्स का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें दौड़ने से लेकर स्वीमिंग पूल, बैडमिंटन, हॉकी, बॉलीवॉल तथा सब तरह के खेलों के अलग-अलग कोर्ट्स का निर्माण कराया गया है। यह दिव्यांगजनों के लिए समर्पित देश का पहला खेल केन्द्र है, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से प्रारम्भ किया गया है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में जिस तरह से खेल-कूद की गतिविधियों में दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों का परिणाम यह है कि जो ओलम्पिक खेल टोक्यों में हुए थे, फिर ओलम्पिक के बाद पैरा ओलम्पिक खेलों का आयोजन हुआ था। उन पैरा ओलम्पिक खेलों में हमारे देश से 54 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे। इसमें हमारे दिव्यांग खिलाड़ी 19 मेडल जीतकर आए थे। इसी तरह से उसके पहले ब्राजील रियो में हमारे 19 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे और चार मेडल जीतकर आए थे। यह ओलम्पिक खेल वर्ष 2016 में हुए थे। वर्ष 2016 के बाद टोक्यो ओलम्पिक का चार साल के बाद दूसरा खेल हुआ था, जिसमें हमारे देश के 54 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए और 19 मेडल जीतकर आए। यह इस बात को बताता है कि आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित भावना के साथ काम कर रही है। उन्होंने जहां तक दिव्यांगजनों की पेंशन का प्रश्न उठाया है तो पेंशन के संबंध में सभी राज्य सरकारों की अलग-अलग राशियां होती हैं। वह राशि कहीं कम दी जाती है, कहीं ज्यादा दी जाती है।

मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि उन्होंने ओडिशा के संबंध में कुछ जानकारी चाही थी। ओडिशा राज्य के कटक में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसमें रोगी उपचार के लिए 200 बिस्तर के अस्पताल की सुविधा है। यह अस्पताल दिव्यांगजनों के लिए सर्जीकल सुधार की पेशकश करने वाला एक बड़ा अस्पताल है। यह नैदानिक उपचार, चिकित्सकीय सेवाओं, सहायक उपकरण समर्थन के साथ दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण का काम भी किया जाता है। इसके साथ ही साथ ही आजीविका के सृजन के लिए कौशल विकास के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का काम उस केन्द्र के माध्यम से किया जाता है। इस केन्द्र में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही साथ भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास से संबंधित विभाग हैं, जो विकृति सुधार जैसी महत्वपूर्ण सर्जरी को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्रोथेटिक्स, ऑर्थोटिक्स विभाग है और कृत्रिम अंग दिव्यांगजनों के लिए बनाए जाते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री रवि किशन जी – उपस्थित नहीं।
श्रीमती प्रतिमा मण्डल।

(1110/UB/SPS)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, despite conducting identification camp, with the help of the Ministry of Social Justice & Empowerment and the local administration receive artificial limbs and other rehabilitation aids, physically challenged persons are facing a challenge. Sometimes, we are unable to distribute the materials to the identified persons. Physically challenged people come with high expectations that they would receive these materials and aids in the camps. I personally met our hon. Minister a couple of times and shared this problem. Other hon. Members from West Bengal also are facing this problem in their constituencies.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government has formulated any plan to solve this problem and whether the Ministry has conducted any meeting with ALIMCO Kanpur which provides these artificial limbs and other rehabilitation aids.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण का वितरण करने के लिए माननीय सदस्य के द्वारा एलिम्को कानपुर का उल्लेख किया गया है। जो 60 वर्ष पुराना संस्थान था, जिसकी निर्माण क्षमता काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच रही थी। एक समय स्थिति यह थी कि एलिम्को प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर आ गया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के द्वारा 200 और 138 करोड़ रुपये एलिम्को के द्वारा लगाकर एलिम्को का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे एलिम्को की लगभग ढाई गुणा उत्पादन क्षमता बढ़ने वाली है। पहले वहां जिस तरह के सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य किया जाता था, तो पहले के उपकरण और आज के उपकरणों में बहुत बड़ा मूलभूत अंतर आया है। पहले ब्लैक कलर की ट्राई साइकिल, ब्लैक कलर की बैसाखी और ब्राउन कलर की दी जाती थीं, लेकिन आज वहां पर ब्लू कलर, यलो कलर, रेड कलर, सिल्वर ग्रे कलर और तरह-तरह के कलरों का उपयोग करके सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। देश भर में इस एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण करने के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा या राज्यों से अनुरोध या प्रस्ताव आता है। इसमें डॉक्टर्स के बोर्ड के द्वारा परीक्षण कराया जाता है। जिन दिव्यांगजनों के दिव्यांगता के प्रमाण पत्र होते हैं, उनका भी डॉक्टर्स के द्वारा परीक्षण किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि किस दिव्यांगजन को किस तरह के उपकरण की आवश्यकता है। किसी को कान की मशीन की आवश्यकता है, किसी को बैसाखी की आवश्यकता है, किसी को ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को मोटर साइकिल की आवश्यकता है, किसी को कमोड

चेयर की आवश्यकता है, इस तरह की अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए कैम्प के बाद सहायक उपकरणों को वितरण करने का काम किया जाता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि एडिप योजना के अंतर्गत देश भर में 16,571 वितरण शिविरों के माध्यम से 2079.52 करोड़ रुपये की लागत से 28.97 लाख दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं और एलिम्को का आधुनिकीकरण किया गया है। समय-समय पर एलिम्को के साथ में हमारी बैठकें भी होती रहती हैं। हम और हमारे साथी राज्य मंत्री वहां पर दौरा करके आने वाले समय में इसकी उत्पादन क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि बढ़ी हुई मांग के अनुरूप पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

श्री परषोत्तमभाई रुपाला (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। दिव्यांग बच्चों और खासकर दृष्टिबाधित बच्चों के पढ़ने और उनकी सुविधा के लिए जो लिपि होती है, उसको ट्रांसलेट करके ऑडियो की फॉर्म में करने का काम कच्छ-भुज की एक संस्था कर रही है। दिव्यांगजनों की सेवा के लिए हमारे गुजरात की एक बहन मुक्तबेन को पदमश्री का अवार्ड देकर संवेदनशीलता का परिचय इस सरकार ने दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देते हुए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस ऑडियो लाइब्रेरी को बढ़ावा देने की कोई योजना सरकार के इस विभाग के पास है? यदि है तो कृपया बताने का कष्ट करें।

(1115/MK/SRG)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा देश भर के हमारे इस तरह के जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगता अलग-अलग तरह की होती है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनकी अलग-अलग तरह की आवश्यकताएं होती हैं। इन्होंने दृष्टि बाधित दिव्यांगता का उल्लेख किया है। ऑडियो-विजुअल माध्यम से गुजरात का उदाहरण भी उनके द्वारा दिया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, हमारे 9 संस्थान पूरे देश में काम कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन दृष्टि बाधित राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। यह संस्थान इस दिशा में विशेष रूप से काम कर रहा है, अनुसंधान भी कर रहा है। ब्रेल प्रेस की स्थापना भी देश भर में की गई है। 25 ब्रेल प्रेस देश में काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ साइन लैंग्वेज के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराये जाने का काम भी किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि देहरादून का जो हमारा नेशनल इंस्टिट्यूट है, वहां पहली बार साइंस और मैथ्स की क्लास 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों से प्रारंभ की जा रही है, जिसमें ब्रेल लिपि के माध्यम से जार और परखनली में उभरे हुए अक्षरों को लगाया गया है। आज हमारे दृष्टि बाधित छात्र और छात्राओं के लिए 11वीं कक्षा का बैच शुरू किया गया है। अगली बार 12वीं कक्षा के लिए किया जाएगा। हम सीआरसी के माध्यम से भी उन विद्यार्थियों के लिए इस तरह की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए निरंतरता के साथ प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे जो दृष्टि बाधित छात्र हैं, उनके लिए तरह-तरह के कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर

उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें उनके लिए आईटीआई और निजी क्षेत्र के जो आईटीआईज हैं, उनके माध्यम से सीओपीए, कटिंग, सिलाई, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बाल व त्वचा की देखभाल, मेटल कटिंग, इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। … (व्यवधान)

दादा, काम किए जा रहे हैं, इसलिए बताए जा रहे हैं। यदि काम नहीं किया होता तो कैसे बताते।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे मेरे मन जो सवाल था, उसका मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। लेकिन, मेरा एक सवाल रह गया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर, ग्वालियर में है, आपने पैरा ओलम्पिक खिलाड़ियों को जो बखशीश मिला, उसके बारे में बात की, लेकिन एक बात नौकरी की है। उनकी नौकरियों के बारे में जो बात हो रही है, वह अभी भी पूरी नहीं हो रही है। यह सेंटर जो ग्वालियर में हैं, देश के अन्य राज्यों में इस तरह का सेंटर कब खुलेगा? खासकर हमारे महाराष्ट्र में बालेवाडी स्टेडियम है, अगर वहां यह सुविधा मिलेगी तो अच्छा रहेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर अन्य राज्यों में भी खुलेंगे और महाराष्ट्र में कब खुलेगा?

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से दिव्यांगजनों के लिए जो दिव्यांग खेल केंद्र, ग्वालियर में प्रारंभ किया गया है, उसके संबंध में अपनी जिज्ञासा रखी है और पैरा ओलम्पिक खिलाड़ियों का भी उल्लेख किया है। मैं माननीय सांसद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय, खेल-कूद की गतिविधियों में दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा नेशनल इंस्टिट्यूट तो काम कर ही रहा है। नेशनल इंस्टिट्यूट के साथ-साथ देश भर में हमारे जो 9 नेशनल इंस्टिट्यूट्स हैं, उसके साथ-साथ हमारे 25 सीआरसीज हैं, उनके माध्यम से भी हम विभिन्न तरह की सुविधाएं और सहायक उपकरणों के वितरण का काम करते हैं। उनके खेल-कूद की गतिविधियों को बढ़ाने के क्षेत्र में भी वहां के राज्य सरकार के साथ, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग लेते हुए समय-समय पर खेल-कूद की गतिविधियों को बढ़ाने का काम किया जाता है।

DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR): Sir, with regard to persons with disabilities, especially blind persons, is the Government going to include them into the skill development and internship programmes? What arrangements have been made to provide them employment and jobs in future?

(1120/SJN/RCP)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की नौकरियों के संबंध में बात कही गई है। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के उत्तर में बताया था कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दवारा कौशल विकास का कार्यक्रम एमएसएमई के साथ मिलकर, देश भर में कौशल विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन प्रशिक्षित होने के लिए आगे आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो आंकड़े आए थे, निजी कंपनियों ने दिव्यांगता रखने वाले लगभग 10,000 योग्य व्यक्तियों की मांग की थी।

मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसमें कौशल विकास और रोजगार सेतु का निर्माण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया गया है, जो नियोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच में सेतु बनने का काम करता है। लगभग 10,000 नौकरियों में से मात्र 827 रिक्तियां शेष रह गई हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इसके प्रति पूरी सजगता के साथ अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है और विषय भी बहुत गंभीर है। मैं अगले सत्र में यह प्रयास करूंगा कि इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा हो जाए।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महोदय, मेरा एक छोटा-सा सवाल है। मंत्री महोदय बहुत अच्छी स्कीम लेकर आए हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने सारी स्कीम का लाभ अकेले ही उठा लिया।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, In our Pune district, we are among the toppers in the country for this scheme. मेरी मंत्री जी से यह विनती है कि अभी तक सारा सामान नहीं आया है, क्योंकि बजट नहीं था। वहां सब लोगों को मेरिट पर मिला है। देश के अन्य टॉपर्स की तुलना में महाराष्ट्र के पुणे जिले में उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में इस बजट में सोचा जाए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा सुझाव दिया गया है। इस संबंध में जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो सभी विभागों के द्वारा इन सारी चीजों को वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जाता है। हम इस बात के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि देशभर में जहां-कहीं से भी दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की जरूरतों के प्रस्ताव आते हैं, हम उनको बजटीय उपलब्धता के आधार पर पूरा करने का प्रयास करते हैं।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : कोई कमी नहीं है।

(प्रश्न 202)

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ा है?

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, उन प्रयासों का अच्छा प्रभाव पड़ा है। वामपंथी उग्रवाद इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है, खतरा है।

महोदय, वामपंथी उग्रवादियों का न तो भारत के संविधान में विश्वास है, न ही भारत के लोकतंत्र में विश्वास है। भारत राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों पर इनको कोई भरोसा नहीं है। वे हिंसा के माध्यम से सत्ता हथियाना चाहते हैं। इन्हें न तो लोकतंत्र में विश्वास है और इस विचारधारा वाले सारे संगठन भारत की मूल भावनाओं पर हमेशा प्रहार करते रहते हैं। इन वामपंथी उग्रवादियों ने हजारों-हजार निर्दोष लोगों की हत्या की है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो यह बताओ कि इसमें वर्ष 2010 से लेकर अभी तक कितनी कमी आई है।

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, इसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। जो प्रभाव पड़ा है, मैं इस सदन और देश के माध्यम से उसको तुलनात्मक आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूं।

महोदय, जो एलडब्ल्यूई हिंसा की घटनाएं मई, 2004 से लेकर अप्रैल, 2014 तक घटित हुई थीं, वे 16,274 थीं। मई, 2014 से लेकर अप्रैल, 2024 तक जो घटनाएं हुई हैं, वे 7,696 हैं, जिसमें 53 प्रतिशत की कमी आई है।

(1125/MM/PS)

महोदय, हमारे सुरक्षा बलों के जिन जवानों ने अपना जीवन खोया है, जब विपक्ष की सरकार थी, वर्ष 2004 से 2014 के बीच, 1824 जवानों ने अपनी जान गवांयी थी, लेकिन एनडीए की मोदी सरकार के इन दस वर्षों में 509 जवान शहीद हुए हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो 72 प्रतिशत की कमी हुई है। जिन नागरिकों ने अपना जीवन खोया है, विपक्ष की सरकार के समय में, वर्ष 2004 से 2014 के बीच में, 4744 नागरिकों ने अपना जीवन खोया है। मई, 2014 से 2024 के बीच 1481, यह भी ठीक नहीं है, लेकिन नागरिकों की जान गंवाने में कमी आयी है। वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की जाने वाली हत्याओं में 69 प्रतिशत की कमी आयी है। एलडब्ल्यूई हिंसा में जान गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों के शहीद जवानों को कुल-मिलाकर देखें तो यह 6568 हुई थी। यह घटकर वर्ष 2014-24 में 1990 रही है। इसमें 70 प्रतिशत की कमी आयी है। इस प्रकार से जान गंवाने वाले तथा शहीद सुरक्षाकर्मियों की संख्या, जो पहले वर्ष 2010 में थी, उसमें 86 प्रतिशत की कमी आयी है। हिंसा की घटनाओं में 73 प्रतिशत की कमी आयी है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष 2013 तक 126 जिले वामपंथी हिंसा से प्रभावित थे। यह अब वर्ष 2024 में घटकर केवल 38 जिले रह गए हैं। वर्ष 2010 में 96 जिले थे जो कम होकर वर्ष 2023 में 42 जिले रह गए हैं। वर्ष 2010 में 465 थानों में एलडब्ल्यूई का प्रभाव था, जो वर्ष 2023 में घटकर 100 थानों तक रह गया है। वर्ष 2024 के मात्र छ: महीनों में 166 वामपंथियों को मार गिराया गया है। यह एक रिकॉर्ड है। इन छ: महीनों में 600 से ज्यादा वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया

है। यह दर्शाता है कि दस वर्षों की श्री नरेन्द्र मोदी जी की एनडीए सरकार के नेतृत्व में, उनके संकल्प और प्रेरणा से, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो प्रयास किए गए हैं, उसका प्रभाव स्पष्ट दिखायी पड़ता है और आगे आने वाले दिनों में भारत से वामपंथी उग्रवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा।

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण विकास योजना चलायी जा रही है?

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना बनायी गयी है। माननीय सदस्य ने वामपंथ प्रभावित जिलों में विकास कार्य के बारे में प्रश्न पूछा है, उसका ही एक शीर्षक है, जिसमें सुरक्षा के उपाय और विकास के उपाय, नागरिकों के अधिकार तथा हकदारियां सुनिश्चित करने सहित कई उपाय शामिल हैं। राज्यों की क्षमता निर्माण, केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, फ्लैगशिप योजनाओं के अतिरिक्त कई विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह विकास को सुनिश्चित करने में बहुत सहायक हुए हैं।

महोदय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता के लिए सहायता प्रदान की जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभा

वित जिलों के लिए स्पेशल सेंट्रल असिसटेंस स्कीम चलायी जाती है। इस स्कीम में प्रभावित जिलों, डिस्ट्रिक ऑफ कंसर्न में सार्वजनिक संरचना तथा सेवाओं में मौजूद कमी को पूरा करने के लिए कार्य किया जाता है।

(1130/YSH/SMN)

इस स्कीम के अंतर्गत 3,450 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सड़क के क्षेत्र में दो प्रकार की योजनाएं चलती हैं। एक तो 'सड़क आवश्यकता योजना' है और दूसरी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 'सड़क सम्पर्क परियोजना' है। दोनों के माध्यम से काफी काम होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, 12 हजार 230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 12 हजार 228 किलोमीटर सड़क, यानी 1,347 सड़कें और 700 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 9 हजार 237 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है और 420 पुल बनाए गए हैं तथा 898 सड़कें पूर्ण रूप से निर्मित की जा चुकी हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी भी वहां अच्छी तरह से स्थापित की जा रही है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 10 हजार 449 मोबाइल टावर्स प्लान किए गए हैं, इनमें से 5 हजार 139 टावर्स चालू कर दिए गए हैं।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास की योजनाएं भी चल रही हैं। 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई एवं 61 कौशल विकास केन्द्र, एडीसीए की स्थापना के लिए क्रियान्वयन जारी है। अब तक 46 आईटीआई और 49 एडीसीए क्रियाशील हो चुके हैं। केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय की भी स्थापना की गई है। केवीसी और नवोदय विद्यालय सुनिश्चित करने हेतु 11 केन्द्रीय विद्यायल और 6 नवोदय विद्यालय खोल दिए गए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय वहां पर अच्छी तरह से कार्यरत हैं और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में

254 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं, उनमें से 130 क्रियान्वित हैं। वहां वित्तीय समावेशन की भी योजनाएं चल रही हैं। अब तक 5,371 डाकघर खोले गए हैं। 1,007 बैंक की शाखाएं खोली गई हैं और 937 एटीएम्स भी चालू किए गए हैं।

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAGAON): Sir, I would like to ask a question related to this particular topic. The House is aware that India's North-East is surrounded by several, at least four, sovereign foreign countries and we have seen that in the last 50 years whenever or wherever there is not so friendly Government installed or take route in any of these countries, there seems to be an umbilical cord or connection with the insurgency in the North-East.

Sir, considering this, what would be the perspective plan of the Government to contain the insurgency in the North-East?

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। यह वामपंथी उग्रवाद पर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में इतना काम किया गया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस बारे में माननीय गृह मंत्री जी बता रहे हैं।

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य सूचना दे दें तो मैं इसकी डिटेल दे दूंगा। वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों के अनुसार ही हिंसा के हेड में पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगभग 60 प्रतिशत से ज्यादा हिंसा में कमी हुई है। परंतु, यह प्रश्न आज के प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट है कि इस पर अलग से नोटिस दिया जाए।

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): Thank you Speaker Sir for giving me this opportunity to ask a supplementary question. Left wing extremism is a problem, which has plagued Andhra Pradesh and even attempted on the life of our leader and hon. Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu. In response, a select unit of police officers called the Grey Hound Commanders was established. They recently won the top honours at the 14th All India Police Commando Competition.

Would the hon. Minister clarify the current status of the training of the Grey Hound Commandos, the steps undertaken and also the timeline for additional training infrastructure, if any?

(1135/RAJ/SM)

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, प्रशिक्षण के लिए ग्रेहाउंड्स को चुना गया है। राज्यों की पुलिस और केन्द्रीय पुलिस बलों की ग्रेहाउंड्स में राज्यों के साथ मिल कर वहां ट्रेनिंग देते हैं। भारी मात्रा में ट्रेनिंग दी गई है। वहां आंध प्रदेश की पुलिस को भी उस संस्था से ट्रेनिंग दी जाती है। आंध्र प्रदेश में भी वामपंथी उग्रवाद में काफी कमी आई है, अभी मैंने जिसका आकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर दिया है। उस प्रकार से अब वह आंध्र प्रदेश में भी सिमट कर रह गया है। आंध्र प्रदेश के लिए माननीय सदस्य चिंतित हैं। यह चिंता सभी की है, लेकिन चिंता बहुत हद तक दूर कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के विषय में जो प्रशिक्षण की बात है, हम अच्छी तरह से ग्रेहाउंड्स में प्रशिक्षण देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री सौगत राय जी।

आज आप बैठे-बैठे प्रश्न नहीं पूछिए।

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सर, मैं खड़ा होकर प्रश्न पूछ रहा हूं।

सर, वामपंथी उग्रवादी की समस्या 10-15 सालों में तीन-चार प्रांतों में हो रहा है। यह सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, उसके बाद ओडिशा का कोरापुट, उसके बाद आंध्र प्रदेश के कुछ अंश में है। अभी भी मैं हर हफ्ते देखता हूं कि सिक्योरिटी फोर्स के साथ माओवादियों का एनकाउंट हुआ। यह बंद नहीं हुआ है। मैं आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी उग्रवाद हुआ, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी की सरकार ने डेवलपमेंट का जो कार्य किया है और ट्राइबल लड़कों को नौकरी दिया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है?

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सर, मेरा सवाल यही है कि वहां केवल एक किशनजी को मारना पड़ा।... (व्यवधान) अभी पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद बंद हो गया। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे और वही मॉडल छत्तीसगढ़ एवं दूसरे जगहों पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं?... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, कोई भी राज्य अच्छा करे, उसके उदाहरण को पूरे देश में लागू करने में नरेन्द्र मोदी सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए।...(व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 203)

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सर, मेरा सीधा सवाल माननीय मंत्री जी था कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को आसान तरीके से कैसे मिलेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है, जब वह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो देश के किसानों को क्या समझ में आएगा?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सर, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरी जो पीड़ा है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप मेरे संरक्षक हैं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फसल बीमा का लाभ जब खेतों की खड़ी फसल में आग लग जाती है, तो उसे क्यों नहीं कवर किया जाता है, किसानों को उसका लाभ क्यों नहीं मिलता है? उसी के साथ-साथ जो किसान बंटाई पर खेती करते हैं और बंटाई पर खेती करने वाले किसानों का भारी नुकसान होता है, उसे सरकार संज्ञान में नहीं लेती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र चंदौली में करीब हजारों एकड़ में खड़ी फसल जल गई, तो क्या उनको उसका लाभ मिलेगा? हमारे जो बटाईदार कृषक हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं यह उत्तर सीधा-सीधा चाहता हूं।

(1140/KN/RP)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का आदर करता हूं। अगर ऐसा उत्तर भी उन्हें समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य है कि मैं कैसा उत्तर दूं? लेकिन किसान समझदार हैं। मैं इसका भी उदाहरण दे रहा हूं। मैं उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। जो पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाएं थीं, उनमें कई तरह की कठिनाइयां थीं। अनेक फसल बीमा योजनाएं उधर की सरकार भी लाई थी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज इस पर बहुत सारे प्रश्न है।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल माननीय सदस्य नहीं, बल्कि किसान भी जानना चाहते हैं। कई फसल बीमा योजनाएं थीं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा। लेकिन किसानों के लिए उच्च प्रीमियम थे, जो दे नहीं पाता था, अपर्याप्त दावे थे, बीमित राशि कम मिलती थी, दावों के निपटान में विलंब होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को और किसान संगठनों को कई तरह की आपत्तियां थीं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि जब से यह फसल बीमा योजना आई है, आप तुलना करके देख लीजिए। पहले केवल 3 करोड़ 51 लाख आवेदन आते थे, लेकिन अब 8 करोड़ 69 लाख आवेदन आए हैं, क्योंकि किसानों को भरोसा है। किसानों को यह समझ में आ रही है। जब इनकी सरकार थी तो गैर ऋणी कैटेगरी में केवल 20 लाख आवेदन आते थे, लेकिन अब 5 करोड़ 48 लाख आए हैं। ... (व्यवधान) जब उधर की सरकार थी तो कुल किसान आवेदन 3 करोड़ 71 लाख आए थे, अब 14 करोड़ 17 लाख आए हैं। सकल

बीमित राशि बढ़कर 2 करोड़ 71 हजार 295 हो गई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। … (व्यवधान) मैं आपकी बात पर आ रहा हूं।… (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : आप कहानी मत बताइये।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई है। किसानों ने 32 हजार 440 करोड़ रुपये प्रीमियम दिया है। इस फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये का क्लेम दिया गया है। … (व्यवधान) भाइयों का भी ख्याल है, इसलिए तो मामा हूं। माननीय सदस्य, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अगर नेचुरल कारण से फसल खराब होती है तो वह पूरी की पूरी कवर्ड है और किसान को उसका लाभ मिलता है। राज्य सरकार के सर्टिफिकेट के आधार पर बटाईदारों का भी कवरेज है। इसलिए आप चिन्ता मत कीजिए। अगर राज्य सरकार सर्टिफाई करती है तो हम बटाईदारों को भी कवर करते हैं और उनको भी इस योजना में सम्मिलित करते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र चंदौली लोक सभा क्षेत्र में हजार एकड़ में आग लगी और वहां फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। उनको बहकाने-फुसलाने के लिए आप लोगों ने मंडी समिति से थोड़े-थोड़े पैसे देकर बहलाने का काम किया है, जो बड़ा ही दु:खदायी है। मैं आपसे केवल पूछना चाहता हूं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बता दीजिए कि फसल बीमा योजना में आग आती है या नहीं?

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही आग्रह किया है।… (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : आप सीधे-सीधे कहिये कि उसमें आग नहीं आती है।… (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : जितने भी प्राकृतिक कारण हैं, वे सब के सब कवर्ड हैं। अगर प्राकृतिक कारणों से आग लगेगी तो उसमें आग भी कवर्ड है। उसमें क्या दिक्कत है?

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह देखा गया है कि जो कृषक मजदूर हैं … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी जी।

(1145/VB/NKL)

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that there are thousands of farmers in the Nandurbar district living in the forest areas and mountainous regions, who are not being able to get the benefit of the PM Fasal Bima Yojana. … (*Interruptions*) Their photographs have to be uploaded within 48 hours. But unfortunately, due to network and internet problems, they could not upload their photographs. So, how would you tackle this issue? This is a very big issue. To get the benefit, not just under this Yojana but under any other Yojana of your Government, people have to connect to the internet. But the internet

facility is not there, and the problem always remains pending. So, how do you try to tackle this issue?

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि डीजी क्लेम के नाम से एक पोर्टल बनाया हुआ है। किसान को किसी कारण से लाभ नही मिल रहा हो, जब वे इसकी शिकायत करते हैं, तो इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। अगर नेटवर्क की कोई समस्या है, तो उसका भी समाधान करने का हम प्रयत्न करेंगे।

श्री भारत सिंह कुशवाह (ग्वालियर) : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से ऋणि किसान कितने थे, बीमित किसान कितने थे और सकल बीमित राशि कितनी थी?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आजकल सदन को अवगत हो जाना चाहिए कि बीमा कराना स्वेच्छा से किसान के ऊपर निर्भर करता है। किसान चाहे तो बीमा कराए, चाहे तो न कराए। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, तो कई बार लोगों को यह जानकारी नहीं होती है। बीमा कराना कम्पल्सरी नहीं है, यह स्वैच्छिक है।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप फसल बीमा की डिटेल्स बता दें।

श्री शिवराज सिंह चौहान : जब पुरानी फसल बीमा योजना थी, तो उस समय जो बैंक का ऋणी रहता था, उसका बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था। बीमा की प्रीमियम की राशि को बैंक अपने आप काट लेता था। सरकार ने इस विसंगति को दूर किया और इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया। अपनी मर्जी है, तो बीमा कराएं और मर्जी नहीं है, तो बीमा न कराएं। इस योजना में बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं है। पहले अऋणी किसान बीमा नहीं करवाता था, लेकिन अब वह भी चाहे तो बीमा करवा सकता है।

माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आज तक कितना क्षेत्र कवर हुआ है, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि अब तक इसमें 5 लाख 1 हजार हेक्टेयर क्षेत्र कवर हुए हैं, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 5 लाख 98 हजार हेक्टर हो गया है। इसमें 3 करोड़ 97 लाख किसान कवर हुए हैं। किसान निरंतर फसल बीमा योजना को अपनाने का काम कर रहे हैं।

महोदय, योजनाओं को सरल बनाने के अनेक उपाय सरकार ने किये हैं, जिसके कारण योजना का लाभ लेने में किसानों को दिक्कत और परेशानी न हो।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक लाभदायक योजना मानी जाती है। इससे आकस्मिक फसलों के नुकसान की भरपाई भी होती है। लेकिन हमारे बिहार राज्य में फसल बीमा की प्रीमियम अन्य राज्यों की तुलना में तीन गुना

ज्यादा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि बिहार में फसल बीमा की प्रीमियम को तर्कसंगत बनाया जाए।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अलग-अलग तीन मॉडल्स हैं। केन्द्र सरकार केवल पॉलिसी बनाती है। लेकिन राज्य सरकार जिस मॉडल को चुनना चाहे, उस मॉडल को चुनती है।

(1150/PC/VR)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मॉडल चुनने के बाद बीमा कंपनियां प्रतिस्पर्धी दरों पर, क्योंकि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कई बीमा कंपनियां, फसल बीमा योजना लागू करने का काम करती हैं। यह फसल बीमा योजना हर राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। जो राज्य इसे अपनाना चाहें, अपनाएं, जो राज्य नहीं अपनाना चाहें, वे न अपनाएं। बिहार ने अभी तक प्रधान मंत्री फसल बीमा को अपने यहां लागू नहीं किया है। बिहार राज्य की एक अपनी योजना है। वे उस योजना के हिसाब से अपने किसान को लाभांवित करते हैं।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, the Standing Committee on Agriculture in its Report on the 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: An Evaluation' on 10th August 2021 had highlighted several key issues. One of the important things it mentioned was about the delay in settlement of the insurance claims to the farmers. It is a very complicated process to get the claims. For example, during the last December in 2023, we had an unprecedented flood in my constituency Thoothukkudi. Many of the farmers, who have insured their crops, have not got the claims settled even after seven months. They have not got any money from the insurance companies. They are still waiting for that.

In a reply, the hon. minister has said that there is no proposal for constituting a Committee of Experts on simplification of the rules on crop insurance. Will the hon. Minister reconsider that because it is a quite complicated process as it goes district-wise? Unless the crop failure is district-wise, sometimes they do not give the insurance. So, it is very complicated. Will the Government consider constituting a committee to simplify it further?

I would also like the hon. Minister to reply about the farmers of my constituency, Thoothukkudi. Thank you, Sir.

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना पूरे देश के हर जिले के, हर किसान के लिए है। योजना की इकाई भी, पहले कभी विसंगतियां होती थीं, जब ब्लॉक को इकाई बना दिया जाता था। अब ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया है, ताकि ग्राम पंचायत में अगर किसान का नुकसान हो, तो उस किसान के नुकसान की भरपाई ढंग से की जा सके। … (व्यवधान)

पहले की योजनाओं में जो कमियां थीं, उनको हमने दूर करने का काम किया है। इसके साथ हर ग्राम पंचायत में कम से कम चार क्रॉप-कटिंग-एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, यह आवश्यक कर दिया गया है। हमने माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक और नवाचार किया है। अब नुकसान का आकलन नज़री नहीं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, 30 परसेंट कम से कम करना अनिवार्य कर दिया गया है। … (व्यवधान) ताकि अगर रेवेन्यू कम करता है, तो कई बार गड़बड़ होने की संभावना रहती है।

यह बात सही है कि क्लेम के भुगतान में देरी होती है, लेकिन उन देरियों में हमने सारे कारण देखे। अभी तक जो व्यवस्था है, राज्य सरकार से उपज डेटा प्राप्त होने के एक माह के भीतर दावे की गणना की जाती है। देखिए, हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको ठीक से इंप्लिमेंट करना राज्य सरकार का काम है। उन दावों के भुगतान में अगर देर होती है, तो अब एक प्रावधान के बारे में माननीय सदस्या जी को बताना चाहूंगा, जो हमने कर दिया है। अगर बीमा कंपनी देर करेगी, तो उस पर 12 परसेंट की पैनाल्टी लगेगी, जो सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। … (व्यवधान) लेकिन अगर हम देरी के कारण में जाएं, तो राज्यों द्वारा प्रीमीयम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करना इसका 90.9 परसेंट एट-प्रेजेंट कारण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा। मैं तमिलनाडु की राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी तरफ से प्रीमियम की सब्सिडी में अपना हिस्सा जारी करने में देर न करे। 90 परसेंट से ज्यादा देरी इसीलिए होती है। कई बार उपज के आंकड़े विलंब से प्राप्त होते हैं। कुछ मामलों में बीमा कंपनी और राज्य के बीच कुछ विवाद होता है। कई बार कुछ किसानों के नंबर्स गलत आ जाते हैं, उसके कारण थोड़ी देरी होती है।

(1155/CS/SNT)

पहले एक और व्यवस्था थी कि जब राज्य सरकार प्रीमियम की अपनी राशि देती थी तभी केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती थी। हमने एक प्रावधान और किया है कि हमने राज्य के शेयर से अपने आपको डी-लिंक कर लिया है, केंद्र सरकार अपना शेयर तुरन्त जारी करेगी ताकि किसान के भुगतान में देरी न हो, केंद्र सरकार का जो हिस्सा है, वह तो उसे मिल ही जाए। मैं फिर से माननीय सदस्या जी को आश्वस्त करता हूँ कि अगर क्लेम प्राप्त करने में किसान को देर होगी तो इसी खरीफ की फसल से यह 12 परसेंट पेनॉल्टी लगाकर सीधे किसान के खाते में पैसा डलवाने का काम होगा। जहाँ तक योजना के बारे कोई समिति बनाने का सवाल है, आज मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अगर माननीय सदस्या कोई सुझाव देना चाहेंगी तो उनका स्वागत है।

माननीय अध्यक्ष : श्री हरेन्द्र मलिक जी।

आप एकदम से क्यों उठ गए हैं?

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : महोदय, आपने मुझे बुलाया है।

माननीय अध्यक्ष : आप तो पहले ही खड़े हो गए थे।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी ने अभी इस सम्मानित सदन में कहा है कि यह बीमा योजना स्वैच्छिक है। मेरी निश्चित जानकारी है कि आज हर किसान कर्जमंद है। सबके पास केसीसी है और केसीसी जो बैंक जारी करता है, वह तुरन्त फसल का बीमा करता है। यह नंबर एक प्रश्न है।

नंबर दो, जो आप क्लेम देते हैं, जो किसान की फसल का लागत मूल्य है, क्या वह उसके समकक्ष है या नहीं?

श्री शिवराज सिंह चौहान : महोदय, जितना नुकसान होता है, उतना ही क्लेम दिया जाता है, समकक्ष का सवाल इसमें कहाँ है। नुकसान के आधार पर क्लेम का भुगतान होता है।

माननीय अध्यक्ष : केसीसी का काटना, इस संबंध में भी बता दीजिए।

श्री शिवराज सिंह चौहान : महोदय, ऐसा इस योजना में पहले था, अब नहीं है। यह किसान की इच्छा के ऊपर है कि वह बीमा करवाये या न करवाये, जबरदस्ती कोई क्लेम नहीं काट सकता है।... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट रूकिए। इस पर डिबेट नहीं करते हैं। आप बैठ जाइए।

माननीय मंत्री जी ने भी जानकारी दे दी है। मैंने भी जानकारी दी थी। मैं अपनी जानकारी के लिए क्लेरिफिकेशन चाह रहा था। अब जब दोनों तरफ से क्लेरिफिकेशन हो गया है तो आप मन में शंका मत रखिए। कोई जबरदस्ती काटता है तो किसान लिखकर दे दे, उसका नहीं काटा जाएगा। किसान लिखकर नहीं देता है, इसलिए काटा जाता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। आप अलग से नोटिस दे देना। हम इस विषय पर कभी व्यवस्था देंगे।

(pp. 18-30)

(प्रश्न 204)

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : महोदय, देश के आर्थिक विकास में सहकारिता क्षेत्र का अविश्वसनीय योगदान रहा है। इसका तब पता चला जब माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में 6 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया गया और इस विभाग की जिम्मेदारी हम सबके प्रेरणास्रोत माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को मिली। पिछले 3 सालों में देश के आर्थिक विकास में जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटीज हैं, वे काफी मात्रा में देश भर में खोली गई हैं।

मेरा सवाल है कि देश में आने वाले समय में कृषि से लेकर हर क्षेत्र को जोड़ने के लिए और कितनी प्राथमिक समितियाँ राज्यवार खोलने की योजना भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की है?

श्री मुरलीधर मोहोल : महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा है, यह सच है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो संकल्प रखा है, उसकी पूर्ति के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया और तब से माननीय देश के सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में इस सहकार क्षेत्र को अधिक ताकतवर बनाने के लिए, अधिक शक्तिशाली बनाने की बहुत सारी पहलें शुरू हुई हैं। कुल 54 पहलें इस सहकारिता मंत्रालय ने बनाई हैं।

(1200/IND/AK)

महोदय, पैक्स का जिक्र किया गया है। पैक्स सहकारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पैक्स के माध्यम से ज्यादा संख्या में ग्रामीण जनता सहकारिता जुड़ी हुई है। कई-कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में 50 फीसदी से अधिक जनसंख्या सहकारिता से जुड़ी हुई है। अब तक पूरे देश में तकरीबन 1 लाख 5 हजार पैक्स का गठन हुआ है। इनका काम अच्छी तरह से चलना चाहिए। जिला बैंक हो या स्टेट बैंक हो, आपस में इनका कॉर्डिनेशन होना चाहिए ताकि पैक्स को काम करने में आसानी हो। इसके लिए हमने पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन करने की योजना बनाई है। अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 67930 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। केंद्र सरकार द्वारा हार्डवेयर खरीद हो, डिजिटाइजेशन हो या सपोर्ट सिस्टम हो, इन्हें स्थापित करने के लिए अब तक 654 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। कम्प्यूटराइजेशन का काम करने के लिए केंद्र शासन की ओर से 60 परसेंट राशि दी जाती है, 30 परसेंट राज्य शासन देता है और 10 परसेंट राशि नाबार्ड की तरफ से दी जाती है। 18 जुलाई, 2024 तक 568 पैक्स में ईआरपी सॉफ्टवेयर पर कार्यान्वित किया जा चुका है। कुल 583 पैक्स स्वीकृत किए गए हैं और भविष्य में पैक्स को सशक्त करके उसी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करने का जो संकल्प है, आगे जाकर हर प्रदेश में इसे क्रियान्वित करने का हमारा प्रस्ताव है।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

(1200/IND/AK)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, बांग्लादेश में स्थिति बहुत चिंताजनक है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों ने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में सदन को अवगत कराने के लिए आग्रह किया था। माननीय विदेश मंत्री जी इस विषय पर सुओ-मोटो आज 3.30 बजे अपना वक्तव्य सदन में देंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अलग से नोटिस दीजिए।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर - 2, डॉ. वीरेन्द्र कुमार।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): अध्यक्ष जी, मैं दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the years 2022-2023.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) issued under Sections 16, 17 and 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2006:-

(i) The Resin Treated Compressed Wood Laminates (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1018(E) in Gazette of India dated 5th March, 2024.

(ii) The Potable Water Bottles (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1071(E) in Gazette of India dated 6th March, 2024.

(iii) The Insulated Flask, Bottles and Containers for Domestic Use (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1072(E) in Gazette of India dated 06th March, 2024.

(iv) The Wood Based Boards (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1307(E) in Gazette of India dated 12th March, 2024.

(v) The Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1377(E) in Gazette of India dated 15th March, 2024.

(vi) The Air Cooler and Air Filter (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1114(E) in Gazette of India dated 6th March, 2024.

(vii) The Electrical appliance fans (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O. 1124(E) in Gazette of India dated 5th March, 2024.

(viii) The Electrical Appliance for Skin or Hair care (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O. 1125(E) in Gazette of India dated 7th March, 2024.

(ix) The Electrical appliance for domestic clothes washing (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O. 1126(E) in Gazette of India dated 7th March, 2024.

(x) The Electrical appliance for Kitchen (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O. 1128(E) in Gazette of India dated 7th March, 2024.

(xi) The Water meters and accessories (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O. 1142(E) in Gazette of India dated 7th March, 2024.

(xii) The Electrical Appliances for domestic water heating (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O. 1253(E) in Gazette of India dated 11th March, 2024.

(xiii) The Cookware, Utensils and Cans for foods and beverages (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1365(E) in Gazette of India dated 15th March, 2024.

(xiv) The Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 1512(E) in Gazette of India dated 22nd March, 2024.

(xv) The Copper Products (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1801(E) in Gazette of India dated 26th April, 2024.

(xvi) The Telescopic Ball Bearing Drawer Slide (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1962(E) in Gazette of India dated 08th May, 2024.

(xvii) The Self-Contained Drinking Water Cooler (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 2112(E) in Gazette of India dated 28th May, 2024.

(xviii) The Bottled Water Dispensers (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 2173(E) in Gazette of India dated 4th June, 2024.

(xix) The Precision Roller and Bush Chains, attachments and associated Chains sprockets (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 2174(E) in Gazette of India dated 4th June, 2024.

(xxx) The Cast Iron Products (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 2287(E) in Gazette of India dated 21st June, 2024.

(xxxi) The Steel Wires or Strands, Nylon or Wire Ropes and Wire mesh (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 2581(E) in Gazette of India dated 4th July, 2024.

(xxxii) The Safes, Safe Deposit Locker Cabinets and Key locks (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O. 5293(E) in Gazette of India dated 12th December, 2023.

(xxxiii) The Hinges (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O. 5294(E) in Gazette of India dated 12th December, 2023.

(xxxiv) The Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O. 32(E) in Gazette of India dated 2nd January, 2024.

(xxxv) The Laboratory Glassware (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O. 44(E) in Gazette of India dated 03rd January, 2023.

(xxxvi) The Electrical Accessories (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O. 43(E) in Gazette of India dated 03rd January, 2023.

(xxxvii)The Gypsum based Building Materials (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1153(E) in Gazette of India dated 7th March, 2024, together with a corrigendum thereto published in Notification No. S.O. 2007(E) (in English version only) dated 17th March, 2024

(xxxviii) The Asbestos of Fibre Cement based Products (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1152(E) in Gazette of India dated 7th March, 2024.

(xxxix)The V-Belt (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 1252(E) in Gazette of India dated 11th March, 2024.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Sub Section (2) Section 40 of the National Institute of Design Act, 2014:-

(i) The National Institute of Design, Assam First Ordinance, 2024 published in Notification No. F.No. NIDJ/2024-25/Senate in Gazette of India dated 24th July, 2024.

(ii) The National Institute of Design, Andhra Pradesh Ordinances, 2024 published in Notification No. F.No. Senate-20/07/2023 in Gazette of India dated 26th July, 2024.

(4) A copy of the Calcium Carbide (Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.312(E) in Gazette of India dated 5th June, 2024 under sub-section (4) of Section 29 of the Petroleum Act, 1934.

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992:-

(i) S.O.2754(E) published in Gazette of India dated 15th July, 2024, regarding amendment in Policy condition of Sl.No. 55 & 57, Chapter 10 Schedule-2, ITC(HS) Export Policy, 2018.

(ii) S.O.2644(E) published in Gazette of India dated 5th July, 2024, regarding amendment in import policy condition for items under ITC (HS) code 07019000 of Chapter 07 of ITC (HS), 2022, Schedule - I (Import Policy).

(6) A copy of the Boiler (Inquiry, Adjudication and Appeal) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.339(E) in Gazette of India dated 21st June, 2024 under sub-section (2) of Section 28A of the Boiler Act, 1923.

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष जी, मेरे सहयोगी श्री रामदास अठावले की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क(4) के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) केरला एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2016-2017, 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) केरला एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2016-2017, 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग) (एक) हरियाणा स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हरियाणा स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत घी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2024 जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 408(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1785(अ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में

मेसर्स नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक (तरल) के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 20 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 795(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 1202(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स इफको द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया उर्वरक के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है,

(तीन) का.आ. 1366(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए, उसमें उल्लिखित किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के विनिर्माताओं को किसानों को प्रत्यक्ष रूप से थोक बिक्री के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(चार) का.आ. 1718(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स इफको द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया (तरल) 16 के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 1782(अ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए, उसमें उल्लिखित अनुकूलित उर्वरकों के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 1783(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड

द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया उर्वरक (तरल) के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 1784(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया उर्वरक (तरल) के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) (दूसरा) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 8 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1781(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) (तीसरा) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 8 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1963(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) का.आ. 1786(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो जिंक (तरल) के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 1787(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए भारत में मेसर्स भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले नैनो कॉपर (तरल) उर्वरक के संबंध में विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, आशुलिपिक ग्रेड 1 (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 13 अप्रैल, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 41 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, बहुकार्य स्टाफ, भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 13 अप्रैल, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 43 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, निम्न श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 13 अप्रैल, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 44 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, रेडियो मैकेनिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 27 अप्रैल, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 48 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, इलेक्ट्रीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 29 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 86 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, अग्रणी अग्निसेवक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 29 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 87 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर, निम्न श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 29 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 88 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, न्यायाधीश महान्यायवादी (उप महानिरीक्षक) और उप न्यायाधीश महान्यायवादी (उप समादेष्टा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 20 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 284(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, युद्धक मंत्रालयी और युद्धक आशुलिपिक संवर्ग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 10 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सशस्त्र संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 जो दिनांक 26 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 136(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य कर्तव्य संवर्ग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 22 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, डिप्टी कमांडेंट (राजभाषा) और सहायक कमांडेंट (राजभाषा) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 26 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 137(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, शिक्षा और तनाव परामर्शी संवर्ग, निरीक्षक (शिक्षा और तनाव परामर्शी) और उप-निरीक्षक (शिक्षा और तनाव परामर्शी), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 10 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 319(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (आशुलिपिक-सह-निजी सचिव), सूबेदार (आशुलिपिक-सह-वैयक्तिक सहायक) और नायब सूबेदार (आशुलिपिक-सह-वैयक्तिक सहायक), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 22 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 79 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 172 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ख की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1231(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह अधिसूचित किया गया है कि राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में अधिकार प्राप्त समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के निदेशक (जनगणना प्रचालन) द्वारा की जाएगी तथा जो उसमें उल्लिखित अधिकारियों से मिलकर बनेगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): I beg to lay on the Table a copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development for the year 2024-2025.

(1205/RV/UB)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) : माननीय अध्यक्ष् जी, मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित 'मत्स्यपालन क्षेत्र में रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन की संभावना' विषय पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) : महोदय, मैं, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

संसद भवन के द्वार पर धरना और प्रदर्शन करने के बारे में टिप्पणी

1207 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभी दलों से चर्चा करने के उपरांत यह सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। संसद भवन के द्वार के अवरुद्ध होने के कारण कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में मुझे सामूहिक रूप से लिखकर दिया था कि रास्ता रुकने से उनको असुविधा होती है। विशेष रूप से, महिला सांसदों ने भी अलग से मुझे पत्र दिया था और यह निर्णय भी हुआ था कि हम किसी भी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिससे माननीय सदस्यों को आने-जाने में अवरोध न हो।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा लिए हुए निर्णय को हम सब कार्यान्वित करें। जो निर्णय और फैसले हो जाते हैं, उन निर्णयों और फैसलों को लागू करने में सामूहिक सहमति बने।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं खुद आज वहां गया था। यह उचित नहीं है। इस बारे में आप सबसे सहमति बन चुकी थी, इसलिए जब सहमति बन गयी हो, तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी सबकी है।

… (व्यवधान)

*लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे

1208 बजे

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I would like to bring to the notice of the House that there are several All-India Services like the Indian Administrative Service, Indian Railways Service, and Indian Police Service. We have 20 such services in this country. There has been a long pending demand from the medical fraternity. Though healthcare is one of the biggest subjects in this country, less than two per cent of GDP is allocated towards healthcare whereas the recommendation was six per cent. So, Rs. 3 lakh crore should have been the budget allocation for healthcare.

If you look at the services, the people who are joining these services do not have any medical background. Similar to Forest Services or Foreign Services, we wish to have an Indian Medical Service where preferably somebody from the medical background, either MBBS doctors or BDS doctors can be selected so that the healthcare delivery can be much better because when you have an administrative person working in a hospital or a healthcare department, it is difficult for him or her to understand the problems which are being faced. Especially, if you look at all the statistics we have, be it about anemia or Vitamin-D deficiency, we are considering only western standards. We do not have any research which is India specific. If somebody from the medical fraternity is there, it would be very helpful.

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान (रतलाम) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं रतलाम संसदीय क्षेत्र से आती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अलीराजपुर जिले के तीन पंचायतों की 600 हेक्टेयर कृषि भूमि की नीलामी बोली लगायी गयी थी, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) कंपनी को ग्रैफाइट खनन के लिए स्वीकृति दी गयी।

(1210/GG/SRG)

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इसे रद्द किया जाए। लोग भयभीत हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि पूरी ज़मीन पर खेती की जाती है, सब उसी पर निर्भर हैं।

धन्यवाद।

---

* Please see pp.318-319 for List of Members who have associated

माननीय अध्यक्ष : ये हमारी नई सदस्य हैं। जिला परिषद की सभापति भी रही हैं और दूर-दराज़ के गांव से आती हैं।

… (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर जिले के लगभग लाखों लोग मुंबई में रहते हैं और अपना कारोबार करते हैं। लेकिन उनके लिए रेलवे का उचित साधन नहीं है। एक साकेत ट्रेन चलती है, जो अयोध्या से मुंबई के लिए सप्ताह में केवल दो दिन चलती है। एक तो मेरी माँग है कि उस ट्रेन को प्रति दिन चलाया जाए। मान्यवर, इसके साथ ही, मुगलसराय से ले कर लखनऊ तक एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जो तमाम स्टेशनों पर जैसे कटेहरी, गोसाईगंज, अलनाभारी आदि-आदि से हो कर गुज़रती थी। आज उस मुगलसराय पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया है। हमारी मांग है कि मुगलसराय पैसेंजर ट्रेन को फिर से चलाया जाए।

मान्यवर, इसके साथ ही, टांडा बुनकर क्षेत्र है। अम्बेडकर नगर जिला बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। लोगों को बिज़नस के लिए प्रत्येक दिन खलीलाबाद जाना पड़ता है। संत कबीरनगर, खलीलाबाद जाना पड़ता है। बीच में कोई रेलवे लाइन नहीं है। टांडा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन है। वहां से कोई भी यात्री ट्रेन नहीं है। हमारी यह मांग है कि टांडा और बस्ती के बीच में नई रेलवे लाइन बिछाई जाए और अकबरपुर जंक्शन से बस्ती के लिए खलीलाबाद, गोरखपुर तक के लिए अलग से ट्रेन चलाई जाए। मान्यवर, आपके माध्यम से यह हमारी माँग है।

SHRI ARVIND DHARMAPURI (NIZAMABAD): Hon. Speaker, Sir, it is an honour to stand here before you to present a crucial request related to the revered spiritual Guru Sant Sri Sri Sri Sevalal Maharaj Ji.

Sant Sri Sevalal Maharaj Ji was born on 15th February, 1739 in Surgondankoppa, Davengere district of Karnataka. He emerged as a beacon of social reform and spiritual guidance for the Banjara community. With his profound knowledge in Ayurveda and Naturopathy, he dedicated his life to dispelling myths and eradicating superstitions among the tribal communities, thereby transforming their way of life.

Travelling across the country with his Ladeniya Troupe, Sant Sevalal Maharaj Ji served the forest dwellers and nomadic tribes, inspiring them to abandon their nomadic lifestyle and settle in their traditional Tandas. His efforts ensured that the Banjara community preserved its cultural heritage while adapting to a settled way of life. There are about 12 crore people belonging to the Banjara Community in our country today. Today, his legacy resonates in States like Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, and Madhya Pradesh where his birth anniversary is celebrated with great reverence every February.

The samadhi sthal of Sant Sevalal Maharaj Ji, located in Pohradevi, Maharashtra, often referred to as Banjara Kashi stands as a testament to his enduring influence. His life's work in eliminating atrocities and his dedication to public service and humanitarian causes continue to inspire generations.

In the Parliament House Complex, adorned with portraits and statues of illustrious personalities like Chhatrapati Shivaji Maharaj Ji, Kittur Rani Channamma Ji, Sri Aurobindo Ji, Gurudev Rabindranath Tagore Ji, Mahatama Basaveshwara Ji, and Devi Ahilyabai Holkar Ji, it is only fitting that we also honour Sant Sri Sevalal Maharaj Ji. His teachings, emphasizing education, cultural preservation, and patriotism, are crucial in our pursuit of a Viksit Bharat, a developed India.

By installing a statue of Sant Sri Sevalal Maharaj Ji in the Parliament House Complex, we will not only pay homage to a great guru revered by the Banjara community and beyond, but also reaffirm our commitment to the values he championed.

(1215/RCP/MY)

Let us celebrate his contribution and ensure that his legacy continues to inspire and guide us towards a brighter future.

Jai Sevalal. Jai, Jai Sevalal.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : मोहतरम स्पीकर साहब, हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है, उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी के सीईओ के अपाइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3.11.2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेन्ट सीईओ की अपाइंटमेंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में हिन्दुस्तान से जो हाजी सऊदी अरब जाते हैं, वहां पर जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, वे सब-स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सेलेक्शन करते हैं। इससे हमारे हिन्दुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई है। सीईओ नहीं रहने की वजह से वहां के ओहदेदारों ने मीना मुसदल्फा आरफात में हाजियों की खिदमत के लिए एक कंपनी को जो काम दिया जाता है, उनसे पैसे लिये गए।

सर, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता है, जब तक एक-एक हाजी के ऊपर एक-एक लाख रुपये रिश्वत उन ऑफिशियल्स को नहीं दी जाती। मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये ऑफिशियल्स आठ साल से मिनिस्ट्री में हैं। यह सीएसएस रूल्स के खिलाफ है। उनका ट्रांसफर नहीं होता है। एक ओहदेदार को टर्मिनेट कर दिया गया। उसके रिश्तेदार दिल्ली में 50-60 हजार रुपये तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। गैर जरूरी तौर पर मुम्बई में 35 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया।

सर, मेरा आपके जरिए हुकूमत से मुतालिबा है कि सीबीआई के जरिए हज कमेटी के करप्शन की इंक्वायरी कारवायी जाए। इन तमाम ओहदेदारों को हटाया जाए। आखिर में, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए, ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से हिन्दुस्तान के जो गरीब हाजी जाते हैं, उनको तकलीफ से बचाया जाए। मेरी हुकूमत से मुतालबा है।

جناب اسد الدین اویسی (حیدرآباد): محترم اسپیکر صاحب، حج کمیٹی میں جو کرپشن چل رہا ہے، اس کے بارے میں، میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حج کمیٹی کے سی۔ای۔او کا اپوائنٹمنٹ کا ڈپوٹیشن ٹرمینیٹ **3.11.2023** کو دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی ایک پرائیویٹ سی۔ای۔او کی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنے کی وجہ سے حج کمیٹی میں ہندوستان سے جو حاجی سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں پر جو کرپشن شامل ہیں، وہ سب ٹینڈرنگ کے سلیکشن کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے ہندوستان کے حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ سی۔ای۔او نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں کے عہدے داروں نے منیٰ عرفات میں حاجیوں کی خدمت کے لئے ایک کمپنی کو جو دیا جاتا ہے ان سے پیسے لئے گئے۔

سر، پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے لائسنس ری نیو نہیں کئے جاتے ہیں، جب تک ایک حاجی کے اوپر ایک لاکھ روپئے رشوت افسر لیں گے تو نہیں دی جاتی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک افسر ہیں 8 سال سے منسٹری میں ہیں۔ یہ سی ایس ایس۔ رولز کے خلاف ہیں۔ ان کا ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے۔ ایک عہدہ دار کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ اس کے رشتہ دار دلی میں *50-60 ہزار روپئے* تنخواہ پر کام کر رہے ہیں۔ غیر ضروری طور پر ممبئی میں **35** لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا۔

سر، میرا آپ کے ذریعہ سے حکومت سے مطالبہ ہے کہ سی بی آئی کے ذریعہ حج کمیٹی کے کرپشن کی انکوائری کروائی جائے۔ ان تمام عہدہ داروں کو ہٹایا جائے۔ آخر میں، پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کے لئے گورنمنٹ ایک سسٹم بنائے تاکہ ان پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کو کرپشن سے بچایا جائے۔ حج کمیٹی سے ہندوستان کے جو غریب حاجی جاتے ہیں، ان کو تکلیف سے بچایا جائے۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے۔

(ختم شد)

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

इस समय विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि भारत में हो रही है। वर्तमान में यह भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गयी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। इसके पीछे अशिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधा, बाल विवाह, सामाजिक सुरक्षा, अंधविश्वास आदि जैसे बहुत से तर्क दिए जाते हैं, लेकिन अब इसके उचित निवारण का समय है। पूरे विश्व में हर साल 8 करोड की जनसंख्या वृद्धि होती है, जिसमें से 2 करोड़ की वृद्धि अकेले भारत में होती है।

भारत में प्रति मिनट 52 बच्चे पैदा होते हैं। जनसंख्या वृद्धि हमेशा से ही भारत के लिए एक समस्या रही है। इसके कारण देश में अनके समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं - पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी, बेरोजगारी, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने और जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करना अति आवश्यक है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि देश में सीमित संसाधनों और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति से देश को बचाने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति बनायी जाए। मेरा असम और नॉर्थ-ईस्ट भी इससे अछूता नहीं है। असम की जनसंख्या करीब चालीस प्रतिशत तक पहुंच गई है। असम सहित पूरा पूर्वोत्तर, बिहार और बंगाल भी इस समस्या से काफी दिनों से जूझते आ रहे हैं। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो पूरा पूर्वोत्तर भारत से अलग होने की मांग करने लगेगा। जो विचार जिन्ना का था- हँस कर लिया हिन्दुस्तान, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। उनका जो पुराना प्रण व प्रतिज्ञा है, उसको वे सफल कर सकते हैं। इस विषय के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष नीति अपनाएं।

माननीय अध्यक्ष:श्री मनीश तिवारी जी।

इस विषय पर विदेश मंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक हो चुकी है।

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस विषय को उठा रहा हूं, क्योंकि विदेश मंत्री जी को दोपहर में इसके ऊपर बयान देना है। हमारी जो चिंताएं हैं, उनको भी अपने संज्ञान में ले लेंगे, जब वह बयान देंगे। मैं दो-तीन बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, बांग्लादेश से भारत का एक विशेष रिश्ता रहा है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की संरचना में भारत ने एक विशेष भूमिका निभाई थी, जिससे जो दक्षिण एशिया का भगौलिक मैप है, वह वर्ष 1947 के बाद एक बार फिर से बदला था। जो परिस्थितियाँ बांग्लादेश में आज की तारीख में उत्पन्न हैं, वह बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत चिंताजनक हैं।

(1220/CP/PS)

जनवरी, 2024 में शेख हसीना जी के नेतृत्व में आवामी लीग की चौथी बार सरकार बनी थी। लगभग 6 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हुई कि एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और शेख हसीना जी को वह मुल्क भी छोड़ना पड़ा।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पिछले तीन-चार वर्षों में दक्षिण एशिया के कई ऐसे मुल्क हैं, जहां पर राजनीतिक अस्थिरता काबिज रही है, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो और पाकिस्तान में भी जो फौज का वर्चस्व है, वह सिविलियन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओसियन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख मुल्क है। अगर दक्षिण एशिया में अस्थिरता होती है तो उसका सीधा-सीधा असर भारत पर पड़ता है और सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ता है।

मैं सरकार से जानना चाहूंगा, जब विदेश मंत्री जवाब देंगे तब बतायें कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? अगर यह राजनीतिक अस्थिरता इसी तरह फैलती रही तो इसके जो

नकारात्मक प्रभाव हैं, वे भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं? यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।…(व्यवधान)

श्री अतुल गर्ग (गाजियाबाद) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय की तरफ ले जाना चाहता हूं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन में आप वरिष्ठ सदस्य हैं। लाखों वोटों से आपको जनता जिताकर भेजती है। आप सब जानते हैं कि इस तरीके से बहस करने से न तो कुछ रिकार्ड में जा रहा है और न इस तरीके की चर्चा करनी चाहिए। वरिष्ठ सदस्य को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे आपस में डिबेट, चर्चा न करें, तो वह उचित रहेगा। नहीं तो वे अपनी प्रतिष्ठा खुद गिरा रहे हैं। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अतुल गर्ग जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अतुल गर्ग (गाजियाबाद) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय पर उठाना चाहता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि साढ़े 30 लाख लोगों को भारत के अंदर कुत्तों ने काटा है और उसमें 286 लोगों की मृत्यु हुई है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, कोई अपने आप न समझे।

… (व्यवधान)

श्री अतुल गर्ग (गाजियाबाद) : आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर यह आंकड़ा ठीक है, तो अकेले मेरे गाजियाबाद के अंदर एक साल में 35 हजार लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। छोटे-छोटे बच्चे इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। … (व्यवधान) परसों के जागरण अखबार में एक फोटो के साथ खबर छपी है कि एक बच्चे का पूरा कान कुत्ता काटकर ले गया। …(व्यवधान) 4 दिन पहले मजदूर के छोटे बच्चे की रेबीज़ के कारण दर्दनाक मौत हुई। … (व्यवधान) मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अतुल गर्ग (गाजियाबाद) : अगर पालतू कुत्ता किसी को काट ले, तो कोई जिम्मेदार होता है।…(व्यवधान) अगर कोई प्राइवेट कुत्ता गंदगी कर दे, तो कोई जिम्मेदार होता है। …(व्यवधान)

(1225-1230/SM/SK)

अगर कोई आवारा कुता हो तो कोई कुता प्रेमी काटने वाले के सामने नहीं आता, उसे बचाने के लिए सामने नहीं आता, … (व्यवधान) कोई कुत्ता प्रेमी … (व्यवधान) आपसे मेरा निवेदन है कि पहले भी संसद के अंदर … (व्यवधान) और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे निर्णयों पर पुनर्विचार हुआ है। … (व्यवधान) ऐसे नियम बनाए गए हैं कि यदि कुत्ते की नसबंदी करा दी जाए तो उसको वापस नहीं छोड़ना पड़ता है, … (व्यवधान) मेरे बच्चे खेल नहीं सकते हैं … (व्यवधान) आपके लिए ही कह रहा हूं, सुन लीजिए, … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप इधर देखकर बोलिए।

श्री अतुल गर्ग (गाजियाबाद) : बच्चे खेल नहीं सकते हैं, शहर के अंदर एक आतंक का वातावरण बना हुआ है … (व्यवधान) और दूसरी जगह भी बना हुआ होगा। आपसे मेरा निवेदन है कि इस पर दोबारा से एक कमेटी बनाकर विचार हो। एबीसी कार्य बहुत अच्छा चल रहा है तो कुत्ते काटने वालों और उससे मरने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? … (व्यवधान) इन नियमों में पशु प्रेमी और मानव की स्वतंत्रता के बीच में कहीं न कहीं कोई असंतुलन है। यह कोई भी सरकार हो या कोर्ट हो, हमेशा मानवता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपसे निवेदन है कि इस विषय में एक कमेटी बना दें।

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बांसवाड़ा को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय आया है। अभी कुछ दिन पहले परमाणु ऊर्जा सयंत्र के कार्मिकों और स्थानीय प्रशासन द्वारा … (व्यवधान) अभी वहां बारिश का समय है, बारिश के दौरान वहां पर लोग बैठे हुए हैं, उनके मकान बने हुए हैं, … (व्यवधान) वहां खेती बाड़ी करते हैं लेकिन प्रशासन ने लोगों को हटाने का काम किया। … (व्यवधान) लोगों ने इसका विरोध किया तो लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, इसमें अधिकतर महिलाएं हैं। … (व्यवधान) वर्तमान में माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा के कार्मिक, एनपीसीएल के कार्मिक जिला प्रशासन द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है।

मैं आपकी जानकारी ला दूं, यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र उस क्षेत्र के लिए आने वाले समय में एक विनाशकारी योजना होगी।

कई जगह देखा गया है, कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, फुकुशिमा, जापान 2011 में भूकम्प आया और वहां तबाही मची, वहां परमाणु बिजली घर लगी हुई थी। चर्नोबिल, पूर्व सोवियत संघ 26 अप्रैल, 1986 में हल्का सा भूकम्प आया और उसकी वजह से परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हुई और 40 लोग मारे गए। … (व्यवधान)

मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना के लिए माही बांध से पानी लिया जाएगा और दूषित पानी वहां छोड़ा जाएगा। माही डैम से वहां से एग्रीकल्चर और पीने के लिए पानी जा रहा है, उसको उपयोग करने वाले लोगों के उनके उनके स्वास्थ्य के साथ आने वाले समय में खिलवाड़ किया जाएगा और वह कई तरह की बीमारियों से पीड़ित होंगे। … (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): In protest, I am walking out. You are here only for the BJP Members.

1228 hours

(At this stage, Shri Kalyan Banerjee left the House.)

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक रिपोर्ट आयी है जिसमें कहा गया है जहां परमाणु संयंत्र लगता है वहां के आसपास के एरिया में तीन डिग्री तापमान बढ़ जाता है। आपसे मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को रोका जाए। वहां से लोगों को विस्थापित न किया जाए। पूर्व में

परमाणु बिजली घर की वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं, आने वाले समय में भी वह विनाशकारी साबित हो सकता है। जिन लोगों को बारिश के समय वहां से विस्थापित किया जा रहा है, उनको रोका जाए और इस परियोजना को रोका जाए।

*SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): Hon. Speaker, Vanakkam. Thank you for this opportunity. I wish to bring to your notice the issues pertaining to Valparai Assembly Constituency of the Pollachi Parliamentary Constituency. Valparai is a mountainous area which is famous for natural beauty and tea plantation. As many as 60,000 people live in the Valparai Tea Estate area. Most of them are plantation workers working in the Tea Estates of this area.

This Valaparai Tea Estate area comes under the recently announced Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park. Many people have died in this area due to attacks by wild animals. As this place is declared as Reserve Forests and Wildlife Sanctuary, the people living in that area have to live with a sense of fear in their minds. Moreover, the people in this mountainous area should be protected by way of fencing and electric fencing. There should be water tanks at designated places with a view to restrict the movement of wild animals to the lower part of the forest area where we have human habitations.

(1230/SK/SM)

I wish to state that these remote human habitations do not have proper road connectivity due to the ban of such construction activity by the Environment and Forest Ministry of the Union Government. I urge that necessary permissions be given. I also urge upon the Government to provide a compensation of Rs. 10 lakh to the families affected by these wild animals causing loss to lives and property. I urge that the Government should come forward to extend this scheme. The demand for the Upper Valparai area people was that to make arrangements for alternative profession besides tea plantation. The Union Government should give three cents of land free of cost to each of the tea plantation labourers who live in Valparai area as their permanent habitation. Valparai, called as the princess of mountains, should be made as a tourist destination permanently. The BSNL network does not work properly and there are connectivity issues in Valparai tea estate area in the mountainous region. I urge that the telecommunication facilities should be better enhanced in this area. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Annan* Thiru Thalapathy M.K. Stalin has already ordered for enhancement of daily wages of tea plantation labourers from Rs.350 per day to Rs.425 per day as per the new G.O.

1231 बजे (श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुई)

I wish to state that almost 25,000 tea plantation labourers have been benefitted by this Scheme. The farmers living in the villages at the foothills should be permitted to take their cattle like goats and cows for feeding in the forest areas. I urge that the Union Government should allow the cattle of farmers to be fed from nearby forest areas. With this I conclude. Vanakkam. Thank you.

डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले (जालना) : मैं आपके माध्यम से सरकार को एक बात बताना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र जालना, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से बाहर वर्ष 2006 में ज्ञानराधा मल्टी कोऑपरेटिव स्टेट सोसाइटी स्थापित की गई। इसकी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर 51 शाखाएं हैं, जिनमें 5000 लोगों ने 1500 करोड़ रुपये डिपोजिट रखे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इसका मास्टर माइंड सुरेश कुटे है, उसके ऊपर पुलिस ने दस केस भी दाखिल किए हैं। उसने लोगों को लालच देकर, डिपोजिट पर 12 से 14 परसेंट इन्टरस्ट देने की बात कहकर गरीब लोगों से पैसे जमा कर लिए लेकिन इसके बाद वह रफूचक्कर हो गया। उसने बहुत सी प्रापर्टी भी परचेज की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। गरीब लोग, जो डिपोजिटर्स हैं, उनको सरकार की तरफ से राहत देने के लिए कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।

* Original in Tamil

SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI (VISAKHAPATNAM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity in the Zero Hour. I want to speak about developing a national programme for cancer screening. I am a trustee of a non-profitable cancer hospital in Hyderabad. I know how much amount it costs to treat the cancer.

Unfortunately, our screening level is far lower than it should be. Our cervical cancer screening rate is about one per cent and the breast cancer screening rate is about two per cent of the total population. In the USA, the screening is about 70 to 80 per cent for cervical and breast cancer.

Why am I saying this? It is because the hospitalisation cost for cancer treatment is the highest of all the diseases. This cost is 50 per cent greater than cardio vascular disease. The average hospitalisation cost each time is about Rs.70,000.

There is a new investment happening in the nanotechnology which, for the last 10 years, has not become as viable as it should be. The IIT Mumbai and Tata Memorial Cancer Hospital have together come out with a CAR T-cell therapy which is showing promising a result. But it is very expensive. We have still not done enough investment in cancer screening. As a trustee of the Basavatarakam Cancer Hospital, we do cancer screening through mobile cancer screening bus. But the challenges are that we are not able to reach the remote areas. There is also social stigma for women to come for checking breast cancer and other illness.

One thing which has been developing over the last decade in particular, has been the blood-based cancer tests, which today have come to be costly or slightly cheaper than Mammography, which is done traditionally in the hospitals. It costs about Rs.1,500. So, the blood-based cancer tests are becoming better and cheaper. I think we can take it as our national mission and scale up the cancer screening from one per cent to, maybe, 10 to 20 per cent, in the coming years. The Central Government needs to give a message to everybody to do that.

(1235/KDS/RP)

What is causing cancer? Is it microplastics? Is it lifestyle? I think, the Government should increase funding on research to know why the incidents of cancer are increasing. This is going to be very important for the country. The investment into AI will help us to screen cancer at an early stage.

Thank you, Madam.

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से सदन और सरकार के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दे को लाना चाहता हूं। भारत का किसान जिस फसल का उत्पादन करता है, पूरे देश में उसका समान मूल्य होता है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूं, कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठिए। अब आप काँटीन्यू करें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : महोदया, एग्रीकल्चर के इनपुट्स जैसे खाद, बीज का मूल्य भी समान होता है, परन्तु सिंचाई, जो महत्वपूर्ण चीज है, उसका मूल्य अलग-अलग है। जो किसान बिजली से सिंचाई करता है, अपने निजी नलकूप द्वारा सिंचाई करता है, केंद्र सरकार उसे राज्य सरकार का विषय कहकर छोड़ देती है। आज देश का किसान बिजली के मामले में लुट रहा है। निजी नलकूप के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जिन किसानों ने चार, पांच वर्ष पहले पैसा जमा किया था, आज उन्हें यह कहकर पैसा वापस किया जा रहा है कि अब अनुदान समाप्त हो गया है। पहले 300 मीटर लंबी लाइन नि:शुल्क बनती थी। आज आप पूरा पैसा जमा करेंगे, यानी 2 लाख रुपये तक जमा करने पड़ेंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसान की मजबूरी को देखते हुए पूरे भारत में बिजली की एक समान दर तय करनी चाहिए और जो विद्युत लाइन किसान को बनानी है, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह इन्हें अनुदानित करे और प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि लाइन के लिए जो एस्टिमेट आते हैं, उन सबकी लाइन पुरानी दरों पर बनाए ताकि किसान को लाभ हो सके और पूरे देश में बिजली की एक दर निश्चित करे।

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : धन्यवाद सभापति जी। आपने मुझे अपने क्षेत्र समस्तीपुर के एक गंभीर मुद्दे को उठाने का अवसर दिया। हमारे क्षेत्र में कई ऐसी नदियां हैं, जो वहां से बहती हैं और बहुत सारा एरिया बांध का एरिया है। हमारी मांग यह है कि यहां पर वाटर स्पोर्ट्स एरिया को डेवलप किया जाए पर समस्या यह है कि जो सिल्ट है, वह बहुत अधिक जमा हो जाता है। प्रत्येक वर्ष गंडक नदी में 50 हजार क्यूबिक मीटर सिल्ट जमा हो जाता है, जिससे वाटर फ्लो अफेक्ट होता है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। सिल्ट की सफाई से हमें कई लाभ मिलेंगे और नदियों की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाढ़ का खतरा भी कम हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक उपयुक्त वातावरण भी तैयार होगा तथा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वजह से वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहां के जितने भी लोग हैं, उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग करे और एक सफल परियोजना बनाने में अपना योगदान दे। यह सिर्फ जल संसाधनों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि शिवाजी नगर प्रखंड, खानपुर प्रखंड, कल्याणपुर प्रखंड जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, उनका भी विकास होगा। ये सारे क्षेत्र विकसित करने में हमारा सपना भी साकार होगा और विकसित भारत, विकसित बिहार का लक्ष्य भी हमें प्राप्त होगा।

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारा केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव समुद्र किनारे बसा हुआ प्रदेश है, जहां मछली मारना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है रोजगार का एकमात्र साधन भी माना जा सकता है। हमारे ज्यादातर मछुआरे कम पढ़े-लिखे होते हैं, जिनको समुद्री सीमाओं का ज्ञान नहीं होता, जिसके चलते समुद्र में मछली पकड़ते समय गलती से पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाते हैं और वह निर्दोष गरीब मछुआरा पाकिस्तान की जेल में पहुंच जाता है।

(1240/MK/NKL)

ऐसे काफी गरीब मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में वर्षों से बंद हैं। उनमें काफी बुजुर्ग और बीमार मछुआरे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की जेल में बंद अनेक मछुआरों की हालत बहुत खराब है। वे कभी भी मर सकते हैं। पाकिस्तान की जेलों में बंद मछुआरों को अनेक प्रकार की यातनाएं और पीड़ाएं दी जा रही है। पाकिस्तान की जेल में बंद मछुआरे इस बारे में लिखित में अपने परिवारजनों को दे रहे हैं।

महोदया, अनेक मछुआरों को तो पाकिस्तान की कोर्ट ने बरी भी कर दिया है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक वहां की सरकार ने उनको रिहा नहीं किया है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र दमन और दीव सहित पूरे देश के मछुआरे, जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उनको अतिशीघ्र रिहा करवाकर भारत लाने की कृपा की जाए और हमारी समुद्री सीमाओं को मजबूती किया जाए, ताकि हमारे निर्दोष मछुआरे पड़ोसी सीमा में न पहुंच पाएं।

महोदया, इसके साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे देश में प्रतिबंधित लाइम फिशिंग, लाइट फिशिंग, फिक्स बोया फिशिंग और काबा फिशिंग बंद करवाई जाए। काफी लोगों ने समुद्र पर कब्जा कर रखा है, जिससे हमारे मछुआरों को फिशिंग के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है। वे सीमा लांघ जाते हैं और पाकिस्तान में बंद हो जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे मछुआरों की रक्षा की जाए।

*DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): I thank you, hon. Madam Chairperson for giving the opportunity to speak on a matter of urgent public importance. Madam, today I will raise a matter pertaining to MNREGA. I urge upon the Rural Development Minister to kindly pay attention to what I say. Madam, when the NREGA task force was constituted, I was lucky to be one of its members. I was a bureaucrat at that time and I was part of this task force during its inception. I know everything about its history. Why was this scheme envisaged? It is to provide a safety net for poor people to bail them out of problems. However, in the last 20 years, a lot of technicalities have been enforced for labourers to mark their attendance. This has led to difficulties for these poor people in marking their attendance and getting their due payment. Please ease this and find a solution to this problem. Secondly, the number of days needs to be increased to at least 150 days. Over 20 years have passed. The labourers should get at least Rs. 450 to Rs.500 per day. This is the genuine demand of labourers of Punjab. Thirdly, in Punjab, a lot of politics is taking place in the MNREGA scheme. Only people belonging to a particular Party are being enrolled as MNREGA labourers. I urge upon the Government to please look into this matter. The deserving people should be enrolled as labourers under this scheme. Otherwise, a grave injustice is taking place with poor deserving labourers. This menace should be checked and justice should prevail. Thank you.

* Original in Punjabi

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity. This is a very important survival issue of the Tamil fishermen in Tamil Nadu.

Madam, there are almost 87 fishermen who are languishing in various jails of Sri Lanka. … (*Interruptions*) There are about 175 boats which were captured by the Sri Lankan Navy. The boats have been kept for years together in the Sri Lankan land. … (*Interruptions*)

Madam, on August 1st, to all our surprise, our Tamil fishermen were attacked brutally by the Sri Lankan Navy and the boats got capsized which is never in the order. There is an international agreement. This criminality of the Sri Lankan Navy has to be taken note of by the Government of India.

Our hon. dynamic Chief Minister has been, time and again, writing to the Government of India, detailing about the plight of the Tamil fishermen and the problem they face with the Indian Army.

Madam, I would like to draw the attention of the Government towards a fact that there is a strong presence of the Indian Coast Guard and the Indian Navy, the headquarters of which is at Madras. What are they doing? They have become silent spectators. They do not come into action when they know the fishermen are being attacked. Time and again, the hon. Chief Minister has been writing to the Government of India but in vain.

(1245/VR/SJN)

Madam, I would like to point out that there was a sovereign agreement in the year 1974 between India and Sri Lanka providing a right to dry the net in Katchatheevu, which means right to fish was also allowed as per the international agreement. But in 1976, two Joint Secretaries of the Government had absolutely turned over the sovereign agreement entered into between thetwo countries and removed the clause of right to dry the net in Katchatheevu. This is the problem now. This is because of which they are going to the extent of killing the Indian fishermen. So, I want to draw the attention of the Government that there must be a diplomatic effort by the Government. The Government should form a

committee consisting of the representatives of the fishermen, who should visit the jails where these fishermen are kept. There are reports that they have been brutally attacked time and again, and their boats are being damaged. These boats are often released only after six or seven years.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI SANDHYA RAY): Please conclude.

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): Madam, this is a serious issue which the Government of India should take up. Today, the External Affairs Minister is going to give a Statement in the House in the afternoon. I would request him to address and respond to this issue also.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): Madam, a committee should be formed, which would visit Sri Lanka and meet the Indian fishermen. After all they are contributing to the nation's wealth. Seven to eight percent of the wealth is generated by them through export. So, it is a very serious issue which the Government should immediately take into account. Thank you.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Thank you, Madam. Just this year alone 27 boats have been confiscated by the Sri Lankan Navy, and around 177 Indian boats are with the Sri Lankan Government. They are nationalized now by them. That means, they make them their own. The boats are never given back to the Indian fishermen even after they are released from the prisons. Even yesterday in my constituency Thoothukkudi, two boats of fishermen infrom Tharuvaikulam have been attacked by the Sri Lankan Navy and 22 fishermen have been arrested and taken away after our Government had raised a concern about what happened recently.

So, we have to find a solution to this problem. The fishermen from Tamil Nadu cannot keep suffering again and again like this.

Thank you, Madam.

(1250/SNT/SPS)

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity.

I stand before you with the deepest grief regarding the severe catastrophe which fell upon my State of Kerala due to landslides at Wayanad and Vilangad regions of Kozhikode. The devastating landslides in Wayanad killed hundreds and left thousands homeless. Search and rescue operations are going on. It is estimated that 48 per cent of Kerala's total land area, that is, 38,865 sq. kms., is occupied by the Western Ghats where this major tragedy has occurred.

Madam, what hurts me even more is the blame game that has happened after this incident. The Centre claims they have issued a warning; the State says they have not been provided with sufficient warnings. Between this Centre-State tussle, thousand innocent lives are severely affected.

What happened to the Geological Survey of India? It is the nodal agency for landslide prediction. Unfortunately, the agency has said that it could not issue an accurate early warning for Wayanad because of inadequate and inaccurate rainfall readings from the Indian Meteorological Department. The State needs more rain gauges in landslide-susceptible areas, better coordination between various agencies, and more reliable data to mitigate such disasters in the future. To mitigate such disasters in the future, we need a more reliable rainfall data. The current system is inadequate. In such critical locations, a rain gauge every five sq. kms. is required for better and accurate predictions.

I request the Government of India, through you, Madam, to urgently initiate the following measures:-

(1) Provide assistance for rehabilitation of the affected victims.

(2) The families of those affected now have to begin from zero. They have lost their beloved and all their life savings. Hence, the Government must provide for, at least, Rs. 1 crore per family.

(3) Provide adequate financial support for those survivors for building their life.

(4) Establishment of more rain gauges for accurate rainfall predictions along with latest technologies such as all-weather radars and others.

(5) Special Central package for rebuilding Wayanad such as those announced in the Budget for certain States.

(6) Special considerations for Kerala to adopt and mitigate disaster response in future.

(7) Special battalions of NDRF, Indian Army for speedy rescue and relief operations.

(8) My request is to declare Wayanad as the national disaster spot.

Thank you, Madam.

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदया, हमारे राज्य बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र के सहरसा जिले में आरसीडी डिपार्टमेंट की दो सड़कें एनएच 107 पर रंगनिया से सोनबरसा राज 15 किलोमीटर और पंचगछिया से नौहट्टा 8 किलोमीटर सड़क सिंगल पथ है, जिसके कारण उस पर बराबर दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की मृत्यु होती है। यहां पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और प्रशासन के लिए भी परेशानी का सबब बना रहता है। इन सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करना बहुत आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सेंट्रल रोड फण्ड से रंगनिया से सोनबरसा राज और पंचगछिया से नौहट्टा तक के पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाया जाए।

श्री यूसुफ पठान (बहरामपुर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक आवश्यक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे लोक सभा क्षेत्र के निम्नलिखित रेलवे गेटों पर डबल लेन फ्लाईओवर या अंडरग्राउंड बाईपास के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। पहला गेट -111ए रेल गेट है, जो बेलडांगा-नौदा राज्य राजमार्ग के पंचराहा मोड़ पर हैं। दूसरा, 120 ई रेल गेट, बेलडांगा-भबता एनएच-34 के भबता बेलडांगा-I ब्लॉक पर हैं। तीसरा, गेट -104 टी रेल गेट, रेजिनगर-नदिया राजमार्ग के रेजिनगर, बेलडांगा-II ब्लॉक पर है।

सभापति महोदया, ये सभी गेट्स सियालदह-लालगोला लाइन पर स्थित हैं और बार-बार ट्रेन गुजरने के कारण यातयात में समस्याएं पैदा करते हैं। इन रेल गेट्स पर भीड़-भाड़ के कारण आपातकालीन सेवाओं में देरी होती है, जिससे जान और संपत्ति का नुकसान होता है। कई गंभीर बीमार लोगों ने इन गेट्स पर फंसने के कारण रास्ते में ही दम तोड़ दिया और उन्हें

सही वक्त पर हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया जा सका। कुछ दिन पहले एक मकान में आग लगने के कारण पूरा घर जलकर राख हो गया, क्योंकि रेल गेट बंद होने के कारण फायर ब्रिगेड को उस मकान तक नहीं पहुंचा सके। इन समस्याओं को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन रेलवे गेट्स पर डबल लेन फ्लाईओवर अथवा अंडरग्राउंड बाईपास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जाए, जिससे इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके।

(1255/MM/AK)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों के कल के शून्य काल में नाम थे, मैं उनको बुलवाने की कोशिश करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी बात एक मिनट में रखने की कोशिश करें।

… (व्यवधान)

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam, I rise today to draw the attention of the august House to a significant issue affecting the nursing community in our country. I have raised the issue of nurses in private hospitals in this House several times.

The Indian Professional Nurses Association has consistently appealed to the Ministry of Health and Family Welfare asking for the adoption of standardized nomenclature for nursing professionals in both the Government and the private sector hospitals. Unfortunately, despite the directive issued by the Union Ministry on 9th September, 2016, the private sector remains unaffected by this policy.

Nurses in private hospitals are also the cornerstone of our healthcare system demonstrating unwavering commitment to saving the nation, particularly during the challenging times. However, they encounter discrimination and lack of acknowledgement in comparison to their counterparts in the Government institutions. This inequity is not only unjust but also undermines their invaluable contributions to our health sector.

I urge the Central Government to take necessary steps to ensure that nurses in the private hospitals are accorded the same respect, recognition and standing as those in the Government hospitals. … (*Interruptions*) It is imperative that we uphold the principles of equal justice

enshrined in our Constitution and provide our nurses with dignity and recognition that they deserve. … (*Interruptions*) Thank you.

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में रखने का अवसर दिया।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आज की सबसे बडी जरूरत मोबाईल फोन की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज दुनिया में मोबाईल फोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला गैजेट है, मोबाईल फोन गांव-गांव, हर घर, प्रत्येक व्यक्ति बच्चे से लेकर बड़े-बूढ़ों तक इसका उपयोग किया जाता है और वाकई में यह बहुत उपयोगी भी है। अब तो शासकीय, निजी दस्तावेजों में मोबाईल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है तथा शासन की अधिकांशतः हितग्राही योजनाओं का लाभ मोबाइल नम्बर के माध्यम से दिया जाता है।

महोदय मोबाइल फोन की कॉलिंग दर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस कारण ग्रामीणजन रिचार्ज की बजाय नया सिम ले लेते हैं, क्योंकि मोबाईल कम्पनियां शुरूआत में तो दो-तीन महीने तक फ्री ऑफर देती हैं और फिर रिचार्ज के माध्यम से वसूलती हैं। कोई भी रिचार्ज पूरे महीने का न होकर 28 दिन, 24 दिन या उससे भी कम दिनों का होता है। रिचार्ज न करने पर नम्बर बंद कर दिया जाता है, इसलिये नया सिम लेना लोगों की मजबूरी हो जाती है। हितग्राहियों के नम्बर बदलने के कारण वे सरकार की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मोबाइल फोन की कॉलिंग दर को सस्ता किये जाने के लिए सभी कम्पनियों को एडवाइज़री भेजें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जनहित का मामला है। धन्यवाद।

श्री पार्थ भौमिक (बैरकपुर) : सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में एक एम्स है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुश्री ममता बनर्जी जी ने उसके लिए जमीन दी थी। पेशेंट्स के आने-जाने की सुविधा के लिए उन्होंने एक स्टेट हाईवे भी बनाया है। लेकिन दमदम एयरपोर्ट से कोल्लानी एम्स हाईवे से जाने में 50 मिनट लगते हैं और ट्रेन से जाने में डेढ़ घंटा लगता है। अगर रेल मंत्री दमदम एयरपोर्ट से कोल्लानी एम्स तक मेट्रो चलाने की कृपा करेंगे तो यह पेशेंट के लिए बहुत सुविधाजनक होगा।

(1300/YSH/UB)

श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा) : महोदया, मेरा विषय ओबीसी सूची में 'गुर्जर' शब्दावली स्पष्टीकरण से संबंधित है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान चण्डीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश के विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया की दिशा में कराना चाहता हूं। इस भर्ती प्रक्रिया में पूरे देश से आवेदन स्वीकार किए गए थे। इसी क्रम में जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास की, उन्हें अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाया गया था, जिसमें जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में गुर्जर जाति से सम्बन्ध रखते हैं, उनको ओबीसी सूची से यह कह कर बाहर कर दिया गया कि उनकी जाति प्रमाण पत्र में लिखित उनकी जाति की शब्दावली (स्पैलिंग) चण्डीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश की ओबीसी सूची में लिखित शब्दावली से मिलान नहीं करती है।

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली गुर्जर जाति को रेजोल्युशन (संकल्प संख्या) नम्बर 12011/68/93 बीसीसी(सी) दिनांक 10/09/1993 के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में पंजीकृत किया गया था तथा केन्द्र सरकार द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसमें गुर्जर जाति की शब्दावली 'गुजर' लिखी जाती है और चण्डीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश की ओबीसी सूची में शब्दावली गुर्जर लिखी गई है, जो मूलत: एक ही है। … (व्यवधान)

श्री राजीव राय (घोसी) : सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र में रेलवे की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अगर सरकार सर्वे करे तो वह पाएगी कि मऊ जनपद रेलवे के हिसाब से सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारे यहां से बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुम्बई के लिए किसी तरह की कोई भी डेली सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है। मेरी पहली मांग यह है कि वंदे भारत ट्रेन जो बनारस से शुरू होती है, चूँकि हमारे यहां के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए बिहार जाना पड़ता है, बक्सर जाना पड़ता है तो यहां पर दिल्ली-मुम्बई के लिए वंदे भारत या राजधानी एक्सप्रेस की तरह एक डेली ट्रेन चलाई जाए।

दूसरा, मऊ जिले का जो मुख्यालय है, वह एक हिस्से में बसा हुआ है। वहां सबसे ज्यादा आबादी दोहरीघाट इलाके में है। वहां के लोगों को आने में दो घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वहां से ट्रेनें नहीं मिलती हैं तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि मऊ से जो ट्रेनें हैं, वे दोहरीघाट से शुरू हों।

तीसरा, हमारे यहां पर इलाहबाद यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज हाईकोर्ट है तो वहां के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, एक समय में एक विषय काफी है। आप कंप्लीट कीजिए।

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदया, यह बात ट्रेन से संबंधित है। इंटरसिटी एक्सप्रेस को दोहरीघाट से शुरू किया जाए और दक्षिण भारत के त्रिचुर और चेन्नई के लिए भी ट्रेन शुरू की जाए।

श्री रोडमल नागर (राजगढ़) : सभापति महोदया, प्राचीन काल से ही वेद, वेदांग एवं शास्त्र अध्ययन में अनिवार्य रूप से संस्कृत भाषा का महत्व रहा है। संस्कृत को विश्व की सबसे पुरातन भाषाओं में से एक माना जाता है। वैदिक काल में संस्कृत एक अखिल भारतीय वैज्ञानिक भाषा हुआ करती थी और देश में अधिकांश भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। यह भाषा किसी न किसी तरह की आधुनिक व्युत्पत्तियों और क्षेत्रीय बोलियों के कारण अपना अस्तित्व खोती जा रही है।

अत: सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों का पुनर्मुद्रण कर भारतीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद संस्थानों, आधुनिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संस्कृत शिक्षण केंद्रों की स्थापना कर एवं उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेद विद्वान तैयार करने हेतु आयुष पाठ्यक्रमों की परीक्षा संस्कृत भाषा में वरीयता देकर अनुग्रहित करें।

SHRI ISHA KHAN CHOUDHURY (MALDAHA DAKSHIN): Madam, I rise today to bring to your urgent attention the dire situation faced by the residents of Shibpur in Chachanda Gram Panchayat, Samserganj Block, Murshidabad District of my Maldaha Dakshin Lok Sabha constituency.

On the 29th of July, ten concrete houses were lost to the river due to the relentless erosion caused by the Ganges. The situation is equally grave in Loharpur village of Pratapganj Gram Panchayat. On the 30th of July, erosion began in Loharpur, and many houses now stand perilously close, within 50 meters, to the eroding banks. As a result, 400 families from Samserganj Block have fled their homes, with no place to seek refuge. These displaced families are now facing severe challenges, including lack of shelter, drinking water crisis, and inadequate drainage systems. They need immediate relief.

Given that the Farakka Barrage Authority is controlled by the Government of India and the Farakka Barrage is the primary cause of river erosion caused by the Ganges, I again ask the Ministry of Water Resources to take full responsibility for anti-erosion work along the 120 kms long stretch of the Ganges – 80Kms downstream into Murshidabad and 40 kms upstream into Malda – from the Farrakka Barrage. This was the situation under the UPA Government from 2005 onwards. Immediate measures must be taken by the Central Government to prevent further erosion and immediate support must be given to prevent further erosion. The Government should provide immediate relief to the affected families of Samsergan Block, and work on preventing an imminent humanitarian disaster.

(1305/RAJ/SRG)

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल (वलसाड) : महोदया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वलसाड लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत वलसाड जिले के वलसाड पारदी, उमरगाम तालुका समुद्र तट पर स्थित है। हर साल बारिश के कारण, हाई टाइड के कारण, कई बार तूफान और साइक्लोन के कारण समुद्र तट पर बसे गांवों में बाढ़ का पानी भर जाता है और उसके कारण लोगों की जान, पशु और संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचता है। आज भी बाढ़ के कारण पूरे वलसाड में पानी भरा हुआ है। इसके कारण इन गांवों का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की सहायता से पूरा टेक्निकल अनालाइसिस करके गांवों में प्रोटेक्शन वाल बनायी जाए। वलसाड तालुका में बड़ीदाती, नांदाती, काकड़वाड़ी गांव, भागल गांव, बढ़ेली, कोसम्बा, सुरवाडा, मनोहर डूंगरी, पारडी तालुका में उमरसडी, उमरगाम शहर, दहेरी, नारगोल, सरोंदा, तड़गाम, कलगाम, मरोली, फणसा और कालई में प्रोटेक्शन वाल बनाई जाए। धन्यवाद।

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Madam, through you, I would like to draw the attention of the House to the long-pending issue of construction of the Kavalapur airport in my Parliamentary constituency of Sangli. We are known historically for production of commodities like sugarcane, turmeric, maize, raisins and pomegranates. यहां बहुत सारे ट्रेडर्स आना चाहते हैं। हमारी मंडी बहुत बड़ी है, लेकिन वहां बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि वहां कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे यहां प्लेन नहीं उतरने के कारण बहुत सारे ट्रेडर्स नहीं आते हैं। हम हल्दी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हल्दी का एक्सपोर्ट 288 मिलियन डॉलर का हुआ है। We could contribute to it. But unfortunately, somebody does not want to get this airport completed, इसमें कोई रोड़ा अड़ा रहा है।

मै आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे सांगली की कनेक्टिविटी बढ़ानी जरूरी है। वहां पर बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके माता-पिता उनसे मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए जल्द से जल्द एयरपोर्ट का निर्माण हो।

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : सभापति महोदया, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, मै आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय 'जल जीवन मिशन' माननीय प्रधान मंत्री जी की अति महत्वपूर्ण योजना 'हर घर नल से जल' है। हमारे मध्य प्रदेश में कार्य प्रगति पर है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, किन्तु हमारे लोकसभा क्षेत्र के सीधी जिले में इस योजना का निर्माण कार्य दो कंपनी, एल.सी.सी और के. पी. टी. एल. कर रही हैं। ये दोनों कंपनियां आम जन को पानी देने की

योजना पर पानी फेर रही हैं। एनएच रोड को बिना परमशिन के खोद कर क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जिसे कार्य पूर्ण होने के बाद ठीक भी नहीं किया जा रहा है। वहां कई ऐक्सिडेंट्स हुए हैं एवं जीवन की क्षति भी हो चुकी है। टंकियों का निर्माण किया गया है जो क्रैक हो गई हैं और पानी लीकेज होने लगा है। पाइप की गुणवत्ता बहुत खराब है। वे कई जगहों से टूट चुकी हैं। महोदया, मै आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि 'जल जीवन मिशन' माननीय प्रधान मंत्री जी की अति महत्वकांक्षी योजना है, उसके गुणवत्ता पूर्ण निर्माण हेतु सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए, जिसमे सिविल सोसाइटी के लोगों को भी रखा जाये, जो राज्यों व जिलो में जाकर इसकी जांच कर सकें। इसके साथ ही निर्माण का समय निर्धारण भी किया जाए। जो कंपनी खराब कार्य कर रही हैं उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए। साथ ही, सिंगरौली जिले में रिहंद डेम से व सोन नदी से पानी लिफ्ट करके नगरीय क्षेत्र में सप्लाई किया जाए।

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Madam, thank you very much for allowing me to draw the attention of this House to a very important issue regarding my constituency. The Sholinganallur Assembly constituency in my South Chennai Parliamentary Constituency is a densely populated constituency, especially with the re-settlement tenements which spread in Perumbakkam, Semmenchery and Kannagi Nagar. The nearest One-Stop Centre is 45 kms away in Chengalpattu.

(1310/RCP/KN)

It makes the interventions really difficult to help the women victims and the child victims. So, I would like to request the hon. Minister of Women and Child Development, through you, that a one-stop centre should be installed in those areas in the Sholinganallur zone. Also, we have a longer fishing coast. The issues of fishermen being attacked, their boats confiscated and killed have now been raised by two DMK Members. What about the plight of the wives of those fishermen, the trauma they face? So, I want another one-stop centre in the Nochikuppam area also. The Government of Tamil Nadu under the able leadership of our Chief Minister has been enacting a lot of Acts regarding the safety and security of women. The Thozhi women hospitals and the 181 helpline which is a 24x7 helpline are important ones, to mention a few. So, I urge upon the Union Government to not only immediately sanction these two one-stop centres, but also allot funds to expedite the process. Thank you, Madam.

*SHRI A. MANI (DHARMAPURI): Hon Speaker, Vanakkam. Being an elected member form the Dharmapuri parliamentary constituency, on behalf of myself, and on behalf of the voters of my Constituency, I thank you in the first instance. River

* Original in Tamil

Cauvery originating from Kudaku (Kodagu) mountain merges in a place called Hogenakkal at the border of Dharmapuri district in Tamil Nadu. River Cauvery becomes a waterfall at Hogenakkal. I wish to bring to the notice of Hon Minister of Tourism the importance of this Hogenakkal waterfalls with enhanced feasibilities of becoming a most sought-after tourist destination. Hon Chairman Sir, from January to July this year, in 6 months, more than 35 lakh tourists have visited this waterfalls. There is a possibility of more than One Crore tourists visiting this Hogenakkal waterfalls every year. I therefore urge that Hogenakkal waterfalls is a tourist destination with possibilities of having a rope car facility, motor boat rides, Biological Park, massage centres, fish food restaurants, etc. I therefore urge upon the Union Minister for Tourism to allocate funds and develop Hogenakkal into a Tourist Centre with international standards. Thank you.

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : चेयरपर्सन महोदया, वायनाड में जो हादसा हुआ और हम देख रहे हैं कि बार-बार बारिश के कारण किस प्रकार से शहरी विकास तथा शहर पूरे ध्वस्त हो चुके हैं? उस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार भारत के विभिन्न राजधानियों और प्रदेशों से रिपोर्ट मांगे कि जब इस प्रकार की बारिश आती है, चाहे पहाड़ हो या शहरी इलाका हो, तो वहां किस प्रकार से तैयारी हो रही है? हमने पिछले ही दिनों गुवाहाटी में देखा है कि थोड़ी सी बारिश से ही लोगों को बहुत असुविधाएं हुईं। जोरहाट में फ्लाईओवर पर लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। ड्रेन काम नहीं कर रहा, ट्रैफिक काम नहीं कर रहा और गुवाहाटी के आस-पास भी ऐसे पहाड़ हैं, जहां पर लैंडस्लाइड होने की बहुत संभावना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से शहरी विकास और शहरी उन्नयन के संदर्भ में रिपोर्ट मांगे कि जब इस प्रकार से बारिश तथा जलवायु परिवर्तन होता है तो वह किस प्रकार ट्रैफिक, पार्किंग एवं लैंडस्लाइड से बचने के लिए सुविधाएं दे रही हैं? धन्यवाद।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you Madam, Chairperson. Way back in the year 2010, an enactment was passed in the Tamil Nadu Assembly in the name of the Tamil Nadu Arunthathiyars Act when the late leader Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu, who is an embodiment of social justice in the country. That Act was challenged by some people in the High Court, and it went up to the Supreme Court. The Supreme Court gave a judgement a few days back that the Act that was passed in the Tamil Nadu Assembly is constitutionally valid. However, some observations have been made by their Lordships when they were disposing the writ petition about the creamy layer theory not only in terms of the economic criterion, but in terms of the generations,

that the reservation must be limited to the first generation alone. That has been observed in the judgement.

(1315/PS/VB)

Madam Chairperson, it is known to the entire House that even the IPS Officer in Haryana was not permitted to sit on the horse for the marriage ceremony. What does it mean? The economic criterion will not be a solution for the social stigma attached to a particular community. So, in order to meet the entire social justice, that Act was enacted. Now, the apprehension is there in the minds of the *dalit* people and Scheduled Caste people that -- because of the observation made by the hon. Supreme Court -- it may prejudice their rights.

I would request the Government that since the judgment was passed by the hon. Supreme Court, the observation is not prejudiced … (*Interruptions*) Madam, please give me one minute. I will conclude. … (*Interruptions*)

My humble prayer to the Government is to please revisit the judgment or have some safety measures to protect the reservations without any delay.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी, जो विषय माननीय सदस्य श्री ए. राजा का था, क्या आप उसी विषय से संबंधित बात कहना चाहते हैं?

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : नहीं मैडम। मेरा विषय मेरे संसदीय क्षेत्र का है।

माननीय सभापति : ठीक है।

श्री शाहू शाहाजी छत्रपति।

SHRI SHAHU SHAHAJI CHHATRAPATI (KOLHAPUR): Madam Chairperson, I would like to bring to your notice the woes of the Employees' Pension Scheme, 1995 (EPS-95).

There are 75 lakh pensioners associated with the EPS-95 scheme. They reside in every corner of India. Just a few days back, there was an ongoing agitation at Jantar Mantar. I visited that place. Having seen and heard the distressing plight of the pensioners, I would like to bring to your notice a serious situation.

The present members of this Fund are employees of the Central and State Government sector and private sector undertakings. The members enrolled are approximately 30 crores. The statistics state that the corpus in the pension fund has increased from Rs. 3,93,000 crore in 2017-18 to Rs. 7,80,000 crore in 2022-23.

Madam Chairperson, will the Government be pleased to state, whether the Government is aware of the inflation and rising cost, and the minimum pension needed to survive in 2024? I would also like to know whether the Government is aware of the Directive Principles of State Policy of the Constitution of India which places the responsibility on it to help the elderly to lead a respectable life.

Madam Chairperson, the pension is not protected against inflation. Furthermore, it has not increased by a single rupee in the last ten years. The price of a household gas cylinder is itself Rs. 1,200. So, in such circumstances, how do the pensioners, who are drawing an average of Rs. 1,451, continue to live? I do not understand this. It is shocking to note the Government's indifference to the crumbling lives of the pensioners who are naturally of old age.

Article 41 of the Constitution provides for old-age pension schemes and therefore, it not only covers the elderly pensioners, but also, the sick and the disabled.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : माननीय सभापति महोदया, मेरे जनपद देवरिया में मेहरौना गांव है। वहाँ विद्यालय का बहुत ही सुंदर नाम- पंडित दीनदयाल आश्रम पद्धति विद्यालय, मेहरौना है। वहाँ आज का भोजन परसों, परसों का भोजन नरसों और कल सबेरे का बना हुआ भोजन कल शाम को खिलाया जाता है। इससे गरीब लोगों के 93 बच्चे बीमार हो गए, जिनमें से 50 बच्चे अब तक, जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, वे हॉस्पिटल में हैं।

इसी तरह से चलने वाले विभिन्न प्रकार के सरकारी आश्रम पद्धति वाले विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में इसी तरह के सड़े-गले भोजन दिये जा रहे हैं। बीमार पड़ने वाले बच्चों में से 50 बच्चे हमारे जनपद के हैं, जिनकी जान पर आफत आई हुई है।

(1320/PC/SMN)

मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे जनपद बलिया और देवरिया में जितने भी आश्रम पदत्त विद्यालय हैं, सबकी जांच कराई जाए। बच्चों को ताजा भोजन मिले, इतना तो इंतजाम सरकार करे।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो दोषी हैं, उन पर सरकार सख्त कार्रवाई करे और हमारे जो बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं, उन बच्चों को उच्च श्रेणी की स्वास्थ्य सहायता दी जाए।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri A. Raja	Shri Navaskani K. Dr. T. Sumathy *alias* *T*hamizhachi Thangapandian Shrimati Supriya Sule
Shri Shahu Shahaji Chhatrapati	Dr. T. Sumathy *alias* *T*hamizhachi Thangapandian Shrimati Supriya Sule Shri Navaskani K.
Shri Dinesh Chandra Yadav	Shri Navaskani K.
Shri Yusuf Pathan	Shri Navaskani K.
Shri Anto Antony	Shri Navaskani K.
Shri Partha Bhowmick	Shri Navaskani K.
Shri Rajeev Rai	Shri Navaskani K.
Shri T. M. Selvaganapathi	Shri B. Manickam Tagore Dr. T. Sumathy *alias* *T*hamizhachi Thangapandian Shri Navaskani K.
Shri A. Mani	Dr. T. Sumathy *alias* *T*hamizhachi Thangapandian Shri Navaskani K.
Shri Atul Garg	Shri Navaskani K.
Shri Manish Tewari	Shri Navaskani K. Dr. T. Sumathy *alias* *T*hamizhachi Thangapandian

Shri Asaduddin Owaisi	Shri Navaskani K.
Shri Lalji Verma	Shri Navaskani K.
Dr. Kalanidhi Veeraswamy	Shri Navaskani K. Dr. T. Sumathy *alias* *T*hamizhachi Thangapandian
Shrimati Kanimozhi Karunanidhi	Dr. T. Sumathy *alias* *T*hamizhachi Thangapandian
Shri Rajkumar Roat	Shri Navaskani K.
Shri Eswarasamy E.	Shri Navaskani K. Dr. T. Sumathy *alias* *T*hamizhachi Thangapandian
Dr. Kalyan Vaijinathrao Kale	Shri Navaskani K.
Shri Sribharat Mathukumilli	Shri Navaskani K.
Shri Harendra Singh Malik	Shri Navaskani K.
Shrimati Shambhavi	Shri Navaskani K.
Shri Umeshbhai Babubhai Patel	Shri Navaskani K.
Dr. Amar Singh	Shri Navaskani K.
Shri M. K. Raghavan	Shri Navaskani K.
Shri Dilip Saikia	Shri Chandra Prakash Joshi
Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar	Shri Umeshbhai Babubhai Patel
Shri Gaurav Gogoi	Shri Navaskani K.
Shri Isha Khan Choudhury	Shri Navaskani K.
Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	Shri Navaskani K.
Dr. T. Sumathy *alias* *T*hamizhachi Thangapandian	Shri Navaskani K.

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1320 बजे

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है, वे मामलों को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

Re: Need to provide relief package to farmers of Karnataka affected by drought

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Our culture teaches us to treat farmers like Gods, yet in Karnataka farmers are tragically driven to end their lives. The heart-wrenching reality of 1,182 reported cases of farmer suicides in the past 15 months in Karnataka is a painful reminder of the challenges they face. The reasons behind these tragedies include economic exploitation, severe drought, crop failures, and insurmountable debts. In my constituency of Chikkaballapur alone, there have been over 89 farmer suicides. The statistics reveal that 22.59 lakh farmers have borrowed a total of Rs 17,534 crore from cooperative institutions by January 31, 2024, while 8.5 lakh farmers have taken loans amounting to Rs 17,424 crore from nationalized banks by December 31, 2023. Shockingly, only 238 farmers have managed to repay their loans to cooperative institutions. The farmers have not been supported in repayment of their loans or in finding the required market for their produce. It is imperative that the Government of India promptly investigates financial irregularities in the apex cooperative banks and misappropriation ensuring that farmers receive their rightful dues, and provides much-needed drought relief packages to support farmers.

(ends)

Re: Need to review the GST structure levied on aids and equipment used by differently abled persons

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Under the visionary leadership of PM Shri Narendra Modi ji, our nation has made significant strides in various sectors, including initiatives for the welfare of Divyangjan. Today, I wish to draw the attention of this House to a matter of great importance concerning our Divyang brothers and sisters. Currently, essential mobility aids such as prosthetic-limbs, Braillers, and wheelchairs are subject to a 5% GST. This tax inadvertently places an additional financial burden on persons with disabilities for their basic needs of movement and access to information. It May be taken into consideration that a motorized wheelchair user is paying GST of Rs.5,000 on Rs. 1 lakh wheelchair and over the lifespan of wheelchair, this amounts to a significant cost for mobility of Divyangjan. Similarly, visually impaired individuals bear an extra cost for accessing reading materials due to GST on Braille publications. While our Government has taken commendable steps through initiatives like the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, addressing this tax issue could further align with our commitment to empower Divyangjan. I humbly suggest to review the GST structure on aids and equipments for Divyangjan considering essential necessity for the daily lives of millions of our citizens. This step would not only ease their financial burden but also reinforce our nation's commitment to inclusivity and dignity for all. (ends)

Re: Railway related issues of Palamu Parliamentary Constituency

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : मैं सरकार का ध्यान पलामू संसदीय क्षेत्र अंतर्गत रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ जो निम्नलिखित हैं:-

1. 12453/12454 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नगर उंटारी स्टेशन पर ठहराव।
2. कोविड-19 के दौरान बंद की गयी बरवाडीह चोपन चुनार पैसेंजर ट्रेन संख्या 53351/53352 का परिचालन पुनः प्रारम्भ करने।
3. वन्दे भारत ट्रेन को टाटा नगर, मुरी, रांची, लोहरदगा, डालटनगंज, गढ़वा रोड़ एवं जपला होते हुए वाराणसी तक चलाने।
4. पटना-सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 23347/23348 एवं शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11447/11448 का मेराल रेलवे स्टेशन पर ठहराव।
5. पलामू एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13347/13348 का रजहरा स्टेशन पर ठहराव।
6. गरीब रथ ट्रेन संख्या 12877/12878 का मोहम्मदगंज पर ठहराव।
7. रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12453/12454 वाया डालटनगंज होकर सप्ताह में 2 दिन चलती है उसे 4 दिन किया जाय।
8. रॉची-नई दिल्ली गरीब रथ ट्रेन 12877/12878 को सप्ताह में 3 दिन चलती है उसे 6 दिन किया जाय।
9. रॉची-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18311/18611 रांची से वाराणसी तक चलती है उसे गोरखपुर तक विस्तार किया जाय।
10. रांची से वाया डालटनगंज होकर गोरखपुर तक एक नई ट्रेन जो कोरोना काल में चली थी। उसे बंद कर दिया गया है पुनः चालू किया जाय। डालटनगंज से गोरखपुर जाने वाले यात्रियों की संख्या अत्यधिक है।

(इति)

Re: Need to develop an alternate route to Shivaji Marg along Sahibi River in NCT Delhi

SHRIMATI KAMALJEET SEHRAWAT (WEST DELHI): Shivaji Marg is spanning from Moti Nagar to Najafgarh in New Delhi. This road is one of the most busiest road and running through very thickly populated area of the National Capital. Traffic Jam is very common phenomenon on this route specially from Raja garden to Najafgarh T Point, and it takes very long hours for the commuters to cover this span. A joint survey was also carried out by the undersigned along with District Magistrate and Delhi Police Personnel, but due to heavy traffic flow on this route, permanent solution to this problem is not visible in the present scenario. It is, therefore, requested to the concerned Ministry/Department that an alternate route to the Shivaji Marg may kindly be developed along Sahibi River which is running parallelly to this route, so that this route may be decongested. The proposed route is still functioning in certain pockets but is very narrow and not properly maintained. It is my humble request to the concerned Ministry/Department to allow to conduct the survey of the newly proposed route and develop an alternate route to Shivaji Marg. It will be a huge relief for the daily commuters in Delhi.

(ends)

Re: Establishment of an airport in Palghar, Maharashtra

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : मैं पालघर क्षेत्र में एक नए हवाई अड्डे की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह करता है। मुंबई हवाईअड्डा देश के वयस्ततम हवाई अड्डो में से एक है। हमें आज भी हवाई यात्रा के लिए पालघर से मुंबई हवाईअड्डा तक पहचने में लगभग २ घंटा ३० मिनट की सड़क यात्रा करनी पड़ती है। निर्माणाधीन नवी मुंबई हवाई अड्डा शुरु होने के बाद नवी मुंबई के लोगों के लिए लाभप्रद होगा और मुंबई हवाई अड्डे पर कुछ दबाव कम करेगा। लेकिन पालघर और आसपास के लोगों के पास तब भी मुंबई जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। पालघर में एक नया हवाई अड्डा पर्यटन और उद्योगों को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा और साथ ही साथ वर्तमान हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ को कम करने में भी मदद करेगा। इस नए हवाई अड्डे के बनने से निवेश को आकर्षित करने में मदद होगी और रोजगार की अपार संभावनाएं उत्पन होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी पालघर क्षेत्र में नए हवाई अड्डे की स्थापना के प्रस्ताव पर ज़रूर विचार करेंगे ताकि पालघर सहित मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी हवाई यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित होगी और पालघर क्षेत्र में पर्यटन, उद्योगों तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

(इति)

Re: Need to frame a population control policy

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : इस समय विश्व में सबसे अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि भारत में हो रही है और वर्तमान में ये भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गयी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। इसके पीछे अशिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधा, बाल विवाह, सामाजिक सुरक्षा, अंधविश्वास आदि जैसे बहुत से तर्क दिए जाते है, लेकिन अब समय इसके उचित निवारण का है। पूरे विश्व में हर साल 8 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि होती है जिसमें से 2 करोड़ की वृद्धि अकेले भारत करता है। भारत में प्रति मिनट 52 बच्चे पैदा होते है। जनसंख्या वृद्धि हमेशा से ही भारत के लिए एक समस्या रही है और इसके कारण देश में अनके समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिनमें प्रमुख है पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी, बेरोजगारी, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने और जनसँख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करना अति आवश्यक है। आपके द्वारा केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि देश में सीमित संसाधनों और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलबधता के आधार पर जनसँख्या विस्फोट जैसी स्थिति से देश को बचाने के लिए एक ठोस "राष्ट्रीय जनसँख्या नियंत्रण नीति" बनाये जाने पर विचार करें।

(इति)

Re: Need to release more funds for development of Indore as a smart city

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : पूरे देश को पता है कि इन्दौर विगत 7 वर्षो से लगातार स्वच्छता में नम्बर एक स्थान पर आ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकासात्मक कार्यो को गति प्रदान करने की तर्ज पर इन्दौर को स्मार्ट सिटी बनाने का सरकार ने निर्णय लिया था जिसमें 5 हजार करोड रूपये की परियोजनांए शामिल हुई थी, जो कि विकासात्मक कार्यो में ऐतिहासिक है । यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन्दौर को स्वच्छता के साथ-साथ देश में अग्रणी सिटी बनाने का जो सपना देखा है उस गति को आगे बढ़ाने हेतु और अधिक राशि की आवश्यकता है, मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूॅ कि इन्दौर को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु लगभग 1 हजार करोड़ की राशि निर्गत की जा चुकी है, और सहयोग के लिए मध्यप्रदेश सरकार भी बधाई की पात्र है । एबीडी एरिया में पेयजल ओर सीवर लाईन का नेटवर्क अभी तक तैयार नही हुआ है, लगभग 350 करोड़ रूपये की परियोजनाएं अभी लम्बित है । अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि स्मार्ट सिटी हेतु और धनराशि निर्गत की जाए ताकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनो को साकार किया जा सकें।

(इति)

Re: Need to introduce a rail service between Anand (Gujarat) and Haridwar (Uttarakhand)

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आणंद) : मेरा मत विस्तार आनंद लौह पुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल जी की कर्मस्थली रही है और महान शिक्षाविद आदरणीय भाई काका जी और आदरणीय भीखाभाई पटेल जी की जन्म भूमि है। आनंद देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था अमूल डेयरी के लिए भी जाना जाना जाता है। भारत के प्रधानसेवक मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे अपने स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है । रेल के क्षेत्र और रेल यात्रा पहले की अपेक्षा सुगम, स्वच्छ एवं नियमित हुई है। हरिद्वार हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल है एवं बहुत सारी परम्पराओं और संस्कारों को निभाने हेतु हर हिंदू को जीवन में हरिद्वार की यात्रा करनी पड़ती है। मेरे मत विस्तार और अमृत स्टेशन में शामिल आनंद जंक्शन से हरिद्वार के लिए कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं है जिससे आम जनमानस ने रेलमंत्री का ध्यान आनंद से हरिद्वार हेतु रेल सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। माननीय रेलमंत्री जी से आग्रह है कि आनंद से हरिद्वार रेल सुविधा हेतु संबन्धित को आदेशित कर जनता को अनुग्रहित करें।

(इति)

Re: Need to remove encroachments in Ramgarh dam area in Jaipur Parliamentary Constituency

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : मैं सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर शहर के पास स्थित जमवारामगढ़ बांध की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। यहां से जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति की जाती रही है। वर्तमान में यहां पर जल भराव क्षेत्र में अतिक्रमण होने के कारण इसमें वर्षा के पानी की आवक ना के बराबर हो रही है। भराव क्षेत्र में लोगों द्वारा जगह-जगह पर अनिकेत बनाए जाने से इस बांध में पानी की आवक नहीं हो पा रही है। इस बांध में वर्ष 1982 में एशियाई खेलों के दौरान नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जो 1982 में एशियाई खेलों में नौकायान प्रतियोगिता जयपुर के रामगढ़ बांध में आयोजित हुई थी। यह कल्पना कितनी खतरनाक और भयावह है। जबकि उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देश-विदेश के नौकायान प्रतियोगी यदि इस बांध को देख ले तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होगा कि जिस लबालब भरे बांध में उन्होंने अपनी नौकाएं दौड़ाई थी, अब वहां केवल जंगली झाड़ियां ही दूर तक दिखाई पड़ती है। 30 लाख की आबादी को पानी पहुंचाने वाला एक बांध देखते ही देखते एक वीराने में तब्दील हो गया। राजस्थान में जल संचय करने का यह एक बेजोड़ उदाहरण था। जिसे लगभग सवा सौ साल पहले बनाया था। जयपुर घूमने आने वाले विदेशी पर्यटक सवा सौ साल पुराने इस परंपरागत बांध को अवश्य देखने आते थे। जयपुर शहर के महानगर में बदलते ही इस बांध के कैचमेंट क्षेत्र की जमीनों पर लोगों द्वारा कब्जा करना शुरू कर दिया गया। कब्जा इतना अधिक हो गया कि इस बांध में चार नदियों से आने वाला पानी ही बंद हो गया। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि रामगढ़ बांध में हो रहे अनाधिकृत कब्जा को तत्काल हटाए जाने की कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि इस बांध में पानी का भराव चालू हो सके।

(इति)

Re: Need to take comprehensive measures to ensure regular flow of water in river Mahanadi to the reservoir of Hirakud Dam

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Water flow beneath the Mahanadi River is being constricted. There is a need for regular flow of water in river Mahanadi to the reservoir of Hirakud Dam during the year, especially non-monsoon season. There is an urgent need to integrate climate resilience models in the river basin management planning of the nation. For Mahanadi, the need is urgent because drought is expanding its grip, marginalising millions of farmers and forcing millions to migrate seasonally. Both Odisha and Chhattisgarh have climate change action plans that need to work in sync with each other to save Mahanadi River, its farmers and other dependent communities from climate impacts. While the dispute between the two states has been fuelled by apprehension and experience of reduced water flow in the basin due to dams and barrages, the State Governments need to recognize that climate change has an equally important effect and its impacts are going to grow manifold. The Tribunal needs to give its decision urgently as it has already crossed more than six years. I urge the Government to take necessary steps for regular flow of water in river Mahanadi to the reservoir of Hirakud Dam during the year so severely affected Odisha in terms of water shortage to fulfill the local agricultural demand and make available as nature resources for the people of Odisha. (ends)

Re: Need to curb illegal immigration of Bangladeshis into Bhadrak in Odisha

SHRI AVIMANYU SETHI (BHADRAK): A very critical issue affecting the Bhadrak district is the increasing number of illegal Bangladeshi immigrants. This situation has become a grave concern for the residents. The previous State Government assisted these illegal immigrants in obtaining Government ID cards, allowing them to stay in the Bhadrak district unlawfully. This has led to problems for locals, with reports of their involvement in illegal activities such as counterfeit currency circulation, cattle smuggling, scrap trade, poaching of endangered animals, human trafficking, drug peddling, and highway robberies. These immigrants pose a significant security threat and harm the local economy. In many coastal villages, they outnumber locals, worsening public safety, economic stability, and social harmony issues. With help from local leaders of the previous ruling party, these immigrants obtained voter IDs and ration cards, benefiting from Government schemes. It's alleged that these leaders helped them to gain votes. After settling in coastal districts like Bhadrak, they are moving to other areas. Furthermore, neighboring states reportedly encourage their entry for political gains, worsening the problem. Immediate and strict actions must be taken. Police should identify these Bangladeshi infiltrators and deport them in order to ensure safety of residents of Bhadrak by curbing illegal activities and illegal immigration.

(ends)

Re: Development of Dhana air strip in Sagar Parliamentary Constituency

डॉ. लता वानखेड़े (सागर) : मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में हवाई सेवा प्रारंभ करने हेतु ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि सागर लोकसभा क्षेत्र संभाग का मुख्यालय है और चार जिले इस मुख्यालय के अंतर्गत आते हैं, संभागीय मुख्यालय होने के कारण यहां मेडिकल कॉलेज, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान है, साथ ही साथ सागर सेना की बड़ी छावनी है,तथा सागर जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर के मध्य स्थित है, इसलिए यहां के नागरिकों का इन शहरों में आना जाना होता रहता है। संभागीय मुख्यालय होने के कारण सागर मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर ढाना मे वर्षों पुरानी एक छोटी हवाई पट्टी मात्र है जिस पर केवल वी,आई पी मूवमेंट होती है। लेकिन वर्तमान मे उस हवाई पट्टी की स्थिति भी ठीक नहीं है इसलिए ढाना हवाई पट्टी का उन्नयन और हवाई पट्टी का विस्तार कर हवाई सेवा प्रारंभ की जा सकती है ताकि सागर भी बड़े शहरों से सीधे हवाई सेवा से जुड़ सकता है। यहां के नागरिकों की भी वर्षों से मांग है कि यहां पर हवाई सेवा प्रारंभ की जाए अत आपसे निवेदन है कि ढाना हवाई पट्टी का विस्तार कर हवाई सेवा प्रारंभ करने की कृपा करें। (इति)

Re: Need to provide financial package for revival of Aska sugar Factory in Aska Parliamentary Constituency

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): The Aska Sugar Factory in Aska Parliamentary Constituency, Odisha is in very bad shape. Because of the inefficiency of the previous Government, many young people have left their homes and are working as migrant labourers in other states. Through you, I would like to request the Hon'ble Minister to offer a financial package to revive the Sugar Factory and make it fully functional. This will offer employment opportunities to some of the youth of my State, Odisha.

(ends)

Re: Implementation of BADP, BRGP and VVP Schemes in Barmer & Jaisalmer in Rajasthan

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : मेरा लोकसभा क्षेत्र बाडमेर-जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के कई राज्यों से बड़ा क्षेत्र है, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों, संसाधनों के अभाव के कारण पिछड़ा क्षेत्र है। यहां बसावट छितराई ढाणियों में होने के कारण आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जिसका मूल कारण केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु तय मानदण्ड में जनसंख्या मुख्य आधार हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम होने के कारण अन्य क्षेत्र की तुलना में विकास बहुत कम हो पाया। सरकारी सुविधाओं के अभावों के कारण इस क्षेत्र के निवासी कठिनाइयों से जीवन यापन कर रहे हैं। इसकी जाँच के लिए केंद्रीय दल दौरा कर रिपोर्ट जारी करें। सीमावती पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों को मूलधारा से जोड़ने और विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा BADP, BRGF आदि योजनाएं संचालित की। इन योजनाओं को बाड़मेर-जैसलमेर में बंद कर दिया और वाईब्रेट विलेज प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। उक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा जिला प्रशासन के निर्देशन में स्थानीय जनता की मांग अनुसार जनप्रतिनिधियों की राय पर जनहित में आधारभूत सुविधाओं के लिए ढांचा तैयार किया जाता था। इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं से क्षेत्र को वंचित करना घोर अन्याय हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि BADP, BRGF, VVP के साथ अन्य महत्वपूर्ण योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया जावे ताकि स्थानीय लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और देश के विकास में भागीदारी के साथ रोजगार भी प्राप्त हो सके।

(इति)

Re: Power situation in Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : भारत सरकार द्वारा Revamped Distribution Sector Scheme योजना के तहत देश के विद्युत ढाँचे को सुदृढ़ किये जाने हेतु घोषणा की थी | मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरु के लिए सरकार द्वारा 285 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, ताकि क्षेत्र के मूलभूत ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकें | GSS व लाइन चेंज आदि के कार्य शुरू भी किये गए लेकिन अभी तक उक्त सभी कार्य अधर में पड़े हैं | राजस्थान में इस समय विद्युत आपूर्ति का हाल अत्यंत ही बुरा हैं | 12 से 15 घंटे तक की अघोषित कटौती की जा रही हैं। राजस्थान का विद्युत ढांचा इतना कमजोर हो चुका है कि आमजन को बिजली उपलब्ध करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं | इस समय राजस्थान के परिपेक्ष्य में RDSS योजना के तहत 33 KV GSS से अधिक क्षमता के GSS लगाये जाने की अत्यंत महत्ती आवश्यकता हैं | साथ ही घरेलू व कृषि फीडर को भी अलग अलग किया जाना अत्यंत आवश्यक हैं। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं जिसके कारण क्षेत्र का आमजन परेशान हो रहा हैं। (इति)

Re: Need for expansion of ESIC hospital at Ezhukone in Kollam district of Kerala with Ayurveda in-patient and OPD facilities

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The ESIC Hospital at Ezhukone in Kollam district of Kerala is an important healthcare delivery institution that serves the common man including the labourers effectively and with dedication. I would like to vouch for the expansion of its present treatment portfolio by means of establishing a full-fledged Ayurveda treatment system and further an Ayurvedic hospital as there is sufficient infrastructure and ample scope for such expansion. Since the Ayurveda stream of treatment is given a major push and fillip by the Government of India, it is only natural that the ESIC too shall explore incorporation of Ayurveda treatment and provide the same for the benefit of the common man. I would request your good self to kindly consider this proposal and be pleased to expand the ESIC Hospital Ezhukone with either an Ayurveda in-patient and OPD facilities and further establish an Ayurvedic Hospital as it would be a milestone for ESIC extending benefit to the patients who are mostly cashew workers, daily wage labourers and other working-class people altogether.

(ends)

Re: Need to introduce regulations to control outsourcing of Public Sector Undertakings

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): The issue of privatization and rampant outsourcing of public sector enterprises to private contractors can have widespread implications, especially concerning reservation policies in jobs that aim to benefit marginalized communities. Providing jobs is a fundamental responsibility of the state but this responsibility has increasingly been delegated to the private sector, where profit motives often take precedence over social welfare policies. Following the privatization of 23 PSUs, the Government is now making efforts to quickly privatize additional sectors, including banks, LIC, and railways. Private enterprises are not legally bound to adhere to the reservation policies of the Government, which would undermine the job opportunities for SCs, STs, and OBCs. In 2013, the public sector had 14 lakh permanent positions, but by 2023, this number decreased to 8.4 lakh. This cycle of privatization resulted in the elimination of nearly 6 lakh permanent jobs, which would have otherwise provided the benefit of reservation. Given the implications of privatization on reservation policies, it is proposed that the Government introduce regulations to limit the outsourcing of PSUs to private players. Rather than opting for privatization the Government should focus upon the objective to enhance the efficiency of the public sector enterprises. (ends)

Re: Need to expedite approval for establishment of integrated Manufacturing Cluster (IMC) at Palakkad in Kerala

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The extension of Chennai Bengaluru Industrial Corridor to Kochi via Coimbatore was approved with Palakkad Industrial Area in Kerala admeasuring approx. 1,710 acres as the priority node for development way back in 2019 as part of the National Industrial Corridor being implemented by the National Industrial Corridor Development and Implement Trust jointly by the State and Central Governments. As part of this project, an Integrated Manufacturing Cluster (IMC) has been planned to be set up in Palakkad. The NICDCT has already approved the project cost of Rs. 3815 crore for the IMC at Palakkad. Out of the total land requirement of 1710 acres for the Palakkad IMC, the State Government had already acquired 1273 acres of land at Puthussery Central and Kannambra by spending a Rs.1344 crore by State Government. The IMC at Palakkad expects investment of over Rs.10,000 crore as well as employment to 10,000 unemployed youth. State Government is yet to get nod of the Central Government for above and matter is pending before the Union Government since December, 2022. Therefore, it is urged that the Central Government may take immediate decision on the above, so that planned project can be implemented and attract investment and create jobs for thousands of unemployed youths.

(ends)

Re: Construction of Outer Ring Road in Badaun district, Uttar Pradesh

श्री आदित्य यादव (बदायूं) : जनपद बदायू में आउटर रिंग रोड के निर्माण कराए जाने हेतु आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जनपद बदायूं में 5000 से अधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां स्थापित है। घनी आबादी होने के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर काफी समय लगता है लोगों का धन व्यय होता है जिसके कारण आम जनता परेशान होती है। बदायू से बरेली मुरादाबाद, शाहजहांपुर आगरा और फर्रुखाबाद के मुख्य मार्ग से यदि बदायूं को जोड दिया जाए तो जाम की स्थिति से छुटकारा मिल सकेगा।

मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध करना चाहूंगा कि बदायू के मुख्य मार्ग से मुरादाबाद, शाहजहांपुर, आगरा फर्रुखाबाद तथा बरेली को बदायूँ शहर के मुख्य मार्ग से जोड़कर आउटर रिंग रोड बनाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें जिससे बदायूं शहर को जाम से मुक्ति मिल सके।

(इति)

Re: Need to ensure return of money to people duped by fraudulent companies and societies in Deoria district, Uttar Pradesh

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी का कानून, 2019 (बैंकिंग ऑफ अनरेग्युलेटड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019) पारित करके ठग कंपनी एवं ठग सोसाइटी में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदको को 180 दिन में जमा राशि से दो से तीन गुना वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। लेकिन हमारे जिला देवरिया में लगभग 9 लाख ठगी पीड़ित लोग हैं, जिनकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी पड़ी है जो बार-बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी वापस नहीं करा रहे हैं, जिस वजह से लाखों परिवारों के समक्ष भूखों मरने की स्थिति बन गई है। इस कारण अनेक लोगो के आत्महत्या करने की खबरे भी आ रही है। अतः सरकार से अनुरोध है कि संसद में पारित कानून की गरिमा को बचाने के लिए अपने क्षेत्र व देश में उपरोक्त कानून के अंतर्गत भुगतान शिविर लगाकर ठगी पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान करवाए।

(इति)

Re: Need to revive the Durgapur Industrial Hub in West Bengal

SHRI KIRTI AZAD (BARDHAMAN-DURGAPUR): The revival of the Durgapur industrial hub is not just a matter of economic necessity but a critical step towards restoring the region's historical significance and providing much needed employment opportunities. Once a thriving center for industries like jute, automobiles, and metals, Durgapur has seen a significant decline in its industrial activities, affecting the livelihoods of thousands of workers. The industrial area's estimated investments worth over Rs. 1,000 crore are now the hub of decay and abandonment, with vast portions of these once valuable assets surrounded by wilderness. The reduction in workforce and the closure of numerous factories, like Corporate Ispat Alloys, Bharath Ophthalmic Glass Ltd, HFCL, Hindustan Cables Ltd., and Mining and Allied Machinery Corporation Ltd, highlights the intensity of the matter. The area's past success in supplying crucial materials, even during times of national need like the Kargil War, demonstrate its strategic importance. The Central Government should revitalize the area and restore it to its role as a key driver of industrialization and a major hub for employment generation. I urge upon the Central Government to revive this industrial area, ideal for brownfield projects due to its existing infrastructure, including buildings, coal, power, water, and railway access through a well-planned and strategic approach. (ends)

Re: Need to enhance the compensation for the workers who die during engagement under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MGNREGS) Scheme

SHRI MURASOLI S. (THANJAVUR): Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MGNREGA) Scheme is providing livelihood to many farmers of my Thanjavur constituency. At present under the Scheme, 100 man days of employment is being provided by the Union Government, which should be increased to 150 man days. This is an important demand raised by not only the people of Thanjavur, but the people of this country. Moreover the wages provided under this Scheme should be doubled by the Union Government. At present Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is being implemented only in rural areas. I urge that the Scheme should be expanded and implemented in areas under Corporation, Municipality and Town Panchayat as well. For those beneficiaries who die while engaged in doing work under this Scheme, a compensation of Rs. 25,000 is being provided now. I wish that this compensation amount should be increased to Rs 50,000. I urge that at least 50 percent of their daily wage should be provided as compensation to the beneficiaries under this Scheme who are affected without work during the non-work period.

(ends)

Re: Need to address the gaps for effective implementation of education policies of Government by various Statutory Bodies

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): The Central Government has introduced commendable reforms aimed at revolutionizing our education system, making it more inclusive, equitable, and conducive to the holistic development of our students. However, there remains a significant gap in the effective implementation of these policies by various statutory bodies. From the view point of coordination and alignment issues, it may be stated that despite the introduction of new education policies, there is a concerning lack of coordination and alignment between the Central Government and various statutory councils overseeing disciplines such as Engineering, Medicine, Pharmacy, Law, and Architecture. Secondly, the University Grants Commission (UGC) has made strides in implementing the new policies, but other statutory bodies have not kept pace, reflecting a deeper issue of disjointed efforts and lack of cohesive action. In view of implementation Challenges, it is stated that firstly, the Government directives aimed at bringing about much-needed change often remain confined to paper, with little to no tangible implementation on the ground. Secondly, the absence of coordinated efforts between these statutory bodies and the Central Government creates a significant roadblock in realizing the full potential of our education reforms. Thirdly, concerning the impact on Education System, I would like to say that this misalignment undermines the very essence of the policies, which are crafted to benefit students and educators alike.

(ends)

Re: Need to ensure the return of Indian child from Germany who was taken away from her parents by Child Protection Services

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : 3.5 साल की बच्ची अरिहा शाह जब 7 माह की थी,तब जर्मनी में फोस्टर केयर होम द्वारा उसे माता-पिता से छीन लिया गया था। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बच्ची को चोट पहुंचाई हैं। हालांकि, पुलिस जांच में आरोप साबित नहीं हो पाए लेकिन जर्मनी के यूथ वेलफेयर ऑफिस (जुगेंडमट) ने बच्ची को वापस करने से इनकार कर दिया। बच्ची 36 महीने से ज्यादा समय से जर्मनी की कस्टडी में फॉस्टर केयर में रह रही है। सितंबर 2021 के बाद से ही यह परिवार अरिहा की कस्टडी के लिए कानूनी जंग लड़ रहा है लेकिन उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा। अरिहा शाह एक जैन समाज के अभिभावक की बच्ची है और जर्मन पालक देखभाल में रखे जाने से उसके सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बच्ची के माता पिता ने जर्मन सरकार से लेकर भारत सरकार तक मदद की गुहार लगाई है और उनकी अपील है कि अरिहा को गुजरात चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी की कस्टडी में लाया जाए। अहमदाबाद चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने अरिहा के लिए एक फोस्टर परिवार ढूंढ लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस मामले में गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए, जर्मनी सरकार से संवाद करके अरिहा शाह को जल्दी से जल्दी भारत लाने की कृपा करें। (इति)

Re: Need to allocate funds for Khagaria – Kusheshwar Asthan railway line project and ensure the completion of the project in a time bound manner

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : 44 किलोमीटर की खगड़िया-कुशेश्वर स्थान रेल परियोजना,पूर्व-मध्य रेलवे (ECR) के सोनपुर मंडल के तहत आती है और खगड़िया को बरौनी-कटिहार और समस्तीपुर-सहरसा सेक्शन से जोड़ती है और यह रेल परियोजना वर्ष 1998 में शुरू हुई थी, जिसमें अलौली स्टेशन के आगे कुशेश्वरस्थान तक रेल परियोजना का कार्य आज भी लंबित है। इस परियोजना में अलौली से कुशेश्वरस्थान के बीच पांच स्टेशन का निर्माण किया जाना है, जिसमें चेरा -खेड़ा, शहरबन्नी, तिलकेश्वर, सुगरैन एवं कुशेश्वरस्थान स्टेशन शामिल है। परियोजना की नींव स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने रखी थी और इसका निर्माण 162.87 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया था जो वर्तमान में 614.45 करोड़ रुपये से भी अधिक है और 26 वर्षों के अधिक समय लगने के बाद भी इसका काम नहीं पूरा हो पाया है। कुशेश्वरस्थान रेल परियोजना पूरी होने पर लाखों लोगों को फायदा होगा जिसमे समस्तीपुर के किसान भी शामिल है। इस परियोजना के लाभ को देखते हुए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस योजना के लिए निर्धारित राशि का आवंटन किया जाए और एक समय सीमा के अंतर्गत इसके कार्य को पूरा किया जाए जिससे मेरे समस्तीपुर लोक सभा क्षेत्र के किसान, महिला और युवाओं को यात्रा करने की सुविधा प्राप्त हो और मेरे लोक सभा में विकास को गति मिले।

(इति)

Re: Need to establish branches of Nationalized Banks and ATMs at different locations in Ramanathapuram Parliamentary Constituency

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): I request to impress upon RBI to set up Branches of Nationalized banks in the following locations of my Ramanathapuram Parliamentary Constituency. Since most of the Government aids are forwarded to the beneficiaries through Nationalised banks, it will be much supportive to the account holders and users:-

1 Sayalgudi, Ramanathapuram District.
2 Erwadi, Ramanathapuram District.
3 Kamuthi, Ramanathapuram District.
4 Devipattinam, Ramanathapuram District.
5 R.S. Mangalam, Ramanathapuram District.
6 Embal village, Arimalam block, Pudukkottai District.
7 Krishnajipattinam Village, Manalmelkudi Block, Pudukkottai District.
8 Kottaipattinam, Manalmelkudi Block , Pudukkottai District.
9 Gopalapattinam Village, Avadaiyarkovil Block , Pudukkottai District.

I would also request to direct the SBI Authorities to install ATMs in the follwoing location where a reasonable number of population reside:

1. Kattumavadi Village, Manalmelkudi Block , Pudukkottai District.
2. Krishnajipattinam Village, Manalmelkudi Block , Pudukkottai District.
3. Vadakku Ammapattinam, Manalmelkudi Block , Pudukkottai District.
4. Kottaipattinam, Manalmelkudi Block , Pudukkottai District.
5. Gopalapattinam Village , Avadaiyarkovil Block , Pudukkottai District.
6. Poyyathanallur, Avadaiyarkovil Block , Pudukkottai District.
7. Muthukuda Village , Avadaiyarkovil Block , Pudukkottai District. Await your necessary support as always.

(ends)

Re: Need to improve mobile network services in Kokrajhar Parliamentary Constituency

श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार) : मेरा संसदीय क्षेत्र कोकराझार असम बोडोलैंड टेरोटोरिअल रीजन में आता है तथा यह इलाका भारत-भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। इस पूरे इलाके में भारतीय मोबाइल नेटवर्क की स्थिति बहुत खराब है, कई बार इस विषय में भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है। इस पूरे इलाके में भारतीय मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क काम ही नहीं करता लेकिन यहाँ पर आपको भूटान की मोबाइल कंपनी का नेटवर्क आसानी से मिल जाता है और यहाँ रहने वाले लोग भूटान के मोबाइल नेटवर्क का ही अधिक उपयोग कर रहे हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है।

असम के बोडोलैंड टेरोटोरिअल रीजन में भारत-भूटान सीमावर्ती गांवों को संचार के लिए भूटान मोबाइल कंपनी और भूटान मुद्रा का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उन्हें भारतीय मोबाइल नेटवर्क और बैंकों का उपयोग करने को नहीं मिल रहा है। इस पूरे इलाके कक्राझा, चिंश, बक्सा, तामीलपुर, चिरोग, दरांग और उदालगुरी में मोबाइल सर्विस की हालत इतनी खराब है की कॉल ड्राप 80 प्रतिशत तक है। बीएसएनएल को इस विषय में कई बार कहा गया है पर फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका है । मेरे संसदीय क्षेत्र और इस पूरे इलाके पहाड़ी जिलों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकारी तथा प्राइवेट कंपनियों के मोबाइल टावरों की आवश्यकता है। इससे अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी तथा इन सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस इलाके में सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) के सभी कैम्प्स में भी यही समस्या है यहाँ भी एक-दो कैम्प्स को छोड़ कर किसी में भी भारतीय मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। मेरा सरकार से अनुरोध है की इस विषय में तुरंत ध्यान दे और क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाये । (इति)

Re: Need to construct a dry port at Sangli in Maharashtra to promote export of agricultural produce of the region

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sangli needs a dry port to boost agricultural and its allied sectors' exports, such as turmeric, raisin, and jaggery. The Government had promised in 2018 that a dry port would be built at Ranjani village in Kavathemahankal taluka of Sangli district. However, a 2023 RTI reply revealed that Maharashtra has been categorized under Red Zone by the Ministry of Finance because of which no new dry port can be established. Later it was reported that the Government had proposed to create a Multi-Model-Logistic-Park (MMLP) and the site was changed to Salgare village in Miraj tehsil, Sangli. The National Highways Logistics Management Company Ltd was tasked to develop 35 MMLPs at Central Government approved locations. Another 2023 RTI reply reveals that Salgare village was not a part of those approved locations. The Standing Committee on Transport, Tourism and Culture in 2021, had noted that lack of rail and road connectivity to the existing ports, holds back the potential of many ports. I urge the Government to consider construction of this dry port which has been a long-standing demand. This will significantly help farmers, increase shipments and market access from Sangli and its neighbouring areas. (ends)

FINANCE (No. 2) BILL, 2024

HON. CHAIRPERSON: Now, item No. 13, Shrimati Nirmala Sitharaman.

1321 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move:

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2024-25, be taken into consideration."

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2024-25, be taken into consideration."

Now, Dr. Amar Singh.

1321 बजे

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : मैडम, अभी माइक पूरी तरह चला नहीं है। … (व्यवधान)

सभापति जी, धन्यवाद। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से फाइनेंस बिल पर बोल रहा हूं। फाइनेंस बिल बेसिकली टैक्सेशन से संबंधित होता है कि कौन सा टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स छूटता है और क्या होता है।

अगर हम यह बजट देखें और जो सरकार ने प्रपोज़ किया है, उससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की मंशा है कि सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, कॉमन आदमी से किसी न किसी टैक्स के माध्यम से एक-एक रुपया ले लिया जाए और इस मुल्क के जितने अमीर लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उनको छूट दे दी जाए।

मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे यह केंद्र सरकार कार्य कर रही है। अब इनकम टैक्स को ले लें। यदि इनकम टैक्स को देखें, चाहे टोटल अमाउंट देख लें, चाहे परसेंटेज देख लें, इनकम टैक्स वह टैक्स है, जो इंडीविजुअल्स पर लगता है। यह टोटल टैक्सेज़ का 19 परसेंट है और कॉरपोरेट टैक्स 17 परसेंट है। क्यों जी? इनकम टैक्स कैसे बढ़ गया? कॉरपोरेट टैक्स की ग्रोथ आपके दस सालों में 2.3 परसेंट हुई है, 4.28 लाख करोड़ रुपए से 10.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जबकि, इनकम टैक्स में आप लोगों के 4.5 परसेंट पर-एनम टैक्सेज़ इनक्रीज़ हुए, in the same period from Rs. 2.5 lakh crore to Rs. 11.8 crore.

कॉरपोरेट टैक्स, as a percentage of GDP, 3.4 परसेंट से 3.1 परसेंट हो गया। इनकम टैक्स 2.1 परसेंट से 3.5 परसेंट हो गया। आप तो हर तरीके से इंडीविजुअल वाले टैक्स को ऊपर कर रहे हो और कॉरपोरेट टैक्स को नीचे ला रहे हो। ... (व्यवधान) आपकी सरकार किसके लिए काम कर रही है? ... (व्यवधान) वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब की रिपोर्ट है कि जो इंडिया के एक परसेंट अमीर हैं, उनके पास 22 परसेंट इनकम है और 40 परसेंट वैल्थ है। यह आपके पिछले दस सालों में हुआ है। आप देख लो कि आप यह क्या कर रहे हो? ... (व्यवधान)

मैं इनकम टैक्स के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या किया है? बहुत सारी चीजें जैसे डिडक्शन फीस सरचार्ज पर होती है, फलाना होती है। मैडम वित्त मंत्री बैठी हैं। पांच करोड़ रुपए से ऊपर वाली इनकम का सरचार्ज 37 परसेंट से 25 परसेंट कर दिया, बाकी तो किसी का कम नहीं किया? इसका मतलब जिनकी हायर इनकम है, उनका आप फायदा कर रहे हो।

जितनी एग्जेम्पशंस थीं, 80(c) में जो डेढ़ लाख रुपए की एग्जेम्पशन थी, जो पर-इंश्योरेंस और फलाना-फलाना करते थे, सारी खत्म कर दीं। 25,000 रुपए का फायदा दिया है कि नए टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए के बजाए 75,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स, इंप्लॉयमेंट वाला टैक्स, एचआरए पर, हाउस-लोन पर बहुत सारा, एक लाख, दो लाख रुपए का इंटरेस्ट-वेवर मिलता था, वह सारा भी खत्म कर दिया। आप लोगों ने जो इंप्लॉयज कॉन्ट्रिब्यूशन वाली डिडक्शन होती थी, वह भी खत्म कर दी। मेडिकल इंश्योरेंस वाला भी खत्म कर दिया है।

(1325/CS/SM)

आपने कौन सी चीज छोड़ी है? एफडीआई, जो बाहर से आ रहा है, कारपोरेट ला रहा है, उसे आपने कम कर दिया है। हर चीज पर आप इस तरह से काम कर रहे हैं। किसी भी हालत में, अच्छा 80 साल की जिनकी उम्र है, उनके लिए बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट पहले रिजीम में 5 लाख रुपये की होती थी, आपने वह लिमिट 3 लाख रुपये कर दी है। आपने बूढ़े लोगों को क्या राहत दी है? हम सभी लोगों को बूढ़ा होना है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी को एक सुझाव है। देखो 70 परसेंट आपके आईटीआर निल वाले होते हैं। हिन्दुस्तान की दो परसेंट पॉपुलेशन टैक्स दे रही है। 5 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोगों को छोड़ दीजिए, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उसी से पब्लिक कंजम्प्शन बढ़ेगी, इस मुल्क में गरीबी कम होगी। आप मेरा यह सुझाव मान लीजिए।

अब हम आगे बढ़ते हैं। मिडिल क्लास, सैलरीड वालों को इतने पर ही नहीं छोड़ा। आपने कैपिटल गेन टैक्स में दोनों तरफ उनको मार दिया। शॉर्ट टर्म गेन पर भी उनको मार दिया। शॉर्ट टर्म गेन साल भर का होता है। लांग टर्म गेन पर भी उनको मार दिया। आपने दोनों तरफ उनको मार दिया। शॉर्ट टर्म गेन पर आपने 15 परसेंट से बढ़ाकर 20 परसेंट टैक्स कर दिया। लांग टर्म में तो बहुत ज्यादा नुकसान है। वह इंडेक्सेशन जो प्रॉपर्टी, गोल्ड, अदर ऐसेट्स पर था, वह सारी

खत्म कर दी है। उस पर लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यह केंद्र सरकार किधर जा रही है? जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सैलरीड क्लास है, जो छोटा-मोटा काम करने वाला है और यही नहीं, आपने ऑप्शंस और फ्यूचर्स पर भी ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। इस तरह से ये क्लासेज किधर जाएंगी? ये मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास के लोग किधर जाएंगे, जो बेचारे ऑप्शंस लेते हैं, फ्यूचर्स लेते हैं? इनका तो आपने हर जगह नुकसान किया है।

वित्त मंत्री जी, मेरा कहना है कि इन सारी चीजों पर आप री-थिंक कीजिए। इन सबसे सैलरीड क्लास, मिडिल क्लासेज का नुकसान हुआ है, रिच को आप फायदा कर रहे हैं। कारपोरेट टैक्स फॉरगॉन आपका अपना इन्फर्मेशन है। इसी बजट में वेरियस स्कीम्स में 1,09,333 करोड़ फॉरगॉन रेवेन्यू की वर्ष 2022-23 में फिगर दे रहे हैं। पिछले 5 साल में, मैं कम्पाउंड नहीं कर रहा हूँ, 1.7 लाख करोड़ फॉरगॉन रेवेन्यू है। आप रिलैक्सेशन इसलिए देते हो कि जॉब्स क्रिएट होंगी। बेरोजगारी की तो हिन्दुस्तान में इतनी बुरी हालत है, सीएमआईई पिछले साल कह रहा था कि 45 परसेंट अनएंप्लॉयमेंट है। अभी भी 8-9 परसेंट अनएंप्लॉयमेंट है। जो कारपोरेट को देते हैं, हमारी आपसे विनती है कि कृपा करके हमें बताइए कि कारपोरेट्स का जो टैक्स छोड़ा है, उससे कितनी नौकरियाँ पैदा हुई हैं, क्योंकि यह वाला काम नहीं चलेगा कि आप छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ और कोई उसका हिसाब-किताब न लें, क्योंकि अनएंप्लॉयमेंट इस मुल्क की बेसिक प्रॉब्लम है। आपका तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि that 78.5 lakh jobs will have to be created in non-farm sector annually. आप कितनी जॉब्स पैदा कर रहे हैं? डीओपीटी की तरफ से तो अभी सूचना आयी थी कि 7.2 लाख नौकरियों के लिए 2.2 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। आप बेरोजगारी का हिसाब-किताब लगा लीजिए कि वह कितनी है।

हमें इस बजट में अनएंप्लॉयमेंट के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई रिलीफ चाहिए। नॉट ओनली दैट, मैडम क्रिसिल की रिपोर्ट है that household savings has come down to 18.4 per cent of GDP in 2023-24. यह डीकेडल लो है, हाउसहोल्ड सेविंग्स 20 परसेंट से कम कभी नहीं गई थी। Household financial liability is at an all-time high at 5.8 per cent. आप हमें बताइए कि ये दो चीजें क्या बताती हैं? ये यह बताती हैं कि डे-टू-डे एक्सपेंडिचर में मेरे हाउसहोल्ड को बहुत तकलीफ है और कंजम्प्शन इसलिए इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। आप हमें कुछ बात बताइए कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि न अनएंप्लॉयमेंट पर कुछ है, न हाउसहोल्ड कंजम्प्शन पर कुछ है, किसी चीज पर कुछ नहीं है। (1330/IND/RP)

माननीय सभापति जी, हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या बात है? इन्होंने बजट में इंफ्लेशन के बारे में भी कुछ नहीं बताया है। डब्ल्यू.पी.आई. 3.1 परसेंट, रिटेल 5.5 परसेंट और फूड इंफ्लेशन तो करीब-करीब 10 परसेंट है। इसका क्या करना है? यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। आपने बताया ही नहीं कि फूड इंफ्लेशन को कैसे कम करेंगे? मैडम जब जवाब देंगी, तो इस बारे में जरूर बताएं।

महोदया, अब मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करना चाहूंगा। आज भी देश की 50 परसेंट पापुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। 18.4 परसेंट इनकम जीडीपी का हिस्सा है। इसका मतलब 50 परसेंट पापुलेशन सिर्फ 18 परसेंट इनकम पर जिंदा हैं और इसी वजह से किसानों और लेबर को इतनी मुश्किलें हैं चाहे वे आत्महत्या कर रहे हैं या आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत तकलीफ में है। आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि पिछले साल 4.7 परसेंट ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में थी और वर्ष 2023-24 में 1.4 परसेंट है। सरकार के इतने सारे वायदे कहां गए? ग्रोथ कम होने से एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी परेशानियां हो रही हैं। आपका वायदा था कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल करेंगे। उसका क्या हुआ? आपका सर्वे था कि वर्ष 2018-19 में किसानों की इनकम 10218 रुपये हर महीने थी। अब तक किसानों की हर महीने की इनकम 22 हजार या 25 हजार रुपये हो जानी चाहिए थी।

मैडम, आप कृपया हमें जरूर बताएं कि आज किसानों की प्रति माह कितनी इनकम है? नवम्बर, 2021 में किसानों के एजिटेशन के समय माननीय प्रधान मंत्री जी एक दिन रेडियो पर बोलते हैं कि किसान भाइयों, आप बार्डर से उठ जाएं। मैं आपको एमएसपी का हल करके दूंगा। हम इस बारे में पक्का हल करेंगे। यह नवम्बर, 2021 की बात है और आज आप देखें कि कितना समय हो गया है। उस वायदे का क्या हुआ? माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे कह रहे हैं कि मैं किसानों से चर्चा करूंगा। किसानों की मांग बहुत स्पष्ट है कि एमएसपी लॉ बनाकर दो। आप इस बात को कहते ही नहीं हैं। मंत्री जी, आप कहिए कि आप एमएसपी लॉ बनाएंगे। संसद सत्र चल रहा है। यह बहुत अच्छा मौका है, आप सदन में कह दीजिए कि एमएसपी लॉ बनाएंगे। मंत्री जी मुझे जानते हैं, आप मेरे बोलने के बाद बोल दीजिएगा।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, आप चेयर को सम्बोधित कीजिए।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : महोदया, मैं माफी चाहता हूं।

महोदया, एक बहुत विचित्र स्थिति हमारे सामने है। वर्ष 2015 में ढोल धमाके के साथ ब्लैक मनी एक्ट बनाया। बहुत अच्छी बात है कि जो काला धन विदेशों में है, उसका एक-एक पैसा देश में वापस लेकर आएंगे। हालांकि बाद में कह दिया कि हमने ऐसे ही कहा था, वह बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आपने अब कहा कि बाहर कोई 20 लाख रुपये तक का ऐसेट बनाए, तो उसके लिए सूचना देने की जरूरत नहीं है। क्या यह कंट्राडिक्शन नहीं है? पहले आप कह रहे थे कि एक-एक पैसा वापस लेकर आएंगे लेकिन अब कह रहे हैं कि 20 लाख रुपये तक के ऐसेट खरीदने पर जानकारी देने की जरूरत नहीं है।

महोदया, अब मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मैं कई बार सदन में इस विषय पर बोल चुका हूं। मैं उस पवित्र स्थान से आता हूं जहां हमारे दसवें गुरु के दोनों छोटे साहबजादों को औरंगजेब के जमाने में जिंदा नींव में चिन दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हम धर्म नहीं बदलेंगे।

(1335/RV/NKL)

यह वर्ष 1705 की घटना है और अब इसके 318-319 साल हो गए हैं। पर, अभी भी 50 लाख से एक करोड़ लोग 25-26-27 दिसम्बर को हर साल सिजदा करने आते हैं। मैं बार-बार यह कहता हूं कि जो रिलिजियस स्प्रिचुअल प्लेसेज़ हैं, उनको इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में लीजिए और वहां इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट वाली फैसिलिटीज़ दीजिए। इतनी पवित्र जगह बहुत कम होंगी। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह घटना प्रसिद्ध है। उस समय छोटे साहेबज़ादों – बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह – की उम्र 9 साल और 7 साल थी। पर, उन्होंने अपने धर्म नहीं बदले। मेरा यह कहना है कि वहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट की जगह दीजिए, इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ दीजिए। ये सब वहां करने की जरूरत है।

इसी तरीके से, मेरी कंस्टीट्युन्सी में कुछ एम.एस.एम.ई. क्लस्टर्स हैं। मैंने एक-दो बार मिल कर भी इसके बारे में बात की है। जी.एस.टी. से संबंधित उनकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं। उनकी प्रॉब्लम्स स्पेशल पैकेज की है। वहां मंडी गोबिंदगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। उसे 'स्टील टाउन' कहते हैं। वहां खन्ना है, दोराहा है, साहनेवाल है। इन सारी ज़गहों पर एम.एस.एम.ई. इंडस्ट्रीज़ हैं। लुधियाना के एम.पी. साहब पीछे बैठे हैं। वहां के लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वे एक बहुत छोटा-सा सजेशन देते हैं। जो स्टील इंडस्ट्री वाले हैं, वे स्क्रैप से, सेकेन्डरी सोर्स से स्टील बनाते हैं। इनके पास प्राइमरी सोर्स आयरन-ओर नहीं है। वे कहते हैं कि स्क्रैप पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. है। आप हमसे ले लीजिए, क्योंकि स्क्रैप वाला बेच कर गायब हो जाता है और फिर आप उसकी रिकवरी हमसे करते हैं, इसलिए आप हमसे सीधा ही उतना टैक्स ले लीजिए। आप उस चिंता में क्यों पड़ते हैं, ऐसा उनका कहना है।

दूसरी बात, मैं यह मांगता आया हूं कि मेरे यहां एक मेडिकल कॉलेज दीजिए, एक ट्रॉमा सेन्टर दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी मांग रखता हूं, पर मेरी कोई मांग मानी नहीं गयी है।

आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस फाइनैंस बिल में आपने जितने टैक्सेशन प्रोपोजल्स दिए हैं, इसमें अगर कोई भी प्रोपोजल कॉमन मैन के लिए हो, तो उसे आप अपने जवाब में बता दीजिएगा। ये सारी की सारी 'रिच' को सुविधा देने के लिए है, और गरीबों के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए इस बिल में कुछ नहीं है।

मैडम, मैं इसका विरोध करता हूं।

(इति)

1338 बजे

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के इतने ऐतिहासिक बजट के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज 6 अगस्त है। स्पीकर साहब ने हिरोशिमा और नागासाकी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दूसरी श्रद्धांजलि मैडम सुषमा स्वराज जी को है, जिनकी आज पुण्य तिथि है। जब मैं पहली बार यहां सांसद बन कर आया तो लीडर ऑफ ऑपोजीशन के नाते उन्होंने हमारे जैसे लोगों को बढ़ाने का काम किया और उसी कारण से आज मैं पार्टी के आदेश के अनुसार, प्रधान मंत्री जी के कारण इस फाइनैंस बिल पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, मैं सोचता था कि कांग्रेस के जो स्पोक्सपर्सन हैं, या जो वक्तव्य देने वाले हैं, वे फाइनैंस बिल पर चर्चा करेंगे, वे देश की स्थिति के बारे में बताएंगे, हमारी सरकार ने क्या बुरा किया, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन जैसा कि कांग्रेस एक कन्फ्यूज्ड पार्टी है तो उस कन्फ्यूज्ड पार्टी की तरह ही कन्फ्यूज्ड वक्ता रहे।... (व्यवधान) फाइनली कांग्रेस पार्टी को उनका समय 'कट' करना पड़ा और अब दूसरे मेम्बर बोलने के लिए खड़े होंगे।... (व्यवधान)

सभापति महोदया, आज स्थितियां कैसी हैं, मैं यह देख पा रहा था। मैं 'डिरेल' नहीं होना चाहता।... (व्यवधान) आज पूरी दुनिया की स्थिति क्या है? अगर वर्ल्ड बैंक की, आई.एम.एफ. की, फोर्ब्स की, अमेरिका की, जिनकी नीतियों से कांग्रेस बहुत प्रभावित रही है, यदि उनकी रिपोर्ट्स को देखें तो पूरी दुनिया में 2.5 प्रतिशत से लेकर 2.7 प्रतिशत ही जी.डी.पी. बढ़ रही है।

(1340/GG/VR)

पूरी दुनिया कराह रही है। आप लंदन जाइए, आप न्यूयॉर्क जाइए, आप वाशिंगटन जाइए, आप पूरे यूरोप जाइए, सारी दुकानें बंद होती नज़र आएंगी। बेराज़गारी की भयंकर सीमा है। इनफ्लेशन का रेट, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां आठ पर्सेंट से कम इनफ्लेशन है। पूरी स्थिति खराब है। चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, फिसकल डेफिसिट हो, जिस भी पैमाने पर आप पूरी दुनिया को आँकने का काम करेंगे, आपको लगेगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी की नीतियां इस देश के लिए इतनी सक्सेसफुल हैं कि आज भी भारत पूरी दुनिया में आशा की किरण है और सात पर्सेंट से अधिक जीडीपी ग्रोथ है।

सभापति महोदया, हम धर्म के मानने वाले लोग हैं। जो धर्म कहता है, उसी के आधार पर हम चलते हैं। हमारे धर्म में एक बड़ा श्लोक है कि :-

"कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी।
सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी॥"

अर्थात भगवान सभी कालों में, सभी भगवान में, सभी गरीबों में एक ऐसी ऊर्जा का संचरण करते हैं, जिसके कारण दुनिया में गरीब कैसे खत्म होंगे, भारत में गरीब कैसे खत्म होंगे, उनको अमीर कैसे बनाया जाएगा, इसी पॉलिसी के आधार पर भारत सरकार चलती है, इसी पॉलिसी के आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है।

सभापति महोदया, किसान बिल की बात हो रही है और उस दिन मैंने बजट पर माननीय एलओपी, जिनके लिए मैंने सोचा कि क्या संबोधन दिया जाए, तो मैंने ... (*Expunged as ordered by the Chair*) सोचा है। ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की जो ज़बान होती है, उसको जो पढ़ाया-लिखाया जाता है, वही उसको बोलना है और इस बजट पर चर्चा करते-करते अमर सिंह साहब भी वही चर्चा कर गए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ कि यदि कोई ऐसा शब्द आया है, तो उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज़ आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप भी सुनिए कि यदि कोई सदस्य बोल रहा हो तो बैठे-बैठे कमेंट्स मत कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : वह जो भी शब्द आया है, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, आज हम क्या कर रहे हैं? हम भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं और उसके लिए इस बजट में जो सबसे बड़ा प्रपोज़ल है कि जो फॉरन फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट है, एफडीआई में जो कॉर्पोरेट आते हैं, हम इकोनॉमी में जा रहे हैं, आरएण्डडी में जा रहे हैं, नई-नई इंडस्ट्री में जा रहे हैं। यदि वे कंपनियां हमारे देश में इनवेस्ट करना चाहेंगी, तो उनके टैक्स को हमने कम किया है। और वह टैक्स हमने कम क्यों किया? क्योंकि हमारा मुकाबला सिंगापुर से है। हमारा मुकाबला अबु धाबी, यूएई, आदि देशों से है, जहां कॉर्पोरेट टैक्स 20-22 पर्सेंट से ज्यादा नहीं है और कई जगहों पर तो टैक्स ही नहीं है। उस इंडस्ट्री को जब बैठना है, जब वह इंडस्ट्री आएगी, तो यहां के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, डेवल्पमेंट होगा, मेक इन इंडिया में जाएगा और जो वर्ष 2047 का एक संकल्प है कि हमको एक विकसित भारत बनाना है, जो वर्ष 2027 का एक संकल्प है, जो फॉर्ब्स की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2027 तक ऐसा संभव है कि भारत जिस इकोनॉमी के साथ बढ़ रहा है, हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। उसमें यह जो राइडर है, जिस पद पर सभापति महोदया, उन्होंने बोलते हुए, जिस तरह से अराजकता फैलाने का काम किया, यह मैं आपको बताऊंगा। वे क्या कहते हैं? वे महाभारत को गलत कोट करते हैं। वे रामायण को गलत कोट करते हैं। वे शिव को गलत कोट करते हैं। उसके बाद वे कहते हैं। ... (व्यवधान)

(1345/MY/SNT)

वह कहते हैं कि हम अराजकता फैलाएंगे, तुमको जो करना है, करो। अनुराग सिंह ठाकुर जी ने उस दिन जो बात कही, मैं उससे कंप्लीट सहमत नहीं हूं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी की तरफ से इस सदन में माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन क्यों, इसीलिए कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने उनके ऊपर जाति का आरोप लगाया, लेकिन जाति तो है ही नहीं। आप यह समझें, वह कहते हैं कि जो मैं हूं, वही दिखता हूं। मैं जो दिखता हूं, वह मैं नहीं हूं, तो वह साधू है। इस देश में कहा गया है कि जाति न पूछो साधू की। साधू की जाति नहीं पूछना है। जब साधू की जाति नहीं पूछना है तो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने गलती कर दी कि उनसे जाति पूछ लिया।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और सारे अपोजिशन से जवाब पूछना चाहता हूं। आप यह बताइए कि इस देश में कई एक ऐसे लोग हैं, जिनको धर्म में आस्था नहीं है, कई एक ऐसे लोग हैं, जिनको जाति में आस्था नहीं है तो वह किस तरह से जातिगत जनगणना करेंगे? जिस पद पर राम सुभग सिंह, चरण सिंह, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह के बड़े-बड़े लोग रहे, जिस जगह पर शरद पवार जैसे लोग रहे, वाई.बी.चव्हाण जैसे लोग रहे, उस जगह की गरिमा का आप इस में बजट में अराजकता फैला कर, इस बजट का नकारात्मक पहलू दिखा कर हरैसमेंट कर रहे हैं। आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इसी बजट में जाता है, यही टैक्स है। इसी टैक्स के आधार पर जाता है।

सभापति महोदया, आज मैं बहुत कुछ चीज लेकर आया हूं। मैं वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 1990 तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। यदि आप कहेंगे तो मैं ले कर दूंगा। उस दिन वित्त मंत्री जी ने कहा कि नेहरू ने यह कह दिया, राजीव गांधी ने आलोक मेहता को इंटरव्यू दे दिया। इसे तो इंडिविजुअल कह सकते हैं कि राजीव गांधी जी का वह अलग से विषय था। राजीव गांधी जी का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं था या नेहरू जी का पार्टी से लेना-देना नहीं था। ये बार-बार कह रहे हैं कि कई एक चीजें हमने कांग्रेस के न्याय-पत्र से लिया है। यदि कांग्रेस के न्याय-पत्र से लिया तो यह पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो है, वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 1990 तक का मैंने पूरा असेसमेंट किया। इसमें आपको आश्चर्य होगा कि पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1969 में, वर्ष 1971 में, वर्ष 1977 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1984 में, वर्ष 1989 में और वर्ष 1991 में, इन सभी मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि हम ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। आप ओबीसी की बात करते हो, मध्य प्रदेश में आज तक कांग्रेस ने किसी ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज तक किसी ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। बिहार में दरोगा राय जी को छोड़ कर किसी एक भी ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। जब भी ओबीसी की बात आई, यदि दरोगा राय जी ने रिजर्वेशन दिया तो उनको आपने अलग किया। वर्ष 1977 में जब चरण सिंह रिजर्वेशन देना चाहते थे तो आपने उनकी सरकार गिरा दी। आपने वर्ष 1989 में वी.पी. सिंह जी की सरकार गिरा कर चंद्रशेखर जी की सरकार बना दी। जब गुजराल साहब ओबीसी की जनगणना कराना चाहते थे, तो आपने वर्ष 1997 में उनकी सरकार गिरा दी।... (व्यवधान) आप ओबीसी रिजर्वेशन के पिच पर खेल रहे हो। आज इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, चायवाला है, बैकवर्ड है। यदि वह

ओबीसी सुरक्षा की बात करते हैं, वह ओबीसी सरकार की बात करते हैं, तो आप ओबीसी-ओबीसी करते हैं। इसीलिए, ओबीसी के बारे में कांग्रेस का कोई मुंह नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कृष्ण की तरह जो एजेंडा सेट किया है, आप उसके चारों तरफ बिल-बिला रहे हो। अपोजिशन की सारी पोलिटिकल पार्टीज कौरव की तरह प्रधानमंत्री की एजेंडे पर ओबीसी-ओबीसी चिल्ला रही हैं। यदि आप में ताकत है, तो वर्ष 2011 में जो ओबीसी रिजर्वेशन कराया गया, वह क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। यदि आप में ताकत है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, पिछले दो सालों से सरकार है। वहां सोशियो-इकोनॉमिक रिजर्वेशन हो गया है, उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाया? आपने इसलिए नहीं करवाया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दो ऐसे धर्म हैं, जो जाति की बात नहीं करते हैं। उसमें 86 जाति क्रिश्चियन्स की और 56 जाति मुसलमानों की हैं।

(1350/CP/AK)

आप उनको बैक दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से मुसलमानों और क्रिश्चियन्स को ओबीसी रिजर्वेशन देना चाहते हैं, इसलिए आपकी हैसियत नहीं है। आप इसीलिए जातिगत जनगणना की बात करते हो। यदि हिम्मत है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, तो कर्नाटक में वह ओबीसी रिजर्वेशन करके दिखाये तो मैं मानूंगा कि आप हाउस में जो बात करते हो, उसे मानते भी हो। … (व्यवधान)

मैं कांग्रेस का बहुत सम्मान करता हूं, गांधी फैमिली का, यह है भी। मान लीजिए कि भारत का बटवारा हो, नेहरू जी की देन है, तिब्बत से यदि हम जूझ रहे हैं, नेहरू जी की देन है। यदि चाइना हमारे पास तक आ गया, नेहरू जी की देन है। … (व्यवधान) एस्मा वर्ष 1968 में आ गया। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सरकारी अधिकारी आंदोलन करना चाहते थे, तो आप एसेंशियल सर्विस मेंटीनेंस एक्ट ले आए, इमरजेंसी आप लेकर आए, ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लेकर आए, श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स आपने भेज दी, टू जी, थ्री जी, फोर जी सब आपने किया, इसलिए मैं आपकी गांधी फैमिली का बड़ा सम्मान करता हूं। बजट में जो आपने बोला, वह मेरे लिए बड़ा अच्छा है।… (व्यवधान)

सभापति महोदया, इस बजट में हमने एंजेल टैक्स खत्म किया, 56(2) … (व्यवधान) वर्ष 2012 में … (<u>अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>) साहब ने एंजेल टैक्स लगाया 56(2)। इसका कारण था। होता क्या था कि … (<u>अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>) जी के बीच इतनी लड़ाई थी कि वित्त मंत्री के आफिस और घर में बगिंग हो रही थी। … (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Madam, he cannot take names of Members who are not Members of this House. … (*Interruptions*) One is a former President of India who is no longer with us. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, वित्त विधेयक पर चर्चा करें।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : ज्यादा बढ़िया बनने के चक्कर में उन्होंने एंजेल टैक्स लगा दिया।… (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): He is talking about a deceased former President of India. … (*Interruptions*) This is the kind of respect that the BJP has. … (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : एंजेल टैक्स क्या है? माननीय प्रधान मंत्री जी स्टैंड अप की बात करते हैं, स्टार्ट अप की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। माननीय तोता महाराज, लिप्स ऑफ पैरट, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये गुस्सा जाएंगे। हमने देखा कि कहां से बजट आता है, कॉरपोरेशन का कितना टैक्स आता है, इंकम टैक्स कितना आता है, जीएसटी कितना आता है, हमारी देनदारी क्या है, उधार क्या है, यह पूरे फाइनेंस बिल का टैक्स स्ट्रक्चर है। उसमें 8 पर्सेंट के आसपास ऐसा पैसा है, जो डिफेंस को जाता है। आज तक डिफेंस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा इस हाउस में नहीं हुई कि हम इस टैक्स से सेस लेते हैं, सरचार्ज लेते हैं तो डिफेंस में पैसे देते हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि सारे अपोजीशन के लोग अग्निवीर स्कीम के ऊपर लगातार बजट में बोलते रहे। चूंकि एंजेल टैक्स लगाया है, युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको रोजगार दिया जाए। इसको एबॉलिश किया है, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लड़के रोजगार में आएंगे।

मैं इसकी तह पर गया तो पता लगा कि यह कोई नई बात नहीं है। वर्ष 1962 में जब चीन ने भारत को हरा दिया और लगा कि फोर्स की कमी है तो भारत में वर्ष 1962-63 में नेहरू जी शॉर्ट सर्विस कमीशन लाए। ऐसा नहीं है कि केवल फौज के लिए अभी 5 साल की अग्निवीर स्कीम आई है। इसके पहले भी इस देश में वर्ष 1962 में शॉर्ट सर्विस कमीशन आया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में मैंने पार्लियामेंट की सारी डिबेट को पढ़ा। मैं आपको बताऊं कि जो अफसर जॉइन करते हैं, उनकी नौकरी 5 साल से 10 साल होती है और अब वह 14 साल हो गई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोक सभा में या राज्य सभा में या सदन के बाहर कोई क्वैश्चन नहीं किया कि यह शॉर्ट सर्विस कमीशन बना, जबकि सर्विस तो एक ही है। आर्मी में भी जो अफसर ग्रेड के लोग हैं, उसमें एक ग्रेड ऐसा है, जो परमानेंट चलता है, जबकि दूसरा ग्रेड ऐसा है, जो शार्ट सर्विस कमीशन में 10 सालों के लिए चलता है।

(1355/NK/UB)

किसी पॉलीटिकल पार्टी ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन आज हो रहा है, करे कोई भरे कोई। वर्ष 1992-93 में ऐस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट है, यहां रिपोर्टें आती हैं, बनती हैं, चली जाती हैं। आपको आश्चर्य होगा, वर्ष 1966 की एक रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिसे सदन और देश को जानने की जरूरत है। यह रिपोर्ट लेकर आया हूं, कोई भारत सरकार का कागज लेकर नहीं आया हूं। वर्ष 1966 में इंदिरा जी ने आर्मी की रिक्रूटमेंट पर सिलिंग लगा दी, कमेटी ऑफ ऐस्टिमेंट को कांग्रेस पार्टी के मनोरंजन भक्त हेड कर रहे थे। वर्ष 1966 में सिलिंग लग गई, सीलिंग लगने के बाद आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारे यहां इतनी ही आर्मी रहेगी, इतनी ही नेवी रहेगी, इतनी ही एयर फोर्स रहेगी।

आप सीलिंग लगा दो, आप हमको कहो कि रिक्रूटमेंट कैसे होगा, यदि आप फोर्स को बढ़ाना चाहो? सीलिंग के बाद उसी कमेटी की रिपोर्ट है, वर्ष 1975 और 1989 में दो कमेटीज और बनायी गईं। आर्मी को यंग कैसे रखा जाए। एक छोटा सा उदाहरण है, शार्ट सर्विस कमीशन जब बनाया गया था, उस शार्ट सर्विस कमीशन में भी यूपीएससी, राज्य सभी जगह रिजर्वेशन दिया गया था। उसका प्रभाव यह था कि इस देश के होम सेक्रेटरी वी.के.दुग्गल हुए, वह भी शार्ट सर्विस कमिशन से आए और उसके बाद वह आईएएस बने। इन्होंने मैनपॉवर के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद कहा कि आपको पांच और सात साल के लिए, यह वर्ष 1975 की बात है, ध्यान रखिए। वर्ष 1975 से लेकर आज तक 2019-20 लगभग 40-45 साल तक जो रिपोर्ट है, वह गड्ढे में रही, मैनपॉवर की कमी रही है, न आर्मी में आदमी रहा, न नेवी में आदमी रहा, न अच्छा रिक्रूटमेंट हुआ। आज यदि आर्मी के कहने पर वह रिपोर्ट इम्प्लिमेंट हो रही है तो आप युवाओं को देश के साथ जोड़ने के लिए काम कर रहे हो या हमारे यहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से अराजकता हो रही है, जिस तरह से रिजर्वेशन के खिलाफ सारे लड़के रोड पर आ रहे हैं, आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? यह दूसरा सवाल है। बच्चों पर एंजल टैक्स हटाकर, कॉरपोरेट टैक्स 18 परसेंट करके हम बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन आप अराजकता पैदा करना चाहते हैं। तीसरा, इम्पॉर्टेंट पाइंट है। मैंने बहुत सुना, ए1 , ए2 , मैं भी नाम नहीं लेना चाहता। हमारे ऊपर आरोप है कि हम दो कॉरपोरेट्स की मदद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी की डीबीटी स्कीम के पहले, भारत में 1952 से भी एक डीबीटी स्कीम है। लाइसेंस परमिट कोटा राज का डीबीटी स्कीम, डी से... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।), बी से ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) और टी से ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।), यही तीन ऐसे लोग थे।, उसमें ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) को भी जोड़ लीजिए, जूता सिलाई से चंडी पाठ तक, इन्हीं लोगों को करना था, कार वह बनाएंगे, अखबार वह चलाएंगे, सीमेंट वह बनाएंगे, स्टील बनाएंगे।

जब हमारी सरकार आयी तो ट्रांसपरेंसी से काम लिया गया। 32-33 लाख करोड़ रुपये टैक्स आता है, पांच सौ कंपनियां, जिनको ये गाली देने की बात करते हैं। भारत में सबका साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर जब यह सरकार चलती है, तो आपके बिजनेसमैन, आप रोटी खाने जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, शादी में जाओ बहुत बढ़िया है, उनसे गिफ्ट लो बहुत बढ़िया है, आपको चुनाव में पैसा दें बहुत बढ़िया है, लेकिन जब गाली देने की बात आए, ऐसा निकृष्ट विपक्ष ही नहीं देखा। जो लेते भी है, खाते भी हैं, गाली भी देते हैं।

(1400/SK/SRG)

हमारे लिए तो जैसे आम गरीब इम्पॉर्टेंट हैं वैसे ही अमीर भी इम्पॉर्टेंट हैं। … (व्यवधान)

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Madam, I have to raise a Point of Order.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय): रूल नंबर बताएं?

… (व्यवधान)

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Madam, you once reminded the Members about speaking on the Finance Bill. Rule 356 says, "The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either in one's own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct that member to discontinue the speech." Hon. Chair once reminded the respected Members about this. Madam, kindly invoke it.

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय सभापति जी, मैं एंजल टैक्स की बात कर रहा हूं, कॉरपोरेट टैक्स की बात कर रहा हूं। … (व्यवधान) आप एंजल टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स को कैसे डिरेल कर रहे हैं? … (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि आप जिस डबल 'ए' कंपनी के बारे में कह रहे हैं, चार लाख करोड़ रुपये इस देश की किट्टी में दे रही है और उसके कारण यह देश चल रहा है। … (व्यवधान) क्या आप चाहते हैं कि यह कंपनी बंद हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि वह बैंक बंद हो जाए? आप चंदा भी खाओ, आप उनकी शादी में भी जाओ और फिर उसके बाद गाली भी देते रहो, क्योंकि वे डिफेंड करने वाले नहीं हैं। … (व्यवधान) अब आप ये काम करो। … (व्यवधान) इस देश का कौन ऐसा पोलिटिशियन है जो अंबानी की शादी में नहीं गया? … (व्यवधान) कौन ऐसा आदमी है? … (व्यवधान) इनकी पार्टी की महासचिव … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) क्या वह शादी में नहीं गईं?… (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं? … (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : कोई नहीं गया। … (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी गए हैं और आप बोल रहे हैं कि कौन गया है? … (व्यवधान) आप उनका नाम लेंगे। … (व्यवधान) वह सदन के सदस्य नहीं हैं और दोबारा नाम लिया गया है। … (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, आप महासचिव कहिए। … (व्यवधान) आप कहिए कि … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) शादी में गईं, इतना मान लीजिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बजट पर अपनी बात कम्पलीट कीजिए।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, हमने फाइनेंस बिल में एक बड़ा अच्छा पार्ट आता है, पीएमएलए। इस सदन में जितने लोग बोलते हैं, इनकम टैक्स के बारे में बोलते हैं, ईडी के बारे में बोलते हैं और सीबीआई के बारे में बोलते हैं। खैर, सीबीआई तो अलग संस्था है। इनकम टैक्स और ईडी महत्वपूर्ण हैं और फाइनेंस बिल में ईडी के लिए कुछ चीजें बताई गई हैं। मैं जब … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) की लिप सर्विस की बात कहता हूं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कहते हैं।

महोदया, यह सदन के जानने लायक चीजें हैं, वर्ष 1988 में राजीव गांधी साहब बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट लाए और वर्ष 1988 से वर्ष 2017 तक 30 साल में उसके रूल्स नहीं बन पाए। आप हमसे हिसाब लेते हो कि हमने किसको पकड़ा? किसको नहीं पकड़ा। कौन जेल गया? कहां ब्लैकमनी है? कहां व्हाइट मनी है? क्या आपने कभी अपने गिरेबान में झांका है? आपकी सरकार वर्ष 1991 से वर्ष 1996 और वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक रही तो फिर आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम सरकार में नहीं रहे। आप वर्ष 1988 में बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट लाए लेकिन इसे लागू नहीं कर पाए। आप किसका साथ दे रहे थे? … (व्यवधान)

दूसरी बात, मैं आपको बताऊं, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वर्ष 2012 में दिसम्बर महीने में बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में संशोधन हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ था और उस तरफ माननीय चिदंबरम साहब थे। वह बहुत फेमस वित्त मंत्री थे। मैंने उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो अपने जीवन में देखा ही नहीं। मैंने कहा कि आप जो एक्ट लेकर आ रहे हैं, एक दिन यदि वाइफ हसबैंड में लड़ाई होगी तो उसमें पीएमएलए लग जाएगा। यह जितना स्ट्रिंजेंट है, आप जिस भी आधार पर लगा रहे हो, भगवान न करे कि एक दिन आप ही जेल चले जाओ। उस जमाने में मेरा सीट नंबर 545 था। मैं अंतिम बोलने वाला सदस्य था, मैं 545 नंबर सीट पर था। जब मैं बोलकर बंद हुआ तो चिदंबरम साहब खड़े हुए और चिदंबरम साहब का बड़ा फेमस भाषण है।

(1405/KDS/RCP)

भारतीय जनता पार्टी बहुत पढ़ी-लिखी पार्टी है। मेरी अपेक्षा यह थी कि पीएमएलए कानून पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने एक विद्वान आदमी को खड़ा करेगी, लेकिन उसने सबसे मूर्ख, बुद्धू और दकियानूसी आदमी को, जिसे पीएमएलए पता ही नहीं है, उसे खड़ा कर दिया। … (व्यवधान) यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसके एफएटीएफ में चिदंबरम साहब का जो वर्ष 2012 का स्टेटमेंट है, उसी को क्वोट करते हुए यह रिपोर्ट आई है। जब रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होय। इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स क्वोट पर हमारी फाइनेंस कमेटी, जिसमें यशवंत सिन्हा चेयरमैन थे और मैं उसका मेंबर था, 5 साल तक हम लोग मेहनत करते रहे कि डायरेक्ट टैक्स क्वोट को हम लोग बदल दें। पीएमएलए में आप स्ट्रिंजेंट कानून लेकर आ गए। … (व्यवधान) बिना एक पैसा खर्च करते हुए यदि कांग्रेस पार्टी ने आपको 90 करोड़ रुपये दे दिए और आपने यंग इंडिया, नैशनल हेराल्ड खरीद लिया। 750 करोड़ रुपये की सम्पत्ति बिना किसी पैसे के आपको

मिल गई, … (व्यवधान) तो क्या राहुल साहब, जो चिदंबरम साहब का कानून, उसमें आप जेल नहीं जाएंगे? … (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): The matter is *sub judice*. The Member cannot raise a matter which is *sub judice*. … (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर क्वोट कर रहा हूं, इसीलिए आप सीबीआई और इनकम टैक्स की बात करते हैं। यह आपकी कारस्तानी है। हमारी सरकार, माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ऊपर केवल वह उसको इम्प्लीमेंट करती है। हमने अपनी एजेंसी को फ्री छूट दे रखी है। जो भी भ्रष्टाचारी है, वह जेल जाएगा। वह किसी कीमत पर नहीं छूटेगा।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, कृपया कम्प्लीट करिए।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, इस देश के हालात बहुत अच्छे हैं। हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की कल्पना में हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी से यक्ष-युधिष्ठिर वार्ता में उस दिन बोलते हुए माननीय राहुल जी ने कहा कि छ: महारथी थे। … (व्यवधान) छ: महारथी नहीं थे, नौ महारथी थे, जो अभिमन्यु से लड़ रहे थे और सात महारथी चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरने के लिए बैठे थे और दो महारथी ऐसे थे, चक्रव्यूह के बार चार पांडवों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे अंदर न जाने पाएं। । उसमें भीम, सात्विक, नकुल और सहदेव थे। … (व्यवधान) उस दरवाजे की रक्षा जयद्रथ कर रहे थे कि वे उसमें नहीं जा पाएं। महाभारत के दूसरे प्रसंग में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा। एक प्रश्न था कि क: पंडित और दूसरा है, को मूर्ख:, तीसरा है क: मत्सर: । मैं मूर्ख पर नहीं जाऊंगा, केवल दो ही चीजों पर जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है ये अपने पर ले लें, लीडर ऑफ अपोजीशन पर ले लें कि उनको मूर्ख कह दिया। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। पंडित वह है, जो विद्वता की बात करता है। ... (*Expunged as ordered by the Chair*) केवल और केवल डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट, जो हमारे रामायण, महाभारत, गीता का है, वही करते रहते हैं, इसलिए उनको सोचने की बात है कि वह पंडित हैं या नहीं।

महोदया, जो मत्सर है, मत्सर के बारे में बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जिसको ईर्ष्या, द्वेष, जलन हो, किसी के आगे बढ़ने पर परेशानी हो, उसे मत्सर कहा जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, वह यक्ष-युधिष्ठिर वार्ता का मत्सर है। भारत इतना ग्रो क्यों कर रहा है? भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी में क्यों जा रहा है? भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी वर्ष 2027 में क्यों हो जाएगा? इस कारण से युवाओं को भड़काओ, किसानों को भड़काओ, जातिगत रिजर्वेशन के आधार पर, जिस रिजर्वेशन के आधार पर आज बांग्लादेश जैसा देश जल रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, श्रीलंका खत्म हो रहा है। लीडर ऑफ द अपोजीशन के नाते जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है और जिम्मेवारी कैसे होगी?

(1410/MK/PS)

सभापति महोदया, जिम्मेवारी नहीं होने के पीछे रीजन हैं। रीजन यह है कि मैं तीन किताबें अभी पढ़कर आया हूं, वे तीनों किताबें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक किताब अशोक मित्रा ने लिखा है- A Prattler's Tale. अशोक मित्रा साहब बंगाल के सबसे लांगेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे और इंदिरा जी के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। दूसरी किताब नटवर सिंह की है, जो कहता है – One Life is Not Enough और तीसरी किताब संजय बारू की है -The Accidental Prime Minister. ये तीन किताबें हैं और तीनों आदमी, संयोग से अशोक मित्रा साहब को छोड़ दीजिए तो दो आदमी अभी भी हैं। … (व्यवधान) किसी को कांग्रेस ने आज तक कांट्राडिक्ट नहीं किया। तीनों किताबें क्या कहती हैं? अमेरिका तय करता था कि इस देश का वित्त मंत्री कौन होगा। संजय बारू कहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सरकार नहीं चलाते थे, सरकार नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की सोनिया गांधी जी चलाती थीं। … (व्यवधान) यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह संजय बारू की किताब है। मैं तो केवल किताब को कोट कर रहा हूं। … (व्यवधान)

महोदया, मैं सीआईए की कुछ डी-क्लासिफाइड फाइल्स लेकर आया हूं। ये सीआईए की डी-क्लासिफाइड फाइल्स हैं। ये फाइल्स कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सोवियत रूस से बिके हुए थे। वे पैसा लेते थे और पैसा लेकर देश की पॉलिसी बनाते थे। देश का कैसे नुकसान हो, वही काम करते थे। … (व्यवधान) ये डी-क्लासिफाइड फाइल्स कहती हैं। अगर आप तीनों किताबों को देखेंगी, चाहे वह अशोक मित्रा की हो, संजय बारू की हो या नटरवर सिंह की हो, यह कांग्रेस पार्टी इस देश को बदनाम करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। … (व्यवधान) ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ पूरा माहौल बने, इस देश के खिलाफ पूरा माहौल बने, लेकिन वह हम होने नहीं देंगे। … (व्यवधान) ये देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे लोग हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि –

"जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
अन्तिम संकल्प दोहराता हूं,
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा।"

इस देश को बनाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी होगी तो हम कुर्बानी देंगे। हम वित्त मंत्री जी के इस फाइनेंस बिल का समर्थन करते हैं और पूरे सदन से यह आग्रह करते हैं कि इस बिल को पास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत। … (व्यवधान)

(इति)

1413 बजे

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : सभापति महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2024 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आभारी हूं आंवला लोक सभा की महान जनता का, जिसने अपना आशीर्वाद देकर हमें आपके बीच में भेजा है।

महोदया, यहां बड़ी लंबी-लंबी बातें करने वाले लोग हैं। आज एक बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि वर्ष 2047 में 'विकसित भारत' बनेगा। लोक सभा चुनाव के पहले सरकार ने एक विकसित भारत यात्रा निकाली थी। वह यात्रा चुनाव प्रचार की दृष्टि से निकाली गई थी। हमारे लोक सभा क्षेत्र में जब विकसित यात्रा पहुंची तो तत्कालीन सांसद महोदय जी एक माताजी को एक मकान की चाबी देते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। जब उस माताजी से पूछा गया कि माताजी आपको आवास मिला है, इसके लिए किसी ने आपसे कुछ लिया तो नहीं? पूरी दुनिया ने वह वीडियो देखा, उस माताजी ने कहा था कि तीस हजार रुपये देकर आवास मिला है।

(1415/SJN/SMN)

माननीय सभापति महोदया, आज किसानों की हालत बहुत खराब है। उस पर सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। जहां एक तरफ बात होती है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, मुझे लग रहा है कि जो बजट आया है, उसमें किसानों के बारे में कोई चिंता नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश का किसान इतना दुखी और परेशान है कि वह अपनी फसल लगाने के लिए रात-रात भर जागता है। जब तीन डिग्री तापमान होता है, तब वह अपनी मेढ़ पर खड़ा रहता है। उसके बाद भी फसल नहीं बचती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में वादा किया था कि आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाया जाएगा, लेकिन वे आज उसको भूल गए हैं।

आज उत्तर प्रदेश में किसानों को कतई बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे-ऐसे गांव हैं, जहां 15 से 20 दिनों तक सप्लाई नहीं हो रही है, धान की रोपाई नहीं हो रही है। उसके बारे में कोई चिंता नहीं की जा रही है। हमारे नौजवान साथी भी दुखी हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है। ये युवा पीढ़ी गांवों में रह रही है। उनके लिए न तो अच्छे कॉलेज हैं, न ही अच्छे स्कूल हैं और न ही खेल के मैदान हैं। शाम को युवा तीन घंटे कैसे खेले, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। युवा या तो शराब पीने लगता है या यू-ट्यूब में मस्त हो जाता है। सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए।

केवल कहने से विकसित भारत नहीं बनने वाला है। अगर विकसित भारत बनाना है, तो रेलवे को सुधारिए। रेलवे की हालत बड़ी खस्ता है। मैं समझता हूं कि बगैर गांवों का विकास किए विकसित भारत की कल्पना करना केवल और केवल दिखावा-छलावा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा से पहले जो सरकारें थीं, हमारे नेता जी ने 'लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना' शुरू की थी। 'लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना' के माध्यम से गांवों का विकास हो रहा था। ये डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग हैं, लेकिन 10 साल में एक भी गांव का विकास नहीं किया है। जब ये वर्ष 2014 में आए थे, तब इन्होंने कहा था कि सांसद गांव को गोद लेंगे। जो गांव गोद लिए गए, उन गांवों में कोई

भी विकास नहीं हुआ है। उन गांवों की हालत पहले से ज्यादा बदतर हो गई है। आज ऐसे हालातों पर सर्वे किए बगैर, गांवों के विकास की योजना बनाए बगैर, केवल यहां से कह देना कि विकसित भारत बनाएंगे, ये केवल देश को गुमराह करने वाला जुमला है।

माननीय सभापति महोदया, जब वर्ष 2014 में ये लोग सरकार बनाने के लिए प्रचार कर रहे थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विदेशों में काला धन जमा है। आज उस काले धन पर बात नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका मिला है, लेकिन उसके बाद भी सरकार सुधार की तरफ नहीं बढ़ रही है। यहां पर जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, गरीब की बात केवल भाषणों में होती है। गरीब का कल्याण कैसे हो, ये सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमने 39 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है, यानी हमारे देश में लगभग 120 करोड़ लोग गरीब थे। अगर 140 करोड़ में से 120 करोड़ लोग गरीब हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की क्या स्थिति है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सरकार का दावा है।

महोदया, मैं तो आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को जमीनी हकीकत पर आना चाहिए, जमीन पर आना चाहिए और जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए इस सदन के माध्यम से कुछ कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे इस देश का भला हो सके, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं आंवला लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। वहां अस्पतालों का बुरा हाल है। हमारे यहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। वहां लोग परेशान हैं। जब स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट पर चर्चा हो रही थी, तब मैंने कहा था कि चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल्स हों, सबने लूट मचा रखी है।

(1420/SPS/SM)

आज इस वित्त विधेयक में कैसे हमारा किसान मजबूत हो, उसके लिए मेरा एक सुझाव है। देश के अंदर अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने के बाद हम उसको काट नहीं सकते हैं। अगर सरकार औद्योगिक क्षेत्र में लकड़ी के इस्तेमाल और रिहायशी क्षेत्र में लकड़ी के इस्तेमाल के पेड़ों को लगाने की योजना बनाए तो यहां से कानून बनना चाहिए कि अगर आप पेड़ लगाते हैं तो आपको पेड़ काटने की भी अनुमति दी जाएगी। अगर किसानों की इनकम को बढ़ाना है, किसान को आगे बढ़ाना है तो ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाए बगैर हमारे देश का किसान समृद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पर आधारित है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर अन्नदाता ही सबसे ज्यादा दुखी होगा, परेशान होगा तो मुझे लग रहा है कि यहां पर बैठने वाले लोगों को भी कोई माफ नहीं करेगा।

महोदया, हमारे यहां सरकार की तरफ से 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का हो-हल्ला मचाया जा रहा था। उस पर अभी कुछ काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं यह मांग करता हूं कि इस देश में एक शिक्षा व्यवस्था कब लागू होगी? अगर इस देश में एक शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी जाए तो शायद लोगों का कल्याण हो जाए, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। गरीब का बच्चा कब पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

अगर 'एक देश, एक स्वास्थ्य' व्यवस्था लागू कर दी जाए तो इस देश का कल्याण हो सकता है। … (व्यवधान) माननीय सभापति जी, हम लोगों की पार्टी का समय अलॉट हुआ है, लेकिन अभी चार मिनट भी नहीं हुए हैं।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : माननीय सभापति महोदया, मैं वित्त विधेयक को पढ़ रहा था। इसमें आम जनता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इनकम टैक्स का है। जब वर्ष 2019 में मोदी जी की सरकार बनी और तत्कालीन वित्त मंत्री जेटली साहब थे तो उन्होंने कहा था कि हम इनकम टैक्स एक्ट को बदलेंगे। पूरे देश के लोगों से सुझाव मांगे गए थे और पूरे देश के लोगों से इस पर चर्चा की गई थी। अब जब जेटली जी नहीं रहे तो उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यह एक्ट जटिल है, क्योंकि इसमें बार-बार संशोधन हुए हैं। यह एक्ट इतना जटिल हो गया है कि जो लोग टैक्स देते हैं, वह इसमें उलझ जाते हैं। वित्त मंत्री जी ने भी स्वयं अपने बजटीय भाषण में कहा है और इस स्थिति को स्वीकार भी किया तो वित्त मंत्री की असफलता इसमें साबित होती है।

सभापति महोदया, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम छ: महीने के अंदर इस एक्ट को रिव्यू करेंगे, लेकिन उसके लिए किसी कार्य योजना के बारे में कुछ भी विस्तार से नहीं बताया गया है। इसलिए इस पर गंभीरता के साथ योजना बनाकर, सदन को विश्वास में लेकर, सदन में यह बात रखी जाए, जिससे आम टैक्स पेयर को कुछ राहत मिले। अभी इनकम टैक्स का संशोधन आया है, उसमें सरकार ने कहा है कि बचत स्कीम्स के माध्यम से, चाहे उसमें एलआईसी हो, चाहे पीपीएफ हो या अन्य कोई टैक्स रिबेट वाली स्कीम्स हों, उनसे जो लोग छूट लेते थे, उसको भी इन्होंने खत्म करने का काम किया है। जो हमारे सामान्य लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके अंदर एक बचत की भावना थी कि हम टैक्स में छूट पाएंगे, इसलिए कुछ बचत कर लें, लेकिन उसका भी इस नई टैक्स प्रणाली में नुकसान हुआ है, इसलिए इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। … (व्यवधान) आप मुझे दो मिनट बोलने के लिए और दे दीजिए। जो 30 परसेंट का टैक्स स्लैब है, वह बहुत ज्यादा है। कॉर्पोरेट से 25 परसेंट टैक्स लिया जाता है और जो एम्प्लॉई है, जो काम कर रहा है, जिसकी आमदनी कम है, उससे 30 परसेंट लिया जा रहा है।

(1425/MM/RP)

इस टैक्स स्लैब को भी ठीक करने की आवश्यकता है। सेक्शन 115 बीए में 15 परसेंट टैक्स की रियायत दी जाती है, इसको कम किया जाए जिससे मैन्युफेक्चरिंग के क्षेत्र में बढ़ावा मिले। कम्पनी से, कॉरपोरेट से जो 25 परसेंट का टैक्स लिया जाता है, यही टैक्स पार्टनरशिप कम्पनीज़ पर भी लगाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, जो बातें यहां से होती हैं, उनको कैसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर भी यहां से कोई न कोई कमेटी बननी चाहिए। हमारे क्षेत्र में बिशारतगंज रेलवे स्टेशन है। मैं वहां ओवरब्रिज बनाने की मांग करता हूं। वहां लोग पटरी फांद कर जाते हैं और कई बार वहां दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यहीं, बिशारतगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग 6ए, रमपुरा-अलीगंज में … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : धन्यवाद माननीय सदस्य।

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : महोदया, मुझे दस मिनट का समय बोलने के लिए मिला है।

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं।

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : अंडरपास बनाने की आवश्यकता है। कोरोना काल में हमारे यहां से एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जिसको बंद कर दिया गया था। उसको पुन: चालू करने की मैं मांग करता हूं। हमारे यहां फरीदपुर से बुखारा रेलवे क्रॉसिंग, जहां अत्यंत जाम रहता है और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, वहां भी ओवरब्रिज बनाने की मांग करता हूं। अंत में मैं अदम गोंडवी साहब की चार लाइनों को कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा-

"तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है
मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है।
उधर जम्हूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो
इधर परदे के पीछे बर्बरीयत है, नवाबी है।
लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में
तुम्हारी मेज़ चांदी की तुम्हारे जाम सोने के
यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रक़ाबी है।"

मैं आपका आभार प्रकट करते हुए उम्मीद करता हूं कि मोदी जी का सैद्धांतिक रूप से एक साल का ही कार्यकाल बचा है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय श्रीमती महुआ मोइत्रा जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : महोदया, मुझे बोलने के लिए दस मिनट का समय मिला है और अभी मेरे दस मिनट नहीं हुए हैं।

माननीय सभापति : आप दस मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : माननीय मोदी जी का सैद्धांतिक रूप से माननीय मोदी जी का एक साल का कार्यकाल है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने नियम बनाया है कि 75 साल के बाद न तो चुनाव लड़ना है और न ही मंत्रिमंडल में रहना है।… (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

1429 hours

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Chairperson, Madam and my respected colleagues, I stand here today on behalf of my party, the All-India Trinamool Congress, to speak on the Finance Bill.

Madam, I have to say, I am deeply pained. At the very outset. I must point something out. When we speak on the President's Address, the hon. Prime Minister leaves the Chamber. Today, when we are speaking on the Finance Bill, the hon. Finance Minister leaves the Chamber. We, Members of the Opposition, are deeply pained by this. We hope that the Government will take notice of our pain and be present in the House each time when we speak on the relevant issues.

Theodore Roosevelt, the 26th President of the United States, had said: "In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing." The hon. Finance Minister has made a mockery of the people of India in this Union Budget by doing absolutely nothing.

(1430/NKL/YSH)

Whatever little changes are there are regressive and ill-thought-out. This is an illusory Budget where the Government knows fully well the mandate of 2024. This Coalition Government means that the people did not want the 'business-as-usual' approach. People wanted a course correction. What have you done? You have not listened to the mandate. *'Vinash Kale Viprit Buddhi'* – you have done the exact opposite. You have kept the same Cabinet; you have kept the same Finance Minister who has given the same shoddy Budget.

Who is this Budget for? The middle-class make up 31 per cent of India and the poor make up between 60 and 65 per cent of India. I will demonstrate how this Budget systematically strangles the poor and the middle-class. This is a '*Kursi Bachao Budget'*, a 'Save-the-Chair Budget' for this Government, and even that, it does not do very well.

Broadly, there are two types of taxes, that are, Direct Taxes and Indirect Taxes. Direct Taxes are known as progressive taxes. Why are they progressive? If we talk about income tax, property tax, and investment tax on the capital gains, these are done in a way that the richer you are, the more tax you pay. So, they are kind of fairer…. (*Interruptions*) Indirect Taxes are

regressive because everyone from the richest billionaire to the poorest labourer is paying the exact same tax. So, if we talk about GST, the duties on petrol and the duties on diesel are all indirect taxes. When we strive for a fair and equitable economy, we must have the balance of Direct Taxes and Indirect Taxes right. The US and the Europe broadly collect about 60 per cent through the Direct Taxes and 40 per cent through the Indirect Taxes. Some Scandinavian States with welfare models collect 70 per cent through the Direct Taxes and 30 per cent from the Indirect Taxes. In India, it is the exact opposite. About 65 per cent of tax collection comes from the Indirect Taxes where the billionaires pay the same as the poorest labourers, and only 35 per cent comes from the Direct Taxes. Even within the Direct Tax bracket, for the first time in our country's history, the salaried professionals and the middle class are sharing a greater tax burden than that of the rich corporates. The middle-class is contributing 55 per cent of the Direct Income Taxes under this Government, up from 38 per cent under the UPA. The richest corporates in India today contribute only 45 per cent of the Direct Taxes. Not only is the middle-class being taxed, but now with this Budget, the savings of the middle class have also been taxed with removal of indexation and with a rise in the short-term capital gains. The investors, who have made more than 11 per cent returns – we have done the calculation – that is about the threshold rate, if you have made more than 11 per cent returns, the higher returns, then this new tax regime in which the removal of indexation has happened, is good for you.

Now if we talk about the people like our parents, pensioners, salaried middle-class, risk-averse people, who invested in gold, in property, in debt mutual funds, the removal of indexation has harmed them disproportionately. So, the middle-class has lost out. The Debt mutual fund holders will end up paying more than 40 per cent more tax because the indexation is being changed from 20 per cent to 12 per cent for the investments made before April 1st, 2023.

So, this is effectively penalizing those who have made low profits. People think real estate has made enormous profits. If you look at the RBI's Housing Index for the past 10 years, the average rise in property prices has been between 4.5 per cent and 5 per cent. So, if the middle class has invested

in property, that is below 11 per cent return, and thus, the indexation is going to harm you.

The current GST regime is irrational and iniquitous. There is an 18 per cent GST levied on life insurance and medical insurance products. The hon. M.O.S., Finance, on Monday, told this House that the Government has collected Rs. 8,263 crore as GST on health insurance for the fiscal year 2023-2024 alone. This is blood money. Our hon. Chief Minister, Mamata Banerjee ji wrote a letter to the hon. Finance Minister in the Centre, pointing out that this is a completely anti-people tax. What is life insurance? What is health insurance? It is protecting people, protecting against life's uncertainties – against accident, against injury, against ill health, against death. What are you doing? You are imposing GST, which the poorest and the middle-class person has to pay, at the same rate that a billionaire pays. So, the people are deterred from taking out new policies and continuing existing insurance. This should be removed at the earliest.

(1435/VR/RAJ)

Let me now move on to what affects more than 70 per cent of the Indian citizens – the social sector allocations. The general trend over the past decade in every Budget in the last 10 years, of which our hon. Finance Minister has presented seven, has been in nominal terms that you have allocated more money to the social sector. But if you account food inflation, and you look at real allocations, which is inflation adjusted, the allocations have seen reductions of over 25 per cent in the past 10 years.

I am going to look at real allocations that is adjusted for inflation for some major schemes in the past 10 years. The allocation to Sarva Shiksha Abhiyan is minus 18 per cent, the allocation to Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan is minus 9 per cent, the allocation to Integrated Child Development Scheme (ICDS), which affects every child as it is a school scheme, is minus 34 per cent, the allocation to Mission Anganwadi is minus 5 per cent, the allocation to PM POSHAN scheme is minus 45 per cent, the allocation to Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana (PMGSY), those of us who have rural areas, has been reduced minus 47 per cent in real terms, the allocation to the National Social Assistance Program is minus 20 per cent, and the allocation to the combined expenditure on five social schemes, the top five social schemes

as a percentage of GDP, has declined from a peak of 0.93 per cent. So, from almost one per cent of GDP in 2009-10, do you know where is it today in 2023-24? It is at 0.36 per cent. It is only one-third of what it was in 2009-10. Do you know where is the MAGREGA budget today? The MANREGA budget during COVID-19, when the Centre was asking all the States to give employment to the labourers as they were going back, was 0.6 per cent of the GDP. Today it is just 0.26 per cent.

The specific Budget figures for 2024-25 are shameful. Let us look at the specific figures. The allocation for Samarth scheme, which is maternity entitlement and the crash scheme, has been reduced by Rs.70 crore compared to the Budget Estimates of last year. The budget for the National Social Assistance Program – again those of us from the rural areas know how important is this – is unchanged from last year, and is at Rs.9652 crore. The National Social Assistance Program is what gives social security pensions to the elderly, to single women and to the disabled. It is same as last year. There is no adjustment for inflation.

The Central contribution to social security pensions has been unchanged since 2014. It was Rs.200 in 2014; it is still Rs.200 per person today. The price of the cutlets in the Parliament canteen in the last 10 years has been adjusted for inflation with the Government's approval. The price of the cutlets in the Parliament canteen has more than doubled. But when it comes to giving social security for the poorest of the poor, it is still Rs.200 in the last 10 years. There is no change.

Under this year's Budget allocation, there is no room for higher salaries for Anganwadi workers. Their salaries have been unchanged since 2018. There is no room for higher honorarium for Mid Day Meal cooks. You have to understand that a lot of the women in villages depend on only Anganwadi sectors and Mid Day Meal sectors for any source of employment. There has been no higher allocation for supplementary nutrition given to the children.

The National Food Security Act (NFSA) mandates coverage of 67 per cent of the population through the Public Distribution System (PDS). The Prime Minister has very proudly proclaimed that this is a food surplus country. Then, why have we not increased the population covered under rations? Since 2011,

you have not had a census. Since you have not had a census, you have not increased the number of people being covered under rations.

Also, there is one very important question. Why is the Central Government blatantly defying the direction of the Supreme Court? We went to the Supreme Court on the migrant workers' case. The Supreme Court gave a direct order to the Central Government that the Central Government has to give rations to eight crore migrant workers of the unorganized sector, who have been left out of the food security net. The last hearing was on 16th July 2024. The Court again said that you have to please give money to the States which have issued additional ration cards. But there is no room in the Budget for this. There is no allocation.

In this rush to protect its own chair, the Government is making a very dangerous mistake that it is not giving enough to protect our borders. Military experts have repeatedly warned us that India's military capability has to be modernized because we are fighting on two-fronts. One is against China where we need a dissuasive deterrent, and the other is against Pakistan, where we need an offensive deterrent. The budgetary allocation for Defence in this Budget is Rs.6.22 lakh crore. There is a marginal decrease of Rs.2000 crore compared to the Revised Estimates. This year's budget allocation for Defence is 1.9 per cent of the GDP.

(1440/SAN/KN)

This is the lowest since 1960. Despite many economic constraints, the past Governments had always given close to three per cent of GDP, which is a universal norm, for defence. Over the last decade, ever since this Government has been in power, it has been hovering around two per cent. We have been unable as a Government to compel China to restore *status quo ante* April 2020 on the Line of Actual Control. We have been unable to deter Pakistan. In the last two months alone, over 50 security personnel and about 10 civilian pilgrims have been killed in Jammu. The capital expenditure on military equipment is Rs. 1.75 lakh crore. On paper, this shows that it is almost a ten per cent increase. What we have not taken into consideration is that this increase was largely due to Russia’s inability to supply contracted weapons to us because of the Ukraine war. If we take into account the inflation and the rising dollar rate, it is almost flat.

The gap between the projections made by the Armed Forces and the actual allocations is 17 to 23 per cent. That is the gap. आप कुर्सी बचाने में मस्त हैं, आप देश को भी देखिये। We need to allocate 2.5 to 3 per cent of GDP to defence. This is something that the country needs to look at.

The hon. Finance Minister started off her speech by talking about the focus on *annadata* or farmers. How much has this Government done for the farmers? The *Economic Survey* of 2024 says 42.3 per cent of Indians depend on agriculture, that is, 600 million or 60 crore people. I looked at the *Economy Survey* presented on 22nd July very carefully. What did the headline say? The headline says 'Agricultural sector has registered an annual average growth rate of 4.18 per cent in the last five years', but then I needed to read and read and read, and in the fine print was written that last year, it was only 1.4 per cent. Anyway, when you compare the growth rate of 4.18 per cent over the last five years to inflation, it is nothing, but when you compare last year's growth rate of only 1.4 per cent, what is it saying to 60 crore of our people who depend on farming?

Productivity and Resilience in Agriculture was one of the first themes. It was priority number one, according to the Finance Minister's Budget. She had made nine priorities. This was priority number one. But the provision for agriculture and allied sectors is only Rs. 1,52,000 crore whereas the provision for one Bullet Train from Ahmedabad to Mumbai is Rs. 1,08,000 crore. I would request everybody to please look at the comparison.

The Finance Minister said that the priority number two is 'Employment and Skilling'. This Government has got the worst track record of creating jobs. India has more jobs in the informal sector, not in the formal sector. The Budget is talking of an internship programme with the top 500 companies. This is a joke. The top 500 companies employ 70 lakh people in total. That is one per cent of the total workforce. Our workforce is about 57 crores. You are expecting companies, which employ 70 lakh people, to give employment to one crore interns. Please let us know how this is going to happen. I am really curious to know this. The real problem is somewhere else. The real problem is that 10.3 crore youths have basically become so dejected that they have given up looking for jobs. The Finance Minister mentions skilling loans and education loans. The skilling loans would be given to 25,000 people and the education

loans would be given to one lakh people. The country has 140 crore people. What are we doing?

The priority number three, according to the Finance Minister, is 'Inclusive Human Resource Development and Social Justice'. In this section, the Budget says that they will support construction of expressways in Bihar. What you are not saying is that you will make expressways which will charge very high tolls. So, you are recovering the money; you are not doing anyone a favour. You are charging back-breaking tolls. You might give another bridge which might collapse! You will setup another power plant which, like in Jharkhand, may also be outsourced to a favourite businessman. It can be given a nice, juicy PPA and sell more imported coal.

Secondly, to Andhra Pradesh, there are no grants, but only loans, that too from multilateral agencies. So, basically dollar loans will be given to Andhra Pradesh, which the future generations will have to pay back with interest.

There was also another sweeping statement that grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasam and North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. I looked into the entire Demands for Grants with a toothcomb, with a microscope and I also looked at the Expenditure Budget also. Nothing was provided anywhere. I do not see the intelligent people of Andhra Pradesh being fooled by this.

The priority number four is Manufacturing and Services. The Finance Minister has devoted an entire section on how MSMEs are a priority. I believe her, and it should be a priority, but I am very confused because most medium and small enterprises are either proprietorships or partnerships. Madam, can you please explain why proprietorships and partnerships are taxed at higher rate that companies are? This makes no sense. Is the 'A' team the only businesses who are sending truck loads and tempo loads. MSMEs are not sending them. Is that the problem?

Also, the Government needs to get rid of the bizarre Section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code because it is killing companies that are in trouble. It does not allow promoters to propose a resolution plan.

(1445/SNT/VB)

As long as we have this Code, the promoters cannot propose a Resolution Plan. We need to get rid of this.

Priority 5 in the Finance Minister's speech is 'Urban Development'. The Prime Minister had said every citizen will get a house by 2022. We are now in 2024 and we are still making allocations for three crore more houses. Can you please tell us how many more houses we need and when it is going to be done? Let us get this over with.

Priority 6 is 'Energy Security'. The less I speak about this, the better it is. Energy security is security for best friends. It is created by allowing best friends to import low-grade quality coal, marking it up as high-grade quality coal and selling it to the State Development Corporations at the cost of the country's environment and at the cost of the health of our citizens.

Priority 7, the Finance Minister said, was 'Infrastructure'. She announced in a true style of *shagun* that she is gifting the nation Rs. 1,11,111 crore. This is flat on last year. Sadly, most of this money will go towards crony capitalists. You make roads that have potholes; you will have airports that leak; and you will have bridges that fall out; and the taxpayer will pay for this. The Budget speaks of private sector participation but remember one thing. They bid out six airports to one company for a fee to be paid to the Government. Then they created a policy that allows the regulator to keep increasing the User Development Fee. So, actually, it is the flying public of India that are paying for this.

Priority 8 is 'Innovation, Research and Development'. These are just grand words. The Finance Minister seems to have forgotten that most of the entrepreneurs register their product and software IPs in foreign countries like the US since the IP registration system for patents is a complete failure in our country. Unless you fix patent registrations, this is not going to happen.

The last priority she talks about is 'Next Generation Reforms'. This is also another *jumla*. She says: "I propose to earmark a significant part of the 50-year interest free loan for competitive federalism." So, this is doublespeak. They will keep this money in their pocket. If Nitish ji and Chandrababu ji see

through their *jumla* and they make a big fuss, they will have some additional funds to keep them happy and to keep the Government going.

Finally, I have to mention one interesting fact. I hope that the Treasury Benches will have the patience to hear me out. I wholly agree with the Finance Minister on one thing. The budgets for the CBI and the ED have been reduced this year and I was wondering why. Is it because the voters did not like the fact that you were using the CBI and the ED to go after the Opposition and file fake affidavits? Or, is it because you have outsourced the CBI and the ED completely to a businessman in Ahmedabad who is controlling the whole thing? Why have you reduced it? The former Maharashtra Home Minister highlighted how the BJP leaders and the agencies have threatened him to file a fake affidavit. In the case of Sandeshkali in West Bengal, the women have confirmed on video that the BJP leaders forced them to file fake statements. Similarly, I am told in my matter, ... (*Expunged as ordered by the Chair*) on October 16, 2023 got my friend to his office in Ahmedabad and threatened him with dire consequences to file a fake affidavit. Actually, it was ... (*Expunged as ordered by the Chair*) who filed the fake affidavit and forced him to sign it. Even today, every mid-level official in ... (*Expunged as ordered by the Chair*) office calls mid-level officials in the CBI and says: "161 स्टेटमेंट्स चेंज कराइए। सर को बुलाइए। मैडम के अगेंस्ट में स्टेटमेंट लीजिए।" I am telling the CBI via you, Madam, please take 161 statements once and for all. Do not keep calling back people at ... (*Expunged as ordered by the Chair*) behest to change 161 statements to implicate me. It is going to get you nowhere. Let us reduce the CBI and the ED budget to zero. Let Mr. Adani pay the full amount of Rs. 1,500 crore. Let us outsource it completely to him. It will be the end of the story. In short, this *kursi bachao* budget is a desperate attempt by the Government to stick its head in the sand and act like the mandate of 2024 never happened. But the coming days are going to prove the instability of this Government and the inefficacy of its economic policy. We wait for that day.

Thank you very much, Madam.

(ends)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Chairperson, the hon. Member has made a specific allegation against the Government and a particular business house. She has been tortured like anything. The matter may be referred to the Committee of Privileges. The Committee of Privileges has to take *suo moto* action on this.

(1450/AK/PC)

It is a very serious allegation. … (*Interruptions*) A Member of Parliament is being tortured by a business house, and still it is doing it. … (*Interruptions*) This has to be looked into by the Privilege Committee. … (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, ये जिस केस के बारे में ज़िक्र कर रही हैं, वह लोकपाल पर मेरा केस है। … (व्यवधान) वह मेरा केस है, मैंने कंप्लेंट की है। … (व्यवधान) मेरी कंप्लेंट पर वह केस है। … (व्यवधान) वह मामला सब-ज्यूडिस है। … (व्यवधान) उसको सीबीआई और ईडी इनवेस्टिगेट कर रही हैं। … (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): No. … (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : इसीलिए, इस सदन में … (व्यवधान) क्या नो, नो, नो? … (व्यवधान) यह मेरा केस है, लोकपाल पर मैंने कंप्लेंट की हुई है। … (व्यवधान) यह केस मेरे ऊपर है। … (व्यवधान) मैं यहां बैठा हुआ हूं। … (व्यवधान) यह कुछ भी हो रहा है, तो दर्शन हीरानंदानी को यदि हिम्मत है, जिसके बारे में ये बात कर रही हैं। … (व्यवधान) उसको हिंदुस्तान में आकर, सीबीआई उसको बुला रही है, वह आ क्यों नहीं रहा है? … (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, when I was on my legs, I was not provided the mike. … (*Interruptions*)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): It is my case. … (*Interruptions*) So, I have every right to speak. … (*Interruptions*)

1451 hours

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): *(Hon Speaker Sir, Vanakkam. I thank Hon Chief Minister of Tamil Nadu Thiru Muthuvel Karunanidhi Stalin and Hon Udhayanidhi Stalin, and the voters of the Perambalur parliamentary constituency for making the voice of this ordinary person to be heard in this august House. I express my foremost thanks to the people of this country who have stressed that those who are in power should work in a coordinated way.)

Madam, I would like to start with something that is very fundamental to the Constitution of this country. It says, India, that is Bharat is a Union of States. But today, after 10 years, in fact in the 11th year, we are in the position of asking, 'what is the state of the Union'? We still do not know what is the state of the Union. So, India, that is Bharat, is actually a Union of States where the States make up this country, and what the Finance Minister has done is to ask us the question, 'what is this state of this Union'?

Now, as my colleague has pointed out, we are missing on the collective wisdom of this House when the senior Members of the Treasury Benches are actually missing in action. When the Opposition wants to draw the attention to the various schemes, the trouble and the problems of the people, we still, through you, Madam, insist that the senior Members be present when important Bills like the Finance Bill is being discussed. … (*Interruptions*)

What is this Budget about? It is actually primarily about misplaced priorities. The State with its resources is not being provided enough support so that they can carry on the people's work. I will go point by point, Madam.

---

* ()Original in Tamil

A lot has been talked about job creation, and the hon. Finance Minister has been forthcoming with providing training for youngsters. What she has failed to address is that the majority of the youth is not in the formal sector. The total EPFO paying customers is only 3.05 crore whereas the total workforce is above 45 crore people. What is being spoken about in the Budget is less than five per cent of the actual workforce, and the amount of EPF that the formal companies are paying is actually much lesser than that. So, Madam Finance Minister's statement about providing training actually does not cause any impact at all on the youth who is actually looking forward to training. So, I guess that the Government should take note of the informal economy and the need for training there.

There are three important segments that constitute the everyday life of the populace, namely fertiliser, food and education. Based on last year's numbers, the total allocation on fertiliser has been reduced by 13.5 per cent; food by minus 3.1 per cent; and education by minus 2.2 per cent. The Government has many reasons to reduce, but what I fail to understand is this. These three segments are the basic for any life to be lived upon in this country and on this planet. Now, when you reduce the allocation of the basic input that goes into life, then how does the Government expect the country to grow? How does the Government expect the country to have food on the plate of a common man and then work to pay taxes, which again is the next big topic?

(1455/UB/CS)

How can they pay with all the basic things reduced? I think the Government should take proper care while allocating the resources.

I am going to talk about a very important segment which is education. The hon. Finance Minister and the hon. Education Minister have been talking about the resource allocation, the NEET issue and that the Central Government is actually taking care of the people. What

I fail to understand are two important things. What the Opposition is talking is the outcome. What the Treasury Benches are talking about is the output. Let me explain it with an example. The Central Government says that they have brought about transparency and they have brought about equality in education. They might talk about the process only. They have got the exam. They have got the QR code and let the students in. There are a lot of harassment issues before the students make it to the exam. All that is the output. But we are talking about the outcome. What does the outcome talk about? The outcome talks about a fair chance a common man in this country gets to make it to the medical exam and serve the people of this country. They are not talking about outcome at all. They are only talking about the output. The process is great. We are not talking about the process. The process is unfair. The point from the Opposition is that the Government should not try to justify the unfair system saying that the Government follows the procedure. The procedure may be wrong. Please listen to the Opposition.

A number of people in my constituency is missing Anita, a student who should have been here with me as a doctor in Tamil Nadu. We are missing her because of the bad policies of this Government. So, please take note and please get the outcome right. Forget about the output. Please get the outcome right.

I will also give you an analogy. So, the hon. Members here have asked about national the highways, which is really good for the country. You are building the national highways all across the country. Now, we have very good highways across India. You have opened a new highway. That is the output. What is the outcome? Now, if you have 50 accidents or 50 deaths in a year, that is the outcome. So, what we are saying is that we need to avoid deaths. There is no use building a four-lane highway so that people die faster. What you are trying to do in the NEET Exam is actually pushing the inequality in the name of the

process. Please open your eyes. There are people who are really suffering. There is a lot of inequality in the system. Before it gets out of hands, please open your eyes and give a fair chance to each one of the individuals who really need it.

Now, there is a lot of talk about the middle class. A very important point for the Treasury Benches and the Ruling party to note is that three per cent of the vote of the middle-class has shifted from the BJP to the INDIA Alliance. You would know that the hon. Finance Minister actually again misplaced a priority in actually addressing the middle-class. What have you done to the middle-class? The middle-class earns money. They are the salaried people. They are hardworking people. They put their resources in three very important things. You have gold; you have real estate; and you have stocks. The Government has been pushing saying that they are going to increase the width and the depth of the market. What they have done is basically taking away all possible deductions that every common man before paying taxes calculates very vigorously. What have you done? Section 80(d), which provides for deductions across for the salaried classes, actually remained flat. As my colleague pointed out, based on inflation, it is actually minus now. By remaining flat, your deduction has reduced, but you are actually paying more taxes. So, the middle class is actually being punished for being honest. I think the misplaced priority on taxation must actually be addressed by the Treasury Benches.

Now, one of the things that I am really puzzled about is when the hon. Finance Minister talks about the cess. Not all of the hon. Members would know, but I would want everyone to be educated on cess. There is separation of power with regard to indirect taxes and direct taxes. The resource allocation to the State is being made by eminent institutions like the NITI Aayog. Does that cess go only to the Central Government, and the Union Government decide which States

to get what? The amount of cess has increased in the last 10 years, 10 times. It is not one per cent or two per cent. It is 10 times. What does this 10 times mean? You are actually taking away the resources of the States. You think it is fair for the States to come and ask for the cess amount? I do not think they even ask. So, the Government should take note that they are providing direct taxation, indirect taxation and something else totally different.

(1500/SRG/IND)

Madam, I am also speaking for the hon. Finance Minister because her maternal side is from my Constituency. I am actually speaking for her also. So, I need the two extra minutes to get to her. I hope she were here.

Now, I come to the important things about the State - what they have done to the State, and what this Budget has done is basically kill the golden goose. Tamil Nadu, with its impressive manufacturing strength, a large tax base and honest, hard working people, is being short-changed in this Budget. We are contributing, and for every rupee we get only 29 paise. We are very proud of the one rupee that we contribute. But what we ask is to give us a fair share so that we can actually contribute more. We are not complaining about not receiving less, but we are saying you are not giving us a fair share.

Very importantly, I will talk about relief and rehabilitation. You have seen in the last year that there are so many States that are being affected by natural calamities and Cyclone Michaung which affected Chennai, and the heavy rainfall which affected Thoothukudi and the other districts by a record rainfall. What had we asked? The same IAS officers who have been passed by the UPSC, have recommended for a package of Rs. 37,000 crore, and what we got is Rs. 450 crore. It is not even one day's interest, not even according to anybody's standards. So, I think it has been very, very unfair on the part of the Central Government.

The most important thing, Metro Rail project, was actually inaugurated by the Union Home Minister Amit Shah Ji on 21st November, 2020 in Chennai. The State Government has allocated Rs. 16,000 crore from its own resources. The Budget that was passed for this under this Budget was supposed to be given to Tamil Nadu which is still not given. What again we are asking is for our fair share. We are not complaining about not receiving money.

So, the general takeaway from this Budget is this. Do not punish the States that are contributing. Second, you are actually giving loan to the States that were actually your allies.

Last but not least, the Government has come up with a new East Policy. The new East is Odisha, you have Bihar and Andhra. I do not know what kind of East that is. But as far as I know, the East also covers the State of Tamil Nadu. I will also join the bandwagon. All we are asking for is a fair share from the Central Government. On the maternal side of the Finance Minister also, I am saying this. It is also your Constituency. Madam, through you, I tell the Finance Minister to actually do fairness for the Dravidian State that educated you, that put you into this place, that actually forms a big portion of the decisions you make. So, please be fair to the State of Tamil Nadu.

With these words, I conclude. Madam, thank you for the opportunity given to me.

(ends)

1503 hours

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Madam, thank you for allowing me to speak on the Finance Bill, 2024.

Madam, I cannot speak on this before thanking the tax payers who have been coming out in big numbers. The number has increased from 6.7 crore to almost 7.28 crore this year. Even the earnings from income tax have increased by almost 32 per cent. So, this shows the confidence that the income tax payers are having on the Government, importantly NDA. But we have to keep in mind the process that has been implemented for the last four years. A faceless assessment has been implemented. There are numerous issues that have been raised about it. Of course, this is useful for a lot of tax payers, but recently, a lot of people are complaining that too many sections are being invoked. For example, if someone has given Rs. 10 crore as penalty, if that person has to go for re-assessment, he has to pay 20 per cent to actually go for it. Because of this, tax payers are actually bearing the burnt. I wish and I hope the Finance Ministry will take this matter into account, so that we will make it easy for the tax payers to actually come into the fold.

Also, there is a rise in the gross revenue by almost 14 per cent. I have to thank the Finance Ministry for reducing the corporate tax from 40 per cent to 35 per cent. We have made numerous representations to the Finance Minister regarding the Angel Tax that was levied. It is a boon that the Finance Ministry has removed this. This will help start-ups, and the whole eco-system will develop in the few years to come. But the one word that has to be removed from the history of the Finance Ministry is with respect to the retrospective tax which we keep hearing from time to time.

(1505/RCP/RV)

Yesterday also, I was reading somewhere with regard to the mineral development and mineral industry which has come forward saying that the industry cannot function if you go in for retrospective tax. A few years back also, on some other industry, there was another retrospective tax. I think, the Finance Minister has to sit with them. Even the rice exporters also have come to me and said that the retrospective tax has been applied on them. If you keep doing this just to earn some money from the businesses that are doing very well, this will not encourage the businesses to flourish. So, I think and I

hope that the Finance Minister will take this into account and take this retrospective tax out of the dictionary.

Coming to the capital expenditure, there has been almost 17 per cent increase. This Government has been doing it for the last five or six years and Capex has been the main go to area whereby the development in the country is happening. Every year, the capital expenditure has been increasing. This year, almost Rs.11 lakh crore has been put in place for capital expenditure. But the problem is this. Last year, out of Rs.10 lakh crore that had been earmarked for capital expenditure, only Rs.9.48 lakh crore have been spent. So, almost Rs.52,000 crore were not even spent on capital expenditure. So, I would request the Finance Ministry to actually look into it. Having a capital expenditure allocation of Rs.11 lakh crore or Rs.11.5 lakh crore is one thing, but actually spending it on the ground is a different thing. So, I hope that the Finance Minister will look into it.

A lot of Members have raised a point with regard to the reduction in Long Term Capital Gains Tax from 20 per cent to 12 per cent. They also mentioned about the indexation. A lot of Members mentioned about it. There is also a lot of talk outside. So, I hope and expect that the Finance Minister will look into it. This is because this is taxpayers' hard-earned money. Also, the middle-class people are being affected by this. So, I think, there should be a relook at this indexation because the middle-class people think that real estate is one thing that they can safely invest in. We feel that it should be protected. I hope that the Finance Minister will listen to this.

My colleague Sushri Mahua Moitra has mentioned very agitatedly that she does not know wherefrom the funds are coming to Andhra Pradesh because she did not see any special allocation that was made. Correct me if I am wrong, but I think that it has been mentioned by the Department of Economic Affairs wherein Rs.62,000 crore, the entire amount, has been earmarked for capital expenditure and also for the new schemes that have been announced. So, I hope and I wish that the Purvodaya Scheme which has been announced for Andhra Pradesh and all the other Eastern States that my friend, my colleague has mentioned, this amount of Rs.62,000 crore will be given to us. The majority will be given to Andhra Pradesh.

My next point is with regard to Clauses from 88 to 99 which deal with the Vivad Se Vishwas Scheme, this has been a scheme which has been in effect for the last four years. This is used by a lot of taxpayers as well as a lot of industry people. This has been a successful scheme. But the problem right now that we should revisit is this. I have been reading the clauses but nowhere in the clauses there is a mention of timeline. I am looking for them because almost 5.4 lakh income tax appeals are pending at the Commissionerate level. We can only address this when we have a timeline defined in those clauses. I hope that the Finance Minister will look into this and try to address this issue.

Coming to health care, we have done amazingly well in the last 10 years or so. Numerous medical colleges and AIIMS have been developed. Also, the number of post-graduate seats have been increased. But there is 18 per cent GST on health insurance policies. If you look at the percentage of people having life insurance, 75 per cent of them are having life insurance. Only 25 per cent of them are having health or medical insurance. There are uneven numbers that are here. It should be the opposite way. More people should have health insurance or medical insurance and less people should have life insurance or the number should be equal, at least. But somehow it is skewed in one direction. It can be addressed only if GST can be reduced so that more people can have access to medical insurance and health insurance.

Coming to the point with regard to agriculture, in agriculture we have come up with numerous schemes in the Central Government. Every year, the Central Government is giving Rs.6000 to every farmer under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. The Soil Health Cards have been given.

(1510/PS/GG)

Insurance has also been given. Various other schemes have also been given by the Central Government. There is a definite effort from the Central Government to improve the conditions of the farmers and also, to double the farmers' income. But we need to review the 12 per cent GST on agriculture equipment, 18 per cent GST on tractors and machines for processing and milling, and 15 per cent GST on pesticides. I think, instead of having these many numbers of percentages, and these many brackets of GST numbers, I hope and wish that the Finance Minister will come with a lesser number like

how the Government has it for fertilizers, which is five per cent. I hope all the others will also come into the same bracket so that the farmers will get the benefit.

Madam Chairperson, now, I come to the textile industry, which is one of the backbones of my district. A lot of textile parks are there. A lot of textile industries are there. A lot of yarns are there. But the problem that they have -- and I request the Finance Minister to look into this -- is with regard to the 11 per cent import duty, which is levied on cotton that is imported. Yes, we have to protect the farmers. And the Cotton Corporation of India is buying cotton from the farmers at a good price. Yes, we appreciate that. Protecting the farmers is one thing but protecting the industry is also our duty. The only way that we can protect the industry is actually giving it enough raw material so that it can produce good quality products, and it can become competent when it exports to other countries. They have to compete with countries like Bangladesh and Vietnam. They can only be competitive when these raw materials, which are needed for these cotton mills, are provided at a reasonable price. Not only that, they can become much more competitive if the import duty of 11 per cent is decreased.

Now, I come to handlooms. Again, it is a huge employment-generated sector across the country, and also, we take pride in the handlooms. The hon. Prime Minister keeps on talking about handlooms and handicrafts every year. With regard to handlooms, there is a growth of five to seven per cent in the last five years. But the problem is with regard to the National Handloom Development Programme. Every year, the Estimates and Revised Estimates have been decreasing. In 2021-22, the Estimates were Rs. 485 crore; now, the Estimates have been reduced to Rs. 200 crore. In 2021, the Revised Estimates were Rs. 344 crore; and in 2023, it has been reduced to Rs. 156 crore. Handlooms is one of the backbones of our country and we take pride about it. Therefore, I wish the Finance Minister looked into this matter. … (*Interruptions*) I am the only Member from my Party who will speak. … (*Interruptions*) Madam, we have enough time.

Now, I come to the SEZs Act in the textile industry. There is one friend of mine Shri C.M. Ramesh, in whose constituency, there is a company called ‘Brandix’, which employs almost 30,000 women. From this industry, exports

are happening at a breathtaking pace. The industry is very much quality-oriented. They are manufacturing the products and they are exporting the products to other countries, and they are ready to pay tax to sell in India. But there is no provision for them to sell in India. If i-phone can be manufactured by Foxconn in India, and it can be exported as well as sold in India, why can that not have the same provision? I request the Ministry to look into this.

Now, I come to aquaculture. This is one of the major industries in Andhra Pradesh. Almost 70 per cent of the aqua exports happen from Andhra Pradesh. There are so many new schemes which have been implemented. Aqua farmers and processors have been pushed and nudged to do well. Aqua processors have been doing very well. The MoFPI is coming up with new schemes. The PLI scheme has also come up. The aqua processors are using such schemes to a large extent. In our country, capacity with regard to aqua processing is very high. But the problem is with regard to the farmers. They are doing less production. There is a scheme called Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. The problem is that the Budget Estimates were Rs. 2000 crore in 2023-24, but the Revised Estimates were Rs. 1500 crore. More so, the Revised Estimates of Rs. 1500 crore have actually gone to the Government. The Government has taken that amount and has spent on fishing harbours and other things. The Ministry has to understand that 90 per cent of the production and processing is done by the private players. The Government has not much of a role to play in this. But somehow, the Government is accessing all these funds. So, I hope the scheme will be rephased or reworked in such a way that the private players, who are in the process of exporting and who are in the process of production of aquaculture, can take the benefit of this Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So, I hope the Ministry will look into it.

(1515/SMN/MY)

Now, I will come to the last point. A white paper has been released in Andhra Pradesh with regard to the Andhra Pradesh financial situation. I am sure we will print it and distribute to all the Members in this House and also in the Rajya Sabha. So, I hope you will go through it and I hope you will understand the financial position of Andhra Pradesh. I will just briefly put on record the financial position. Please give me one minute.

The expenses as of this year are Rs. 1.64 lakh crore and the revenue is Rs. 1.45 lakh crore. That means we are deficit by almost Rs. 19,000 crore in this financial year. The State debt has increased from Rs. 3.35 lakh crore to Rs. 3.75 lakh crore in 2019 and now it has reached Rs. 9.74 lakh crore in 2024. The growth rate has decreased from 13.5 per cent to 10.5 per cent now.

Agriculture sector has gone down from 16 per cent to 10 per cent. The Capex used to be around Rs. 60,000 crore from 2014 to 2019, as per the white paper. It has gone down to Rs. 24,000 crore from 2019 to 2024. So, there is a decrease of capex and there is a decrease of sectoral growth in agriculture and also in all other sectors. There is a decrease in overall sectoral growth. Per capita debt has almost doubled from Rs. 74,000 per head to almost Rs. 1,44,000 in Andhra Pradesh. Inflation has also risen from 4.5 per cent to 6.2 per cent. So, on one side, we are having a huge debt and revenue deficit every year and on the other side, whatever we have borrowed in the last five years, we have not infused it into the capital expenditure. This has brought the State to its knees. We are ready to work with the Central Government. We are ready to actually again stand up and again try to rebuild the State, Madam.

So, I would request the Finance Ministry to look into it so that they can actually restructure the loans that are taken by the State of Andhra Pradesh and that would help us to run with the other States as well.

(ends)

1517 बजे

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर) : सभापति महोदया, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 पर चल रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया, यह प्रस्ताव मुख्य रूप से आम बजट वर्ष 2024-25 के अनुसार आयकर दरों में संशोधन के लिए लाया गया है। साथ ही प्रत्यक्ष कर की धारा 2 के साथ अप्रत्यक्ष कर की सीमा शुल्क की धाराओं में संशोधन, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम 2024 में संशोधन कर विवादों के समाधान को और सरलीकरण बनाने का संशोधन, सीमा शुल्क टेरिफ में बदलाव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धाराओं में संशोधन, केन्द्रीय माल और सेवा कर जीएसटी की धाराओं में संशोधन, बेनामी संपत्ति अधिनियम की धाराओं में संशोधन, काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 का संशोधन आदि प्रस्ताव पर संशोधन होने जा रहा है, जो आम नागरिकों के लिए काफी लाभदायक होगा।

सभापति महोदया, अब से आम नागरिकों को 75000 रुपये का स्टैन्डर्ड डिडक्शन मिलेगा। सेक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में भी बदलाव का प्रस्ताव है।

सभापति महोदया, लोगों को मकान खरीदने और बेचने में भी अब आगे टैक्स देनदारी के बदलाव से काफी फायदा होगा। 30 लाख युवाओं को पीएफ में एक महीने का कंट्रीब्यूशन देकर सरकार रोजगार के अवसर को भी बढ़ाने का काम कर रही है। इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खासकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी, क्योंकि यह एक आकर्षक योजना है।

महोदया, करदाताओं को ब्याज सहित मांगे गये कर का भुगतान करके कम किए गये जुर्माने का लाभ उठाने के लिए वर्तमान समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन किए जाने का प्रस्ताव है।,

महोदया, उक्त संशोधनों से अब अधिनियमन में सरलीकरण करने का सरकार का जो लक्ष्य है, उसे पूरा किया जा रहा है।

(1520/CP/SM)

ईज़ ऑफ डूइंग बिजेनस की कल्पना सरकार में हो रही है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अंत में, हमारे जितने भी माननीय सांसद हैं, इनमें कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। महंगाई बढ़ रही है और खर्च बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोगों को महंगाई भत्ता देने का संशोधन लाया जाए और हम लोगों पर कृपा की जाए। धन्यवाद।

(इति)

1521 hours

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you Madam. I rise to speak on this Finance Bill on behalf of my Party, NCP(SP). In the entire discussion, a lot of my colleagues have already mentioned that in 2023-24, the income tax paid by the middle class is far more than the corporate tax.

When UPA was in power, corporate tax was much higher than what the common citizens and the middle class of India paid. Today, it is exactly flipped. Corporate tax has gone down and the middle class is paying much more taxes. So, I would like the hon. Finance Minister to justify why they are taking more taxes from the middle class and the poor people of this country.

I appreciate her efforts. I remember her statement. In 2019, she had mentioned, “I am reducing the corporate tax so that more investments come into this country.” I am not talking about the intention of this Government. But what is the outcome? Can you quantify and justify the reduction of this corporate tax? No investments have come in. As a matter of fact, a news item of today says that the rupee has fallen and has become 84.09 against a dollar and the foreign portfolio investors have pulled down about 1.20 billion dollars.

Shri Dubey from the Treasury Benches was talking very highly about the Government and its policies. He also said how the world is doing badly and how well India is doing. I have very less knowledge in finance in comparison to him. But with full humility, I would like to tell him that India is no more an insulated economy. What happens globally will happen in India, if not today. One of the biggest growth engines of any economy is exports. India is not doing well in exports.

Atmanirbhar Bharat is a very good statement. I am the biggest example of Atmanirbhar Bharat. I do not use anything which is imported from any part of the world. But I would like to put it on record that this whole jingoism sounds very good in speeches only. I think we need to think beyond politics. I think we should stop being a prisoner of past and history and start living the present moment because I do not think I will be alive in 2047.

But we need to handle the economy well because the rupee has fallen to 80.49, which is very, very alarming. So, I am telling this Government to wake up and smell the coffee. There is a bloodbath in domestic markets. Today,

Sensex and Nifty have tanked nearly 3 per cent, which, I think, is a substantial amount.

I would like to even highlight one or two alarming points. Yesterday, in the discussion on Demands for Grants, hon. Shri Nadda ji was very, very honest and I appreciate what he said in his speech. He reached out to Opposition parties yesterday. I must appreciate his humility. He said that Rs.3,000 crore were left with the Health Department. यह इनका स्टेटमेंट है। मैडम, कल शायद आप भी हाउस में थीं। उन्होंने कहा कि यह पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आप मेरी मदद करिए। I think Prof. Saugata Ray was here. I was also in the House.

भूपेन्द्र जी, शायद कल आप भी यहां थे। तब मैंने पूछा था कि आप बताइए कि कौन सा पैसा रह गया है? हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारा डेवलपमेंट रह गया है। ये एक हजार करोड़ रुपये हमें दीजिए। हम अपने स्टेट में यूज कर देंगे। If the Health Minister of India says that money is not getting spent, it is very alarming to us. Then what is this Budget doing for this country?

I think there was a question on Rashtriya Vayoshri Yojana in today's Question Hour. My district is number one. वयोश्री योजना में पूना डिस्ट्रिक्ट इस देश में फर्स्ट नंबर पर आया है। हमने जो प्रॉमिस किया है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। जब भी मैं मंत्री जी से मिलती हूं, वीरेन्द्र सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वे मान-सम्मान देते हैं और बोलते हैं कि सुप्रिया मेरे पास बजट नहीं है। So, on the one side, the Health Minister is saying that he has extra money and on the other side, the Ministry of Social Justice, about which Government is saying that it is doing work for the poor, does not have money for the commitment they have made to us in a policy. Then, who do we turn to? (1525/RP/NK)

किस गरीब को पैसा जा रहा है, सोशल जस्टिस और हेल्थ मिनिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन नहीं है, I will ask the hon. Finance Minister whether यह बजट है या इस देश में गरीब आदमी का मजाक बनाकर रखा है? They really need to clarify on this.

My next point is regarding the Bima Karmachari Sangathan. It is a very, very important point. As a matter of fact, we all even agitated today for it. The All-India Insurance Employees Association is the oldest and the biggest trade union of public sector insurance in this country. I think, my colleague Mahuaji also spoke about it. We demand the withdrawal of GST on life and medical insurance premium. We had income tax relief under 80C and 80D. We do not want any reduction. In fact, we want withdrawal because it is very, very important for the common man of India. I think, Mahua ji had extensively

spoken on it so I will not repeat that point. It has to be tax free on maturity which was done. I do not know why this government is taxing it. There should be reintroduction of deduction under Section 80G in income tax when it comes to health insurance.

1526 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

I remember, there was a talk that this Government wants to sell the public sector insurance companies like LIC but, now, they are not talking about it. So, I am grateful to the Government. But, companies like National Insurance, New India Assurance, Oriental Insurance, and United India Insurance are demanding a merger. If they are all merged, they will be far more effective. एक तरफ आप एन्श्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप टैक्स लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे तो गरीब आदमी को कैसे एन्श्योरेंस मिलेगा? This is another contradiction of this government. So, I request this government to consider this.

My colleague Arun Nehruji spoke extensively about cooperative federalism. I think, Nishikantji talked about Sushmaji very fondly. Sushmaji and Arunji were two people, we all looked up to when we first came to the Parliament. Cooperative federalism was something which Sushmaji and Arunji had always talked about. As a Finance Minister, he used to talk about it. I would like to seek a clarification from the hon. Finance Minister when it comes to cooperative federalism. The Government brought GST and we are very happy with it. But, we are unhappy with the way it is implemented. I want to ask what is the share of the states. According to the Finance Commission, the States should get 41 per cent but, be it 2021-22, 2022-23, or 2023-24, it has never reached that percentage. Where is all this money going? Why is it not going to the States?

As far as cess is concerned, my colleague Arun Nehruji talked about the cess. Now, there is Krishi Kalyan Cess, Swachh Bharat Cess, Education Cess, and Health Cess which is 9 percent. Plus, there is Oil Cess which we discussed at length yesterday. There is a windfall tax. There is an income tax, and there is a customs duty. There is so much money coming to the Central Government. Why is this money not going to the States? It is very interesting that my colleague Krishna was talking just now about the States getting money, the way his state is doing, and what is the White Paper. Now, this is applicable in most States.

I compliment the hon. Prime Minister when, during the campaign, he used to talk about *revadis*. Now, every Government, which he is a part of, is giving *revadis* pan-India. Now, I would like to seek a clarification from this Government. My colleague Krishna has raised the issue of Andhra Pradesh. If you go to Chapter – III, Article 293, of the Constitution, it is about borrowing by the States. I would like to seek a clarification in this respect. It is Article 292, Part-3, which says:

> "(3) A State may not without the consent of the Government of India raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the State by the Government of India or by its predecessor Government, or in respect of which a guarantee has been given by the Government of India or by its predecessor Government.
>
> (4) A consent under clause (3) may be granted subject to such conditions, if any, as the Government of India may think fit to impose."

Now, in the case of Andhra Pradesh, which was your ally for five years, how did you allow the State to go through this? The same is the case with Maharashtra. So, I seek a clarification. You give as many *revadis* as you want. अभी तीन-चार राज्यों में इलेक्शन्स होने हैं, हरियाणा में भी है, रेवड़ियां तो बंटेंगी। I have no problem with those *revadis*. गरीब को कुछ देना है तो जरूर दे दीजिए। But, it should not be at the cost of misleading the nation and misleading the State for the next 25 years. आपका सारा सपना वर्ष 2047 का होता है। We will come to power but, unfortunately, be stuck with their bad dealings. We do not want this inheritance tax from this Government. So, we really need to know. The Government keeps talking about one thing.

(1530/NKL/SK)

इसे अटल जी तो लाए थे। The FRBM Act was not brought by us. मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि 70 साल में कुछ नहीं किया। हर सरकार कुछ तो अच्छा करती है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार कुछ अच्छा नहीं करती। Even if we have worked in different ideologies, I would say that Atal ji was the tallest leader of this nation. The FRBM Act was brought by him, and we followed it meticulously. Now, how much of the FRBM

Act has been implemented in the Central Government is what I want to ask this Government and seek a clarification on this.

A lot has been said about the GST. I would talk about the GST mismanagement. What is happening in Infosys is something I am very curious about. हर रोज पेपर में आ रहा है, पता नहीं कितने हजार-करोड़, इसमें कितने शून्य हैं, मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा कच्चा है। इनफोसिस को 30,000 करोड़ रुपये या 3,000 रुपये करोड़, पता नहीं कितना? एक बार न्यूज आई कि वह विड्रा कर रहे हैं, आज फिर से न्यूज आई है। Is this not a mismanagement of GST? Infosys is such a big international company, doing such a good service. I do not know whether taxing them is right or wrong. But is this the GST management? This is not management but a mismanagement. How can you keep changing the GST numbers all the time?

I have a delegation after delegation coming to meet me saying that the MCA website does not work. Even, people who do not fit in that tax bracket, because they do not file papers on time, are taxed. जो टैक्स ब्रेकट में नहीं है, because they could not file the documents because of the website issue, they are also being taxed. आप वैबसाइट सुधारिए, जिस आदमी का काम डिलोइट में है, उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जो आम आदमी है, जिस पर आप इतना टैक्स लगा रहे हैं, उसको दिक्कत आ रही है। So, this entire MCA website needs to be improved. … (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : टैक्स देना है या नहीं देना है? … (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : टैक्स भरने में कोई दिक्कत नहीं है। देश के बहुत आदमी ईमानदार हैं, टैक्स भरना चाहते हैं, लेकिन टैक्स भरेंगे लेकिन सर्विस भी चाहते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप यह सदन के बाहर ही पूछ लेना।

… (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, another issue which Shri Krishna also mentioned about is this. किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं। The input tax is so high. What was the idea of the GST? The idea was, 'One Nation, One Tax'. It is 5 per cent, 12 per cent, 18 per cent and so on. Then, you say कृषि प्रधान देश है, लेकिन आप किसान पर ही टैक्स लगा रहे हैं। I am not reading the whole list which my colleague Shri Krishna read. But if we talk about tractors, irrigation equipment and sprinklers, सबके लिए 12, 18 और 5 परसेंट है। My demand is that anything that concerns agriculture should have zero tax on it. अगर आप मिनरल्स पर जीरो कर सकते हैं तो किसान के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? मिनरल्स का टैक्स आपने जीरो किया है। देश का ही टैक्स नहीं, जो बाहर से मिनरल्स आएंगे, उनके लिए भी

जीरो टैक्स किया है। किसके लिए किया है? I am not a mineral expert. मैं इनकी तरह आरोप नहीं कर रही, मैं झूठे आरोप नहीं लगा सकती। आप बताएं कि मिनरल्स पर जीरो टैक्स लगा रहे हैं, इम्पोर्ट पर जीरो टैक्स लगा रहे हैं तो एग्रीकल्चर पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? अन्नदाता सुखी भवे, देश में जो किसान हैं, उन पर 18 परसेंट टैक्स लगाएंगे और मिनरल्स पर जीरो लगाएंगे। Which country are they coming from? I am not a mineral expert. लेकिन पढ़ने से समझ में आता है कि शायद चाइना है। ऐसा पेपर में आया है, मुझे नहीं पता। मिनरल्स के बारे में सरकार जवाब दे। गोल्ड पर किया है, अच्छी बात है, और कम करिए ताकि जो गलत काम गोल्ड में हो रहे हैं, बंद हो जाएं। आप गोल्ड पर भी कम करिए। But the Government must justify why agriculture is taxed so highly, and the import of minerals have zero tax on it. This is an answer they owe to the nation and to the farmer of this country. जीरो टैक्स करने की क्या जरूरत है। आप किसे प्लीज़ कर रहे हैं?

HON. SPEAKER: Hon. Member, please conclude.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, the other thing is about the research.

Sir, we have to discuss about agri-research. रिसर्च कितना करनी है, यह सरकार जानती है। How much of the Budget have they allocated for agricultural research is what the Government should tell us. There is the Indian Agricultural Research Institute which has got Rs. 710 crore out of which Rs. 540 crore goes only in salary and Rs. 90 crore in Administration. How much money is left for research? You would be very shocked to find out that the Customs Duty on chemicals has been increased. So, there are people from all the labs and IITs who need chemicals for research, and are in trouble. A delegation of students came to meet me. They are not the students of private colleges.

(1535/VR/KDS)

नहीं तो ये बोल देंगे कि ये तो प्राइवेट कॉलेज है। यह प्राइवेट कॉलेज का सवाल नहीं है। देश में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके रिसर्च लैब्स दिक्कत में हैं because of the customs duties on chemicals. This has to be reduced. अगर आप मिनरल्स का कम कर रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए तो कम करिए। मिनरल्स का पता नहीं किसके लिए किया है?

Sir, everybody has discussed about the increase in the Capital Gains Tax. So, I would not go into it. But I still want to ask this Government, if you have reduced the tax for foreign companies, then why is the Indian farmer getting affected? किसान के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कॉरपोरेट्स और फॉरेन के लिए बहुत-कुछ करेंगे। But they are not coming into the country. They are leaving the

country. This is what the data is saying. Even today's morning data speaks of it. आज सुबह का डेटा है। So, this is something this Government has to clarify.

Sir, there is a lot of confusion on indexation. In the first discussion on the Budget, I did not speak on the indexation because the hon. Finance Minister gave a clarification in a Press release. But even after the clarification, there is no clarity on indexation. You cannot tax a person who had bought any old house. Why is this 12 per cent?

Sir, if you had bought a house in 2002 for Rs.1 crore and you sold it for Rs.5 crore, Rs.34 lakh is the tax of indexation. If you only go by five to 12 per cent as the Government has made it now, it is Rs.50 lakh. It is completely unfair. So, in terms of the indexation, the Government has taken a semi u-turn, not a full-turn. So, this indexation must be brought back. It is in the larger interest of the nation and the poor hard-working people of this country.

Sir, EPS-95 is a very important issue. Just today's morning, a Congress Member of Parliament from Kolhapur Constituency raised this issue in the Zero Hour. ईपीएस 95 के लिए हाउस में जो-जो सांसद मिले, चाहे उधर के हों, चाहे इधर के हों, each one of us has met some senior citizens. You will be surprised to know that in 2023-24, only the interest earned on pension corpus is Rs.51,000 crore and the money given is Rs.14,000 crore. This was the commitment given by Shri Prakash Javadekar ji. I do not want to name Arun ji because he is no more. उनके साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई थीं, and Shri Prakash Javadekar ji had committed in a Press Conference that अगर हमारी सरकार, जो पहले मोदी सरकार थी, आज एनडीए सरकार है, यह जब आएगी तो हम ईपीएस 95 का पैसा देंगे। But you have not given the money. I urge the Government to release money under EPS-95.

Sir, one last point that I want to highlight is about the ransomware attack. This is a very serious issue because this whole Bill is about taxation. It is unfortunate that the Treasury Benches spoke everything but taxation. It is unfortunate that they have ignored taxation completely. But I would like to raise this important issue that the TCS and the State Bank of India had been hit with a ransomware attack last week. This has affected many banks and hurt the common man. So, I would urge the hon. Finance Minister to address this technical issue as this is very, very important. The cyber attacks are increasing. She must do something about this to salvage it.

Sir, the last point is that the hon. Treasury Benches talked a lot about the ED and the CBI. मैं तो उसको आइस बोलती हूं। आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। That is what 'ICE' stands for. They were talking about it, and they were taking this high morality ground. With full humility and data, I want to tell the hon. Members from the Treasury Benches that आइस केवल अपोजीशन वालों पर चलता है। आइस वाले जब यहां से वहां जाते हैं, तो वाशिंग मशीन से निकलकर पूरा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का केस साफ हो जाता है। I can give you the data, and I can table that on the floor of this House. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, इनको पूरा बोल लेने दीजिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I am happy to yield on this. *....(Interruptions)*

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, इनको बोल लेने दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप मौका क्यों देंगे? आप थोड़े आदेश दे सकते हैं। सुप्रिया जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I am happy to yield on the issue of Income-Tax, CBI and ED. *....(Interruptions)*

Sir, the BJP was in the Government which talked about high morality. न खाऊंगा, न खाने दूंगा। बड़ी अच्छी बात थी। मैं भी प्रभावित थी, क्योंकि इस देश से अगर करप्शन जा रहा होगा, तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा महाराष्ट्र और देश में नहीं हुआ, क्योंकि यह इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का आइस है। एक स्टोरी महाराष्ट्र में चलती थी, जिसको बोलते थे, डर्टी डजन, जिसका मतलब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता, जो सांसद रहे थे, वे आरोप लगाते थे कि एनसीपी-नैशनल कांग्रेस पार्टी यानी नैचुरली करप्ट पार्टी उसको कहते थे।

(1540/MK/SAN)

जो ओरिजनल है, वह क्लेम करती है, वही है। अगर ओरिजनल नैचुरली करप्ट पार्टी ओरिजनल है, तो अभी उनकी तरफ है। So, I seek a clarification from the hon. Finance Minister that she should give us a line and tell us that इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी नैचुरली करप्ट पार्टी ओरिजनल, बड़ा क्लेम करती है, उनकी है तो ये बता दें कि इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का क्या हुआ और डर्टी डजन का क्या हुआ?

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : स्पीकर सर, मैंने पिछली बार बोलते हुए यह कहा था कि यह मोदी जी की सरकार है, ये अपनों को भी नहीं छोड़ती है। … (व्यवधान) इसी सदन के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के … (<u>अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>) थे, उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ। उनसे 80 करोड़ रुपये भारत सरकार ने लिये। यह मोदी जी की सरकार है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चोरी करेंगे, तो उनके ऊपर भी

इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई होगी। जो राहुल गांधी जी के ऊपर है, वह चिदम्बरम साहब का पीएमएलए एक्ट है, जिसके कारण उनके ऊपर ईडी का केस चल रहा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ओके।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, every time the hon. Chair allowed Shri Nishikant Dubey to speak, whenever he spoke in the House…

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको भी बोलने की अनुमति दी है।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): He spoke ... (*Expunged as ordered by the Chair*) only. Last time, he spoke about ... (*Expunged as ordered by the Chair*) ji.

माननीय अध्यक्ष: यह आपके माननीय सदस्य ने कहा।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, please give me one minute.

... (*Expunged as ordered by the Chair*) ji is not a Member of this House. He told in this House that ... (*Expunged as ordered by the Chair*) ji attended the Ambani's marriage, which is totally wrong. Every time, he is telling this *galat baat*. You are allowing that. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: ओके। No.

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : प्री-वेडिंग में … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) जी गई हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ओके।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप कन्क्लूड कीजिए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I would like, on behalf of my colleague, to put it on record that she is not a part of this House, but at a personal level, she is a woman and nobody should talk about, first, a lady who is not a part of this House and, second, she has not attended it. And, there is nothing wrong in attending even if somebody did.

माननीय अध्यक्ष: मैं इस विषय को देख लूंगा।

… (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : उसमें कोई चोरी नहीं है। जिस शादी में प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने में। … (व्यवधान) Sir, it is not fair to bring somebody's wedding in it. … (*Interruptions*) Sir, it is not fair. She is not a Member of this House. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: बैठे-बैठे बोलने वालों की बात रिकॉर्ड में नहीं जाती है।

… (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, she did not attend. Let us go by the facts. There is nothing wrong in attending a wedding officially. What is wrong in it? But let us not do a fake narrative.

माननीय अध्यक्ष: ओके।

… (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, the problem with the BJP is that they do fake narrative and malign people. They have maligned my family as the way they have maligned hundreds of other families. Have they ever thought what our families go through? … (*Interruptions*) जब आप लोगों को झूठ-झूठ अरेस्ट करते हैं, तो कभी सोचा है कि उसकी बीबी क्या सोचती है, उसकी माँ क्या सोचती है, उसके बच्चे क्या सोचते हैं? They are doing this only to be in power, for their selfish needs.

माननीय अध्यक्ष: आप उस डिबेट पर मत जाइए। आप फाइनेंस बिल पर बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, they should be fair. I remember Amit Shah ji's statement and I would like to quote it.

माननीय अध्यक्ष: नो। आप फाइनेंस बिल पर बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I would like to quote Amit Shah ji's statement. He says "जब आप एक ऊंगली सामने दिखाते हैं तो तीन ऊंगलियां खुद की तरफ होती हैं।" With full humility, I would say to the BJP, quoting Amit Shah ji only, that जब एक ऊंगली हमारी तरफ दिखाते हैं तो तीन ऊंगली आपकी तरफ है।

That is all I say. Thank you very much.

(ends)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठे-बैठे इस सदन में अन-ऑफिशियल डिबेट बंद कर दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने सबके लिए बोला है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जाता है।

माननीय विदेश मंत्री जी।

… (*Interruptions*) *… (Not recorded)*

STATEMENT RE: RECENT DEVELOPMENTS IN BANGLADESH

1544 hours

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Mr. Speaker, Sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As hon. Members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum.

Mr. Speaker, Sir, since the election in January 2024, there have been considerable tensions, deep divides and growing polarisation in Bangladesh politics.

(1545/SNT/SJN)

This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstructions. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counselled restraint and urged that the situation be defused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch.

Speaker Sir, despite a Supreme Court judgement on 21st July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that Prime Minister Sheikh Hasina should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on police, including police stations and Government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear.

Speaker Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the

security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi.

Speaker Sir, the situation in Bangladesh is still evolving. The Army Chief, General Waker-Uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim Government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic Missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of students have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna, and Sylhet. It is our expectation that the host Government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes.

Speaker Sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation.

Speaker Sir, in the last 24 hours, we have been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbour on which there has always been a strong national consensus.

Thank you.

(ends)

वित्त विधेयक, 2024 – जारी

माननीय अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी।

1549 बजे

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक, 2024 जो कि सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी से संबंधित है, कैसे सरकार अपने बजट को फाइनेंसिंग करती है, आज मुझे उससे संबंधित विषय पर बोलने का अवसर मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हम इस फाइनेंस बिल के बारे में अपना भी आकलन देना चाहते हैं और कई बातों पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करना चाहते हैं। अभी मुझसे पहले के वक्ता ने चर्चा के दौरान सही कहा कि सरकार की टैक्सेशन पॉलिसीज़ देश के गरीब पर, किसान पर, आम आदमी पर ज्यादा बोझ डाल रही हैं और कोऑपरेट और देश के अमीरों पर कम बोझ डाल रही है।

(1550/SPS/AK)

सरकार की ऐसी नीति दिखाई दे रही है, जिसमें आम आदमी के लिए जीरो नीति है। सरकार की दो नीतियां हैं। पहली नीति आम आदमी के लिए है, वह है - जीरो बजट, जीरो बचत और टैक्स की पूरी चपत। खास नागरिकों के लिए सरकार की नीति है - टैक्स में राहत और कमाई खटाखट।

1550 बजे (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार पीठासीन हुईं)

मैडम, मैं यह एक्सप्लेन करना चाहता हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था में दो तरह के टैक्स होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स हैं। इन डायरेक्ट टैक्सेस को प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्लैब के साथ होता है, जिसमें जितनी कमाई है, उस पर लगाकर सरकार अर्थव्यवस्था में आर्थिक संतुलन ला सकती है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, और एक्साइज टैक्सेस हैं, जो पूरे देश पर बराबर लगते हैं और गरीब आदमी पर ज्यादा हो जाता है। कोई मेडिसिन है, पेरासिटामोल है या क्रोसिन की गोली है, अगर देश का सबसे गरीब व्यक्ति उस गोली को खरीदेगा तो उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, जितने टैक्स पर देश का सबसे अमीर व्यक्ति उसे गोली को खरीदेगा। टैक्सेस का संतुलन देश के आर्थिक संतुलन से जुड़ी हुई बात रहती है।

मैडम, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अगर हम इस वर्ष स्टेट और सेंट्रल के दोनों टैक्सेस को ऐड करके देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में देश का लगभग एक तिहाई कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स से हो रहा है और दो तिहाई इनडायरेक्ट टैक्स से हो रहा है, जो टैक्स देश के गरीब, किसान और आम आदमी से ज्यादा लिया जा रहा है। अगर हम इसकी तुलना दुनिया के बाकी देशों से करें तो ज्यादातर एडवांस्ड इकोनामी, ओईसीडी कंट्रीज़, एशियाई देशों में लगभग दो तिहाई देश के टैक्स का कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस से रहता है और एक तिहाई इनडायरेक्ट टैक्सेस रहता है, जो गरीब आदमी से लिया जाता है। अगर हम यूपीए के समय से तुलना करें तो यूपीए के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी संतुलन आया था। यह लगभग आधा-आधा था। यूपीए के समय डायरेक्ट टैक्सेस से 43 प्रतिशत हमारी सरकार लिया करती थी और 57 इनडायरेक्ट टैक्सेस से लिया करती थी। सरकार ने इस संतुलन को विपरीत दिशा में ले जाने का काम किया है। आज डायरेक्ट टैक्स के माध्यम

से कम कलेक्शन हो रहा है और उसमें भी कॉरपोरेट के टैक्सेस में सरकार ने सबसे ज्यादा राहत देने का काम किया है। पहली मर्तबा देश में कॉरपोरेट टैक्स से ज्यादा इनकम टैक्स से कलेक्शन हो रहा है। अगले वर्ष तक पहली मर्तबा जीएसटी कलेक्शन भी कॉरपोरेट टैक्स से ज्यादा होगा। कॉरपोरेट टैक्स से सबसे कम कलेक्शन हुआ है तथा पिछले कुछ वर्षों में कॉरपोरेट टैक्स के कलेक्शन में गिरावट आई है। वर्ष 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में एक राहत दी गई थी। उस राहत में कॉरपोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत तक कम किया गया था। उस समय आपकी नीयत क्या रही, मैं उस पर प्रश्न नहीं करूंगा, लेकिन जब आपने बड़े उद्योगपति घरानों, कॉरपोरेट्स को यह राहत दी तो आपने कहा था कि आप यह राहत इसलिए दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश हो, अर्थव्यवस्था में निवेश बड़े तथा इन्वेस्टमेंट हो। इस वजह से पिछले पांच सालों में 8.7 लाख करोड रुपये की राहत देश के कॉर्पोरेट्स को देने का काम आपकी सरकार ने किया है, लेकिन हकीकत क्या हुई? हकीकत यह हुई कि निवेश बढ़ने के बजाय, इन पांच वर्षों में निवेश लुढ़क गया। कॉरपोरेट टैक्स में टैक्स कट आपने उनकी मार्जिन को बढ़ाने के लिए नहीं दिया था, आपने निवेश बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन निवेश लुढ़क गया।

मैडम, आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी निजी निवेश दर देश में 20 वर्षों में सबसे निम्नतम स्तर पर है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर, 2025 में जो निवेश दर आई, वह बीस साल में वर्ष 2004 के मुकाबले की निवेश दर देश की अर्थव्यवस्था में आई है। आज एफडीआई भी 16 वर्षों में सबसे निम्नतम स्तर पर है। इस वर्ष हमारी जीडीपी की 1.1 प्रतिशत एफडीआई मिली। मंत्री जी कह रही थीं और मैं सुन रहा था कि एफडीआई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कम हुई है, लेकिन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए। दुनिया के बाकी देशों में एफडीआई में गिरावट नहीं आई। हिंदुस्तान एफडीआई रिसिप्ट्स में आठवें नंबर पर होता था। एफडीआई में हमारा देश एक ही वर्ष में गिरकर 15वें नंबर पर आ गया। एफडीआई में तो रिकॉर्ड गिरावट आई है, लेकिन उसके साथ-साथ आउटफ्लो में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। एक ओर केवल 27 बिलियन डॉलर की इस साल एफडीआई है और दूसरी ओर 14 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो हो गया है। आपने कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स कट किया कि कॉर्पोरेट्स निवेश करेंगे, जॉब क्रिएशन होगा, लेकिन निवेश दर बीस सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है, एफडीआई 16 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। निवेश नहीं हुआ है, इसलिए आज देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है।

(1555/MM/UB)

आप जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए हैं, इस इकोनॉमिक पॉलिसी को ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं कि कॉर्पोरेट के हाथ में पैसा दो, वे निवेश करेंगे। लेकिन यह पॉलिसी दुनिया में गलत साबित हो चुकी है। अगर कॉर्पोरेट के हाथ में पैसा होगा तो वे वहां निवेश करेंगे, जहां डिमांड स्ट्राँग है। आपने डिमांड को स्ट्राँग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। डिमांड को अगर आप देखें तो रूरल सेक्टर में डिमांड फ्लैट है। आज कृषि सेक्टर में हमारी डिमांड फ्लैट है। जब तक इकोनॉमी में डिमांड नहीं आएगी, तब तक कॉर्पोरेट्स हमारी इकोनॉमी में निवेश नहीं करेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी, जो थियोरी फेल हो चुकी है, उसको हिन्दुस्तान में सफल करने के लिए आपने दस साल लगा दिए। एक बार आप हिन्दुस्तान के आम आदमी के हाथ में पैसा देकर देखें। आप डिमांड साइड इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाएं। किसान और गरीब को कोई राहत नहीं मिली है, आप उनको भी राहत देकर देखें। आप एमएसपी की लीगल गारंटी देकर देखें। आप मनरेगा

में चार सौ रुपये की वैज करके देखें। आप हमारे देश के आम आदमी के हाथ में पैसा देकर देखें। उनके हाथ में जब पैसा आएगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी तो कोर्पोरेट्स की इंवेस्टमेंट तब हमारे देश में सही रूप में हो पाएगी।

महोदया, इतना ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देने के बाद भी निवेश नहीं हो रहा है, इसका एक कारण और भी है और वह मोनोपोलीज़। हमारे देश में क्रोनी, क्रोनिएज़म और क्रोनी मोनोपोलिज़ क्रिएट हो रही हैं। हमारे देश के पांच बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने देश में आज लगभग 40 सेक्टर्स में सरकार की सहायता से अपनी मोनोपॉलीज़ बनाने का काम किया है। सीमेंट, पोर्ट डिफेंस, टेलिकॉम सेक्टर्स में और अब तो न्यूक्लियर सेक्टर की भी बात आ रही है कि कुछ कॉर्पोरेट घराने इन सेक्टर्स में अपनी मोनोपॉलीज़ क्रिएट कर रहे हैं। सरकारी एजेंसीज़ के माध्यम से लीगल और पीनल एनवायरमेंट ऐसा बनाया जा रहा है। जब मोनोपॉलीज़ क्रिएट हो जाती हैं तो मोनोपॉलीज़ सेक्टर में दूसरा निवेश नहीं होता है। हमारी सरकार से यह मांग है कि यह जो असंतुलन बना है, जिसमें गरीब आदमी से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और कॉर्पोरेट्स को जो राहत दी जा रही है, इसको सरकार सुधारने का काम करे।

महोदया, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे टैक्स लिया जा रहा है। पेट्रोल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर हमारी सरकार ने 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये एक्साइज़ ड्यूटी से टैक्स लेने का काम किया था। यह यूपीए सरकार के आखिर वर्ष में है। मगर 1 लाख 42 हजार करोड़ रुपये वापस सब्सिडी के रूप में देने का काम भी किया था। उस समय मात्र 30 हजार करोड़ रुपये की कमाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से उस समय सरकार को हुई थी। आपकी सरकार में इस वर्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से कमाई 4 लाख 32 हजार करोड़ रुपये है और सब्सिडी मात्र 11 हजार करोड़ रुपये दी गयी है। केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से आपने 4 लाख 20 हजार करोड़ रुपये की कमाई देश की आम जनता से की है। हमारी सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से जहां 30 हजार करोड़ रुपये की करती थी, वहीं आप 4 लाख 20 हजार करोड़ रुपये की कर रहे हैं। हमारे समय में पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी 9 रुपये थी, आज 20 रुपये है। डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी 3 रुपये थी, लेकिन आज 15 रुपये है। आज पेट्रोल-डीज़ल से आप कमाई कर रहे हैं। वर्ष 2014 में टोल के माध्यम से कुल कलैक्शन तीन हजार करोड़ रुपये थी, लेकिन आज 65 हजार करोड़ रुपये है। हर वस्तु पर जीएसटी लगाकर सारे कर का बोझ आप आम आदमी और किसान पर डालने का काम कर रहे हैं। हम इस नीति का विरोध करना चाहते हैं। हम यही मांग करते हैं कि पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइज़ में राहत दी जाए। केपिटल गैन्स टैक्स के इंडैक्सेशन को आपने वापस लिया है, उसको फिर से बहाल किया जाए। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस में जीएसटी को विद्ड्रॉ किया जाए। ये सारी मांगे मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ मैं हरियाणा के विषय में एक महत्वपूर्ण बात सदन में रखना चाहता हूं। माननीय खट्टर साहब भी बैठे हैं, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार अगर किया गया है तो वह हरियाणा प्रदेश के साथ किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे? जैसे कि अभी बताया जा रहा था कि हर प्रदेश केन्द्रीय टैक्स कलैक्शन में भागीदारी करता है। कितना केन्द्र एक प्रदेश से लेती है और कितना उस प्रदेश को वापस देती है। हरियाणा से जीएसटी कलैक्शन पूरे देश का 7.10 प्रतिशत होता है। लेकिन हरियाणा को केन्द्र की तरफ से मात्र 1.009 प्रतिशत राशि वापस मिल रही है यानी एक प्रतिशत के करीब।

(1600/YSH/SRG)

यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो केन्द्र सरकार हरियाणा से सात रुपये ले रही है और केवल एक रुपया वापस दे रही है। अगर प्रतिशत में बात करें तो यह 15 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार हरियाणा से 100 रुपये ले रही है और 15 रुपये वापस दे रही है। अगर पूरे देश में सबसे कम फंड किसी एक प्रदेश को दिया जा रहा है तो वह हरियाणा को दिया जा रहा है। हम मानते हैं कि प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में थोड़ा कम है, लेकिन दूसरे नम्बर पर महाराष्ट्र है, जिसको कम फंड दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में यह 29 प्रतिशत है, यानी कि केन्द्र सरकार 100 रुपये ले रही है तो महाराष्ट्र को 29 रुपये दे रही है। कर्नाटक में केन्द्र सरकार 100 रुपये ले रही है तो 40 रुपये वापस दे रही है। पूरे देश के 29 प्रदेशों में आज हरियाणा ही एक प्रदेश है, जहां सबसे कम 15 प्रतिशत फंड ही केन्द्र सरकार वापस दे रही है। अगर हम नेट डेवलूशन की बात करें कि केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाए और अगर इसे प्रति व्यक्ति में देखें तो मैंने कैलकुलेट किया है कि 29 प्रदेशों में सबसे कम पिछले वर्ष हरियाणा को 22 हजार करोड़ रुपये दिए गए, यानी कि प्रति व्यक्ति 6 हजार 938 रुपये दिए गए। यह भी 29 राज्यों में सबसे कम है, जो हरियाणा को दिया जा रहा है।

हम बाकी राज्यों को देखते हैं तो गोवा में 40 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति 1 लाख 40 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। तेलंगाना में केन्द्र सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 25 हजार रुपये की राशि दी जा रही है, लेकिन हरियाणा में मात्र 6 हजार रुपये की राशि प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष दी जा रही है। यह पिछले पांच साल से दी जा रही है, यानी कि 15वें फाइनेंस कमीशन में एक प्रतिशत डेवलूशन का जो फॉर्मूला हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया था, चूँकि यहां पर खट्टर साहब भी बैठे हैं, उन्होंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। उस समय नीचे भी भाजपा की सरकार थी, ऊपर भी भाजपा की सरकार थी। … (व्यवधान) अभी सबसे कम राशि हरियाणा को दी जा रही है। … (व्यवधान) खट्टर साहब, आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद में जवाब दे दीजिएगा। … (व्यवधान)

आवासन और शहरी कार्य मंत्री; तथा विद्युत मंत्री (श्री मनोहर लाल): सभापति महोदया, मेरा नाम लेकर कहा जा रहा है इसलिए मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मैं बजट के आँकड़ों के ऊपर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं यह बता सकता हूँ कि दिल्ली के आसपास होने के नाते हरियाणा को काफी लाभ हुआ है, वह चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या बाकी चीजों में हो। इनका सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट देने के लिए उकसाने का काम है। मैं यहां पर बैठा हूँ इसलिए ये बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर इनको राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। … (व्यवधान) दिल्ली-अलवर की लाइन हरियाणा से होकर निकलती है। दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस यहां से होकर निकलती है। … (व्यवधान) दिल्ली-कटरा रोड हरियाणा से होकर निकलती है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार) : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदया, ये सारे प्रोजेक्ट्स हरियाणा के हैं। … (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हरियाणा का क्या कसूर है? हमारी आबादी देश में 2.1 प्रतिशत है तो क्या हमारा यह कसूर है? देश के क्षेत्रफल में हरियाणा का क्षेत्रफल 1.34 प्रतिशत का है। आज देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान 4 प्रतिशत का है तो क्या हमारा यह कसूर है? देश के जीएसटी कलेक्शन में 7 प्रतिशत हरियाणा का योगदान है तो क्या हमारा यह कसूर है? देश के खाद्यान्न और अन्न भंडारण में हरियाणा का किसान 33 प्रतिशत दे रहा है तो क्या हमारा यह कसूर है? देश की आर्म्ड फोर्सेस में 11 प्रतिशत हरियाणा से आर्म्ड फोर्सेस का ह्यूमन रिसोर्स आ रहा तो क्या यह कसूर है? देश के लिए 50 प्रतिशत मेडल्स हरियाणा से आ रहे हैं, क्या यह कसूर है? इसके बाद देश के 29 प्रदेशों में से हरियाणा को केन्द्र सरकार द्वारा केवल एक प्रतिशत की राशि मिल रही है। बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया। मुझे इस बात का दुख है।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कंक्लूड कीजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति महोदया, मैं कनक्लूड की तरफ जा रहा हूँ। आप 'खेलो इंडिया' का बजट देखिए। आज देश के लिए तीन मेडल्स आए, जिसमें से दो हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए हैं। 'खेलो इंडिया' का बजट 2200 करोड़ रुपये रखा गया है, उसमें से मात्र 60 करोड़ रुपये हरियाणा को दिए गए हैं, यानी कि खेल बजट का सिर्फ दो प्रतिशत दिया गया है। गुजरात में 500 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। यह खेलो इंडिया के बजट का 20 प्रतिशत है। वहां से एक मेडल भी नहीं आया है। मैं समझता हूँ कि यह अन्याय है।

मैं कनक्लूड करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा को केन्द्र सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ एक भी परियोजना नहीं मिली है, अपितु यूपीए के समय में हमारी जो मंजूरशुदा केन्द्र सरकार की परियोजनाएं थीं, वे 1 लाख 55 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं थीं। चाहे वह हमारा महम में एयरपोर्ट हो, जो कि जेवर चला गया। वह 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहा था। चाहे हरियाणा के अंदर रेल कोच फैक्ट्री हो, जो बनारस में चली गई। चाहे तीन रेल लाइन्स का काम हो, यमुनानगर-चंडीगढ़ रेल लाइन परियोजना पर एक इंच लाइन भी नहीं बिछी। चाहे हिसार, फतेहाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, न्यू अलवर तक रेलवे लाइन काम हो, चाहे बाडसा के अंदर एम्स हो। हमारे 9 मेडिकल के प्रोजेक्ट्स थे। केन्द्र सरकार ने 10 साल में एक भी प्रोजेक्ट हरियाणा को नहीं दिया, जो यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने हरियाणा सरकार को देने का काम किया था। आपने उन प्रोजेक्ट्स को भी खत्म कर दिया।

(1605/RAJ/RCP)

… (व्यवधान) मैडम, हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बजट देने में हरियाणा को भूल गई है, उसी तरह हरियाणा भी वोट देने में बीजेपी को भूल जाएगा। हम यह विश्वास दिलाते हैं।… (व्यवधान)

(इति)

1605 hours

SHRI BASAVARAJ BOMMAI (HAVERI): Madam, I thank the hon. Chair for giving me the opportunity. This is my maiden speech in this House.

I was just observing the entire discussion on the Finance Bill. Very little has been spoken on the Finance Bill. More lies have been spoken on the respective positions which are political. Of course, politics plays an important role in finance also because political science is the science of all the sciences. How the politics shape up depends on the person who is there because man is a political animal. So, we are talking about a man. A lot has been said about that man and a lot has been discussed about that man. He is discussed globally also. He is a man who has changed the destiny of this country for the last ten years. For a second, if you think that our hon. Prime Minister Narendra Modi ji had not been a Prime Minister, what would have happened to this country? The whole country would have been in such a confused and chaotic state economically, politically and socially.

I am really wondering when a lot of people speak about poverty, the farmer and the women. It has become a fashion to speak about the farmers and the farmers' causes. We are using the name of the farmer time and again. But one should remember that the farmer does not belong to any political party, but all the political parties belong to the farmer. However, we forget that. We know that the life of the farmer is very uncertain. It has been known for the last 75 years, and it is still going on. I wish somebody really took a serious note of it. We discussed about a lot of problems of the farmers, but nobody discusses about the solutions for the farmers. अपोजिशन वालों ने बहुत बड़ी बात की है। वे समस्या उठाते हैं, लेकिन उनकी समस्या के हल के बारे में बात करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वे हल नहीं चाहते हैं। समस्या ज्यादा होने पर समस्या का हल होना चाहिए। ऐसी राजनीति बहुत दिनों से चल रही है। इसलिए किसानों की हालत वहीं की वहीं है।

I just want to say a few words. I stand before you to reflect the remarkable journey of our nation undertaken under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. He has defined poverty as the foremost enemy.

(1610/PS/KN)

Madam Chairperson, before Independence, we had only one enemy, and that was the Britishers. Today, we have गरीबी, अशिक्षिता, बेरोजगारी और बीमारी। We have these enemies. We have to tackle them with a population of 140 crore. Madam, I want to say one thing to the entire House. Disraeli said, 'There is no magic in economy, only results'. There is no magic. हम भी समस्या के ऊपर बात कर सकते हैं।

महुआ मोइत्रा जी बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थीं। मैं सुन रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफरेंट सेक्टर्स पर जो एलोकेशन किया है, she wants to compare that with the inflation. मैं पूछ रहा हूं कि आज तक चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, which budget allocation has been done according to inflation. And if that is to be done, then we need four to five times the budget size of what we have today. Is it possible? Will our revenues allow this? You run away from the reality. You want to make your own point. Come to the solutions. This is not the way the country should be run. We have to understand the issues and tackle the problems in the most scientific way and not in a political way. I know that the Opposition has a political say. But this is not the way. The real issues are lying somewhere else. I just want to highlight a few of them.

Prime Minister Shri Narendra Modi ji transformed our population into a demographic dividend. एक जमाना था, जब हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी चुनौती थी। But here is one Prime Minister who has converted calamity into opportunity. And he said that our demographic dividends are through our population and we have to skill them up. I am telling you on record that no Prime Minister has talked about skill in the way Shri Narendra Modi did it.

The former Finance Minister was saying that we have taken a leaf from the Congress manifesto. In 2016, an Act was passed in this very House about entrepreneurship and skill development. Madam, we brought reforms in GST and banking. We also brought reforms with regard to revitalising the manufacturing sector and digital economy. जीएसटी के बारे में बहुत कुछ बातें हुई हैं। The people who introduced GST Bill are disowning it now. अपने बच्चे को डिसऑन क्यों कर रहे हैं? Why is it so? It is because you are now on the other side of the fence. Kindly look at the figures with regard to the growth of taxes through GST. In the pre-GST regime, -- if you take five years, that is, from 2012 to 2017 -- it was Rs. 38,52,000. But in the last five years of GST, -- I am not

talking about 2022 and 2024, but I am talking about 2017-22 -- it was Rs. 57.5 lakh. This is the growth of taxation. The tax base has increased. The number of people who are involved in businesses is more into the tax net. This is the revenue to the country. Once a revenue comes, then we can talk about development. Therefore, the year-on-year increase is almost 12 per cent. In the last month, that is, in the month of July, GST collected was Rs. 1.8 lakh crore.

(1615/SMN/VB)

Therefore, GST was just an impossible thing because consciousness was not there. It was the leadership of Shri Narendra Modi Ji who brought consciousness in making GST. The great poet Tiruvalluvar of Tamil literature had said, 'In between concept and creation, there lies the shadow'. There was a concept and to create that concept, we need to remove that shadow and Narendra Modi Ji Government removed the shadow in GST. That is why, it is the reality today. It has to be acknowledged and this is one thing which will take the country to new heights. History will remember Narendra Modi Ji for doing this.

Secondly, Madam, the greatest thing what he did was the digital economy. The digital economy through DBT eliminated middlemen and also eliminated corruption between *janta* and the *sarkar* and it was achieved through DBT. It ensured that the benefits reach the people directly and efficiently and it has saved Rs. 3.48 crore. Otherwise, it would have gone to the middlemen. This is what the honesty of this Government speaks as far as taxation is concerned and sharing the benefits with the people are concerned.

I just want to say that here is a leader, here is a party with the true spirit. We do not wait for things to happen. We do not wait for destiny to create growth for us. We create growth and through that growth, the destiny of this nation is written. That is what Mr. Narendra Modi Ji stands for. We are racing against all the international and developed countries, not only are we racing against them but we are also racing against time.

This is the Government where time and management has been done in the right direction with the right speech which was otherwise lacking in all the previous regimes.

Madam, taxation has got four pillars: taxes should be purposeful; taxes should be affordable; taxes should be equitable; and taxes should be accountable. I am very proud and happy to say that all these three pillars and the policies have been adhered to for the last ten years. All taxes are purposeful and they have been affordable, equitable and accountable. This has led to a sustainable growth and fiscal consolidation. Fiscal consolidation is very important aspect for our growth trajectory. Therefore, our principled tax policy has posted a favourable environment resulting in increased tax payer numbers and enhanced tax affordability. This reflects our success in balancing both equitable tax and ensuring resilient and thriving economy.

Madam, I just want to tell you that people are talking about only one or two successful businessmen where they have become the subject of position.

Madam, the number of people who filed income tax in 2014 was 3.65 crore. In 2023, it was 8.18 crore. This is almost three times. Year on year, the increase is nine per cent. This is very interesting.

(1620/SM/PC)

In 2014, the number of people who earned more than Rs.1 crore and filed tax returns was just 48,417. In 2023, nearly 2,16,000 people are earning more than Rs.1 crore. So, we are creating people who are capable of earning more. Now, more than two lakh people are earning more than Rs.1 crore.

So, it is not just one or two companies which are driving this country. It is these people who have gone through the policy of this Government. They are driving this country. The per capita income of the common man in 2013-14 was Rs.89,000. In 2022-23, it was Rs.1,94,879. It is almost double. In 10 years, the per capita income has been doubled. This what it means; this is what this Budget, this tax policy means.

We should really look into these aspects so that we can get a better vision to build this country, not in a dejected way just to find faults only. Yes, no system is hundred per cent perfect. That is why, I said that there is no magic wand in economics. The problems cannot be solved in one day. But the important thing is in what direction we are going. That is why, our Prime Minister has said that we will achieve the target of Viksit Bharat in 2047.

Madam, I greatly honour Shrimati Supriya Sule ji. She was saying that she might not be there in 2047. We do not work only for ourselves. Our elders

and ancestors worked hard and we are having the fruits of their hard work. अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, 'आत्मनिर्भर भारत' से लेकर 'विकसित भारत' तक का संकल्प अभी लिया है और उसे वर्ष 2047 में हम हासिल कर लेते हैं, तो हम रहें या न रहें, यह देश तो रहेगा। ... (व्यवधान) हमारे देश के देशवासी तो रहेंगे, हमारे बच्चे तो रहेंगे, हमारी अगली पीढ़ी तो रहेगी। उनके लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे? क्या एग्जाम्पल छोड़कर जाएंगे? क्या उनके लिए खाली भंडार छोड़कर जाएंगे? ... (व्यवधान)

हमारा हर एक कदम, हमारा हर एक निर्णय 'विकसित भारत' की ओर है और हम इसे करके दिखाएंगे। ... (व्यवधान) यह हमारा हौसला है। ... (व्यवधान) चाहे आपका हौसला हो या न हो, फर्क नहीं पड़ता है। ... (व्यवधान)

इनकम टैक्स के बारे में बहुत बातें हुई हैं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। यह तो आप सबको मालूम है कि ग्रैजुअली इनकम टैक्स में बदलाव आ रहा है, छ: महीनों में एब्स्ल्यूट बदलाव लाने का वित्त मंत्री जी का इरादा है। उन्होंने अभी जो किया है that Standard Deduction of salaried individuals and pensioners are proposed to be increased from Rs.50,000 to Rs.75,000. इससे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को यह दिखता नहीं है। Secondly, deduction from family pension is also proposed to be increased from Rs.15,000 to Rs.25,000 and pension contributions from the employer will be up to 14 per cent. Earlier, it was 10 per cent. यह सब इंडीविजुअल, सैलरीड पर्सन्स के फायदे के लिए हमारी वित्त मंत्री महोदया ने किया है। हमें इसे देखना चाहिए।

Equalisation of levy of two per cent of the proceeds received by non-resident e-commerce operators for supply of goods and services will not be applicable from 1st August. वह दो परसेंट निकाल दिया गया है।

एंजल टैक्स के बारे में सब लोगों ने बताया है। Angel Tax is imposed on the companies for receiving funds in excess of face value of their shares. This provision will cease to apply.

(1625/CS/RP)

अभी रियल एंजल हो गया है। अभी तक तो एंजल नहीं था, अभी रियल एंजल हो गया है। There is immunity to benami transactions. बेनामी एक्ट बहुत दिन से है, लेकिन बनामी एसेट जिसके नाम पर है, अगर अभी वह अप्रूवर बन गया तो, the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 makes the benamidar and the beneficial owner equally culpable. In order to encourage a benamidar to turn approver, provision is being made to provide immunity. इससे बेनामी एसेट बाहर आती है। This is the honesty of our leader Narendra Modiji, 'न खाएंगे, न खाने देंगे।'

A lot has been said about capital gains tax where it is being said that indexation is a little bit confusing. However, as the time goes, they will realise that it is better than the previous one. I need not explain the whole thing because the hon. Finance Minister has already explained the whole thing. There are certain examples which I do not want to quote here.

There is also a reduction in customs duty on certain precious metals like gold and silver; it has been reduced from 15 per cent to 6 per cent. The same is the case with platinum which goes to automotive industries. There are a lot of such sensitive decisions taken this time which were ignored by the previous Governments. There is an increase in tariff of certain things because the Government has to support the local industries. Hence, it is a very well-balanced tax system. For example, the tax on three cancer drugs has totally been reduced to zero per cent on humanitarian grounds. There is growth in all the sectors. The overall value-added growth in health and social sector is 244 per cent in the last ten years. This is the economic stimulus which this Government has given. Similarly, there is growth in all the sectors with value addition.

A special care has been taken in steel and copper sector where the import duty has been reduced. Same is the case with the electronic sector, textile sector, and leather sector. I just want to highlight some points and conclude my speech. The present Budget is in the right direction.

As far as COVID-19 is concerned, we have to see the economy in two parts – pre-COVID-19 and post-COVID-19. This pandemic has not only made dent on the lives of the people but also on the economy. But, it is the Narendra Modiji's Government which has handled COVID-19 and saved lakhs and lakhs of lives. He, once again, took it as a challenge and converted it into an opportunity. The growth of our economy is astonishing the whole world. That is what our friend

Nishikantji was trying to say. On the one hand the growth in some developed countries is not more than 2 per cent or 3 per cent, on the other hand our growth is 6 per cent to 7 per cent. We are going to have a double-digit growth very shortly. Our expenditure has been increased by 8.5 per cent in this Budget. Our receipts have increased by 14 per cent in this Budget. Therefore, our fiscal deficit has been reduced from 6.4 per cent in 2022-23 to 4.9 per cent this year. Likewise, the revenue deficit has been reduced from 3.9 per cent to 1.8 per cent and primary deficit has been reduced from 3 per cent to 1.4 per cent. Therefore, this Budget is in the right direction.

(1630/NKL/IND)

Madam, I just want to say that this Government has got a vision and a will to do. The things, which were impossible till yesterday, have been made possible today by Shri Narendra Modi ji and his Government. As I said, population was just a stumbling block in the development but he converted it into a human asset. Secondly, it was said that poverty cannot be removed. But he waged a war on poverty, and 25 crore people have come out of poverty. How did they come out of poverty? They were given houses, electricity, gas, water, food, etc. The next step is for improvement in their economic systems.

Thirdly, it was impossible to remove corruption. But he removed it. And, the best example is DBT, where Rs. 3,48,000 crore have been saved. This DBT benefit is for 38,00,000 crore people.

Madam, a leader should have two qualities. They are credibility and acceptability, which our leader has. If we talk about the credibility of Shri Narendra Modi ji, after Shri Lal Bahadur Shastri, the former Prime Minister and a great leader, it is only Shri Narendra Modi ji who has won the hearts of the people. Shri Lal Bahadur Shastri asked to give one meal for the sake of the country, and the whole country was ready to give it. No other Prime Minister had that kind of morality, leadership quality, and the confidence of the people. … (*Interruptions*)

Shri Narendra Modi ji asked people to give up their LPG benefits, and more than six crore people gave up the LPG gas benefits. No other Prime Minister had done it. It requires a lot of guts to do it. And, that is what Shri Narendra Modi ji did through his honest personality.

Madam, I have last two points to make. A lot has been said about the Constitution that the changes in Constitution will happen. In fact, most of the amendments made during the last 10 years by Narendra Modi ji only consolidated the Constitution. The fear was put in the minds of the people from SC/ST community that the reservation will be removed. How can one remove the reservation? It is Shri Narendra Modi ji who extended 10 years of SC/ST reservation. It is Shri Narendra Modi ji who gave the Constitutional Status to the National Commission for Backward Classes. It was Shri Narendra Modi ji who revoked Article 370, and gave the opportunity to SC/ST in Jammu and Kashmir. It was not there for 75 years. It was Shri Narendra Modi ji who had given the opportunity to all the SC/ST community people and poor people for their economic entrepreneurship through MUDRA loans.

Lastly, madam, I just want to tell this House that a lot of criticism has made against on our Leader. I am really not worried about it because अच्छे लोगों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, जो है नाम वाला वही बदनाम है।

Our Prime Minister is like a Neelkantha. He will swallow whatever they say. But he will only give *Amrut*. That vision of Amrit Kaal is only due to him, and it will be achieved. And God willing, in 2047, our children will remember our great Leader, Shri Narendra Modi ji, his strategy, his decisions, his administration, and also the great Budget presented by our hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji. Thank you.

(ends)

1634 बजे

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदया, सरकार भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी बता रही है। इसके बावजूद वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में आगाह किया है कि भारत की ग्रोथ के सामने ब्रेकर का खतरा बरकरार है।

(1635/RV/VR)

महोदया, यह बड़ी गम्भीर बात है। हालांकि, यह बजट अपने आप में अपने दायरे में महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन बिहार की विशिष्ट चुनौतियों और संभावनाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से असफल है। सरकार के विभिन्न वादों, योजनाओं और राज्य में 'डबल इंजन' की सरकार के होते हुए भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना बिहार के प्रति इस 'डबल इंजन' की सरकार की नीति को दर्शाता है कि यह 'डबल इंजन' की सरकार बिहार के विकास के प्रति कितनी गम्भीर है, जबकि बिहार की बदौलत ही आज केन्द्र की यह सरकार चल रही है।

महोदया, यह सरकार भावनाओं को जगा कर कैसे राज करती है, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं। गरीबों से वोट लेकर और फिर उनको और पीछे ढकेल कर, 150 करोड़ की जनसंख्या में आधी आबादी गरीब है, और ये गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले 75 से 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम अनाज फ्री दे रही है और ये गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं।

महोदया, हम आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहेंगे कि आप जिन 80 करोड़ आबादी को, जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं, उन्हें आप 5 किलोग्राम फ्री अनाज दे रहे हैं और उसके बदले में उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई जी.एस.टी. के रूप में आप उनसे वसूल रहे हैं। यह कहां का न्याय है? सरकार गरीबों के साथ किस तरह का न्याय कर रही है?

महोदया, हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये छात्रों की बात करते हैं, उनसे वोट लेते हैं, पर एडुकेशन बजट दिन-प्रति-दिन कम करते जाते हैं। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, इस पर सरकार की स्पष्ट नीति इस बजट में नहीं दिखती है। जो कमरतोड़ महंगाई है, उस महंगाई को यह सरकार कैसे कम करेगी, उस पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

महोदया, दक्षिण बिहार में सुखाड़ वाले क्षेत्र के किसानों को ये उससे कैसे निजात दिलाएंगे, इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि ये गरीबी उन्मूलन की जो बात करते हैं, तो हमारे भारत में जातियों का एक समूह है और इन जातियों को तभी लाभ हो सकता है, जब जनगणना जाति आधारित होगी और 65 प्रतिशत आरक्षण देकर उसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यह सरकार गरीबी की बात करती है, पर गरीबों के कल्याण के लिए हम महंगाई को कैसे दूर करेंगे, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है।

महोदया, हम औरंगाबाद, बिहार से आते हैं। औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद का अधिकांश इलाका राष्ट्रीय राजमार्ग - 2 पर बसा हुआ है। औरंगाबाद से गया की दूरी तकरीबन 112-114 किलोमीटर है। वहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, लेकिन औरंगाबाद में किसी प्रकार के कोई मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि औरंगाबाद में एन.एच. की काफी लम्बी दूरी है, इसलिए वहां एक ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण किया जाए। औरंगाबाद के देव प्रखण्ड में जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हुई है, उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का विचार सरकार करे।

सभापति महोदया, आपने हमें इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

(इति)

(1640/GG/SAN)

1640 बजे

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : सभापति मोदया, एक युवा महिला सांसद होने के नाते मैं यह अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से फाइनेंस बिल, 2024 पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। मैडम, हम आम बजट के बाद पहली बार बोल रहे हैं, इसीलिए हम अपनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देंगे कि उन्होंने सातवीं बार सफलतापूर्वक एक बजट पेश किया है और इस बात से एक चीज़ तो ज़रूर साबित होती है कि बजट घर का हो या देश का, अगर वह किसी महिला के हाथ में है तो परफॉर्मेंस और प्रॉसपेरिटी दोनों की गारंटी है। इस सदन में हम उन दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस देश का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं यानि युवा और महिला।

महोदया, जब देश में चुनाव होता है तो लोकतंत्र अपना एक जनादेश देता है और हम बहुत गर्व के साथ यह बता रहे हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म के लक्ष्य के साथ तीसरी बार जनता ने हमें अपना मतदान रूपी आशीर्वाद दे कर सरकार बनाने के लिए अपना जनादेश दिया है।

आज 11 जून, 1964 का वह दिन याद आता है, जब तब के प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने देश को पहला संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि “There comes a time in the life of every nation when it stands at the crossroads of history and must choose which way to go.” 140 करोड़ देशवासियों ने इस चुनाव में हमें अपना निर्णय दे कर एक स्टेबल सरकार को चुना है। वर्ष 2004 से 2014 का जो दस साल का हमारे देश का पीरियड था, उसको उन्होंने चुनौती दी है, जब देश को सिर्फ घोटालों और देश विरोधी गतिविधियों से जाना जाता था। मैम, जब हम यूपीए सरकार को याद करते हैं तब उसको थ्री-सी की सरकार से याद करते हैं – करप्शन, कम्यूनलिज़्म एण्ड कनफ्यूज़न। परंतु जब हम एनडीए की सरकार को याद करते हैं तो हम उसको थ्री-डी सरकार के नाम से याद करते हैं, जो है डेवल्पमेंट, डेडिकेशन एण्ड डिलीवरी। डेडिकेशन, हर वर्ग को सुरक्षा और विकास देने की है। हमारा डेवल्पमेंट का विज़न है और हम यह भी प्रयास करते हैं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, वे हरेक व्यक्ति तक टाइमबाउंड डिलिवरी सिस्टम से पहुंचे। हमारे वादे, चाहे वह राम मंदिर का हो, आर्टिकल-370 का हो, जीएसटी का हो या सीएए का हो, हमने जितने भी वादे किए हैं, उनको लागू करने का पूरा प्रयास किया है।

मैडम, हम गर्व के साथ कहते हैं कि जनता ने थ्री सी नहीं थ्री डी की सरकार को चुना है। इस सदन में अक्सर हमारे तब के प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक बात कही जाती है कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली से लाभार्थी को अगर सौ रुपये भेजे जाते हैं, तो

लाभार्थी के पास सिर्फ 15 रुपये ही पहुंच पाते हैं और 85 रुपये भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। हम आज गर्व के साथ कहते हैं कि दिल्ली से सौ रुपये जाते हैं तो एनडीए की सरकार में लाभार्थी तक सौ रुपये पहुंचते हैं और कोई भी नागरिक एक रुपया टैक्स भरता है तो उसको योजनाओं से दस रुपये का लाभ होता है। अगर इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो एनडीए सरकार का रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट सबसे ज्यादा पॉज़िटिव है। मैडम, अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो वर्ष 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब उनको मज़बूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जो हमारे तब के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो अच्छे काम किए गए थे, उसकी वजह से था। वह हमारे देश को एक सुपर पॉवर बनाने का एक सुनहरा अवसर था, पर इन लोगों ने मिल कर हमारे देश को 50 साल और पीछे ले जाने का काम किया। तब भारत का करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस ऑफ 0.5 पर्सेंट जीडीपी पर था। डेफिसिट वर्ष 2009 से 2014 तक 3.3 पर्सेंट हो गया। आज ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बाद भी करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 0.7 पर्सेंट पर है।

विपक्ष के लोग हमेशा सरकार को मंहगाई पर घेरते हैं। हमेशा कहते हैं कि इस सरकार में मंहगाई बहुत ज्यादा है तो उनके लिए भी कुछ आंकड़े हैं। कंज्यूमर प्राइस इनफ्लेशन का एवरेज़ वाजपेयी जी के समय 4.1 पर्सेंट था, जो वर्ष 2004 से 2009 में बढ़ कर 5.8 पर्सेंट हो गया और वर्ष 2009 से 2014 में तो यह 10.4 पर्सेंट हो गया। हमारे कार्यकाल में यह वर्ष 2014 से 2019 तक 4.45 पर्सेंट था और आज जब कोरोना की महामारी के बावजूद वर्ष 2019 से 2024 के बीच कंज्यूमर इनफ्लेशन प्राइस 5.69 पर्सेंट है।

(1645/MY/SNT)

उसके बावजूद हमारे देश का कंज्यूमर प्राइस इंफ्लेशन 5.69 परसेंट पर है। यह हमने तब करके दिखाया, जब हमें एक कमजोर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। आज जब हम इन्वेस्टर्स से पूछते हैं कि “How is the investment?” तो वे कहते हैं कि“High, Sir.” भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक, हर राज्य में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज कश्मीर में यूएई का एम्मार ग्रुप जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है, वह 500 करोड़ रुपये का निवेश करके मॉल और आईटी टॉवर बनाने जा रहे हैं। हम सबको पता है कि इनके कार्यकाल में कश्मीर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या होता था।

महोदया, आज जब बजट आया है और हम लोग बजट की बात कर रहे हैं, तब विपक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं कि यह बजट पार्शियल है, यह बजट सिर्फ बिहार का बजट है। उनके लिए भी कुछ आंकड़े हैं। बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 9.7 लाख करोड़ हैं, जो पिछले वर्ष से 13 परसेंट ज्यादा है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2024 तक 214 मिलियन डॉलर का एफडीआई आया है। वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक भारत में रिकॉर्ड 70 बिलियन

डॉलर एफडीआई आया है, जो वर्ष 2013-14 में सिर्फ 36 बिलियन डॉलर थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार की इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमी है, बिहार की इकोनॉमी एस्पायरिंग इकोनॉमी है। जब भी केंद्र सरकार ने बिहार को सहयोग किया है, तब बिहार और मजबूती से खड़ा हुआ है।

महोदया, मैं बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने बजट के लिए इतनी अच्छी घोषणाएं बिहार के लिए की है। अगर जॉन एफ. कैनेडी की बात कहें तो वह कहते थे कि American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good." मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इन सारे शब्दों के लिए बिहार का उदाहरण दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार बिहार को लगातार विकास की ओर लेकर जाएगी। सरकार ने बिहार को हाइवे डेवलपमेंट के लिए 26 हजार करोड़ दिये हैं, जिसमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेसवे है। इससे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बल मिलेगा तथा रोजगार क्रिएट होगा।

महोदया, इतनी सारी योजनाएं, 48 लाख करोड़ रुपये का बजट, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, हर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सब सिर्फ इन्हीं दस सालों में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था तो वही है और अधिकारी भी वही है, लेकिन जो बदला है, वह सिर्फ हमारा काम करने का ढंग, क्योंकि हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीति भी है और हमारे पास देश का सेवा करने का नियत भी है।

आज जो फाइनैंस बिल आया है, वह हमारे देश के लिए एक नयी ग्रोथ स्टोरी लिखेगा. क्योंकि आज हम टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपरेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर फाइनैंस बिल और टैक्सेशन की बात करें तो हमारा टैक्स सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम हैं। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वह इस पर निर्भर करती है। पिछले दस वर्षों में टैक्स बेस्ड रिफॉर्म्स किए गए हैं। हमारा जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, वह पिछले वर्ष 34,64,792 करोड़ रुपये था। इस वर्ष 38,40,170 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। विपक्ष वाले हमेशा आरोप लगाते है कि केंद्र सरकार उनकी सहायता नहीं करती है। मैं उनको बता दूं कि इस 48 लाख करोड़ रुपये में से 30 प्रतिशत जो 12,47,211 करोड़ रुपये राज्यों को दी जाएगी। हमारी सरकार की नीतियों के कारण हमारा नेट टैक्स रेवेन्यू वर्ष 2014 में नौ लाख करोड़ रुपये था। वह आज बढ़ कर 25 लाख करोड़ रुपये हो गया है। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो रिकॉर्ड 11.8 प्रतिशत पर है। हमारी सरकार ने जीएसटी लगा कर पिछले 70 वर्षों में जो सबसे बड़ा सुधार है, उसे किया है। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में दो लाख करोड़ रुपये का स्तर पार किया है। जीएसटी काउंसिल की गठन के बाद हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बल दिया है। उसने एक नयी मीनिंग और डेफिनेशन दिया है।

महोदया, फाइनैंस बिल बहुत ही आवश्यक बिल होता है, क्योंकि हर सेक्टर को इसमें इंसेंटिव देने का काम किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आम आदमी जब बजट का भाषण सुनता है तो सबसे ज्यादा अगर वह गौर से सुनता है तो वह हमारे टैक्सेशन प्रपोजल्स को सुनता है। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने उन्हें निराश नहीं किया है और न्यू टैक्स रिजीम रेट स्ट्रक्चर को रिवाइज करके एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम लाया है, जिसने सैलरीड एम्प्लॉइ हर साल 17,500 रुपये का इनकम टैक्स सेविंग कर पाएगा। इसका लाभ मध्यम वर्ग के लोगों और निम्न वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा होगा। सरकार द्वारा Standard deduction for salaried employees को 50 हजार रुपये से बढ़ा कर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। Deduction on family pension for pensioners को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है।
(1650/CP/AK)

इन प्रावधानों से मिडल क्लास को लाभ होगा, कंजंप्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पुश मिलेगा। हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना है, उसको पूरा किया जाएगा। आज भारत स्टार्ट-अप के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हम यह बता देना चाहते हैं कि आज भारत थर्ड लार्जेस्ट स्टार्ट-अप हब है, जिनकी संख्या 1.25 लाख है और 110 यूनीकार्न्स हैं।

मैं एक बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्ट सदन के सामने रखना चाहती हूं। ये जो रेकग्नाइज्ड स्टार्ट-अप्स हैं, उनका 45 पर्सेंट टायर टू, टायर थ्री सिटीज़ में है। इसका यह मतलब होता है कि सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, बल्कि हमारे बिहार के बक्सर या भागलपुर में कोई बैठे हुए हों तो वे भी आज लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वे अपने स्टार्ट-अप के माध्यम से हमारे प्रदेश का विकास कर रहे हैं। इन स्टार्ट-अप्स को और बढ़ावा देने के लिए एंजेल टैक्स को एबॉलिश करने की घोषणा की गई है। इससे अर्ली स्टेट स्टार्ट-अप को फंडिंग देने में आसानी होगी और लिटिगेशन कम करेगा। जब लिटिगेशन कम होगा तो फोकस इनोवेशन और ग्रोथ पर होगा।

हमारे जो छोटे-छोटे क्षेत्र हैं, जैसे मेरा क्षेत्र समस्तीपुर है, ऐसी सारी जगहों पर भी जोमैटो, स्विगी, अमेज़ान जैसी कंपनीज़ ऑपरेट करेंगी और वहां युवाओं को रोजगार मिलेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजेनस के लिए delays in TDS payments up to the due date of filing the TDS statement is proposed to be decriminalised. एक और आंकडा रख रहे हैं। टैक्सेशन में सबसे बड़ा हिन्ड्रेंस लिटिगेशन होता है। हमारी इकोनॉमी के 12 ट्रिलियन रुपये अभी भी टैक्स डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, जो जीडीपी का ऑलमोस्ट 6 प्रतिशत है। इस बजट में विवाद से विश्वास स्कीम की घोषणा की गई है, जिससे ये सारे जो पेंडिंग इंकम टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। To reduce the litigation in

international taxation and enhance certainty, the Government proposes to expand the scope of safe harbour rules and streamline the transfer pricing assessment process. यह फाइनेंस बिल एक तरह का स्टेटमेंट है। जनता की मेहनत का जो पैसा है, उसे सरकार वापस इनवेस्ट करती है। हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमारी 9 प्राथमिकताएं हैं। हम उन 9 प्राथमिकताओं को जरूर एचीव करेंगे और विकसित भारत, विकसित बिहार का एक नया प्रमाण देंगे। यह देश पिछले 10 वर्षों से रिफॉर्म में है और सकारात्मक बदलाव देख रहा है। हमारा देश आज फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमीज़ से टॉप 5 इकोनॉमीज़ की तरफ बढ़ रहा है और जी-20 के माध्यम से आज हमारा देश एक ग्लोबल सुपर पॉवर बन गया है। हमने अपने देश के नागरिकों के सपनों को पूरा होते हुए देखा है, चाहे चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो, धारा 370 हो या हमारे प्रभू श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा हो।

आज हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हमारे सामने जो चुनौती है, वह तो है। हमारे पास अवसर भी है और एक विजन भी है। अपनी वाणी को विराम देने के पहले हम धन्यवाद देंगे हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जिनके लगातार प्रयासों की वजह से आज हमारे प्रधान मंत्री जी का जो सपना है, उसको बिहार में धरातल पर हम लोग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। … (व्यवधान) विपक्ष के लोग हमेशा हमारी नीयत को कोसते हैं, हमारी नीति को कोसते हैं, हमेशा हमें कोसते रहते हैं। हम रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती से आते हैं। हम इनके लिए सिर्फ दो पंक्तियां पढ़ेंगे।

‘सच है विपत्ति जब आती है,
कायर को ही दहलाती है,
सूरमा नहीं विचलित होते,
सैनिक नहीं धीरज खोते,
विघ्नों को गले लगाते हैं,
कांटों में राह बनाते हैं।’

जय हिंद, जय बिहार, जय समस्तीपुर।

(इति)

1654 बजे

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदया, धन्यवाद। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सरकार की, उस पक्ष की बातों को सुना जाए, तो सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। धन प्रबंधन एक बड़ा विषय है। मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से बहुत कम समय में कुछ कहना चाहता हूं। केवल एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसा धन प्रबंधन है कि हम सांसदों को 5 करोड़ रुपये सांसद निधि मिलती है। यह जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है, लेकिन, इसमें 4 करोड़ 90 लाख रुपये ही मिलते हैं। जब आप जिले पर धन लिखेंगे तो 2 पर्सेंट स्टेश्नरी चार्ज कटेगा और 18 पर्सेंट जीएसटी कटेगा तो आप 3 करोड़ 90 लाख रुपए का ही बमुश्किल काम करा सकते हैं। यह सरकार का धन प्रबन्धन है।

(1655/NK/UB)

अगर इससे अधिक सत्ता पक्ष के साथी पाएंगे तो हमें बताएंगे। जो धन प्रबंधन है, उस दिन वित्त मंत्री जी का भाषण सुनकर बड़ा अच्छा लगा था कि सात लाख रुपये तक हम टैक्स नहीं लेंगे, जो तीस लाख रुपये कमाएगा उससे इतना लेंगे, अस्सी करोड़ रुपये कमाएगा, उससे इतना लेंगे। लेकिन यह नहीं बताया गया कि जो डायरेक्ट कर है, इनडायरेक्ट कर से जनता मारी जा रही है। डायरेक्ट कर वालों को कितना लाख रुपये उनके बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जो अधिक करदाता हैं, उनका कर्ज माफ होता है और उनका धन बट्टा खाता में डाल दिया जाता है और कम कर देने वाले मतदाता पम्पिंग सेट का ऋण भी माफ नहीं होता है। अगर दस हजार रुपये कर्ज लिया है तो वह भी माफी नहीं होता है।

मैं सत्ता पक्ष से कहूंगा, सब चंगा है। जब रेड सिंग्नल पर आपकी गाड़ी का शीशा पोंछते हुए कोई बेटी या बेटा न मिले। जब पैसे के अभाव में किसी बेटी की शादी रुकती है तब पीड़ा होती है। आज तक यह सरकार कहती है, हमको बड़ा भ्रम होता है - विकसित भारत, विकसित भारत। विकसित भारत की कल्पना में मैं भारतीय जनता पार्टी के भाइयों को साधुवाद देता हूं कि सदन में भाजपा का नाम लेना बंद कर दिया है। मोदी जी के नाम से भाषण शुरू होता है और उन्हीं के नाम पर खत्म होता है। विकसित भारत में थाने का चौकीदार आज भी रोज चार सौ रुपये नहीं पाता है, गरीबों की सेवा की करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्री, रोजगार सेवक, सहायिका, आशा बहू, शिक्षा मित्र और मनरेगा के मजदूर को भी चार सौ रुपये रोज नहीं दे पाएं और 400 पार का नारा दे रहे थे।

आपने बहुत सारे शौचालय बनाएं, कितने का शौचालय बनाया - बारह हजार रुपये का। फाइव स्टार होटल में एक कमरे का भाड़ा बारह हजार रुपये है। मैं लाख रुपये वाले

होटल में नहीं गया। आप जल नल से फ्री में पानी दे रहे हैं तो छाती पीटा जा रहा है। यह भी देखिए कि एक लीटर पानी बोतल एक हजार रुपये में और पचास रुपये में एक लीटर दूध मिल रहा है।

डायरेक्ट टैक्स किस तरह से आता है, सभी सांसद महोदय यहां बैठे हैं। अगर सरकार के लोग बड़ी गाड़ियों से न जा रहे हों तो हर शहर में लेबर बाजार देखने को मिलेगा, वहां चार सौ, पाँच सौ और एक हजार लेबर खड़े रहते हैं। कोरोना के बाद आपकी व्यवस्थाओं की वजह से लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले, ट्रेन्स थीं, लेकिन लोगों को पैदल चलना पड़ा, लोग मरे। सारे रोजगार बंद हुए, वे लोग लेबर हैं। काम के अभाव में इतने महंगे सीमेंट और छड़ हो गए हैं कि लोगों ने घर बनाने बंद कर दिए हैं। आप शराब पर सबसे अधिक टैक्स लेते हैं और वह लेबर भी शराब पीकर आपको टैक्स देता है, धन प्रबंधन में आपकी मदद करता है। क्या आपने उसके बच्चे का पढ़ने का इंतजाम किया? जब समय आता है तो कॉपी-किताब पर जीएसटी लगाते हैं।

(1700/SK/SRG)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे दल के साथी को बोलना है। जब इन्वेस्ट करने की बात होती है, इन्वेस्ट के नाम पर उत्तर प्रदेश में करीब सात साल से जब से यह सरकार बनी है, रोज इन्वेस्टर्स बुलाए जाते हैं कि आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमारा विकास होगा और धन बढ़ेगा। इन्वेस्ट करने पर कितने करोड़ रुपये खर्च हुए? इस पर जितने करोड़ रुपये खर्च हुए, उतना निवेश हमारे प्रदेश में नहीं हुआ। आप निवेश ठीक करेंगे नहीं, आप उधार देंगे लेकिन उधार लेंगे नहीं, आप बाजार को देखेंगे नहीं। आपने माल संस्कृति ला दी। आप भूल गए कि छोटा व्यापारी, जो एक हजार रुपये में किराए की दुकान लेता है, 500 रुपये या एक हजार रुपये उस दुकान का भाड़ा देता है। उसने छोटी दुकान खोली थी और आपने बढ़ावा दे दिया कि अब नैट से मार्केटिंग हो रही है। लोग फोन करते हैं, मार्केटिंग शुरू हो गई, मॉल वालों का माल तो घर आ रहा है। मॉल वालों से किरयाने का सामान फोन करने से घर आ जाता है। मॉल वालों के जूते, चप्पल, कपड़े और सौंदर्य सामग्री, सब्जी आदि केवल फोन करने से घर तक पहुंच रही है, लेकिन जो गरीब दुकानदार है, व्यापारी है, ज़रा उसकी दशा पूछें, वह अपनी दुकान का भाड़ा तक नहीं दे पा रहा है, किराया तक नहीं दे पा रहा है।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि आपने जो व्यवस्था दी है, इन व्यवस्थाओं की बदौलत आप विकसित हो सकते हैं, लेकिन देश का गरीब विकसित नहीं हो सकता, देश की झोंपड़ी विकसित नहीं सकता। आप 1 लाख 20 हजार रुपये में आवास बना रहे हैं। क्या 1 लाख 20 हजार रुपये में आवास बनेगा? धन्यवाद।

(इति)

(1700-1710/PS/MK)

1702 hrs

*SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. I thank you for allowing me to speak on Finance Bill, 2024 on behalf of Congress Party. I thank the brothers and sisters of Karur parliamentary constituency who have elected me as a Member of Parliament for the second term with lots of support and affection. Hon Finance Minister usually cites a couplet from Tirukkural or a quote from Sangam literature in the Union Budget. This time she has forgotten Tirukkural, Sangam literature and also Tamil Nadu. The funds that are rightful share to Tamil Nadu are also not provided. Hon Finance Minister has provided the Halwa (sweet dish) to Tamil Nadu and the opposition ruled States of the country. I wish to remind them the Tirukkural which they forgot to quote. “Iyatralum Eettalum Kaathalum, Kaaththa Vakuthalum Vallathu arasu”. A King or a Government should look for the ways of generating income. After collection of such resources, he should protect those resources. Once it is stored, it should be distributed evenly among the subjects. There are several ways to earn money. Important way is taxation. How much and from whom the tax is collected matters a lot. How the collected money is spent and how much it is spent also do matter. Through these aspects one can come to a conclusion how the governance is taking place. You can get more tax from big industrialists and foreign industrial companies. The Government should levy more tax from the richest persons. If industries are set-up and employment is generated, you will get more tax collection as revenue. Particularly for States like Tamil Nadu where you have more Industrial growth, if more funds are allocated, tax collection will also increase resulting in income generation. This was done by the UPA led by Congress. But what are you doing now? You lease aside the big business magnates and the foreign companies. You give tax rebates to them. Whereas you snatch away from the poor and lower strata people as a heartless robber by hitting them and collecting heavy taxes from them. Good example of this is the Diesel, Petrol and cooking gas. You always make a comparison of UPA and NDA Governments. I also make a comparison. When Congress Government

* Original in Tamil

was in power, one litre petrol was sold for Rs 73 and 18 Paise; 1 litre diesel for Rs 40 and 90 Paise; and cooking gas Rs 450 per cylinder. Now whether diesel or petrol both sold at Rs100 per litre. Cooking gas is Rs 1200 per cylinder. Thanks to election. The excise duty on petrol and diesel has been increased to 250 per cent. For one litre of petrol, it has been increased from Rs 1 and 48 Paise to Rs 32 and 98 Paise. The excise duty on diesel increased 800 percent. For one litre of diesel, it has been increased from Rs 3 and 56 Paise to Rs 39 and 81 Paise. During the UPA regime led by Congress, tax revenues stood at Rs. 90,000 crore. During the Amrit Kaal, Ache Din Golden regime of the BJP it stands at Rs 2.7 lakh Crore. Tax revenues have increased upto 176 per cent. This is just a testimony. What can we say other than the day loot. Next issue is GST. During July 2024, the collection of GST increased by 10.3 percent. It stands at 1.82 trillion. Mostly from the domestic transaction. All essential commodities are levied GST from 5 per cent to 18 per cent to 25 per cent. It is 5 per cent GST for cooking oil, sugar, spices, tea, coffee, toffee, and lifesaving drugs. It is 18 per cent GST for hair oil and toothpaste. It is 18 % for luxury items such as small cars, AC and Refrigerators. If you live in a middle-class family in the urban areas, you will come to know what a luxury item is and what is not. On the top of it, there is 15 per cent GST on life insurance and health insurance policies. But the GST on coal has been reduced from 11.69 per cent to 5 per cent. Why is it so? I read something interesting on a website. I quote, “India's first private mining company who pioneered concept of mind developing MDO just about a decade, is our inception we became one of our largest developers and operators of Coal mines in the country”. Unquote. No price for guessing it. It's Adani. Sorry I can't quote. It is A1. As soon as the BJP came to power in the year 2019, the Corporate Tax was reduced from 30 to 22 per cent. But as a result of this, there was a revenue loss of Rs. 1.45 lakh crore. Now the tax for foreign companies has been reduced from 40 to 35 per cent. E-commerce. Amazon and Flipkart are the big companies which were paying 2 percent tax. This was reduced to zero per cent. These companies are poor companies. Can the Government ask tax from them? There are poor and middle-class people for paying tax. This is just a trailer. If you see the whole film, as told by Mahakavi Bharathi, “Our hearts will not tolerate”. What have you done after snatching so many things from the poor and middle-class

people? You have created unemployment unprecedented in this country for the last 45 years. ILO report says Indian youth account for 83% of unemployment population in 2022. If 83 per cent of a country's youth is unemployed, not only their future, the future of that country will also go to darkness. But you are not bothered about that. Manufacturing Sector. Manufacturing sector was in second place as regards employment generation and now it has gone to fourth place. I come from Karur. India's fourth largest exporting city. Our city which gave employment to 2 lakh persons is now struggling to provide employment for 50,000 persons. Thanks to your GST. Make in India had ambitious target of 12 per cent to 14 per cent of manufacturing growth per annum. But what is the outcome? Average 5.8 per cent growth is achieved since April 2014. Why? Micro Small Medium Enterprises MSMEs are facing severe problems during the BJP regime. Government is selling all its resources to its friends A1 and A2. Those who do not get jobs in industries are turning into labourers. You are also affecting the 100 days work guarantee Scheme. If 100 days of work should be given to all 6 Crore registered persons, you have to allot 2.72 Crores. But you have allocated only Rs 86,000 crores. Due to less allocation, it becomes unable to release payments of wages for 3 to 4 months to the people who worked under this Scheme. Next issue is Agriculture. You said you will double the income of farmers by 2022. But in the year 2019-20, the Budget for Agriculture was 4.97 per cent i.e. almost 5 per cent. But now it has been reduced to 2.6 per cent. Between 2018 and 2023, the Agriculture Ministry has returned Rs. 1 lakh crore an unspent balance. You could have waived off farm loans from this amount. You could have built a better infrastructure. But you won't do it. In every one hour, a farmer or a farming labourer is committing suicide in this country. Under this Government, loans of 50 per cent farmers have doubled. Similarly, the Budget outlay for Department of School Education and literacy program was reduced from 3.16 per cent in 2013-2014 to just 1.53 per cent in 2024-25. You are not concerned about the education of our students. You want to impose your New Educational Policy on us. But just remember that Tamil Nadu will never

accept you New Educational Policy. Tamil Nadu is a pioneer to India in public health. Hon *Perunthalaivar* Kamarajar….

HON. CHAIRPERSON (DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR): Please conclude.

*SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Madam, just one minute. I am going to wind up. *Perunthalaivar* Kamarajar brought the midday meal Scheme 50 years ago. Congress Government implemented this Scheme throughout the country. Hon Chief Minister of Tamil Nadu Annan Thiru Stalin is providing breakfast for children in schools of Tamil Nadu. It is nowhere implemented in the country. You should come forward to implement such Schemes. There are so many issues in the country. But for you, the caste is important. Looking at our Leader, you are asking the caste of our Hon Leader of Opposition. This reference is expunged from the proceedings of the House. Hon. Prime Minister discloses the disrespectful conversation along with the expunged portion in the public domain. Are you not ashamed of this?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

*SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Madam just give me 30 seconds. Are you not ashamed? Whether caste is your identity? If caste is your identity; then for us the social justice is our identity. If hatred is your identity, then for us love is the identity. If divisive politics is your identity; then unity is our identity. If the 'Code of Manu' is your identity then democracy is our identity. The Constitution which upholds democracy is our identity. One day or other the 'Code of Manu' will be buried inside this land. Thanks. Our flag of social justice will fly so high. We will conduct the Caste based socio economic census in this country. We will uphold social justice. We will create India as peaceful and prosperous. To whom you have asked for disclosing his caste. To whom you are afraid of. Today's Hon Leader of Opposition will be the Prime Minister of Tomorrow. Our leader Shri Rahul Gandhi will lead and complete this noble task. INDIA will win that day. Thank you.

(ends)

1711 hours

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you, Madam Chairperson.

While speaking on the Union Budget earlier, as far as possible, I had dealt with every aspect of the provisions that were made in the Budget, which was presented by the hon. Finance Minister. I had also spoken on the Demands for Grants under the control of the various Ministries and Departments. The Appropriation Bill was passed by the House.

Today, on the Finance Bill, I will specifically go about the peculiar aspects which are there in the employment sector, which is affecting public sector in particular, and people and employees in general. Madam Chairperson, the Union Government has asked the public sector insurance companies especially, the National Insurance Company Limited, United India Insurance Company and Oriental Insurance Company about the same. The Government has not only asked them, but also, a caution or notice has been given to them to move away from their core business, that is, stop the lines, as it has been spelt that way. And this has been done by the Department of Financial Services (DFS). Their core business includes, motor insurance and health sector, which are the main revenue-earning arms of the insurance companies. Since inception, -- even in the monopoly sector, which prevailed till 1990s, and in 1999, when the entire insurance sector was opened up for the private players -- these public sector insurance companies have been doing extremely well. All along, they have been paying handsome dividends to the Central exchequer, and as far as their functioning was concerned, it had no complaints all over. It was also entrusted with employment by the Government, and they did take the responsibility of putting up with thousands of employee force, which worked under the public sector. But today, what is the situation? They are being asked to go away or to look at some other avenues to mop up insurance revenue by stopping their motor insurance business and health sector, the reason being that whatever revenue is earned, the claim payment is much more than the revenue and, therefore, they are being incurring losses.

Then came the issue of infusion of capital which the Government of India did in the financial year of 2020-21 in two tranches and some Rs. 17,500 crore were infused. Recapitalisation was done in these three companies. After

the same, the turnaround is very evident. If we go by the figures, the United India Insurance Company has made a remarkable turnaround, reducing its losses from Rs. 5000 crore in the financial year 2022-2023 to a profit of Rs. 19 crore in the financial year 2023-24.

(1715/SMN/SJN)

National Insurance Company has significantly narrowed its losses from Rs. 3800 crore in 2023 to Rs. 187 crore. Similarly, Oriental Insurance Company has also done its bit where they are cutting down the losses and they are moving towards profit making economy for their organisations.

There are four insurance companies. Out of them, New India Assurance Company is doing extremely well. They have done Rs. 1000 crore profit in the last year. This time, it is Rs. 1100 crore. But these things which are being pushed on them and what kind of level playing field is being given by the Government and ensured by the Government to see that private players who have entered the industry some 30 years back, now they have taken over or are in the race to take over the public sector companies. The level playing field, I am referring to because social sector schemes, are driven by the public sector companies. These private players never venture into obviously because they are not profit-making schemes. Rural insurance is also taken up by the Public Sector which they are doing diligently but at no reward or no award or no appreciation rather.

But when you come to restrict these public sector insurance companies, the Government seems to be very harsh and this should not be done as public sector banks have seen that over the years when their NPAs grew, over the years, for a decade or so. … (*Interruptions*)

Give me 2-3 minutes. This is very important. If you do not want to know the ground realities, I will sit down. I have no issues.

So, against this backdrop, how are we going to match? The public sector companies are doing well. Piyush Ji is here. He has seen these companies over the years. If we do not give them the kind of impetus or kind of incentive which is needed at this stage, the things will not be in the interest of the Indian economy and it will be suffering like any other thing.

Today, what is the scenario? For last more than 5-7 years in the general insurance industry, all four companies have not seen wage revision. LIC is

doing well. LIC got its way but what about other companies. Why are employees being restricted? Why are employees being deprived of their constitutional right? They have been putting in every effort to see that the company does well. So, my request would be to look at the private players and look at the scenario in the public sector. The DFS has also accepted the fact that there are no recruitments in the public sector which owns the responsibility to shoulder to see the unemployment aspect is addressed in a big way, which is not happening. So, employment needs to be opened up in public sector companies and wage revision needs to take place and with this. On medi-claim which is needed by the people at large, Nitin Gadkari Ji has written to Finance Minister to reduce GST. Time and again, Arvind Sawant Ji and myself have been crying at the top of our voices. We have been making for the people that 18 per cent which is being levied on GST on the health policies and LIC policies is beyond affordability. This needs to be addressed.

Madam, I have a last point. Hon. Finance Minister has come out with the schemes which are really needed. Employment schemes with employment linked incentives have come. These are the schemes that have come up. Three schemes have been spelt out. But what is the reality? Do the manufacturers and private entrepreneurs from MSME come ahead to hire them up? Are they really willing to infuse their own capital or private capital? Otherwise, these schemes which are really looking good on paper will not come into practicality any more. If that is to be stopped, unemployment really is to be answered or it has to be addressed. These are the things which are right in front of you. Otherwise, schemes after schemes will be spelt out but absolutely unemployment will be the biggest problem for the country.

(ends)

(1720/SPS/SM)

1720 बजे

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : सभापति महोदया, आपने मुझे फाइनेंस बिल, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह फाइनेंस बिल, 2024 एक विकसित भारत की ऐसी आधारशिला है, जो एक आर्थिक यात्रा का ऐतिहासिक कदम है। मैं इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। यह बिल कोई राजकोषीय नीतियों का संग्रह नहीं है, लेकिन यह फाइनेंस बिल, 2024 विकास को बढ़ावा देने के लिए है, यह बिल निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है और यह बिल पारदर्शिता तथा दक्षता को सुनिश्चित करने का है। इसमें कर ढांचे को सरल बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगर मैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पर जाऊं तो यह उचित होगा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं कि "किसी राज्य को असभ्यता से लेकर सबसे अधिक समृद्धि तक ले जाने के लिए शांति, आसान कर और न्याय का सहनीय प्रशासन ही सबसे जरूरी है।" यह बिल सारी जरूरतों और कंडीशंस को पूरा करता है।

महोदया, इस फाइनेंस बिल का उद्देश्य देश में ऐसा वातावरण बनाना है, जिससे व्यवसाय और निवेश फल-फूल सकें और आर्थिक समृद्धि का आम नागरिकों को फायदा हो सके। जब मैं आम नागरिकों की बात करता हूं तो प्रधान मंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और सोच तथा उनके नेतृत्व में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने यह फाइनेंस बिल और बजट रखा है, क्योंकि कुछ बातें दोनों पर ओवरलैपिंग आ सकती हैं। एंपावरमेंट ऑफ द टैक्स पेयर, सतत आर्थिक विकास करना, प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना, इस फाइनेंस बिल का इंटेंट है, मोटो है और ऑब्जेक्टिव है। यह मानना है कि जब तक छोटे करदाताओं के हाथ में पैसा नहीं होगा और अगर उनको हम सशक्त नहीं बनाएंगे तो जितना उनके हाथों में पैसा होगा, वे अधिक खर्च करेंगे। अगर वे अधिक खर्च करेंगे तो वह पैसा अर्थव्यवस्था में आएगा। अर्थव्यवस्था में पैसा आने की वजह से ही भारत की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, वह उसी वजह से बनेगी। अगर हम इसकी पूरी स्प्रिट देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत ही एडेक्वेट है, उच्चतम स्तर का है। वर्ष 2023-24 में टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखें तो 11.6 परसेंट है और डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 6.6 परसेंट है, जो यह दर्शाता है कि जब टैक्स का सिंपलीफिकेशन होता है, तब ही यह अचीव होता है। इसका परपज़ है कि मोर पीपल्स इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, मोर कॉर्पोरेट्स पार्टिसिपेट करें और मोर पीपल्स टैक्स पे करें।

सभापति महोदया, अभी हमारे विपक्ष के कई साथियों ने कॉरपोरेट टैक्स रिडक्शन फॉरेन कंपनी पर ऐतराज जताया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रिवीलिंग फैक्ट्स हैं, जिनसे यह पता लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था इनके समय में कमजोर क्यों थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कमजोर क्यों थी? आप देखेंगे कि फॉरेन कंपनीज पर जो कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन हुआ है, वह बहुत जरूरी था। उसको 40 से 35 परसेंट किया गया है। अगर हम ग्लोबल कॉन्टैक्स्ट को देखें, टाइमिंग को देखें तो पोस्ट कोविड के बाद कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्होंने चाइना पल्स पॉलिसी अडॉप्ट की। चाइना पल्स पॉलिसी का मतलब यह होता है कि वह चीन से बाहर आना चाहते हैं और ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन हब ढूंढना चाहते हैं, जिसमें उनके लिए टैक्स भी कम

हो, कंड्यूसिव हो, पीसफुल हो और इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक हो तथा उनको लेबर भी मिल जाए। ये कंपनियां अभी अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बियोंड चाइना देख रही हैं, जिसमें अगर इंडिया के लिए कंपटीशन है तो वियतनाम कंट्री है, थाईलैंड है, टर्की है। इन कंट्रीज़ से है।

(1725/MM/RP)

फॉरैन कम्पनीज़ के लिए 40 परसेंट से 35 परसेंट टैक्स किया गया है। उसका इफैक्ट यह होगा कि It will attract more foreign companies to invest in India. जो कि पहली नहीं होता था। हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत कम थी। It will increase FDI. It will position India as a global manufacturing hub. इसकी वजह से जॉब्स क्रीएट होंगी। Goods-related sectors like logistics creating further employment in logistics, इससे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमें उन कम्पनीज़ की इंकम पर टैक्स भी मिलेगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। इसमें इंडिया की सक्सैस स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो एप्पल इंडिया का एक साल में टोटल प्रोडक्शन 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का हुआ है। उसका एक्सपोर्ट 85 हजार करोड़ रुपये का हुआ है। 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का अगर प्रोडक्शन होता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इंकम टैक्स भी मिलता है और 35 परसेंट टैक्स भी मिलता है। 40 से 35 परसेंट टैक्स करके हमने एक कम्पनी को अट्रैक्ट किया है। This is the highest achievement achieved by any company in a single year. यूपीए के टाइम में वर्ष 2014 तक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 5.3 परसेंट थी। यह डिप्लोरेबल है। एनडीए के टाइम में वर्ष 2023-24 की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9.9 परसेंट है। इनकी टैक्स पॉलिसी प्रूडेंट नहीं होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज़ को इन्होंने नेग्लैक्ट किया। इससे मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम पर आ गयी। 40 से 35 परसेंट टैक्स करने से Potential increase in overall tax collection despite lower rate. You will attract more FDI by lower rates in India. They will earn more. They will pay tax to the country. They will genrate more and more jobs. महुआ मोइत्रा ने अपनी स्पीच में कहा कि हमें इंफोर्मल जॉब्स ज्यादा क्रिएट करनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूं कि इंफोर्मल जॉब्स क्रिएट करने का यही तरीका है। मैं प्रधान मंत्री जी को उनके विज़न के लिए धन्यवाद देता हूं। सीतारमण जी को भी 40 से 35 परसेंट टैक्स करने के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इससे हमारे देश में ज्यादा एफडीआई आएगी। इससे हमारा जीएसटी कलैक्शन भी इंक्रीज़ होगा due to increase in the economic activities. अगर 85 हजार के प्रोडक्ट बिकेंगे तो उससे मिलने वाला जीएसटी भी हमें मिलेगा। Positive impact on India's trade balance और हमें फॉरेन करेंसी भी मिलेगी। 40 से 35 परसेंट टैक्स करने से हमारी इकोनॉमी में कॉन्सीक्वैंश्स इफैक्ट आता है। वह हमें देखना चाहिए। इसका लॉन्ग टर्म इफैक्ट क्या होगा? It will enhance India's competitiveness in global manufacturing. India will be treated as a hub of the manufacturing and it supports Make-in-India. प्रधान मंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं। मेक इन इंडिया डोमेस्टिक इंवेस्टर्स करें या फॉरैन इंवेस्टर्स करें, इससे इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, टैक्स इंडिया को मिलेगा और जीएसटी इंडिया को मिलेगा तभी

हम पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएंगे। इसीलिए प्रधान मंत्री जी कहते हैं- 'यही समय है, सही समय है।' यह डिसीजन सही समय पर लिया गया है जो कि एप्रिसिएबल है। जहां तक टैक्स कलैक्शन की बात है तो वर्ष 2023-24 में टैक्स कलैक्शन करीब 11 लाख करोड़ रुपये का हुआ है। It is due to lower tax rates, 30 per cent and 25 per cent, for manufacturing. (1730/YSH/NKL)

आपकी टैक्स पॉलिसी में हमेशा प्रिंसिपल रहा – 'higher the tax'. Higher the tax, lower the income. So, lower the tax means there will be more income for the Government.

यही कारण है कि वर्ष 2024 में 11 लाख करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ। वर्ष 2014 में यूपीए के समय सिर्फ 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ। एक तरफ 11 लाख करोड़ रुपये का हुआ और एक तरफ 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का हुआ और यह इसलिए हुआ, क्योंकि इनकी जो टैक्स पॉलिसी थी, वह प्रूडेंट नहीं थी। उसकी वजह से देश ने सफर किया और लगातार सफर किया। वर्ष 2014 में मोदी जी के आने के बाद उनकी दूरदृष्टि और विजन की वजह से यह संभव हो पाया।

हम देखते हैं कि हम डोमेस्टिक कंपनीज़ को कैसे कम्पीट करें। इन्होंने यह कभी नहीं सोचा। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो को लेते हैं तो यूके में डोमेस्टिक कंपनीज़ पर 25 परसेंट टैक्स है। यूएसए में 21 परसेंट है और चाइना में 25 परसेंट है। अगर हम इस स्लैब को बढ़ाते हैं तो हमारे डोमेस्टिक इनवेस्टर्स भी दूसरी कंट्रीज में जाकर इनवेस्ट करने लग जाएंगे। हमें ग्लोबली सोचना पड़ता है और कंट्री के हित में सोचकर ही यह डिसीजन लिया गया है।

इसके बाद बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ तो आप देखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ बिजनेस की वजह से लगभग रिकॉर्ड ब्रेकिंग about 1,85,000 new companies were incorporated in 2023-24. यह इसलिए हुआ, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर मिला। चाहे फॉरेन कंपनी हो या चाहे इंडियन कंपनी हो, यह उसकी वजह से ही हुआ। मैं इस प्रिंसिपल के पीछे टैक्स रिडक्शन को मानता हूँ।

What is the principle? What is the object? What is the spirit? Why is this reduction? The reason is, lower rates lead to higher compliance. Once you reduce the tax, everybody will pay it. Once you increase the tax, there will be evasion. So, lower rates lead to higher compliance, more economic activity, and more jobs. This is the reason कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी अचीव कर सकते हैं। इसका रिजल्ट यह हुआ कि हायर एग्रीगेट टैक्स कलेक्शन हुआ, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। Consequently, it provides the Government with more resources for the welfare schemes. This is more important. अदरवाइज अगर यह रिसोर्स नहीं होता तो कोई वेलफेयर स्कीम नहीं होती। मैं जीएसटी की भी बात करता हूँ। वर्ष 2023-24 में करीब 20 लाख 18 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी which does not include

other indirect taxes, or the number would be higher. उसके साथ-साथ मैं जब यूपीए की बात करता हूँ तो इनका डोमेस्टिक कंपनीज़ पर टैक्स 25 परसेंट नहीं था, 30 परसेंट नहीं था, उस समय टैक्स 43 परसेंट था और 34 परसेंट था, जिससे कि प्रोडक्शन और एक्सपेंशन में सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा टैक्स होने से रिजल्ट क्या हुआ? Lower tax rate collection limits the Government's ability to implementing welfare schemes.

यही कारण था कि उस समय हमारी वेलफेयर स्कीम्स होती नहीं थीं। अगर आप देखें कि इस टैक्स पॉलिसी से कंसीक्वेंशियसली इफैक्ट और फायदा सबसे पहले फार्मर्स को हुआ। 11 करोड़ 80 लाख फार्मर्स को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर 'पीएम किसान निधि' के तहत मिला। लगभग 3 लाख 11 हजार करोड़ रुपये की राशि किसानों को मिली। क्या आप सोच सकते हैं कि पिछले पांच सालों में इतना पैसा किसानों को मिला। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह गहनता से सोचने की बात है।

मैं इन पर कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं फिगर्स बता रहा हूँ। 3 लाख 11 हजार करोड़ रुपये पीएम किसान निधि के तहत प्रधान मंत्री जी ने करीब 12 करोड़ किसानों के खातों में भेजा। अगर एक परिवार में चार व्यक्ति हैं तो उससे 50 करोड़ लोग बेनिफिट हुए। सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि गरीबों के लिए भी करीब 3 करोड़ 31 लाख रूरल हाउसेज के लिए पैसा इसी टैक्स पॉलिसी से आया। वर्ष 2016 से करीब 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए, वह राशि चाहे महिला एम्पावरमेंट के लिए हो, चाहे यूथ के लिए हो। मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर यह पैसा इस टैक्स से नहीं आता और टैक्स पॉलिसी प्रूडेंट नहीं होती तो यह वेलफेयर स्कीम नहीं होती। आप जल जीवन मिशन को ही देखिए। यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है।

(1735/RAJ/VR)

आप 'जल जीवन मिशन योजना' को देखिए। यह अपने-आप में विश्व की सबसे बड़ी बात है। 'जल जीवन मिशन योजना' के तहत हर घर को टैप से पानी देने का लक्ष्य है। इससे लगभग 15 करोड़ हाउसहोल्ड्स, लगभग 60 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसका कारण क्या है? The lower tax is leading to higher collection, and more comprehensive welfare initiatives. What is the long-term vision? The long-term vision is, creating a virtuous cycle of lower taxes, higher compliances, increased revenue and enhanced welfare. All these are mixed together. This happened just because of the prudent tax policy of the Government.

मैं आपको एक छोटा-सा चार्ट बतान चाहता हूं। ये टैक्स एग्जेम्पशन की बात करते हैं। इनके समय में वर्ष 2014 तक डायरैक्ट टैक्स एग्जेम्पशन दो लाख रुपए थे, लेकिन अब वे सात लाख, 75 हजार रुपए हैं।

इनके समय में वर्ष 2009 से वर्ष 2014 पांच सालों में इंफ्रा स्पेंडिंग एक लाख, 57 हजार रुपए थे। ये वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के बीच में 44 लाख, 30 हजार करोड़ रुपए थे। आप इसमें यह

फर्क देखिए - एक लाख, 57 हजार करोड़ रुपए और मोदी जी के समय में 44 लाख करोड़ रुपए। इन्होंने वर्ष 2014 में 13 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट की और पिछले पांच सालों में 320 लाख रुपए वेल्थ क्रिएट हुई है और फॉरेक्स एडीशन 50 बिलियन। पिछले पांच सालों में 350 बिलियन, जीडीपी रैंक 10 से पांच हो गई है।

हम कई बार एंजेल टैक्स के कॉन्सेक्वेंशियल इफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। एंजेल टैक्स इन्होंने लगाया, यह समझ के बाहर की बात है। इनके बहुत बड़े फाइनैंस मिनिस्टर थे। हमारे स्टार्टअप्स इनोवेशन करते हैं। वैसे ही हमारे देश में बहुत समय से इनोवेशन बहुत पुअर था, लेकिन यह मोदी जी की सोच थी कि जब तक हमारे यहां इनोवेशन नहीं होगा, हमारे स्टार्टअप्स डेवेलप नहीं होंगे, हम रिसर्च बाहर से लाएंगे। इसलिए एंजेल टैक्स मतलब कोई फरिश्ता आकर यह लगता है। हमारे यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारा स्टार्टअप एक करोड़ रुपए लगता है और कोई इन्वेस्टर उसमें दो करोड़ रुपए लगाता है, तो क्या होता है कि कंपनी एक करोड़ रुपए की है और आपने दो करोड़ रुपए लगाए, तो आपका डिफरेंस एमाउंट एक करोड़ रुपए है, उस पर आप 30 प्रतिशत टैक्स दीजिए यानी उस स्टार्टअप को 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था, तो वह क्या रिसर्च करेगा, क्या इनोवेशन करेगा? इसमें एंजेल टैक्स को खत्म करना, यह प्रधान मंत्री जी के विजन और हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी का बहुत बड़ा स्टेप है। उस एक्सट्रा एमाउंट से स्टार्टअप अपना काम कर सकता है। अंडर सेक्शन 56 ऑफ दी इनकम टैक्स एबोलिशन ऑफ एंजेल टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ा, प्रिवियस सिचुएशन क्या थी? The Angel Tax previously discouraged investment in Start-Ups. Secondly, it created a barrier for early-stage funding in innovative companies.

Then, what is the reason for changing this tax policy? The purpose of change in the tax policy was to push investment in Start-Ups and foster innovation, and align it with the Government's vision of making India a global Start-Up hub. This is what has happened.

What are the positive impacts of it? The positive impacts are that the flow of capital increased into new business. It became easier for the Start-Ups to secure funding without tax complication. It enhanced attractiveness of Indian Start-Ups for domestic and foreign investors. More innovative ideas – now we do not require to get it from outside – have been funded and brought to the market. Finally, it grew the potential of significant job creation in the Start-Up sector.

सभापति महोदया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि it was such a small sector, and it happened within a short span of 2016 to 2019. The other data is not available, कितने जॉब्स क्रिएट की गईं? सिर्फ स्टार्टअप्स ने सात लाख, 50 हजार जॉब्स क्रिएट की। प्रधान मंत्री जी के सिर्फ इस विजन से सात लाख, 50 हजार जॉब्स क्रिएट हुईं। पहले टैक्स

था, तो आपको क्या मिला? इन्वेस्टर्स टैक्स के कारण इन्वेस्ट नहीं करते थे। आपने उसको फ्री कर दिया, तो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए और सात लाख, 50 हजार जॉब्स क्रिएट हुआ।
(1740/KN/SAN)

उसकी सक्सेस स्टोरी क्या हुई? It promoted the Indian startup ecosystem. As a result, 114 Indian unicorns have raised more than Rs. 8.3 lakh crore to date and the combined valuation of these unicorns exceeds Rs. 35 lakh crore. इनको यह कभी ध्यान नहीं आया, जो चीज ध्यान में आनी चाहिए थी। इसलिए मैं डेटा से बात कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। आप इसको रिस्पौंड करिये। इनके पास में क्या जवाब है? आज देश, जो दस साल में बढ़ा है, उसके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। पीएम साहब के दिमाग में क्या है? मैं इसे चार पॉइंट्स में बता रहा हूं।

It supports India's target of having 280 unicorns by 2030. आप देखें कि 114 unicorns में इतनी जॉब्स का क्रिएशन होता है, इतनी वेल्थ का क्रिएशन होता है तो वर्ष 2030 तक कितनी होगी? लेकिन मेरा मानना है कि वह टारगेट उससे भी पहले अचीव हो जाएगा। The next one is to position India as a leading global innovation hub. The third one is to align with Digital India and Startup India initiatives. The fourth one is to curb brain drain from India and help brain gain. It will curb brain drain क्योंकि हमारे लोग बाहर जाते हैं। These are the visions of our hon. Prime Minister. Now, they are not required to go outside. Earlier, it was brain drain and now, it is brain gain. It has been possible only on account of this innovative idea of the abolition of angel tax of 30 per cent on the startups.

Now, we have to see the economic benefits out of it. It accelerated growth of the startup ecosystem and increased innovation across various sectors, not in one sector, covering the entire country. It gave a boost to India's patent and intellectual property creation and funding for R&D. जो कि हम इसमें बहुत पीछे थे। The Government is promoting funding for R&D not by the Government, but by the investor. This is a good idea. This is the vision of the Prime Minister. That is why, we are talking about the 'Viksit Bharat' by 2047. This is the foundation laid down by the hon. Prime Minister by way of this year's Budget and the Finance Bill. Further, it has enhanced global competitiveness of the Indian companies in new technologies.

सभापति महोदया, कई बार हमारे विपक्ष के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि टैक्स के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट का पहले टाइम लिमिट था, पांच साल तक कभी भी कर लो। वह कहां से डॉक्युमेंट लाएगा, क्या करेगा? उसे

परेशानी होती थी। लेकिन वे लोग, जो कमजोर हैं, साधारण हैं, जैसे सर्विस वाले हैं, जिनकी 50 लाख रुपये से कम इनकम है, उनका पहले पांच साल में रीअसेसमेंट ओपन होता था, अब तीन साल के बाद उनका ओपन नहीं हो सकता है। अगर 50 लाख के ऊपर इवेजन है, तो उनका पांच साल के लिए ओपन हो सकता है। इसका इफैक्ट क्या हुआ? इसका इफैक्ट हुआ, पहले क्या प्रॉब्लम थी, एक टैक्स अनसर्टेनिटी थी, एक हार्डशिप थी, उसको खत्म किया। उसका फर्क क्या पड़ा? The reasons for the change are to simplify the provisions for reopening and assessment, reduce tax uncertainty and disputes, and decrease the number of litigations. That is more important because that is a consequential effect. The positive impacts are greater clarity for tax-payers on the finality of their tax assessments - and he is not in doldrums all the time as his tax assessment reaches finality - reduced hardship for tax-payers in dealing with old cases, potential decrease in tax-related stress and anxiety for individuals and businesses, potential for improved tax compliance due to reduced fear of long-term reopening of cases and, finally, ease of doing business, जो कि प्रधान मंत्री जी हमेशा चाहते हैं। जब तक हमारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस का एटमॉस्फियर नहीं होगा, तब तक यह नहीं होगा। Who are the key beneficiaries? The key beneficiaries are over 12 crore salaried employees and the micro and small businesses with moderate income.

महोदया, मैं फाइनली बताना चाहूंगा that now, there are increased monetary thresholds for tax appeals and the introduction of Direct Tax Vivad se Vishwas Scheme. उससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है, जो फ्रीवलस लिटिगेशन था, जैसे कई छोटे एमाउंट्स का था, आप पहले 20 लाख रुपये के मामले पर टैक्स ट्रिब्यूनल में चले जाते थे, अब उसको 60 लाख रुपये कर दिया है। आप हाई कोर्ट में पहले एक करोड़ रुपये के मामले पर चले जाते थे, अब उसको दो करोड़ रुपये कर दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट में पहले दो करोड़ रुपये के मामले पर चले जाते थे, अब उसको 5 करोड़ रुपये कर दिया है।

(1745/VB/SNT)

इससे जो फ्रिवोलस लिटिगेशंस हैं, उनको रोकने में मदद मिलेगी। दूसरे जो इम्पॉर्टेंट केसेज हैं, उनको तय करने में उनको मदद मिलेगी। 'विवाद से विश्वास स्कीम', 2024 है, एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो आर्बिट्रेशन कॉनसिलिएशन डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन स्कीम है, अगर उनका इंट्रेस्ट और पेनल्टी वेवर हो जाता है, अगर वे एमाउंट पे करते हैं। प्रिवियस सिचुएशन क्या थी? प्रिवियस सिचुएशन थ्रेसॉल्ड की थी, वह खत्म हो गई। अभी जो केसेज आईटी ट्रिब्यूनल्स में हैं, वे लगभग 50 हजार हैं। इससे टैक्स रेवेन्यू रुका हुआ है। अब उसको मिलने में जल्दी होगी।

सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिम्पलीफिकेशन से क्या हुआ? अगर मैं एनडीए सरकार की बात करूँ, a record of over 8.18 crore इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किये गये, ईज़ ऑफ डूइंग

बिज़नेस में जबकि यूपीए के एरा में सिर्फ 3 करोड़ 36 लाख रिटर्न फाइल किये गये। दोनों में यह फर्क है।

मेरा लास्ट पॉइंट है। There is revision and simplification of long-term capital gains tax at 12.5 per cent for all asset classes. इस पर बहुत ऑब्जेक्शंस हुए। मैंने सुना कि राज्य सभा की स्पीच में भी ऑब्जेक्शन हुआ। यहाँ पर भी लांग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बातें कही गईं। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है, for which there is no leg to stand, और एक गलत धारणा बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बहुत बढ़िया किया। कई बार लोग कहते हैं कि एक टैक्स होना चाहिए। जब 20 परसेंट टैक्स था, 10 परसेंट टैक्स था, अगर हम उसको यूनिफॉर्म करते हैं, क्योंकि इंडेक्सेशन टैक्स का बेस था। That was very, very complicated. That led to discrimination as well as arbitrariness in the hands of the authorities. दूसरा क्या किया गया? Reduction of long-term capital gains tax on immovable property 20 परसेंट से 12.5 परसेंट किया गया। पहले इममूवेबल प्रॉपर्टीज पर 20 परसेंट टैक्स था, उसको 12.5 परसेंट किया। इससे कैपिटल गेन कम हुआ, जो 10 परसेंट था, उसको 12.5 परसेंट किया गया।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार) : आप बीच में टोका-टोकी नहीं कीजिए। आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : प्रिवियस सिचुएशन क्या थी? Previously, there were different long-term capital gains rates for different asset classes. मूवेबल प्रॉपर्टी में सारे की थी। It was having a confusion. Secondly, there is 20 per cent long-term capital gain on immovable properties. There are different slabs for movable properties. Coming to complicated indexation process leading to tax inaccuracies and litigation for common man, अब अगर हम इसका ग्लोबल कांटेक्स्ट देखें, as we have to learn so many things from other countries, आप देखें कि आपका टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ग्लोबली देखिए। आप एडवांस्ड कंट्रीज में देखिए, डेवलप्ड नेशंस में देखिए, अंडर डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस को ज्यादा पैसे चाहिए। अगर आप ग्लोबल कांटेक्स्ट में देखें, तो चाइना का 20 परसेंट है, हमारा 12.5 परसेंट है, यूएसए का 20 परसेंट है, हमारा 12.5 परसेंट है, जर्मनी का 26.83 परसेंट है, हमारा 12.5 परसेंट है, टर्की का 40 परसेंट है, हमारा 12.5 परसेंट है, फ्रांस का 30 परसेंट है, ब्राजील का 22.5 परसेंट, स्पेन का 28 परसेंट और इज़रायल का 25 परसेंट है। इस तरह से, सबसे कम टैक्स इंडिया में है, जो 12.5 परसेंट है। इसके लिए इन्होंने बहुत ही लम्बा-चौड़ा ऑब्जेक्शन किया।

इन्होंने कहा कि यूरोप-लाइक टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया है। ऐसा अपॉजिशन के हमारे कई नेताओं ने कहा। अगर यूरोप-लाइक स्ट्रक्चर होता, तो टर्की में 40 परसेंट था, हम 12.5 परसेंट नहीं रखते। यहाँ का भी 40 परसेंट जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि lower the tax, and more the gain to the Government. Those amounts to be utilised for the

welfare schemes, for the poor, farmers, women, youth, and infrastructure of the country. आप रीजन देखिए। इसका बेसिक रीजन यह था कि simplify tax calculation process. इंडेक्सेशन का बहुत ही कांप्लीकेटेड था, अलग-अलग जगहों पर डिफरेंट था। इससे किसी को फायदा होता, किसी को नुकसान होता। Next is, 'promote longer holding periods for home buyers and middle-class and align taxation across asset classes'. अब अगर आप रीयल स्टेट मार्केट कांटेक्स्ट में देखें, तो Income Tax Department assumes 12-16 per cent compound annual growth rate on real estate returns over 15-20 years, which is common. Most major cities like Bengaluru, Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata, etc., show growth rates between 12 and 16 per cent over 15 years.

(1750-1800/SRG/IND)

इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? There will be lower tax burden for long-term property investor and encouragement for holding properties for longer periods.

I am completing within 15 seconds. Now, there is stability in the real estate market due to longer holding period. अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इससे सबको समझ में आ जाएगा। ओल्ड रेट 20 परसेंट था, जो कि टैक्स-विद-इंडेक्सेशन था। अब न्यू रेट 12.5 परसेंट टैक्स है, जो कि विदाउट इंडेक्सेशन है। अगर दोनों में प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ 27 लाख रुपए है, तो आप देखेंगे कि इंडेक्स उसका टैक्स 1 करोड़ 50 लाख रुपए बनता है और टैक्सेबल-गेन से 4 करोड़ 77 लाख रुपए बनता है। टैक्स-गेन कितना हुआ? अगर 20 परसेंट वाले से बताएं, तो 3 करोड़ 77 लाख रुपए हुआ। अगर हम टैक्स-एट 12.5 परसेंट गिनें, 20 परसेंट से गिने हैं, तो उसका करीब 75 लाख रुपए टैक्स बनेगा और 12.5 परसेंट से गिनें, तो 59 लाख रुपए टैक्स बनेगा। 12.5 परसेंट टैक्स होने की वजह से टैक्स-पेयर को नेट-सेविंग 15 लाख 80 हजार रुपए की सेविंग होगी। अगर वैल्यू 5 करोड़ 27 लाख की प्रॉपर्टी है और अगर 20 परसेंट टैक्स होता, जो कि ओरिजनल था, वह कम नहीं होता, तो उसमें टैक्स-पेयर के 15 लाख 80 हजार रुपए ज्यादा लगते। अब 12.5 परसेंट टैक्स होने से, टैक्स-पेयर के 15 लाख 80 हजार रुपए कम लगेंगे।

With these words, मैं फाइनेंस बिल को सपोर्ट करता हूं। मैं सभी मेंबर्स से कहता हूं कि वे भी इसको सपोर्ट करें।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1752 hours

*SHRI K. E. PRAKASH (ERODE): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity for allowing me to speak on Finance Bill for the year 2024-25. I am a farmer's son and I could become the member of this august House. I thank Hon Chief Minister of Tamil Nadu *Annan* Thiru M.K. Stalin, Hon Minister of Youth Welfare and Sports Affairs in Tamil Nadu and the Youth Wing Secretary of DMK, Thiru Udhayanidhi Stalin and the voters of Erode parliamentary constituency, which is the birthplace of *PakuthaRivu Pakalavan* Thanthai Periyar. I begin my maiden speech by bowing before Perarignar Anna, *Muthamizh Arignar* Dr Kalaignar and Thiru Murasoli Maran the conscience of Dr. Kalaignar. The Budget of 2024-25 of this minority Union Government is very much disappointing. This Budget, I should say, is completely against the interests of the people of Tamil Nadu. This Budget is presented to appease the coalition parties of the ruling BJP Government. This Budget lacks farsighted vision and clarity. Hon Finance Minister usually cites a Tirukkural while presenting the Budget. But that is missing this time. Tamil Nadu is not even having a mention in this Budget. India is facing unemployment problem in an unprecedented manner never seen in the last 45 years. Prime Minister calls himself as the child of God. He has created the worst unemployment situation in the country which was unseen in the last 45 years. Hon Modi gave so many electoral promises before 10 years. Make in India, Amrit Kaal, depositing Rs 15 lakh in the bank accounts of every Indian citizen are some of those promises. But the data says that only the Swiss Bank accounts are flooded with money more than before. BJP Government has waived off several lakhs of Crores to the Corporate Companies. I have not seen this Government making any initiative to waive off the educational loans of students or farm loans availed by farmers. Many farmers have committed suicides last year. Hon Prime Minister announced in the year 2016 that the income of farmers would be doubled. The achievement of this Government is the deaths of farmers. Union Government has not fixed the remunerative price or the MSP for the

* Original in Tamil

agricultural produce. As usual the Union Government has not allocated money to Tamil Nadu under Sarva Shiksha Abhyan. Union Government is adamant and threatening with the condition that only when National Educational Policy is implemented, there will release of funds for the state of Tamil Nadu. GST has already snatched away the taxation rights of the State Government. GST paid by the people of Tamil Nadu is being utilized throughout the country. If we pay Rs. 100, only 29 Paise is given back to Tamil Nadu. The rest of the amount is being distributed with other states of the country. If you give all that money to us, we could provide a good governance in the State of Tamil Nadu. As mentioned by my brother Shri Arun Nehru, the Chennai Metro Rail Scheme has been kept pending for the last 3 years. Hon Union Home Minister came for the inaugural function. But till now you have not given any fund allocation to this Scheme. You have not even made any announcement regarding any new metro rail project for the State of Tamil Nadu. Under the able Government run by Hon Chief Minister of Tamil Nadu, besides financial crunches, after 3 years of rule, has provided Rs. 4000 to each of the 2 crore families as corona relief assistance. It was to the tune of Rs. 8000 crore. Every month the head of the family i.e. a woman is provided Rs.1000 per family as monthly financial assistance called the 'Women Rights grant' or the Makalir Urimaith Thogai. Free bus rides, has provided today approximately bus rides to 500 crore women of Tamil Nadu. This free bus ride for women is one of the pioneering programmes of the Government of Tamil Nadu. Morning Breakfast is being provided to approximately 20 lakh students and children during morning by the hon. Chief Minister. *Naan Muthalvan* Scheme, *Tamizh Muthalvan* Scheme, *Kalaignarin Kanavau Illam*, are some of the Schemes which benefit every poor family of Tamil Nadu. Under the Kalaignar Dream House Scheme, houses at the cost of Rs. 3 lakh are provided to each of the poor families of Tamil Nadu. Immediately after coming to power, he made the first announcement of building a Multi Super Speciality Hospital in Chennai of Tamil Nadu. At a cost of Rs. 250 crore this Super Speciality Hospital was set up within in one year. AIIMS is kept pending in Madurai for the last 10 years. For other States of the country, you completed the setting up of AIIMS was

on priority basis done by you. Only a brick was there in Madurai, Tamil Nadu. Other than this, no action has been taken by the Union Government. Hon Chief Minister of Tamil Nadu has done the best to attract the industrial investments to the tune of Rs. 7 lakh crore. Even at times of financial distress faced by the State Government, Tamil Nadu government is excelling in all fields. When Tamil Nadu was affected by floods, you the BJP Government has not done any help to the people of Tamil Nadu whereas our Chief Minister of Tamil Nadu Annan Thiru M.K. Stalin has provided Rs. 6000 each to the affected families of Chennai, Thoothukkudi, and other areas of Tamil Nadu. Similarly, during the regime of *Muthamizh Arignar* Dr, Kalaignar, the free electricity Scheme announced for the farmers was implemented besides financial crisis and this Scheme has been implemented for the farmers till today for the last 35 years. Even this year hon. Chief Minister of Tamil Nadu has provided free electricity to 2 lakh farmers even between the financial crunches faced by the State of Tamil Nadu. Similarly, the Union Government has reduced the allocation for farmers to 2.75 per cent from 5 per cent. Union Government is aimed at blocking the development of agriculture and farming. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu is heading a democratic government for the welfare of the voters who voted him to power and those who did not vote for him. But you are running a Government which is anti-people. When Tamil Nadu asked for Rs. 37,000 crore as disaster relief fund, you have released an amount which is just Rs. 500 Crore. You did not provide Rs. 37,000 crore which was the demand for disaster relief. Without consulting the Stages, the announcement for reducing Stamp Paper duty was made by you which hampered the rights of the States. You have snatched away the rights of States. You have not provided Rs. 20,000 Crore as GST compensation. But who gave the Union Government the right to restructure the tax system? You said that the last 10 years of your rule was just a trailer and the main film is yet to come

HON. CHAIRPERSON (DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR): Please wait for a minute. The House is extended for an hour with the consent of the members.

*SHRI K.E. PRAKASH (ERODE): The people of Tamil Nadu have not given victory in a single seat to BJP. BJP faced defeat in almost all 40 constituencies of Tamil Nadu and Puducherry. Do not ever imagine to destroy the opponents. There is a proverb in Tamil which says we should not live in a place where there is no enemy. But when you want to grow you need enemies. For a nation to prosper, you should fully recognise the opposition parties. This is the old proverb of ancestors of Tamil Nadu. Erode is my parliamentary constituency. There is no new Scheme that was announced for Erode in this Budget. I condemn and express concern on behalf of the people of my Erode constituency for not announcing anything for Erode in this Budget. “This country is ours and all 40 seats are ours” is the motto claimed by our Hon Chief Minister of Tamil Nadu who is spearheading the Dravidian Model of Governance in Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu gave a historic mandate in Tamil Nadu giving all 40 seats to the Dravidian Model of Governance. But the Union Government has not treated all the States as equal. Everything is for everyone is the motto of our Dravidian Model Government and it is treating all the people as equals.

Finally, I want to say one this. This Budget 2024 may protect your Government in power. But it will not protect the country. Let the Government to function on its own way. Do not act in such a vengeance attitude against those States which defeated you in the just concluded elections. This was the warning given by hon. Chief Minister of Tamil Nadu. I wish to remind his words and conclude my speech. The Second freedom struggle against you by the INDIA Alliance has just begun. Tamil Nadu is celebrating a single brick which is raised against you.

But you are holding the *Sengol*, the sceptre and ruling in anarchical way. Thank you.

(ends)

1802 hours

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): Sir, thank you for this opportunity. While our country is soon becoming the third largest economy, we, the representatives of the House of the People, should observe that 77 per cent of the total national wealth is with 10 per cent population, and only 23 per cent of the wealth is with the remaining 90 per cent population. The issue of inequality between the rich and the poor has to be addressed. Necessary steps have to be taken to ensure that poor people grow wealthier in our country, and only then becoming the third largest economy soon will have some meaning and sanctity.

Coming to income tax, the share of individual income tax payer in GDP has increased from 2.5 per cent in 2017-18 to 3.64 per cent in 2024-25. A comparison with the other BRICS economies shows that effective personal income tax rate in India is among the highest. Section 80D of the Income Tax Act allows tax deductions of up to Rs. 25,000 every financial year on health insurance premiums. This deduction limit has remained the same for the last 10 years. While on the other side, the medical expenses of every individual are growing in a very big way for the last 10 years. So, to address this issue, necessary steps have to be taken to enhance this deduction limit up to Rs. 1,00,000 per financial year on health insurance premiums keeping in view the increased medical expenditure.

(1805/RCP/RV)

The new tax regime curtails several important tax deductions leaving people disincentivised for switching from the old regime. Deductions under Sections 80C, 80D and 80E and various other deductions are not permitted under the new tax regime leaving the middle-class people and the poor people dissatisfied and in financial stress and strain.

Coming to indirect taxes and GST, indirect tax collections are increasing year by year. The Government has been seeing required GST collections with a significant increase in July, 2024 totalling an amount of Rs.1,82,075 crore marking a 10.3 per cent rise compared to July 2023 which was Rs.1,65,000 crore. Given these high collections, now the Government should come forward and consider reducing or exempting GST rates on

certain basic goods and services which are commonly consumed by the poor and the middle class. On behalf of the weavers, I request the Government to exempt five per cent GST on the raw material used by the weavers. The fishermen are making a request for a long time for GST exemption on components used for making fishing nets including nylon towing ropes and floats.

As you very well know, the farming community is in severe distress. We have to address the issues of the farming community. A new Act has to be introduced in this House fixing MSP for all the crops produced by the farmers in this country. More importantly, to promote farm mechanisation and to support farmers, GST should be exempted for all farm supplements.

More importantly, 18 per cent GST is collected on health insurance premium and life insurance premium. We strongly request the Government to withdraw GST on life insurance premium and health insurance premium.

Coming to our State, Andhra Pradesh, our former Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu requested the hon. Prime Minister several times to grant special category status to Andhra Pradesh as was promised in this House by the then Prime Minister Shri Manmohan Singh ji. We strongly urge upon the Government to grant special category status to Andhra Pradesh and fulfil the promise made in this House. In the AP Reorganisation Act, establishment of a steel plant at Kadapa was promised to us. We strongly urge upon the Government to establish the steel plant at Kadapa. In the same AP Reorganisation Act, a railway zone at Visakhapatnam was assured to us. We urge upon the Government to implement its promise.

More importantly, we request the Government to withdraw its plan to privatise Vizag Steel Plant.

Once again, thank you for giving me this opportunity.

(ends)

(1810/PS/GG)

1810 hours

*SHRI SACHITHANANTHAM R. (DINDIGUL): My salutations to this august House including the hon. Chairperson. I wish to say my views on the Finance Bill on behalf of the Communist Party of India (Marxist). The fund mobilization programme of this Government is not in the interest of the people or the nation at large. This seems to be in the interest of the corporates. During the 1950s and 1960s, the corporate tax occupied the predominant place in the tax collection followed by income-tax and then by indirect taxes. Later, the indirect taxes, which were in third place, climbed up the ladder to occupy the first place. During the last 10 years of Shri Narendra Modi-led Government, the corporate tax collection declined and went to the third position and the credit for this goes to the hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman. As regards GST, 10 percent of the rich persons pays a GST of three per cent whereas 50 per cent of the poor pays a GST of 66 per cent. I wish to bring to your notice that the poor and the common people constitute most of the taxpayer base of the GST in India. Concessions were given for those who join the new tax regime. It means the old tax regime will be gradually closed. Giving up the old tax regime means giving up the savings and the encouragement extended to save. Just this encouragement helped to have more domestic savings in the country. This helped in boosting the domestic industrial growth. As much as Rs.11 lakh crore has been provided for the industrial growth. But the old tax regime, which encouraged savings in the country, is not given any new concessions. This will hamper our domestic savings as well as the industrial growth. Not only have the MPs urged upon you to give up the GST on Life Insurance and Medical Insurance policies, but also the senior-most Minister in your Cabinet Shri Nitin Gadkari has also written a letter in this regard. You have not taken into consideration the views of the people of this country. You have not accepted the views of 235 MPs in this House. But you have not even accepted the viewpoint of a senior Minister of your own party. For whom are you running this Government? There is a demand throughout the world for imposing wealth tax. In the G20 nations too, there is a consensus on taxing the super-rich. In France the inheritance tax is 60 per cent. In Japan it is 55 per cent. In Germany, the inheritance tax is 50 per cent. In Britain it is 40 per cent. I wish to say that in India not even one per cent inheritance tax is levied and the Government is not intended to levy this inheritance tax. You have reduced the corporate tax from 40 per cent to 35 per cent. You have disclosed who your boss is. I urge that the corporate tax should be increased. The ways and means to levy inheritance tax should also be considered. You should ponder over taxing the super-rich. You should give concessions to those in the old tax regime and encourage domestic savings in the country. The GST on Life Insurance and Health Insurance policies should be withdrawn.

* Original in Tamil

I will just explain a story and conclude my speech. A farmer who was in distress wanted to meet his family astrologer. After seeing his horoscope, that astrologer came to know that the farmer will die at 8 pm on the same day. But without saying this to the farmer, the astrologer wanted him to meet the next day. While returning, there was heavy rain and cyclone, the farmer had to enter a temple of Lord Shiva to save himself from nature's fury. Since he was inside the temple, he did not die. He was saved by God. Like the heavy rains and cyclones, the Telugu Desam Party and the Janata Dal United have brought this Government to this temple of democracy, the Parliament. This is temporary. Your days are numbered. If your policies are not changed for doing all good to poor, if this BJP Government continues to take a stand favouring the corporates, the people of this country will not forgive you. I wish to register here that your regime will come to an end very soon. As regards this Finance Bill, there is no fund mobilisation policy or announcements for the poor. Therefore, all the Opposition Parties in this House have urged that there should be announcements benefitting the poor. But this Government is not paying attention to such demands. Many MPs said here that if Prime Minister Modi does not return to power, there is no one to save our country. I must say only the corporates were saved during the last 10 years of Modi Government. I urge upon this Union Government that this Budget should be aimed at protecting the welfare of the poor people of our country. This is a Budget which is anti-labourers, anti-poor and anti-people. The objective of this Budget should be changed. The tax system should be changed. Poor-centric programmes should be implemented. In States like Tamil Nadu, several schemes are implemented for the welfare of the poor people. Many schemes, including the Morning Breakfast Scheme, are being implemented in Tamil Nadu. I urge that the Union Government should also implement similar programmes throughout the country taking cue from Tamil Nadu. There should be adequate importance given to education. This Government should try to bring several programmes for the welfare of poor people in the country. Our general insurance … (*Interruptions*)

Three companies are looking after the general insurance in the country. I urge that these three companies should be merged as one. GST exemption should be given for Life Insurance and Health Insurance Policies. I want you to rethink and reconsider withdrawing the taxation of the base and raw material for agriculture and farm products. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

(ends)

(1815/MY/SMN)

1815 बजे

श्री तनुज पुनिया (बाराबंकी) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका दिया और वह भी इस अहम फाइनेंस बिल, 2024 पर बोलने का मौका दिया। यह बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं देवा- महादेवा की पावन धरती बाराबंकी से आता हूं। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के वोटर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया है।

महोदय, उत्तर प्रदेश को हम लोग राम जन्मभूमि के नाम से बुलाया करते हैं। लेकिन, हम अक्सर भूल जाते हैं कि यह भगवान श्रीकृष्ण की भी जन्मभूमि है। भगवान श्रीकृष्ण गायों के बीच में खेला करते थे। वह मक्खन खाने के बहुत शौकीन थे। आज इस युग में अगर वह दोबारा प्रकट हो जाएं तो शायद मक्खन न खा पाएं, क्योंकि मक्खन पर 12 परसेंट का टैक्स इस सरकार ने लगाने का काम किया है। दूध के जितने भी आइटम्स हैं, उनके ऊपर 5 परसेंट से लेकर 12 परसेंट तक का टैक्स लगाया गया है। आम आदमी अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहता है, पनीर खिलाना चाहता है, वह अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है, वह बहुत ही निंदनीय है। आप नई टैक्स रिजीम लेकर आए हैं। साथ-साथ पुरानी टैक्स रिजीम भी चल रही है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि पुरानी में जाएं या नई में जाएं। उसमें अलग कंफ्यूजन है कि आप एक बार बदल लीजिए, उसके बाद वापस आ जाइए। उसके बाद दोबारा आप उसमें चले जाइए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रोक लगी है, नहीं रोक लगी है, यह बड़ा कंफ्यूजन सा है। अगर आपको टैक्स रिजीम रखनी ही है तो कंफ्यूजन हटाकर एक ही रखें।

महोदय, यह जो नई टैक्स रिजीम है, इसमें जो सेविंग्स हैं, उसको आपने इंसेंटिवाइज करने का काम नहीं किया है। उसको बिल्कुल आम आदमी के भरोसे छोड़ दिया है कि आपको जो सेव करना है, वह आपकी जिम्मेदारी है। वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पुरानी टैक्स रिजीम में इनके इंसेंटिव्स दिए जाते थे। देश में बचत दर बढ़ रही थी, बचत हो रही थी, लेकिन क्या सरकार ने सोचा है कि जो आम आदमी है, मिडल क्लास है, वह बचत करना कम कर देगा तो उससे हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। हमारी जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, अगर मैं डोमेस्टिक सेविंग्स की बात करूं तो हमारे प्राइवेट लोगों की भी और सरकार की भी जो वित्तीय आवश्यकता है, उन सबको यह पूरा करता है। सरकार का जो ऋण है, वह 95 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय मुद्रा में है। अगर यह सेविंग्स कम होती चली गई तो फिर इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, क्या सरकार ने इसके बारे में सोचा है?

महोदय, इस बार जो टैक्स स्लैब दिया गया है, उसमें बहुत ही मामूली राहत मिडल क्लास को दी गई है। मिडल क्लास यह सोच कर बैठा था कि हमारे लिए सरकार कुछ करेगी। बहुत सालों से उसकी आस थी, लेकिन हर बार उसको झुनझुना पकड़ाने का काम सरकार ने किया है। इस बार तो खास तौर से उन्होंने जो मामूली बदलाव किया है, उससे कोई ज्यादा फायदा मिडल क्लास

तक नहीं पहुंचा है। इसके साथ-साथ हमारे जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो शायद टैक्स ब्रैकेट में भी नहीं आते हैं, पिछले छह सालों में उनकी आमदनी जो फ्लैट हो चुकी है, उसमें कोई बढ़ावा नहीं हुआ है। उसके बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात ही नहीं की है। उनकी आमदनी को बढ़ाने की कोई बात नहीं हुई है। क्या हमारे देश का मजदूर इसी तरह से मायूस होता रहेगा? हमारे देश में कई सालों से, खासतौर से वर्ष 2018 या 2019 से कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स में भारी छूट दी गई। वह 30 परसेंट था, 25 परसेंट हो गया, कुछ सेक्टर्स में 22 परसेंट हो गया। उनका कर्जा भी माफ किया गया। लेकिन हमारे किसानों, मिडल क्लास और मजदूरों से ऐसी कौन सी गलती हो गई, जो उनके बारे में आज तक सोचा ही नहीं गया? बहुत ही मामूली सी राहत देते हैं, वह एक तरह से झुनझुना पकड़ाने का ही काम है। इंडेक्सेशन के बारे में कई बातें हुईं। हमारे जो आम आदमी हैं, खासतौर से जो किसान वर्ग है, वह एक प्रॉपटी लेता है। वह सोचता है कि आगे अगर कोई वित्तीय संकट हमारे ऊपर आया तो हम इसको बेच करके उससे बाहर निकलेंगे।

(1820/CP/SM)

अगर हमारे घर में बेटे-बेटी की शादी हुई, तो पैसा कहां से आएगा? इसके लिए वह प्रॉपर्टी रखता है। इंडेक्सैशन को हटाकर एक बहुत बड़ा प्रहार हमारे किसानों और मिडल क्लास के ऊपर किया गया है। … (व्यवधान) अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ा फासला आज के समय हो गया है। जो गरीब है, वह गरीब होता चला रहा है और जो अमीर है, वह अमीर होता चला जा रहा है। पूरे देश की जो सम्पत्ति है, पूरे देश का जो पैसा है, वह चंद लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। अमीरों को, बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स को, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीतियां बन रही हैं। उनके टैक्स को बार-बार कम किया जा रहा है। गौर फरमाने की यह बात है कि किसान से किस तरह की वसूली आज हो रही है। किसान की खेती-बाड़ी के जो उपकरण हैं, ट्रैक्टर और उसके पुर्जे हैं, फर्टिलाइजर है, इन सबके ऊपर भारी जीएसटी लगा हुआ है, भारी टैक्स लगा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। वसूली कर रहे हैं, लेकिन देना नहीं चाह रहे हैं।

मैं खाद के ऊपर अगर बात करूं तो केवल 5 पर्सेंट जीएसटी है। लेकिन, उसके रॉ मैटेरियल्स की तरफ किसी ने देखा, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे रॉ मैटेरियल्स के ऊपर 18 पर्सेंट तक का जीएसटी लगा है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने यह रिकमेंड किया कि इससे जीएसटी हटना चाहिए। जीएसटी काउंसिल में भी प्रपोजल गया कि यह टैक्स हटना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बार भी हमारे किसानों को मायूस होना पड़ेगा। किसान की आय क्या ऐसे दो गुनी होगी? आप बार-बार किसान की आय दो गुनी करने की बात करते हैं। अगर किसान की आय दो गुनी हो भी गई तो खर्च चार गुने बढ़ जाएंगे।

चूंकि किसानों की बात हो रही है तो मैं बाराबंकी की बात कर लूं। बाराबंकी में एक फसल मेंथा होती है। यह फसल बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होती है। इससे पिपरमेंट का तेल, मेंथा का तेल निकलता है। वह तेल टूथपेस्ट्स में, चॉकलेट्स में, दवाइयों में, फार्मास्युटिकल्स में हर जगह इस्तेमाल होता है। हमारा जो किसान मई, जून, जुलाई की कड़कती गर्मी में इस फसल को पैदा करता है, उसकी फसल पर 12 पर्सेंट जीएसटी लगाते हैं। टैक्स लगाने से हमारे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सिंथेटिक मेंथा, जो विदेश से आता है, खास तौर से चीन से आता है, उस पर भी 12 पर्सेंट जीएसटी है और हमारे किसानों के ऊपर भी 12 पर्सेंट जीएसटी है। इसके बारे में कई बार बहुत सारे माध्यमों से अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो बुनकर भाई हैं, उनके सूत के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, उनके धागे के ऊपर टैक्स लगा हुआ है और हैंडलूम के ऊपर पहली बार इस सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज हकीकत यह है कि चाइना से पुर्जे उठाकर यहाँ लाये जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर उनको जोड़कर, असेंबल करके, उनके ऊपर मेक इन इंडिया का ठप्पा लगाकर बेचा जा रहा है। हमारे देश में आज मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर असेंबलिंग हो रही है। हमारे देश में जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो छोटे उद्योग का काम करना चाहते हैं, उन सबका क्या होगा? क्या वे सिर्फ असेंबल करते रह जाएंगे? ई-कॉमर्स के बारे में मैंने अभी आपके विधेयक में देखा, जो इक्वेलाइजेशन लेवी जो 2 परसेंट की लगी थी, वह हटा दी गई है। यानी कि जो नॉन रेजीडेंट यहाँ पर हमारे ई-कॉमर्स की कंपनी खोलना चाहते हैं, उनके ऊपर अब लेवी नहीं लगेगी। हमारे डोमेस्टिक जो ई-कॉमर्स करने वाले हैं, उनको इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं।

एक्साइज ड्यूटी की बात करूं तो पेट्रोल, डीजल के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मुख्य रूप से मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस बार जो यह बिल आया है, उसमें पुराने वर्षों से कोई ऐसी नई बात नहीं दिखी। आम आदमी के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया है। केवल बड़े-बड़े जो इनके उद्योगपति दोस्त हैं, उन्हीं को फायदा पहुँचाने के लिए यह फाइनेंस बिल आया है। हमारे मजदूरों को, हमारे भाइयों को, हमारे किसानों को बहुत सारी उम्मीदें थीं। उम्मीदें बहुत बड़ी थीं, इसलिए निराशा भी बहुत बड़ी है। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। जय हिन्द।

(इति)

(1825-1830/SK/NKL)

1825 hours

*DR. D. RAVI KUMAR (VILUPPURAM): Vanakkam. Thank you for allowing me to speak on this Budget. This Finance Bill specifies how the funds will be distributed among the States of the country. The Finance Commission decided on the devolution of funds to each of the States. It was decided at the 13th Finance Commission that 32 per cent will be the devolution of funds to the State. The same was 42 per cent during the 14th Finance Commission. But out of which only 41.5 per cent was provided. Now in the 15th Finance Commission it was decided to give 41 per cent to the States of the country. Till now only 40.1 per cent has been distributed among the States. Through this, an amount of Rs.1,20,000 crore, which were to be distributed among the States by the Union, is left out. During the period of the 16th Finance Commission, I urge that the left-out amount should be included in the devolution of funds to the States. Then, while calculating the amount of funds to be distributed to the States, the Cess and Surcharge are not included. As per the decision taken during the year 2000, this practice is in place since last 20 years or more. Now this volume has grown up. During 2014-15, when the BJP came to power for the first time in the country, the collection of this Cess and Surcharge started increasing year after year. During 2014-15 through cess and surcharge, an additional tax to the tune of Rs.1,19,000 crore was collected. During 2023-24, in the last Budget, under the Revised Estimates, Cess and Surcharge collected stood at Rs. 5,10,000 crore. Out of the total tax receipt, this collection of cess and surcharge has risen up to 14.8 per cent. This is a tactic used to dechannelize the funds that are otherwise to be distributed to the States. These Cess and Surcharge are collected in the name of education, health as well as GST compensation. But the tax for which it was collected is not utilized for that purpose. The cess or surcharge collected for education or health is spent on some other fields. Therefore, in the days to come, while deciding the amount to be distributed to the States by the 16th Finance Commission, I request that the Union Government should take a call in giving the share to the States on the cess and surcharge collected by the Union Government. Only when the devolution of funds is done in a proper manner, the States can be ruled by the respective Governments with better fiscal prudence. In the case of Mineral Authority of India Vs Others, the hon. Supreme Court on 25th July 2024 has given an important verdict. This verdict explains in detail about the

* Original in Tamil

fiscal federalism. The Union Government should take this into consideration. Only by protecting the fiscal federalism, you can protect the unity of our country; you can protect the integrity of our country. You have to learn lessons from the neighbouring country. If the people in the States are deprived of so many things, and if their voices rise up, it will be dangerous to the integrity of India. Therefore, you should properly uphold fiscal federalism. There is an important issue which I expected from this Budget as it was mentioned in the Interim Budget presented by this Government before the elections. Our Indian women die in large numbers due to cervical cancer; probably their death rate is higher when compared to other nations of the world. This is not a pride for India. We are losing at least 1 lakh women due to cervical cancer every year in our country. I raised a question in this regard during the 17th Lok Sabha and got a reply from the Government. Every year this number is on the rise. Earlier there was no vaccine for this. But now HPV Vaccine is found to be effective. The Serum Institute of India headed by Poonawalla has launched HPV Vaccine in India for controlling the cervical cancer. They were the one who manufactured vaccines during the COVID-19 pandemic. This vaccine at a lower cost can be included in the Universal Immunization Programme. I have stressed about this even during the 17th Lok Sabha. During the Interim Budget presented by the previous Government before the elections, there was a mention about the consideration of my demand. I was expecting an announcement about this in the current Budget. But no such announcement was made. The HPV Vaccine meant for preventing cervical cancer should be included without fail in the Universal Immunization Programme because one lakh women are dying every year due to this type of cervical cancer. I urge that the Union Government should come forward to prevent such deaths. This is a demand pertaining to my constituency. The hon. Finance Minister is very well aware of Viluppuram Constituency as she had her primary education in Villuppuram. That is why, the hon. Finance Minister is very much affectionate about Viluppuram. When I became an MP in 2019 for the first time, I placed a demand before her. The labourers, who are engaged in jewellery making, are in large numbers in my Viluppuram Parliamentary Constituency. Viluppuram stands at number two as far as jewellery making in Tamil Nadu is concerned. I demanded for setting up of a Jewellery Park in Viluppuram. The hon. Finance Minister had assured to look into this demand. Now five years have passed. Through you, I request the hon. Finance Minister to kindly consider setting up of a Jewellery Park at least this time in Viluppuarm. Thank you. Vanakkam.

(ends)

1832 बजे

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरकार हमसे खजाने की चाबी मांग रही है कि खर्च करने के लिए खजाने का पैसा दिया जाए। क्या इसलिए खजाने की चाबी दी जाए ताकि आम जनों के हित में, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उनमें भारी कटौती करके दोनों हाथों से अपने कॉरपोरेट मित्रों पर धन की वर्षा कर सकें। इसके लिए तो चाबी नहीं दी जाएगी।

इस देश में करोड़ों दलित, आदिवासी, भूमिहीन, जमीन के अभाव में समुद्र, नहर, सड़क, पोखर के किनारे झोंपड़ी बनाकर, पोलीथीन तानकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम रॉकेट की गति से विकास कर रहे हैं। जिन लोगों का इस देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भारी योगदान है, वे खेतों में काम करके अनाज पैदा करते हैं और देश का पेट भरते हैं। वे बड़े-बड़े कल-कारखानों की चिमनियों से धुंआं निकालकर उत्पादन में सहयोग देते हैं। वे मेहनत करके सुंदर सड़कें बनाते हैं और ऊंची गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं। वे पूरे देश को अपने श्रम से स्वर्ग बना रहे हैं, लेकिन उनको रहने के लिए नर्क में जगह मिली है। उस नर्क में भी उनको शांति से रहने का अधिकार नहीं है। विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर हमेशा उनकी झोंपड़ियों पर बुल्डोजर चलाया जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश में भूमि सुधार कानून लागू करे।

(1835/KDS/VR)

बिहार में वर्ष 2010 में भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ था। जिस आयोग ने कहा कि 21 लाख 85 हजार एकड़ जमीन सीलिंग से फाजिल जमीन है, सरकारी जमीन है, जिस जमीन पर भू-माफियाओं का रायफल-बंदूक के बल पर कब्जा है। इस जमीन को भूमिहीनों में बांटना चाहिए। आयोग की यह भी सिफारिश थी कि बटाईदारी पर ज्यादा खेती हो रही है, इसलिए इसी बजट का लाभ दिलाने के लिए बटाईदार किसानों को पहचान-पत्र दिया जाए। यह केवल बिहार की बात है, पूरे देश में करोड़ों एकड़ ऐसी सरकारी जमीन और सीलिंग जमीनें होंगी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि देश में भूमि सुधार लागू किया जाए और भूमिहीनों को खेती लायक जमीन दी जाए।

महोदय, दूसरी बात, 11 करोड़ निवेशकों के ढाई लाख करोड़ रुपये सहारा इंडिया में जमा है। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई। यह गरीबों का पैसा है, देश के मध्यम वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपनी बहन-बेटियों की शादी के लिए, बाल-बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने संकट के दिनों के लिए वह पैसा जमा किया था। ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। यह दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी-डोहनी करने वाली महिलाएं हैं,

शहरों में जो झाड़ू पोंछा का काम करती हैं, रिक्शा, टैम्पो, ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वे सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते। वे गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं, जो सहारा इंडिया का है और जिसके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि यह पैसा एजेंटों के मार्फत निवेशकों को दिलवाया जाए। उनके पेट पर लात पड़ रही है। उनकी रूह कुढ़ती है, जब वे हमसे कहते हैं। तीसरी बात, हमारे आरा संसदीय क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती हो रही है। जब पावर इतनी पैदा होती है, तो यह कटौती क्यों? आधा घंटा बिजली रहती है, 3 घंटा गायब। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो एक हफ्ते में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जर्जर तारों के गिरने की वजह से कितने गरीबों की मौत हो गई। जबरदस्ती गांव की लाइन काटने का दबाव डालकर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अभी बराखरौनी, शाहपुर में एक गांव है, वहां यह प्रयोग चला। स्मार्ट मीटर लोगों का खून चूस रहा है। आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जनता पर दबाव न दिया जाए। भारी बिजली का बिल आ रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा महंगी दर पर बिजली मिल रही है। इस पर रोक लगाई जाए और हमारे यहां लोग कह रहे हैं कि पावर मिनिस्टर क्या हारे, जिले की पावर चली गई। इस पर रोक लगाई जाए।

महोदय, अंत में कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार में 30 लाख खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। यह ठेका प्रथा खत्म की जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार भी ठेके पर चलने लगेगी। अगर ठेका प्रथा पर रोक नहीं लगाई गई, तो सरकार भी ठेके पर चलेगी, इसलिए इस पर रोक लगाएं। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जितने स्कीम वर्कर्स हैं, उनको सरकार स्थायी करे, उनका वेतनमान तय करे और जो चार श्रम कोड मजदूरों के खिलाफ लाए गए हैं, उनको सरकार रद्द करे। आरा में आधुनिक सुविधाओं से हेली एम्बुलेंस सहित एक ट्रामा सेंटर का इंतजाम किया जाए और माननीय प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया था कि डालमिया नगर में जो कारखाना बंद हो गया है, वहां रेल फैक्ट्री लगाई जाएगी। उसे लगाया जाए। इंदुपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण और नहरों का आधुनिकीकरण किया जाए। नवीनगर की इकाइयों के सीआरएस फंड को स्थानीय विकास में इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद।

(इति)

(1840-1845/SJN/SNT)

1840 hours

*SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Vanakkam. Thank you for this opportunity to speak on the Finance Bill of 2024-25. The BJP is not following justice while doing the allocation of funds. There is partiality being shown in the allocation of funds. There is partiality in announcing Special Schemes. There is partiality in passing legislations. There is partiality as regards languages, religion and race. This BJP is a Government full of partiality. It was seen during the last 10 years as a Government engaged in partisan approach. It is being continued now with no difference in their behaviour. It was never a Government for all. India is the biggest democracy of the world and the Parliament, which is the lifeline of our country, has a historical importance on its own. World famous leaders, administrators have been our Prime Ministers, Union Ministers, and MPs in the past and this is the House where they participated in the constructive discussions. The hon. Prime Minister and other Ministers used to hear what others speak in this august House. But we see nowadays not even the MPs of the ruling party were aware of when the hon. Prime Minister will come to Parliament. Only one solace to this matter is that as the people of this country have given a specific mandate for a strong presence of opposition parties, the hon. Prime Minister comes to this House for at least replying to the views of the hon. Leader of the Opposition. The BJP Government is just providing answers to the issues or questions raised by the hon. Members of Parliament in this House. We do not only expect replies. We want concrete actions. I want to know for how many demands raised in this august House, the BJP Government has taken actions. Whether any one of the demands raised by the Opposition was accepted by the BJP Government? The BJP Government should try to differentiate between governance and politics separately. The BJP should stop using this Union Government for its political mileage. Rameswaram is in my Ramanathapuram Parliamentary Constituency where we have the world-famous temple. Lakhs and lakhs of pilgrims visit this place every year. Our Prime Minister, Union Ministers and other dignitaries come to this place more often. This place should be upgraded as a tourist destination. I have placed this demand several times for consideration by the Government during the last five

* Original in Tamil

years. In the Budget presented by our hon. Finance Minister, it was informed that importance will be given to upgrade the tourist centres in our country. They have allocated special funds for upgrading the holy places of Bihar in this Budget. They call this as development of tourism. You are able to see the holy places of Bihar. Rameswaram is a place of tourist importance which you often use for political reasons. Are you not able to see Rameswaram? The Prime Minister and the Ministers frequently visit Rameswaram. But they are not concerned about the development of this place as it is not visible to them. You give importance to our Rameswaram only for political and election gains and nothing else. What is the action taken by you for the development of Ramanathapuram District? So many districts of the country have been identified as aspirational districts. It means these are the districts which are mainly to be taken up for development. Ramanathapuram District in my Ramanathapuram Parliamentary Constituency and Virudhunagar District are in the list of backward districts of the country. But these districts remain identified for name's sake. No special fund or assistance was provided for developing these backward districts. I want to ask this Government how they will develop these backward districts without allocating any money. I have time and again demanded that a fertiliser factory, palm tree and coconut tree related industries, industries relating to sea products have to set up in this area for providing employment. But nothing has been done by this Government. It has not fulfilled anything. I also placed my demands with the Ministers of Departments concerned. But it was in vain, nothing could take place. They should not only give replies but they should act accordingly. The Union Government should distribute 41 per cent of its tax revenue to the States as per the 15th Finance Commission. But the Union Government distributes only 32 per cent to the States. Tamil Nadu remains a State which is earning more revenue to the Union Government. For every rupee given by Tamil Nadu, the Union Government gives back only 29 paise. But Uttar Pradesh Government, if it pays Rs 1, gets back Rs. 2 and 23 paise. Bihar gets Rs.7 and 6 paisa as against every one rupee given to this Union Government by the State. This is what is called as biased devolution of funds. There are demands for increasing the limit set for spending under the Rural and Urban Housing Schemes. This was not considered in this Budget. The contribution by the State Government is more in the PM Housing Scheme. Without allocating funds under this Scheme, the number of houses to be built under the scheme is increased by the Union

Government. The State Government has to bear an additional burden due to this. For a scheme where the State Government allocates more funds, but is it apt that the Scheme is named after the Prime Minister? In the Budget the capital gain tax on shares has been increased. If one sells the finance and non-finance related assets, and if he gets the profit, then that is called the capital gain tax. In the 2024-25 Budget, short-term capital gain tax for the shares has been raised from 15 per cent to 20 per cent. The long-term capital gain tax has been increased from 10 per cent to 12.5 per cent. This will definitely affect the middle-class people very much. Therefore, the Union Government should take back this announcement. Similarly, the long-term capital gain tax on properties was reduced from 20 per cent to 12.5 per cent. If such properties like plots and houses, including loan bonds, are purchased during 2001-02 or after, the scheme of indexation is removed. If you now try to sell a property purchased by you long back, the procurement price of the investment is corrected as reflective of inflation, accordingly.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude your speech.

*SHRI K. NAVAS KANI (RAMANATHAPURAM): Ok Sir. I want to raise another important issue in this august House. Our Tamil fishermen are attacked by the Sri Lankan Navy time and again. I have demanded here that this issue needed immediate intervention and permanent long-lasting solution. We have placed this demand long ago. But without finding a permanent solution, our fishermen are arrested frequently by the Sri Lankan Navy; their fishing boats are confiscated; resulting in loss to lives and property to fishermen. Near the Delft Island (Neduntheevu) on 1st August 2024 four fishermen of Ramanathapuram, who went on sea for fishing, were attacked by the Sri Lankan Navy's patrolling party. The motor boat got capsized and a fisherman named Ramasamy died. The dead body of another fisherman is being searched as he seems to be missing. Two other fishermen were arrested and released later. Our Tamil fishermen lose their lives due to such attacks. Is it not visible to this Union Government? On 3rd August 2024, four fishermen belonging to Jegathappattinam were arrested along with a motor boat in the Ramanathapuram Parliamentary Constituency. In the Ramanathapuram Constituency, as many as 25 fishermen of Pamban area were arrested by the Sri Lankan Navy with their four country boats on 1st July 2024.

* Original in Tamil

Out of which, only 14 persons were released so far. Nine fishermen and two boats are to be released. On the evening of 22nd July 2024, Sri Lanka has taken into their custody another nine Indian fishermen along with three motorised boats. I have raised this issue several times in this august House. No action has been taken by the Union Government. Talks between the fishermen of the two countries should take place immediately. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has provided a compensation of Rs.10 lakh from the Chief Minister's Relief Fund to each of the fishermen who were arrested earlier by the Sri Lankan Navy and later died. The hon. Chief Minister *Annan* Thiru M.K. Stalin has also provided Rs. 6 lakh each to the confiscated and unrecoverable boats and Rs.2 lakh for the unrecoverable country boats. But the Union Government has not given a single rupee to the affected fishermen and their families. It should, therefore, give compensation fund to the victims. This Government is against the welfare of minorities and passing legislation against the minorities. In all the BJP-ruled States, there is a situation prevailing that the minorities are not safe. The State Government of Uttar Pradesh has issued an order for closure of the unapproved *Madarsas*.

1849 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

It has also stated that those who studied in *Madarsas* cannot continue pursuing their general education in other schools. This Union Government and the Governments in the BJP-ruled States are deceiving the minorities in a continuous manner. Our External Affairs Minister while making a Statement on Bangladesh today in Lok Sabha said that the safety and security of the minorities living in Bangladesh will be protected. This Government is so much concerned about the safety and security of minorities living in a neighbouring country. Similarly, this Government should also ensure the safety and security of minorities living in the country by allowing them to protect their rights. Thank you.

(ends)

(1850/SPS/AK)

1850 बजे

श्री राव राजेन्द्र सिंह (जयपुर ग्रामीण) : महोदय, इस संसार के सार में मनुष्य का जो स्वरूप है, उसको अभिव्यक्त करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसी का यह शिरोधार्य मंच है। मैं अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बात को सूक्ष्म की सार्थक परिणाम तक सीमित रखता हुआ अपने विवेचन को आर्थिक व्यवस्था की उस स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो ये सूक्ष्म क्षण आपने मुझे प्रदान किए हैं।

आदरणीय, मैं आपका ध्यान उस वक्तव्य की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, जिस वक्त हम 8वीं कक्षा के छात्र थे और अर्थशास्त्र की प्रारम्भिक परिभाषा पढ़ रहे थे। किसी गुरु ने हमें यह बताया था कि जिस मुद्रा को आप लोग आदान-प्रदान के रूप में प्राप्त करते हैं, उसकी सूक्ष्म परिभाषा यह है कि : "money is a matter of four functions - a medium, a measure, a standard and a store". आज सुबह से अभी तक जितने भी वक्तव्य आए हैं, वे इन्हीं चार के दायरे में सीमित हैं। मैं आपका ध्यान उस व्यवस्था की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके इस आसन के ठीक पास में न्याय के मूर्त रूप में एक ऐसी चीज विद्यमान है, जिसको हम न्याय कहते हैं। न्याय कानून से परे है। हम पाश्चात्य सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जो सीमित आदर्श लेते हैं, उसका मूल मंत्र यह है कि प्रतिस्पर्धा के अंतिम परिणाम में - survival of the fittest होगा. सनातन धर्म की व्यवस्था जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शुरू होती है, उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कोई ज्ञान नहीं है। हमें वह यह व्यवस्था देती है कि आप अपनी व्यवस्था में यह न्याय करें कि जो अपने से पीड़ित है, अपने से कमजोर है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था पैदा करें कि वह भी जीवन, स्वावलंबन, स्वाभिमानपूर्वक परिव्यक्त कर सके। इसी परिवल्लित और परिपक्व शासन व्यवस्था का नाम भारत की सरकार का है, जो आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने तीसरे कार्यकाल की शुरूआत कर रही है।

मैं व्यवस्था के अनुरूप पाठ्यक्रम में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस व्यवस्था की धुरी पर आज पूरा का पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आपको प्रतिमान की प्रथम पंक्तियों में प्रतिस्पादित करने की प्रतिस्पर्द्धा में श्रीगणेश कर रहा है, आज वहीं इस सदन के अंदर ऐसा भी पक्ष है, जो इसको नकारना चाहता है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि करुणा जनित सहानुभूति का उद्देश्य एक सरकार का परम धर्म है। परदु:खकातरता और परोपकार के कार्य में संलग्नता उसका क्रियात्मक प्रतिफलन है। जन सामान्य की व्यथा और वेदना के समाहार के लिए जब कुछ पवित्र मनोभावों से प्रभावित, प्रचालित और संचालित होकर

आज महापुरुष संघबद्ध होते हैं, तब इस सदन का स्वरूप प्राप्त होता है। इस सदन के माध्यम से समाज के संताप के परिहार की योजनाएं बनती हैं। उन योजनाओं का श्रीगणेश करने के लिए आप और हम यहां एकत्रित हुए हैं।

(1855/MM/UB)

मैं उन घोषणाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं। आपसे चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद के स्वरूप में जो समय मिला है उसका सूत्रपात में अपना अंकेश प्रस्तुत कर सकूं।

हमारे इस सदन में अनेक प्रकार के वक्तव्य आए हैं, लेकिन मैं एक वक्तव्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नौ मूल विचारधाराओं पर आश्रित हमारा यह बजट है। पहली विचारधारा के आधार पर उन्होंने कहा- किसान और कृषि के कल्याण हेतु नवाचार। इस भारत की धरा पर 5104 क्यूबिक किलोमीटर की बरसात होती है। आप इसमें से केवल 10 प्रतिशत पानी का ही संग्रह कर सकते हैं, शेष पानी सागर में चला जाता है। अगर आपको इस अर्थव्यवस्था में किसान को लाभ पहुंचाना है तो आपको नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी होगी। आज इस अर्थशास्त्र की व्यवस्था में जो वित्त विलेखे हैं, उनमें किसान के प्रति संवेदनशीलता और मर्यादित उपक्रम के माध्यम से नवाचार का जो प्रचार किया गया है, उसको मूर्त रूप प्रदान करने की व्यवस्था है। इन अभिलेखों के माध्यम से किसान के घर, और आम आदमी के घर तक पीने का पानी पहुंचे और किसान के खेत को सिंचाई का पानी मिले, यह हमारी आज की अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता है।

मैं दूसरी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमने अर्थव्यवस्था के बारे में कर लगने और कर न लगने के बारे में हर प्रकार की बहस की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज पहली बार इस बात का आभास हो रहा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु अंतरिक्ष में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। चंद्रयान के मायने से अगर हम साउथ पोल पर गए तो वह विज्ञान का कीर्तिमान था। अगर हम मंगल ग्रह पर जाने की शुरुआत कर रहे हैं तो यह भी विज्ञान का कीर्तिमान है। हम स्पेस को कॉमर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वर्ष 2023 में स्पेस नीति लेकर आए। हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जो हॉलीवुड में मूवी बनाने में जितना पैसा लगता है, उतने में तो भारत एक सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकता है। यह इकोनॉमिक फोरम का वह मानचित्र है जो पूरे संसार को अचंभित कर देता है। सौ रुपये में कोई काम होता है तो वह दस प्रतिशत पर मानव संपदा के आधार पर प्रतिपादित हो सकता है। मैं इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्पेस और टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी में इसरो का 15

अगस्त, 1969 को जन्म हुआ तब से अब तक हम 124 स्पेसक्राफ्ट मिशन पूरा कर चुके हैं। 432 फॉरैन सेटेलाइट्स स्थापित कर चुके हैं और 98 लॉन्च की स्थिति में हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब से हमने अपनी अर्थव्यवस्था में स्पेस के लिए नीति बनायी है, हमारे डीपीआईआईटी में 124 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आज इस व्यवस्था को अंजाम देने के लिए आपको वैज्ञानिक परिदृश्य के अंदर उस पूरी अर्थव्यवस्था का मापदंड की पूर्ति करने का एक मानचित्र चाहिए था। आज इसी मानचित्र के आधार पर यह बजट अग्रसर करता है। मैं यह नहीं कहता कि सम्पूर्ण मानचित्र का ब्लू प्रिंट रातों-रात बन गया। सभी वर्गों का और सभी सरकारों का इसमें समय-समय पर योगदान रहा है, लेकिन यह दृष्टि और विज़न वर्तमान सरकार का है। इसीलिए इसका परिणाम और पारितोषिक भी इसी सरकार को जाता है।... (व्यवधान)

I cannot hear you. Can you speak loudly?

मैं इसके लिए सरकार का आभारी हूं। इस सदन का भी मैं आभारी हूं कि मेरा पहली बार इस सदन में आने का सौभाग्य मिला है। जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है, मैं उसका नतमस्तक होकर अभिनंदन और स्वागत करता हूं।

महोदय, मैं सदन से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आप और हम संसार के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं, उसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस चरित्र को प्रतिपादित करने की भी क्षमता होनी चाहिए जो दुर्लभ परिस्थितियां हैं, उनको सुलभ बनाने का हमारे पास क्या मानचित्र है? आज हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। आज इस दस्तावेज के आधार पर यह बात मालूम पड़ती है कि न्यूक्लियर एनर्जी में हम छोटे प्रकार के न्यूक्लियर प्लांट लगाने जा रहे हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें प्राइवेट लोग भी निवेश करना चाहेंगे। ऐसा इसमें लिखा है, लेकिन यह बात आपको और सदन को ध्यान में होनी चाहिए कि वर्ष 1962 एटॉमिक एनर्जी के एक एक्ट के उपरांत वर्ष 1981 में मेकॉनी कमेटी ने यह कहा कि एक इंडिपेंडेंट रेग्युलेटर होना चाहिए तो एईआरबी के नाम से आपने रेग्युलेटर पैदा किया, लेकिन वह रेग्युलेटर सैक्शन 27 के माध्यम से आता है। 16,17 और 23 जो एटॉमिक एनर्जी का एक्ट है, वह उसे स्वायतत्ता प्रदान नहीं करता है।

(1900/YSH/SRG)

अधिकार तो प्रदान करता है इसलिए अगर न्युक्लियर एनर्जी को व्यवस्थित करना है, चूँकि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और अगर न्युक्लियर सिविल लाइबिलिटी के अंदर कोई भी विवाद होगा और अगर आपके इस रेगुलेटर के पास स्टैच्युटेरी अथॉरिटी नहीं होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी व्यक्ति उस पर प्रश्नचिह्न लगा देगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सात बज रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष जी, अगर आप कहेंगे तो मैं कनक्लूड कर दूंगा। I do not disobey any sort of order from anywhere. मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ। यहां पर बहुत सी आशंकाएं व्यक्त की गईं कि अर्थव्यवस्था की इस व्यवस्था के अंदर हमारे पास बाहर से निवेश नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ एक ही चीज देख रहा हूं कि जब से भारत सरकार की सिक्योरिटीज़ को जेपी मॉर्गन के एक इमर्जेंट बॉन्ड इडेक्स में स्थान मिला है, तब से आज की तारीख में 25 बिलियन डॉलर का निवेश आ गया है और लिस्टिंग होने के समय सिर्फ एक हफ्ते के अंदर-अंदर 10 बिलियन डॉलर का निवेश आ गया था। बाहर के बैठे हुए व्यक्ति को आज भी भारत में निवेश करने की पूरी जिज्ञासा है और यहां का प्रतिपक्ष यह बात कहता है कि यहां की अर्थव्यवस्था सही नहीं है। इससे बड़ा और क्या सत्य हो सकता है कि बाहर का व्यक्ति भारत में पैसा लगाने के लिए तैयार है। भारत की अर्थव्यवस्था में मूल रूप से वर्तमान सरकार का जो अपना विजन है, उसको हमने ही नहीं, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संसार ने स्वीकार किया है। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 7 अगस्त, 2024 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1902 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 7 अगस्त, 2024 / 16 श्रावण 1946 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।